आरआईएस

वार्षिक रिपोर्ट

2018–19

आरआईएस

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

विषय वस्तु

अध्यक्ष का संदेश.....iii

महानिदेशक की रिर्पोट..... v

अध्याय 1. नीतिगत अनुसंधान.....1

अध्याय 2. नीति शोध पत्र.....31

अध्याय 3. नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन,
संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ..... 35

अध्याय 4. क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम.....85

अध्याय 5. प्रकाशन कार्यक्रम..... 91

अध्याय 6. आंकड़ें एवं सूचना केन्द्र.....97

अध्याय 7. मानव संसाधन.....101

अध्याय 8. वित्तीय विवरण.....107

संचालन परिषद

अध्यक्ष

डॉ. मोहन कुमार

पदेन सदस्य

श्री विजय गोखले
विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय

डॉ. अनूप वाधवन
वाणिज्य सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

श्री अतानू चक्रबर्ती
सचिव
आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

श्री टी. एस. त्रिमूर्ति
सचिव (आर्थिक संबंध)
विदेश मंत्रालय

प्रोफेसर आशुतोष शर्मा
सचिव
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अपदेन सदस्य

श्री जयंत दासगुप्ता
डब्ल्यूटीओ में भारत के पूर्व राजदूत

श्री शेषाद्री चारी
वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक एवं लेखक

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ
अध्यक्षा, एचडीएफसी बैंक, मुबंई

सदस्य सचिव (पदेन)

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक, आरआईएस

अनुसंधान सलाहकार परिषद

अध्यक्ष

श्री एस. टी. देवरे
पूर्व सचिव
विदेश मंत्रालय

सदस्य

प्रोफेसर एन. एस. सिद्धार्थन
मानद प्राध्यापक, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स

प्रोफेसर पुलिन बी. नायक
भूतपूर्व निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स

सुश्री सिंधुश्री खुल्लर
भूतपूर्व सीईओ, नीति आयोग

प्रोफेसर रथिन रॉय
निदेशक
राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान

सुश्री नगमा मल्लिक
सह सचिव (पी पी एण्ड आर)
विदेश मंत्रालय

विशेष आमंत्रित सदस्य

डॉ नागेश कुमार
प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र एस्कैप के दक्षिण और दक्षिण–पश्चिम एशिया कार्यालय (संयुक्त राष्ट्र एस्कैप–एसएसडब्ल्यूए), नई दिल्ली

सदस्य सचिव

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक, आरआईएस

राजदूत डॉ मोहन कुमार

अध्यक्ष का संदेश

आरआईएस विकासशील देशों के एक थिंक टैंक के रूप में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। संस्थान ने 20–22 मार्च 2019 को ब्यूनस आयर्स में आयोजित 'दक्षिणीय सहयोग पर द्वितीय उच्चस्तरीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (बापा + 40)' में सक्रियतापूर्वक और अत्यंत प्रभावकारी रूप से भाग लिया। इस अवसर पर इन आलेखों को प्रस्तुत किया गया: *'राउल प्रेबिस्च और विकास रणनीति', 'एक साथ मिलकर एक स्वस्थ भविष्य की ओर: स्वास्थ्य सेवा में भारत की साझेदारी', 'डेवलपमेंट कोऑपरेशन रिव्यू का विशेष अंक'* और *'ग्लोबल साउथ में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखलाओं की बढ़ती ताकत (आईटीसी, जिनेवा के साथ संयुक्त रूप से)।'* इसके अलावा भी अलग से कई आयोजन इन विषयों पर किए गए : *'दक्षिणीय सहयोग पर एशियाई गाथाओं का अन्वेषण करना', 'प्रभाव आकलन और निगरानी एवं मूल्यांकन बनाम दक्षिणीय सहयोग: विचार–विमर्श की स्थिति', 'स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच के लिए दक्षिण–दक्षिण सहयोग'* और *'दक्षिणीय सहयोग' की बहुलता।'*

इससे पहले अगस्त 2018 में आरआईएस ने अपने प्रतिष्ठित 'दिल्ली प्रोसेस IV' के एक हिस्से के रूप में 'दक्षिणीय और त्रिकोणीय सहयोग' पर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने विचार–विमर्श में हिस्सा लिया। संस्थान ने टी–20 सम्मेलनों में भी भाग लिया और अपने अहम योगदान के रूप में इन विषयों पर नीतिगत सार–पत्र पेश किए : 'विकास के लिए सतत वित्त पोषण'; '2030 एजेंडे को लागू करने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार का इस्तेमाल' और 'सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा – जी20 के लिए नीतिगत सिफारिशें।'

इनके अलावा, संस्थान ने कई अन्य प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन किया जिन पर वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट में विधिवत प्रकाश डाला गया है। संस्थान का अनुसंधान एजेंडा इन चार स्तंभों के इर्द–गिर्द घूमता है: वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना; व्यापार, निवेश एवं क्षेत्रीय सहयोग पर पहल; व्यापार, सुविधा, संपर्क एवं क्षेत्रीय एकीकरण; और नई प्रौद्योगिकियां एवं विकास के मुद्दे। इस व्यापक रूपरेखा के तहत कई अध्ययन किए गए हैं और संबंधित प्रकाशन या रिपोर्ट पेश की गई हैं।

वैश्विक विकास पहल

राष्ट्रीय स्तर पर, सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि में साथी विकासशील देशों के साथ अपने विकास के अनुभवों को साझा करने की आवश्यकता महसूस की गई है। इस संबंध में आरआईएस ने अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी), ब्रिटेन के साथ मिलकर एक वैश्विक विकास पहल (जीडीआई) का शुभारंभ किया है।

मैं आरआईएस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में बहुमूल्य योगदान देने के लिए आरआईएस की संचालन परिषद और सामान्य निकाय (जनरल बॉडी) में शामिल अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं। मैं इस संबंध में विदेश सचिव श्री विजय केशव गोखले का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। महानिदेशक के नेतृत्व में आरआईएस की टीम आरआईएस के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तन्मयता के साथ निरंतर प्रयासरत है।

मोहन कुमार

महानिदेशक की रिपोर्ट

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी

विकासशील देशों के लिए एक नीतिगत अनुसंधान संस्थान होने के नाते हम अत्यधिक महत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर विकासशील देशों को विश्लेषणात्मक सहयोग प्रदान करने के अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहे हैं। यह संस्थान पिछले साढ़े तीन दशकों के दौरान अपने कार्यकलापों में कई गुना विस्तार करके एक वैश्विक थिंक–टैंक के रूप में उभर कर सामने आया है। हमने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ अपनी साझेदारियों को व्यापक बनाया है। प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान करने तथा विभिन्न हितधारकों के बीच समृद्धि के साझाकरण को और आगे बढ़ाने के लिए नीतियों के निर्माण में सरकार को आवश्यक सहयोग देने के लिए भारत सरकार के साथ अपनी सहभागिता को काफी बढ़ा दिया है। इन पहलों के अपेक्षित परिणाम सुनिश्चित करते समय आरआईएस व्यापार, निवेश, वित्त, प्रौद्योगिकी और व्यापक विकास मुद्दों के चयनित क्षेत्रों में अपनी मुख्य क्षमता एवं विशेषज्ञता के प्रति सचेत है।

हाल के महीनों में आरआईएस कई अग्रणी क्षेत्रों में अपेक्षित परिणाम देने में सफल रहा है। वर्ष 2024 तक भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के राष्ट्रीय लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आरआईएस विशिष्ट क्षमता वाले हमारे क्षेत्रों से जुड़े लक्ष्यों के मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस संबंध में संचालन परिषद और अनुसंधान सलाहकार परिषद के मार्गदर्शन में हमने उन नई चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने पर काम किया है जिनका सामना भारत घरेलू और बाह्य मोर्चों पर कर रहा है या करने की संभावना है।

इस वर्ष आरआईएस ने कई मुद्दों पर विदेश मंत्रालय के साथ अपने संबंधों को व्यापक बनाने का क्रम जारी रखा है तथा इसके साथ ही कई और एजेंसियों एवं संस्थानों को साथ लाकर संबंधित परिवेश का विस्तार भी किया है। संस्थान का उद्देश्य विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रभागों के साथ काम करके विदेश मंत्रालय के साथ अपने जुड़ाव को और बढ़ाया है। इस वर्ष हम प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएम–ईएसी), नीति आयोग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आयुष मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय, दक्षिणीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओएसएससी) और कई राष्ट्रीय मंचो के साथ काम कर सका हैं। इस वर्ष हमें इंडोनेशिया सरकार के साथ काम करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, जैसा कि रिपोर्ट में बाद में बताया गया है।

आरआईएस ने अनुसंधान के चार व्यापक क्षेत्रों पर निरंतर अपना ध्यान केंद्रित रखा। इनसे जुड़ी मुख्य विशेषताओं को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना

वर्ष 2022 में जी20 की भारतीय अध्यक्षता को ध्यान में रखते हुए हमने विशेष क्षेत्र–वार आयामों पर कार्यक्रम शुरू किय हैं। विशेष रूप से अफ्रीका से संबंधित क्षेत्रीय मुद्दों पर तथा अफ्रीका में औद्योगीकरण, विनिर्माण और आईसीटी के संदर्भ में अवसरों, चुनौतियों एवं प्रमुख नीतिगत कदमों का पता लगाने के लिए आरआईएस के कार्यक्रम में एजेंडा 2030 का महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही विभिन्न अध्ययनों ने लक्ष्य विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि

स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला–पुरुष समानता, ब्लू इकोनॉमी और वैश्विक साझेदारी में अहम योगदान दिया। दक्षिणीय सहयोग वित्त एवं विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे आपस में संबंधित मुद्दों के साथ सतत विकास लक्ष्य पर हमारी धुरी बना रहा। साथ ही विकास सहयोग पर कई अध्ययन भी किए गए।

व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल

आरआईएस भी अत्यंत सक्रियतापूर्वक ऐसे अध्ययनों में संलग्न रहा है, जिनका उद्देश्य एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका में मेगा–एफटीए के उदय के मद्देनजर नए देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना और देश की भावी निर्यात रणनीति तैयार करना है। हमने भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से दक्षिण एशियाई देशों जैसे ईरान, बांग्लादेश, मालदीव एवं अफगानिस्तान के अलावा लैटिन अमेरिकी एवं कैरिबियन (एलएसी) क्षेत्र के साथ भी द्विपक्षीय व्यापार संबंधों और भारत–मॉरीशस व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर कई केंद्रित अनुभवजन्य शोध अध्ययन किए हैं।

यह भी रेखांकित करने की आवश्यकता है कि पिछले कुछ वर्षों से हम ज्ञान साझा करने के साथ–साथ नीतिगत अनुसंधान के जरिए इब्सा देशों में सहयोग की संभावनाओं जैसे मुद्दों पर भी काम करने में संलग्न रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने आरआईएस में इब्सा फेलोशिप कार्यक्रम भी शुरू किया है। इस वर्ष भी इब्सा रिसर्च फेलो की भागीदारी के साथ इब्सा फेलोशिप का दूसरा संस्करण फरवरी 2019 में आरम्भ हुआ। भारत–अफ्रीका संबंधों पर नए सिरे से विशेष जोर दिए जाने के मद्देनजर आरआईएस ने एशिया–अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (एएजीसी) के अंतर्गत कई अध्ययनों की शुरुआत की है, जिनके तहत 'डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट' की रूपरेखा के अंतर्गत भारत और अफ्रीकी देशों के बीच गहरे जुड़ाव की संभावनाओं की तलाश की गई है।

विकासशील देशों में वित्तीय क्षेत्र का विकास असमान और विविध रहा है। भारत ने हाल के महीनों में कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए हैं। स्थानीय मुद्रा से जुड़े पूंजी बाजारों के विकास और व्यापार इन्वॉयस–प्रक्रिया के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को अधिक से अधिक प्रमुखता दी जा रही है। आरआईएस ने स्थानीय मुद्रा से जुड़े पूंजी बाजारों के साथ–साथ बिम्सटेक में स्थानीय मुद्रा और वित्तीय प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर अध्ययन कार्य शुरू किए हैं।

क्षेत्रीय स्तर पर हमारे 'पड़ोसी पहले' सिद्धांत को आगे बढ़ाने में एक क्षेत्रीय और रणनीतिक संघ (कंसोर्टियम) के रूप में बिम्सटेक की प्रासंगिकता भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में कुछ अध्ययन भी किए जा रहे हैं। आरआईएस दरअसल बिम्सटेक नेटवर्क ऑफ थिंक–टैंक्स (बीएनपीटीटी) का भी हिस्सा है।

व्यापार सुविधा, संपर्क और क्षेत्रीय एकीकरण

यह संस्थान क्षेत्रीय एकीकरण के अन्य पहलुओं पर भी काम करता रहा है। हाल ही में किए गए अध्ययन संपर्क और क्षेत्रीय एकीकरण की ओर उन्मुख हैं। आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) ने आसियान देशों के साथ जुड़ाव के प्रमुख क्षेत्रों पर निरंतर अपना ध्यान केंद्रित रखा है। एआईसी ने त्रिकोणीय राजमार्ग पर अध्ययन करने के लिए ईरिया के साथ मिलकर काम किया। एआईसी ने भारत और आसियान देशों के

बीच उत्पादन नेटवर्कों के साथ–साथ 'आसियान आर्थिक समुदाय 2025' की प्रासंगिकता का पता लगाने में भी योगदान दिया।

नई प्रौद्योगिकियां और विकास के मुद्दे

नई तकनीकों और अनकी पहुंच, समावेश एवं समता पर उनके प्रभाव पर आरआईएस के शोध ने विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए कई प्रकाशनों या आलेखों एवं नीतिगत जानकारियों को सृजित करना जारी रखा। सेक्टर के स्तर पर हमारे विशिष्ट कार्यों ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि कैसे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे अनूठे परिवर्तन स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की तस्वीर को बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। ये परिवर्तन न केवल आधुनिक चिकित्सा तक सीमित हैं, बल्कि विभिन्न देशों में पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के दायरे और उपयोग को भी प्रभावित करते हैं। हमारे अनुसंधान कार्यक्रम पारंपरिक चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, औषधीय पौधों के व्यापार एवं खेती, वेलनेस पर्यटन और अन्य प्रासंगिक पहलुओं के बीच जटिल तालमेल की संभावनाओं का भी पता लगाते हैं।

नीतिगत सामंजस्य को मजबूत बनाना

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर नीतिगत सामंजस्य को मजबूत करने के लिए प्रभावकारी नीतिगत संवाद को बढ़ावा देना हमारे कार्यकलापों का मुख्य आधार है। वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग के एक ज्ञान साझेदार के रूप में आरआईएस ने जून 2018 में मुंबई में आयोजित एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की वार्षिक बोर्ड बैठक के लिए इससे जुड़ी आठ संगोष्ठियों के आयोजन की जिम्मेदारी ली। इस संबंध में हमने भी *'अवसंरचना के लिए वित्त जुटाने के लिए नई तलाश'* नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया।

अन्य प्रमुख पहलों के माध्यम से नीतिगत विशिष्ट पारस्परिक कड़ियों के साथ आरआईएस कनेक्ट जारी रहा। इस संबंध में हमारे कार्यक्रम के अंतर्गत इन विषयों पर परिचर्चाएं शामिल थीं – 'दक्षिणीय एवं त्रिकोणीय सहयोगः सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य और अनुभवजन्य वास्तविकताएं', 'वैश्विक विकास पर पहल की शुरुआत', 'दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाएं तलाशने पर नीतिगत संवाद।'

इस वर्ष हमारी सबसे सफल नीतिगत जानकारियां टिकाऊ कृषि के अलावा सतत विकास लक्ष्य–2 के तहत 'सभी के लिए स्वस्थ भोजन' सुनिश्चित करने और आसियान 10वां 'दिल्ली–संवाद' पर थीं। इन दोनों ही क्षेत्रों ने बड़े पैमाने पर विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। आरआईएस ने 'नीली अर्थव्यवस्था पर दूसरी आसियान–भारत कार्यशाला' और 'बिम्सटेक शिखर सम्मेलन से पहले उच्च स्तरीय परामर्शदात्री बैठक' की भी मेजबानी की। 'विज्ञान राजनय कार्यक्रम के शुभारंभ' के साथ ही यह नवीनतम पहल इस वर्ष हमारे पोर्टफोलियो में जुड़ गई।

आउटरीच और क्षमता निर्माण

विभिन्न संस्थागत पहलों के माध्यम से आरआईएस सभी के फायदे के लिए ज्ञान के आदान–प्रदान और विकास के अनुभवों को साझा करने के लिए अपनी आउटरीच संबंधी क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरों को बढ़ाने में सक्षम रहा है। इन संस्थागत पहलों में आसियान–भारत केन्द्र, वैश्विक विकास पहल (जीडीआई), विकास सहयोग के लिए

महानिदेशक की रिपोर्ट

फोरम, विज्ञान राजनय के लिए फोरम (एफआईएसडी), ब्लू इकोनॉमी फोरम (बीईएफ), भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के लिए फोरम (एफआईटीएम), नीतिगत अध्ययनों के लिए दक्षिण एशिया केंद्र (एसएसीईपीएस), ब्रिक्स अकादमिक फोरम, बिम्सटेक नेटवर्क ऑफ पॉलिसी थिंक टैंक्स (बीएनपीटीटी), आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स (एआईएनटीटी), नेटवर्क ऑफ सदर्न थिंक–टैंक्स (नेस्ट) और इब्सा अकादमिक फोरम शामिल हैं।

आरआईएस को वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक मुद्दों पर क्षमता निर्माण को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है। यह संस्थान इन विषयों पर प्रमुख आईटीईसी कार्यक्रम आयोजित करता हैः 'विज्ञान राजनय', 'दक्षिणीय सहयोग सीखना' और 'अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों एवं विकास नीति पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम'। इस श्रृंखला में 'सतत विकास लक्ष्य' और 'व्यापार एवं निरंतरता' नामक दो नए कार्यक्रम जोड़े गए। इनके अलावा, 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत और व्यवहार पर आरआईएस–एक्जिम बैंक समर स्कूल' का तीसरा संस्करण भी आयोजित किया गया था।

प्रकाशन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कई आलेखों को प्रस्तुत करने के साथ–साथ इन्हें हितधारकों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। इनमें अन्य के अलावा ये विषय शामिल हैंः *'ग्लोबल साउथ में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखलाओं की बढ़ती ताकत', 'राउल प्रेबिस्च और विकास रणनीति', 'एक साथ मिलकर एक स्वस्थ भविष्य की ओरः स्वास्थ्य सेवा में भारत की साझेदारियां', 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर दक्षिणी परिप्रेक्ष्य', 'विकास के लिए व्यापार और वित्तः दक्षिणी परिप्रेक्ष्य', 'चौथे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के लिए सिफारिशें', 'सतत विकास लक्ष्यः विकासशील देशों की ओर से परिप्रेक्ष्य', 'दक्षिणीय सहयोगः विज्ञान राजनय की भूमिका', 'व्यापार एवं निरंतरता पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य', 'दस दिल्ली संवाद, आसियान–भारत केन्द्र (एआईसी)', 'स्थानीय मुद्रा में व्यापारः नेपाल, ईरान एवं रूस के साथ भारत के रुपया व्यापार का दृष्टांत', 'क्या भारत डिजिटल रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए तैयार है?'*, और *'भारत में सतत विकास लक्ष्य के लिए उभरती वैचारिक रूपरेखा और निगरानी व्यवस्था'*।

इस अवसर पर मैं निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग के लिए अपने अध्यक्ष, संचालन परिषद के सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। श्री सुधीर देवरे के नेतृत्व में आरआईएस की अनुसंधान सलाहकार परिषद सदैव अत्यंत मददगार रही है और इसने हमारे शोध को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहन प्रदान किया है।

हम आरआईएस के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए भारत सरकार, विशेषकर विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नीति आयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आयुष मंत्रालय और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों के अन्य साझेदार संगठनों के प्रति आभारी हैं।

मैं आरआईएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सतत रूप से अहम सहयोग देने के लिए संकाय और प्रशासन के सभी प्रकोष्ठों के अपने सभी सहयोगियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।

सचिन चतुर्वेदी

नितिगत अनुसंधान

अध्याय 1

वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: जी20 पर कार्यक्रम

वर्ष 2022 में जी20 की भारतीय अध्यक्षता की पृष्ठभूमि में आरआईएस का कार्यक्रम उन विषयगत और क्षेत्रवार (सेक्टोरल) आयामों पर केंद्रित है, जो जी20 प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जी20 प्रक्रिया की बारीकियों को समझने के लिए आरआईएस में विभिन्न अध्ययन किए गए हैं। कुछ अध्ययनों में विशेषकर अफ्रीका के संबंध में क्षेत्रीय फोकस रहा है। अफ्रीका में निवेश और व्यापार को आगे बढ़ाने में जी20 की भूमिका पर किए गए अध्ययन में 'सीएफटीए' के बाद के दौर पर फोकस करते हुए व्यापार और निवेश एकीकरण को मजबूत करने के लिए जी20 प्रक्रिया के जरिए अफ्रीका को सहयोग प्रदान करने के तरीकों पर गौर किया गया है।

सीएफटीए के बाद के दौर में अफ्रीका में व्यापार और निवेश तेजी से बढ़ाने में जी20 की भूमिका

डॉ. प्रियदर्शी दाश

जी20 के 'कॉम्पैक्ट अफ्रीका' कार्यक्रम का उद्देश्य इसमें सहभागिता करने वाले अफ्रीकी देशों में निवेश को बढ़ावा देना है, ताकि विकास के मार्ग में मौजूद अड़चनों को दूर किया जा सके। वहीं, दूसरी ओर अफ्रीकी देश अपने ठोस प्रयासों के जरिए प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं और चीन एवं भारत जैसे उभरते बाजारों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के अवसर तलाश रहे हैं। व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (सीएफटीए) को अफ्रीका में आर्थिक एकीकरण को गहरा करने की दिशा में एक अहम कदम के रूप में देखा जाता है। जहां तक जी20 का सवाल है, इसमें कई विकसित देशों के साथ–साथ उभरते बाजारों का भी प्रतिनिधित्व है। यह जी20 देशों और अफ्रीका के बीच टिकाऊ साझेदारी के निर्माण के लिए विभिन्न सेक्टरों एवं मुद्दों की पहचान के लिए एक उपयुक्त मंच या प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। यह अध्ययन दरअसल अफ्रीका में व्यापार और निवेश एकीकरण के मौजूदा रुझानों के साथ–साथ इस प्रयोजन को आगे बढ़ाने में जी20 के ठोस कदमों के विभिन्न पहलुओं पर गौर करने का एक उल्लेखनीय प्रयास है। इस थीम या विषय पर एक नीतिगत सारपत्र का मसौदा तैयार किया गया है। विभिन्न टिप्पणियों और ताजा जानकारियों के आधार पर इस नीतिगत सारपत्र को जल्द ही प्रकाशित किया जा सकता है।

जी20 और अफ्रीका में स्वास्थ्य सहयोग

प्रो. टी.सी. जेम्स और श्री अपूर्व भटनागर

स्वास्थ्य क्षेत्र में अफ्रीका के साथ सहयोग आरआईएस के अनेक पूर्ववर्ती अध्ययनों का विषय रहा है। हमने वर्ष 2015 में 'स्वास्थ्य सेवा में भारत–अफ्रीका साझेदारी: उपलब्धियां और संभावनाएं' विषय पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए अनेक प्रकाशन प्रस्तुत किए थे। बाद में, आरआईएस ने भी ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका में अन्य प्रबुद्ध मंडलों (थिंक टैंक) के साथ भाग लिया और अफ्रीका पर फोकस करते हुए 'एसडीजी3 की प्राप्ति के लिए आईपीआर और स्वास्थ्य नीतियों को सुव्यवस्थित करने' पर एक नीतिगत सारपत्र तैयार किया। 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा एवं अफ्रीका: मुख्य नीतिगत चुनौतियां और जी–20 की भूमिका' पर एक पुस्तक अध्याय पहले ही तैयार किया जा चुका है। जहां तक मौजूदा समय का सवाल है, मार्च 2019 में अर्जेंटीना में 'बापा + 40' की बैठक की तैयारी के तहत आरआईएस अन्य विकासशील देशों, विशेषकर अफ्रीका में भारत के स्वास्थ्य संबंधी सफल कदमों पर एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार कर रहा है। यह 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा एवं अफ्रीका: मुख्य नीतिगत चुनौतियां और जी–20 की भूमिका' पर विभिन्न अध्ययनों का हिस्सा बनेगा।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: जी20 पर कार्यक्रम

जी20: कृषि/खाद्य सुरक्षा

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, डॉ. अमित कुमार, और डॉ. निमिता पांडेय

आरआईएस थिंकटैंक20 (टी20) का एक सदस्य है, जो जी20 देशों के अनुसंधान संस्थानों और प्रबुद्ध मंडलों (थिंक टैंक) का एक नेटवर्क है। टी20 दरअसल जी20 को अनुसंधान–आधारित नीतिगत सलाह देता है, इसके सदस्यों एवं नीतिगत समुदाय के बीच संवाद को सुगम बनाता है, और वैश्विक महत्व के मुद्दों के बारे में आम जनता के साथ संवाद करता है।

नवंबर 2017 में दक्षिण अफ्रीका में टी20 बैठक के लिए आरआईएस ने चीनी एवं इंडोनेशियाई साझेदारों के साथ मिलकर 'अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा बढ़ानेः चुनौतियां और आगे की राह' शीर्षक से एक नीतिगत सारपत्र तैयार किया, जिसमें इसने मुख्य चुनौतियों पर प्रकाश डाला और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए विभिन्न आवश्यक कार्रवाई बिंदुओं या कदमों को प्रस्तावित किया। यह भी कहा गया था कि जी20 अपनी विभिन्न मौजूदा पहलों के जरिए कच्चे माल की आपूर्ति प्रणाली को मजबूत करके खाद्य सुरक्षा बढ़ाने की चुनौती से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नीतिगत सारपत्र को प्रो. सचिन चतुर्वेदी और प्रो. मनमोहन अग्रवाल द्वारा संपादित जी20 संबंधी आगामी पुस्तक में 'जी20 और अफ्रीका' पर एक खंड के लिए एक पुस्तक अध्याय (प्रो. सचिन चतुर्वेदी और डॉ. अमित कुमार द्वारा लिखित) के रूप में विकसित किया गया है।

सतत विकास लक्ष्य के लिए एसटीआई का उपयोग

प्रो. सचिन चतुर्वेदी और डॉ. सब्यसाची साहा

विश्व स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ–साथ विकास वित्त के पर्याप्त स्तर को प्राप्त् करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन के रूप में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) की पहचान की गई है। ज्ञान सृजन, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी प्रवाह के लिए क्षमता निर्माण में सहयोग करने वाली संस्थागत व्यवस्था रियो+20, अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा, सीओपी, आईपीओए और एजेंडा 2030 सहित सतत विकास संबंधी सभी हालिया महत्वपूर्ण वैश्विक गवर्नेंस प्रक्रियाओं के केंद्र में रही है। सतत ऊर्जा, कृषि और औद्योगीकरण के लिए सभी रणनीतियों में एसटीआई समाधानों को सन्निहित करने की आवश्यकता है, ताकि विकास के दौरान कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सके। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में कमी, मानव स्वास्थ्य, टिकाऊ शहरीकरण और स्थलीय एवं समुद्री पारिस्थितिकी के संरक्षण से जुड़े अन्य कार्यों पर भी यह बात लागू होती है। हालांकि, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता में वैश्विक विषमताएं हैं और प्रौद्योगिकी प्रवाह के मार्ग में बाधाएं हैं जो संसाधनों की दृष्टि से कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकल्पों को बंद कर देता है। सतत विकास लक्ष्य के अनुमोदन के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी वैश्विक प्रौद्योगिकी सुविधा व्यवस्था (टीएफएम) के संचालन पर काम करता रहा है, जो अब भी एजेंडा 2030 के प्रमुख प्रदेय में से एक है। इसे यूएनएफसीसीसी सहित इसकी विभिन्न एजेंसियों में संयुक्त राष्ट्र के इसी तरह के प्रयासों का पूरक होना चाहिए। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र की समस्त प्रणाली में किए जा रहे प्रयासों में समेकन एवं समन्वय सुनिश्चित करने और इसे कई गुना बढ़ाने की आवश्यकता है। विश्व स्तर पर टिकाऊ प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए चुनिंदा देशों के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) जैसी नई साझेदारियां उभर कर सामने आई हैं। समावेशी विकास के क्षेत्र में डिजिटल अर्थव्यवस्था ने वित्तीय समावेश और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया है। दरअसल, सरकारें आईसीटी आधारित गवर्नेंस, आपदा से निपटने की तैयारियों और दूरदराज के क्षेत्रों में संपर्क के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को लागू कर रही हैं। निकट भविष्य में 'उद्योग 4.0' प्रौद्योगिकियों के व्यापक उपयोग से सतत और समावेशी विकास के लिए संबंधित रणनीतियों में काफी बदलाव आने की उम्मीद है। सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में पहुंच, समानता तथा समावेश के सिद्धांतों को एसटीआई के संदर्भ में मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता है और इसके साथ ही कारगर वैश्विक साझेदारियों एवं सहयोग हेतु विज्ञान राजनय के लिए क्षमता निर्माण की जरूरत है। ये अंततः ज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रवाह के मार्ग में मौजूद बाधाओं को कम करने में योगदान देंगे।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: जी20 पर कार्यक्रम

व्यापार, निवेश और वैश्वीकरण

डॉ. सव्यसाची साहा

जी20 की मौजूदा जापानी अध्यक्षता में प्रक्रिया के सदस्य के रूप में कार्यदल के तहत 2 नीतिगत सारपत्रों का योगदान दिया गया और टोक्यो में टी20 आरंभिक सम्मेलन में प्रस्तुतियां दी गईं। 1) *डब्ल्यूटीओ में सुधार पर नीतिगत सारपत्र:* पहला, विश्व व्यापार प्रणाली और तकनीकी मोर्चों पर नाटकीय बदलावों के मद्देनजर डब्ल्यूटीओ के प्रासंगिक एवं गतिशील बने रहने की क्षमता। यह अब भी डब्ल्यूटीओ प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है कि वह बहुपक्षीय दृष्टिकोणों और डब्ल्यूटीओ ढांचे से परे संरचनाओं जैसे कि मेगा–क्षेत्रीय व्यवस्थाओं (आरसीईपी, टीपीपी, टीटीआईपी इत्यादि) के बावजूद अपने प्रमुख सिद्धांतों एवं बुनियादी बातों या तत्वों को निरंतर बनाए रखे। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) भी उन मुद्दों को उठाने में विफल रहा है, जिनके तहत विकसित देशों में नीतिगत बदलाव करना आवश्यक है, और जो वार्ताओं में आगे बढ़ने के लिए विकसित देशों के विकल्पों में परिवर्तन करते हैं। दूसरा, वर्तमान व्यवस्था विकासशील देशों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाने वाले विशिष्ट प्रस्तावों में होने वाली अनुचित देरी और इनमें बार–बार स्थगन से निपटने में सक्षम नहीं है। इसके साथ ही सुधारात्मक व्यवस्थाएं तैयार करने की आवश्यकता है। विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देशों की निरंतर भागीदारी के लिए इसके व्यापक निहितार्थ हैं। तीसरा, यह आम तौर पर माना जाता है कि डब्ल्यूटीओ ने अंतरराष्ट्रीय मानक तय किए जाने को आवश्यक वैधता प्रदान की है और इसने निर्णायक की भूमिका निभाई है। हालांकि, मानक तय करने वाली अग्रणी संरचनाओं जैसे कि आईएसओ और कोडेक्स में संस्थागत अपर्याप्तता के चलते अपेक्षित समझदारी एवं जवाबदेही का सख्त अभाव नजर आ रहा है। इन संस्थानों में सुधार करने के मौजूदा प्रयासों को मजबूत करने की आवश्यकता है।

2) *जीवीसी पर नीतिगत सारपत्र:* पहला, सफल अनुभवों से सीखने के प्रयासों को उन देशों में मजबूती से लागू किया जाना चाहिए जहां ज्ञान सृजन से जुड़ी संस्थागत व्यवस्थाएं कमजोर हैं। विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों और घरेलू फर्मों के बीच अधिक से अधिक संवाद के जरिए ज्ञान सृजन और अप्रत्यक्ष प्रभावों को अंततः उत्पादन एवं रोजगार के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के तात्कालिक उद्देश्यों से कहीं परे जाकर जीवीसी में एकीकरण को प्रेरित करना चाहिए। दूसरा, परिवहन और संचार से जुड़ी कई सेवाओं के साथ–साथ वित्तीय सेवाएं (बीमा, फिनटेक इत्यादि) संभवतः अकेले बुनियादी ढांचागत मुद्दा नहीं हो सकती हैं। सेवा संबंधी संपर्क उत्पादन के अतिरिक्त विखंडन के साथ महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जबकि विभिन्न सेवाएं दरअसल उत्पादन के दो मध्यवर्ती चरणों को आपस में जोड़ती हैं। अतः स्वयं उत्पादन प्रक्रिया के साथ सेवा क्षेत्रों (सर्विस सेक्टर) के मूलभूत जुड़ाव को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहायक नीतियों के माध्यम से मजबूत करने की आवश्यकता है। अंत में, विकासशील देशों में छोटी फर्मों से जुड़ी उत्पादकता वृद्धि की बाधाओं को दूर करने के लिए एसएमई विकास की नीतियों को अपनाया जाना चाहिए। क्लस्टर विकास की पहलों के तहत नवाचार संबंधी सहायता, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के साथ जुड़ाव को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। 'उद्योग 4.0' के अनुरूप ढलने के लिए फिर से कुशल बनाने जैसे क्षेत्रों में उच्च विशेषज्ञता (कार्यों में विविधता लाने की क्षमता के साथ) के लिए तकनीकी शिक्षण के साथ–साथ उद्योग में कौशल विकास को बढ़ावा देने की जरूरत है। 21वीं सदी की तकनीकी और स्थायित्व संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जीवीसी के लिए उपयुक्त व्यापार और औद्योगिक नीति रूपरेखा को भी लागू करने की आवश्यकता है।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: अफ्रीका केंद्रित कार्यक्रम

आरआईएस अफ्रीका से संबंधित नीतिगत परिचर्चाओं और अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों में अत्यंत सक्रियता के साथ जुड़ा रहा है। अफ्रीका की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और विकास के एजेंडे को ध्यान में रखते हुए विकास सहयोग, औद्योगीकरण, क्षेत्रवार (सेक्टोरल) विकास, आर्थिक विकास और लोगों के बीच पारस्परिक साझेदारी जैसे विभिन्न मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक गौर किया गया है। इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों में और अधिक तेजी लाने के लिए आरआईएस द्वारा एक अध्ययन किया गया है, ताकि अफ्रीका में औद्योगीकरण, विनिर्माण और आईसीटी के संदर्भ में उपलब्ध अवसरों, चुनौतियों एवं प्रमुख नीतिगत कदमों के बारे में पता लगाया जा सके।

अफ्रीका में औद्योगीकरण, विनिर्माण और आईसीटी: अवसर, चुनौतियां और आगे की राह

डॉ. प्रियदर्शी दाश

अफ्रीका में औद्योगीकरण और विनिर्माण में वृद्धि के लिए ऋण की अनुकूल शर्तों पर निवेश के निरंतर प्रवाह की आवश्यकता होगी। वैसे तो निवेश का स्तर बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ ही वित्त के स्रोतों में विविधता भी जरूरी है। वित्त पोषण के स्रोतों के विविधीकरण में भौतिक अवसंरचना के विकास के लिए बैंक वित्तपोषण की निर्भरता कम करना, नई औद्योगिक परियोजनाओं का वित्तपोषण, औद्योगिक गलियारों में निवेश इत्यादि शामिल हैं। अतः इसके लिए अफ्रीका में गहरे स्थानीय पूंजी बाजार, विशेषकर स्थानीय मुद्रा वाले बांड बाजार और प्रपत्रों के विविध सेट की आवश्यकता होगी जिसमें जोखिमों के उचित संयोजन के साथ–साथ अंश भागिता एवं डेट दोनों की ही विशेषताओं का संयोजन भी शामिल होगा। वैसे तो देरी से हो रहे विकास में आईसीटी का अनुप्रयोग बढ़ रहा है, लेकिन अफ्रीका द्वारा ऊंची छलांग लगाने और विकास के अभिनव पथ पर अग्रसर होने की संभावना नहीं है। 'उद्योग 4.0' के विजन के साथ एसएमई के वित्तपोषण के मुद्दों को सुलझाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

भारत ने हाल ही में 'मुद्रा' योजना के साथ प्रयोग किया है जो एसएमई सेक्टर को ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करती है। इसे डिजिटलीकरण और अन्य वित्तीय प्रौद्योगिकियों के जरिए प्रभावकारी रूप से लागू किया जाता है। विशेषकर पूंजीगत सामान की खरीद के लिए स्थानीय मुद्रा में व्यापार का प्रावधान न केवल विनिमय दर से जुड़े जोखिमों को कम करेगा, बल्कि अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा भी देगा। एशिया और अफ्रीका के चुनिंदा देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में निर्यात एवं आयात का भुगतान सुनिश्चित किया जा सकता है। जब तक अनुकूल वित्तीय सहयोग व्यवस्थाओं को नहीं अपनाया जाएगा, तब तक औद्योगीकरण के नाम पर अधिक निवेश के लिए एमडीबी से अपेक्षाकृत अधिक बाह्य ऋण लेने और अफ्रीकी देशों द्वारा वाणिज्यिक उधारियां लेने की नौबत आ सकती है।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: एजेंडा 2030 पर विशेष ध्यान

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) दरअसल आरआईएस के कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण आयाम है जिसके तहत इन चार मुख्य विषयों पर अनुसंधान और परामर्श करने पर फोकस किया जाता है: सतत विकास लक्ष्य का आपस में जुड़ाव, प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए विकेंद्रीकृत नियोजन, कार्यान्वयन के वैश्विक तरीके और निगरानी एवं आकलन। नीतिगत अनुसंधान, क्षमता निर्माण और आउटरीच संबंधी कदमों के माध्यम से इन मुख्य विषयों की पारस्परिक निर्भरता एवं जुड़ाव दरअसल सतत विकास लक्ष्य और एजेंडा 2030 पर आरआईएस के कार्यक्रम के तीन स्तंभों का निर्माण करते हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न अवधारणाओं और रूपरेखाओं (फ्रेमवर्क) को परिभाषित करना है, ताकि कार्यान्वयन एवं निगरानी पर व्यापक फोकस करते हुए विकास की स्थिति, सर्वोत्तम प्रथाओं, साधकों अथवा अत्यंत सक्रिय लोगों और संस्थानों का विश्लेषण किया जा सके। कार्यक्रम के तहत विभिन्न अध्ययन स्वास्थ्य (एसडीजी3), शिक्षा (एसडीजी4), महिला–पुरुष समानता (एसडीजी5), नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी (एसडीजी14) और वैश्विक साझेदारियों (एसडीजी17) सहित लक्ष्य–विशिष्ट एजेंडे में अहम योगदान करते हैं। यही नहीं, सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) की भूमिका पर गहन चिंतन को आपस में संबंधित एक अहम विषय या थीम माना जाता है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं।

सतत विकास लक्ष्य: राज्यों का विकास, और सांख्यिकीय रूपरेखा

डॉ. पी.के. आनंद और श्री कृष्ण कुमार

इस कार्यक्रम के विभिन्न घटक निम्नलिखित हैं:

- सभी तीन आयामों अर्थात सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण में सतत विकास लक्ष्य को बड़ी तेजी से प्राप्त करने के लिए निगरानी और क्षमता निर्माण करना, जिसमें नीति, रणनीति एवं ठोस कदमों (एक्शन प्वाइंट) को शामिल किया जाएगा।
- भारत की आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली का विकास करना, ताकि साक्ष्य आधारित नीतिगत निर्णय लेने में सहायता के लिए इसे ज्यादा जीवंत बनाया जा सके।
- सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान–प्रदान, विभिन्न क्षेत्रों के दौरे, क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बातचीत, विभिन्न हितधारकों के साथ विचार–विमर्श इत्यादि के जरिए तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ संवाद।
- त्रिपुरा को समृद्ध राज्य बनाने के लिए इसके विकास की रूपरेखा तैयार करना, जिसके तहत संपर्क, सीमा पार साझेदारियों, व्यापार, रोजगार सृजन और गरीबी में कमी करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- विचारों के आदान–प्रदान, क्षेत्रीय परियोजनाओं, तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग इत्यादि के जरिए पारस्परिक लाभ के लिए सीमा–पार विकास साझेदारियां और दक्षिणिय सहयोग।

वर्तमान में आरआईएस त्रिपुरा के लिए एक विकास रोडमैप तैयार करने के लिए नीति आयोग और त्रिपुरा सरकार की सहायता कर रहा है जिसके तहत संपर्क और रोजगार सृजन पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा, यह हितधारकों के साथ संवाद और साझेदारियों के जरिए स्थानीयकरण पर विशेष जोर देते हुए सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में अरुणाचल प्रदेश की भी मदद कर रहा है।

भावी कार्यक्रम में ये शामिल होंगे: जल क्षेत्र में सतत विकास के लिए दक्षिण एशिया की साझेदारी पर एक अध्ययन करना, ताकि सभी के लिए सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा सके; सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन के पहले तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा की गई प्रगति पर एक अध्ययन कराना, और वर्ष 2020 में जल्द प्राप्ति के लिए निर्धारित लक्ष्यों पर इसकी दिशा जैसे कि 'लक्ष्य 3.6' जिसके तहत सड़क हादसों के कारण विश्व भर में होने वाली मौतों और घायलों की संख्या को आधा किया जाएगा; 'औद्योगिक क्रांति 4.0' के बीच रोजगार सृजन के लिए दक्षिणीय सहयोग पर एक नीतिगत सारपत्र तैयार करना; आधिकारिक विकास सहायता पर तुलनात्मक अध्ययन करना एवं शुरू किए गए वैकल्पिक माप संकेतक जैसे कि 'सतत विकास के लिए कुल आधिकारिक सहायता' से विकासशील देशों तथा एलडीसी पर पड़ रहे प्रतिकूल असर पर गौर करना; 'दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए सतत विकास लक्ष्य की निगरानी हेतु एक एकीकृत रूपरेखा' विकसित करना; विभिन्न सतत विकास लक्ष्य सूचकांकों का विश्लेषण करना; अरुणाचल प्रदेश में सतत विकास लक्ष्य पर एक बैठक/कार्यशाला/संगोष्ठी का आयोजन करना; इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी, एडवोकेसी, एंड गवर्नेंस (आईपीएजी), ढाका के साथ मिलकर सतत विकास लक्ष्य तथा बिम्सटेक पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करना; और आंकड़ा उत्पादन एवं सांख्यिकीय उत्पादों के प्रसार की क्षमता को मजबूत करने हेतु क्षेत्र के देशों की सहायता के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन करना।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: एजेंडा 2030 पर विशेष ध्यान

सतत विकास लक्ष्य 3: स्वास्थ्य

प्रो. टी. सी. जेम्स

सतत विकास लक्ष्यों और भारत पर कार्यक्रम के तहत लक्षित समय के भीतर सभी के लिए स्वास्थ्य एवं खुशहाली के एसडीजी3 लक्ष्य को प्राप्त करने संबंधी भारत की चुनौतियों और संभावनाओं पर एक अध्ययन किया जा रहा है। 'स्वास्थ्य एवं खुशहाली: पहुंच और रोकथाम के मुद्दों का एक आकलन' विषय पर एक पुस्तक अध्याय तैयार किया गया है। इस अध्ययन में वर्ष 2030 तक एसडीजी3 प्राप्त करने में भारत द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण के आधार पर इसमें उन सुधारात्मक उपायों को प्रस्तावित किया गया है जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी वर्तमान और संभावित भावी चुनौतियों का सामना करने में भारत को लैस करने के लिए संचालन स्तर पर आवश्यक हो सकते हैं। इसमें वेलनेस पर विशेष ध्यान देने के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास के आयामों के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण की संभावनाओं को भी तलाशा गया है। भारत के संघीय ढांचे के संदर्भ में अध्ययन में एसडीजी3 को प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्थानीय–विशिष्ट नीतियों और रणनीतिक उपायों पर गौर किया गया है।

भारत में सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करें: सतत विकास लक्ष्य 4 प्राप्त करने के लिए पहली आवश्यकता

डॉ. बीना पांडेय

'बदलते भारत' के विजन को साकार करने के लिए भारत सरकार ने 'सभी के लिए शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' के आदर्श वाक्य या उद्देश्य के साथ शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने के लिए कई नीतिगत पहल की हैं। भारत ने 'सभी के लिए शिक्षा' के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। एक मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संवैधानिक रूप से कई प्रमुख कार्यक्रमों और नीतियों को शुरू किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और शिक्षा का अधिकार (आरटीई) जैसी पहलों ने भारत में शिक्षा प्रणाली को आवश्यक प्रोत्साहन दिया है। वैसे तो इसकी बदौलत देश भर में प्राथमिक शिक्षा में दाखिला दरों में काफी सुधार हुआ है, लेकिन आवश्यक ज्ञान या कौशल प्राप्त करने से जुड़ी गुणवत्ता की चुनौती से निपटना अभी बाकी है।

पहले खंड में अध्याय 'सतत विकास लक्ष्य 4' का अवलोकन प्रस्तुत करता है और भारतीय संदर्भ में शिक्षा पर एसडीजी4 को प्रासंगिक बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए वर्तमान दृष्टिकोणों को नीतिगत पहलों में एकीकृत करके उनका विश्लेषण करता है। इसके साथ ही यह नई शिक्षा नीति तैयार करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने पर इसके सकारात्मक असर का भी विश्लेषण करता है, जैसा कि एसडीजी4 में विशेष जोर दिया गया है। दूसरे खंड में भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर शिक्षा प्राप्ति के रुझानों पर गौर किया गया है। तीसरे खंड में शिक्षा क्षेत्र की कुछ बड़ी चुनौतियों जैसे कि पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने (ड्रॉपआउट), सामाजिक बुनियादी ढांचे और पहुंच से जुड़े मुद्दों के बारे में बताया गया है। अंतिम खंड में यह सार प्रस्तुत किया गया है कि भारत ने वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कैसे आगे बढ़ने की योजना बनाई है।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: एजेंडा 2030 पर विशेष ध्यान

सतत विकास लक्ष्य 5: महिला–पुरुष में भेदभाव समाप्त करने के तरीके तलाशना

डॉ. बीना पांडेय

सतत विकास लक्ष्य 5 पर अध्ययन मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण एवं रोजगार तक पहुंच को बढ़ावा देने, निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और महिला–पुरुष में भेदभाव समाप्त करने के लिए गरिमा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसके अलावा, भारत में महिला कर्मचारियों की भागीदारी के निम्न स्तर को पलटा जा सकता है, बशर्ते कि अधिक से अधिक भारतीय महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे महिला–पुरुष समानता सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त होगा जिसका उनकी खुशहाली पर व्यापक आर्थिक असर पड़ेगा।

उस संदर्भ में यह अध्ययन सतत विकास लक्ष्य 5 के साथ अन्य लक्ष्यों के आपसी–जुड़ाव का पता लगाएगा जिनमें विशेषकर गरीबी, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता और ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित लक्ष्य शामिल होंगे। इसके तहत यह पता लगाया जाएगा कि सतत विकास लक्ष्य 5 एवं उसके लक्ष्य आखिरकार कैसे संकेतकों में बदल जाते हैं और क्या ये महिलाओं की स्थिति पर करीबी नजर रखने में प्रभावकारी एवं उपयोगी साबित होंगे। यह महिलाओं पर असर डालने वाले/उनसे संबंधित मौजूदा विधेयकों पर भी गौर करेगा, ताकि उनमें सामंजस्य स्थापित कर उनकी प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके और उभरती जरूरतों के लिए अतिरिक्त विधायी उपाय या संशोधन किए जा सकें। यह विभिन्न मंत्रालयों, उपक्रमों, स्थानीय निकायों इत्यीादि के बीच प्रभावकारी सामंजस्य सुनिश्चित करने का तरीका भी तलाशेगा, ताकि सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा नीतियों के प्रावधान के जरिए अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्यों को मान्यता देने के साथ–साथ उनका समुचित मूल्य भी दिया जा सके।

सतत विकास लक्ष्य 14: महासागर और नीली अर्थव्यवस्था

प्रो. एस के मोहंती

नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) ने हाल के वर्षों में कई तटीय देशों की विकास योजना में प्रतिमान बदलाव लाया है। इनमें से ज्यादातर देशों में यह क्षेत्र विकास के एक अहम वाहक के रूप में उभर रहा है, जिसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। वैसे विभिन्न देशों में इन संसाधनों की उपलब्धैता में काफी अंतर देखा जा रहा है, लेकिन इनमें से ज्यादातर देश इस सेक्टर से काफी लाभान्वित हो रहे हैं। जहां एक ओर कुछ क्षेत्रों का व्यापक दोहन किया जाता है (यथा मछली पकड़ना, एक्वाकल्चर, समुद्री परिवहन, इत्यादि), वहीं दूसरी ओर अन्य क्षेत्रों का अत्यंत कम दोहन किया जाता है (यथा भारी खनिज, अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा, गैस हाइड्राइड, समुद्री विनिर्माण, विभिन्न समुद्री सेवा क्षेत्र)। वैसे तो इस विषय पर पिछले 40 वर्षों से लगातार शोध हो रहे हैं, लेकिन विश्व स्तर पर स्वीकृत कार्यप्रणाली के अभाव के कारण नीली अर्थव्यवस्था से जुड़े मुख्य मुद्दों जैसे कि लेखांकन की रूपरेखा, नीले क्षेत्रों की पहचान, तकनीक की आवश्यकताओं, सतत विकास लक्ष्य से जुड़ाव, रोजगार की संभावनाओं इत्यादि पर ठीक से विचार मंथन नहीं किया जाता है। भारत पिछले कई वर्षों से ब्लू इकोनॉमी पर परिचर्चाएं करता रहा है। आरआईएस इस बारे में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर एक सामूहिक दृष्टिकोण तय करने के लिए नीति आयोग, आईओआरए सचिवालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस क्षेत्र में कार्य प्रगति पर है और दो नीतिगत सारपत्रों एवं एक पुस्तक को प्रस्तुत किया गया है।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: एजेंडा 2030 पर विशेष ध्यान

सतत विकास लक्ष्य 17: वैश्विक साझेदारी, क्षेत्रीय सहयोग, संसाधन जुटाना और स्थानीयकरण

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, डॉ. सब्यसाची साहा, सुश्री प्रतिभा शॉ और श्री आकाश खंडेलवाल

'सतत विकास लक्ष्य 17' संसाधन जुटाने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, व्यापार, क्षमता निर्माण और संस्थागत संरचना पर अमल के वैश्विक साधनों को प्राप्त करने के लक्ष्यों को कवर करता है। विकास एवं विकास सहयोग के लिए वित्त पोषण; प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, एसएंडटी का उपयोग एवं विनियमन; व्यापार व निवेश पर वैश्विक संस्थागत संरचना आरआईएस में शुरू से ही मुख्य अनुसंधान स्तंभ रहे हैं। हाल के दिनों में आरआईएस प्रकाशनों ने सतत विकास लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य से इस तरह के मुद्दों को दमदार तरीके से तलाशा है और इस संबंध में दक्षिणीय सहयोग के दायरे को परिभाषित किया है। विकास वित्त दरअसल विकसित देशों से मिलने वाली द्विपक्षीय सहायता में आई सापेक्ष गिरावट और विकासशील देशों में सतत विकास लक्ष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थागत वित्त की अपर्याप्तता की पृष्ठभूमि में आरआईएस के अनुसंधान प्रयासों का एक प्रमुख केंद्रित विषय रहा है। जहां तक दक्षिणीय सहयोग का सवाल है, यह संसाधन जुटाने और ज्ञान के आदान–प्रदान के एक पूरक साधन के रूप में उभर कर सामने आया है। इससे विकासशील देशों में विकास की रफ्तार तेज करने में मदद मिल रही है। आरआईएस नीतिगत परिचर्चाओं के साथ–साथ उस विकास वित्त की परिचालन रूपरेखा में अहम योगदान देता रहा है जिसे एनडीबी और एआईआईबी जैसे नए बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ–साथ डीएफआई के जरिए नया स्वरूप प्रदान किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि अग्रणी ग्लोबल फोरम (संयुक्त राष्ट्र, डब्ल्यूटीओ, जी20, ब्रिक्स, इत्यादि) बहुपक्षीय और क्षेत्रीय स्तरों पर साझेदारी प्रक्रियाओं को उपयुक्त दिशा प्रदान करते हैं। सतत विकास लक्ष्य वैश्विक प्रयासों पर उतना ही निर्भर करते हैं जितना कि विभिन्न देशों में स्थानीयकरण के प्रयासों पर निर्भर करते हैं। स्थिर संस्थानों और शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के अलावा असमानताओं को कम करके वैश्विक कल्याण को बढ़ावा देना, लीकेज को रोकना, ज्ञान एवं संसाधन प्रवाह की अनुमति देना और समान अवसर प्रदान करना अब भी वैश्विक सहभागिता या जुड़ाव के प्रमुख क्षेत्र हैं। वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अत्यंत उत्साहजनक है कि हाल के वर्षों में सभी बहुपक्षीय एवं अन्य मंचों ने सतत विकास लक्ष्य से जुड़ी अनिवार्यता को बाकायदा स्वीकार कर लिया है और विश्व भर के राजनेताओं ने इसे समर्थन देने का वादा किया है। हालांकि, वैश्विक संसाधन प्रवाह, व्यापार, वाणिज्य, निवेश, प्रौद्योगिकी इत्यादि में विकृतियां और अपर्याप्तताएं अल्पावधि में सार्थक परिणामों की संभावनाओं को बाधित करती हैं। यही नहीं, घटती सहभागिता और बढ़ते संरक्षणवाद के मद्देनजर बहुपक्षीय प्रक्रियाओं को प्रतिकूल माहौल का सामना करना पड़ रहा है। आरआईएस में व्यापार, निवेश, विकास सहयोग और प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान करने की एक लंबी परंपरा है, ताकि विशिष्ट मुद्दों पर वैश्विक संस्थागत ढांचे की अपर्याप्तता और विकासशील देशों को हो रहे नुकसान पर प्रकाश डाला जा सके। हाल के महीनों में आरआईएस ने क्षेत्रीय निकायों जैसे कि बिम्सटेक, आईओआरए इत्यादि के माध्यम से अपनी सहभागिता को जारी रखने के अलावा महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, ताकि विशेषकर विश्व व्यापार संगठन और जी20 एवं ब्रिक्स जैसे वैश्विक जुड़ाव वाले मंचों पर जारी वार्ताओं में योगदान दिया जा सके।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना: एजेंडा 2030 पर विशेष ध्यान

संबंधित थीमः सतत विकास लक्ष्य के लिए एसटीआई – 'उद्योग 4.0' का उपयोग करना और नवाचारों को बढ़ावा देना

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, डॉ. सब्यसाची साहा और सुश्री प्रतिभा शॉ

प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता विश्व स्तर पर सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा एवं गति को काफी हद तक बेहतर करेगी। अब तक अनसुना एक विशेष तकनीकी बदलाव आर्थिक प्रणालियों को नई गति देगा और भविष्य के बुनियादी ढांचे को परिभाषित करेगा। इस तरह के बदलाव अल्पावधि में विघटनकारी प्रतीत होते हैं। इसके साथ ही ये क्रमिक विकास के एक गैर–रेखीय पथ पर अग्रसर होते हुए प्रतीत होते हैं। निरंतरता एवं लचीलेपन की चिंताओं से उभरती आवश्यकता के साथ–साथ नई आकांक्षाएं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विघटनकारी बदलावों को और नई गति प्रदान करेंगी। 'उद्योग 4.0' का यह विचार तकनीकी बदलाव के इसी आयाम से शुरू होता है, जहां हम कंप्यूटिंग और संचार पर आधारित तकनीक के नए युग का आगमन देखते हैं जो जानकारियों को आपस में जोड़ने एवं प्रोसेसिंग करने और अंततः उत्पादन, निर्माण, लॉजिस्टिक्स, परिवहन व सेवाएं मुहैया कराने से जुड़ी कई मशीनों को चलाने की प्रमुख जिम्मेदारियों (मनुष्यों का स्थान लेने!) की अपनी क्षमता की बदौलत अत्यंत प्रभावशाली है। विकास के संदर्भ में डिजिटल अर्थव्यवस्था ने ज्ञान प्रसार एवं सूचना तक पहुंच; प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण; वित्तीय समावेशन; गवर्नेंस में पारदर्शिता; और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को काफी बढ़ा दिया है। विकासशील देशों में सरकारें आईसीटी आधारित संचालन, आपदा में सुदृढ़ता और ग्रामीण संपर्क के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को विकसित कर रही हैं। भारत को अपनी आईसीटी अवसंरचना, आईसीटी की पैठ, आईसीटी सेवाओं, डिजिटल भुगतान एवं कैशलेस प्रणालियों, और आईसीटी–आधारित गवर्नेंस, खरीद तथा सार्वजनिक वितरण प्रणालियों की दृष्टि से विकासशील देशों में अग्रणी के रूप में उद्धृत किया जाता है। इस क्षेत्र में प्रमुख अनुसंधान मुद्दों में निम्नेलिखित शामिल हैं:

- स्वदेशी नवाचार क्षमता का आकलन और उद्योग 4.0 के लिए तैयारियां
- उद्योग 4.0 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रणालियां डिजाइन करना
- सतत विकास लक्ष्य के लिए उद्योग 4.0 से लाभ उठाना – प्रौद्योगिकियों और विकास क्षेत्रों की पहचान करना
- नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत रूपरेखा और सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस तरह की तकनीकों का उपयोग करना

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचनाः

दक्षिणीय सहयोग

दक्षिणीय सहयोग (एसएससी) का संदर्भ, अनुभव एवं अभिव्यक्ति आपस में मिलकर वैश्विक मुद्दों और विकास सहयोग के स्वरूप पर आरआईएस के कार्यक्रम की रचना करते हैं। इस संदर्भ में हाल ही में कुछ अध्ययन किए गए हैं। एसएससी की एक सैद्धांतिक रूपरेखा तैयार करने की दिशा में प्रयासों, एजेंडा 2030 के लिए उत्तर–दक्षिण प्रवाह एवं सहयोग के तुलनात्मक विश्लेषण, भारतीय विकास सहयोग का विश्लेषण करने के लिए अर्थमितीय साधनों और भारत के विकास सहयोग का एक व्यापक आंकड़ा केंद्र विकसित करने पर किए गए अध्ययन इनमें शामिल हैं। इसके अलावा, मोजाम्बिक में सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल विनिर्माण संयंत्र पर अध्ययन भारत के विकास सहयोग का एक अनूठा उदाहरण है।

दक्षिणीय सहयोगः एक सैद्धांतिक रूपरेखा की ओर तलाश

(प्रो. सचिन चतुर्वेदी और प्रो. मिलिंदो चक्रबर्ती)

यह अनुसंधान परियोजना आईसीएसएसआर की ओर से वित्तीय सहायता के साथ कार्यान्वित की जा रही है। प्रस्तावित अध्ययन का उद्देश्य समस्त विकासशील देशों से एकत्र किए गए साक्ष्यों के साथ दक्षिणीय सहयोग में विकास संविदा के संरचनात्मक ढांचे में निहित विचारों को अनुभवजन्य रूप से सत्यापित करना है। जहां एक ओर ज्यादातर साक्ष्य डेस्क अनुसंधान के माध्यम से एकत्र किए जाएंगे, वहीं दूसरी ओर एक पड़ोसी देश में प्राथमिक डेटा संग्रह भी किया जाएगा। इसके तहत विभिन्न विकासशील देशों द्वारा उठाए गए एसएससी के प्रति दृष्टिकोणों में बहुलता का विश्लेषण करने के साथ–साथ इस बात का भी पता लगाने का इरादा है कि इस तरह की विविध प्रथाएं किस हद तक विकास संविदा के विचारों में माकूल बैठती हैं। अध्ययन के तहत उन एकत्रित अनुभवजन्य साक्ष्यों के एवज में एसएससी के लिए एक सैद्धांतिक आधार भी विकसित किया जाएगा जो संस्थागत अर्थशास्त्र, सामूहिक कार्रवाई संबंधी सिद्धांतों और विकास अध्ययनों से जुड़े हालिया घटनाक्रमों से उभर सकते हैं।

परियोजना में विस्तार से जांच के लिए इन शोध प्रश्नों की पहचान की गई हैः एसएससी के पीछे सैद्धांतिक दलील क्या है और किस हद तक आंकड़े (डेटा) एक स्पष्टीकरण के रूप में 'विकास संविदा' का समर्थन करते हैं? एसएससी में गैर–सरकारी निकायों की क्या भूमिका है और वे उपर्युक्त मॉडल में कैसे माकूल या फिट बैठते हैं? मार्च 2018 में किए गए अध्ययन के तहत विभिन्न गतिविधियों का एक वर्ष लगभग पूरा हो गया है। इस अवधि के दौरान संबंधित सामग्री की गहन समीक्षा की गई। गहन अध्ययन के लिए परियोजनाओं की पहचान करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

उत्तर–दक्षिण प्रवाह का तुलनात्मक विश्लेषण और एजेंडा 2030 के लिए सीमा पार सहयोग

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, प्रो. मिलिंदो चक्रबर्ती और श्री प्रणय सिन्हा

यह जर्मन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, बॉन, जर्मनी के साथ एक संयुक्त अनुसंधान परियोजना है, जिसमें इस संस्थान की ओर से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। परियोजना के ये उद्देश्य हैंः विकास सहयोग के प्रति ओईसीडी और एसएससी के दृष्टिकोणों में अंतर की मौलिक विशिष्टताओं एवं दृढ़ रुख की पहचान करना; सामूहिक कदमों के माध्यम से सतत विकास की प्रक्रिया को संस्थागत रूप देने के अंतर्गत वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं को प्रदान करने में सामंजस्य के संभावित क्षेत्रों का पता लगाना; और शांति बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जीएवीआई, वैक्सीन गठबंधन, अनुसंधान सहयोग और इंटरनेट जैसी वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं को सृजित करने के प्रयासों के संबंध में एक बहु–केंद्रीय संस्थागत रूपरेखा के अंतर्गत सामूहिक कार्रवाई या कदमों की विशिष्टताओं की पहचान करना। आरआईएस टीम के योगदान में अध्ययन के लिए वैचारिक रूपरेखा को विकसित करना और शांति बनाए रखने (पीस कीपिंग), अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जीएवीआई एवं वैक्सीन गठबंधन पर केस स्टडी तैयार करना शामिल हैं।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना:

दक्षिणीय सहयोग

दक्षिणीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू चेन

प्रो. एस.के. मोहंती और
डॉ. सब्यसाची साह

आरआईएस दरअसल आईटीसी, जिनेवा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से दक्षिणीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखलाओं या वैल्यू चेन (आईवीसी) पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है जिसे मार्च 2019 में ब्यूनस आयर्स में 'बापा + 40' सम्मेलन के अवसर पर लॉन्च किया जाएगा। इस रिपोर्ट में आईवीसी में भागीदारी के स्वरूप को समझाने के लिए सदी की शुरुआत से ही विकासशील देशों के उल्लेखनीय उदय की वृहद बुनियाद (आईवीसी पर फोकस के साथ दमदार व्यापार प्रदर्शन पर प्रकाश डालना) और फर्म के स्तर पर (कुछ पूर्वी अफ्रीकी देशों के चुनिंदा सेक्टरों में) सूक्ष्म साक्ष्य में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की गई है। इस कवायद ने दिलचस्प नीतिगत सबक दिए हैं जिन्हें व्यापार और आईवीसी को बढ़ावा देकर विकासशील देशों के उदय को बनाए रखने के लिए आगे भी जारी रखने की आवश्यकता है। इससे और भी अधिक मजबूत दक्षिणीय मूल्य श्रृंखलाओं तथा व्यापार को कायम करना संभव हो पाएगा।

भारत के विकास सहयोग पर एक डेटाबेस को विकसित करना

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, डॉ. सुशील कुमार, सुश्री अमिका बावा, सुश्री गीतिका खंडूजा और श्री कार्तिकेय द्विवेदी)

इन आंकड़ों की मुख्य विशेषता यह है कि यह विकास संविदा (कॉम्पैक्ट) के सभी तौर–तरीकों को शामिल करते है। इनमें क्षमता निर्माण (विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति, मेजबान देश में प्रशिक्षण कार्यक्रम, छात्रवृत्तियां, तीसरे या अन्यं देश में प्रशिक्षण, स्वयंसेवकों की तैनाती, व्यवहार्यता अध्ययन कराना और प्रारूप उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र), अनुदान (नकद के रूप में अनुदान, वस्तु के रूप में अनुदान, ऋण माफी और मानवीय सहायता), रियायती वित्त (ऋण रेखा, खरीदार ऋण), व्यापार एवं बाजार पहुंच (शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना, व्यापार में सुगमता के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार, व्यापार संवर्धन एवं व्यापार सहायता सेवाएं, बिजनेस में सुविधा संबंधी सेवाएं प्रदान करना, नियामक क्षमता में सुधार के लिए सहायता, निवेश कोष प्रदान करना एवं इंट्रा क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को विकसित करना) और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (तकनीकी सहयोग, संयुक्त वैज्ञानिक एवं अकादमिक अनुसंधान, लाइसेंसिंग में सब्सिडी या आईपीआर व्यवस्थाओं से छूट देने वाली टर्नकी परियोजनाएं, क्षमता निर्माण के घटक के साथ या उसके बिना प्रौद्योगिकी हस्तांतरण) शामिल हैं। डेटाबेस दरअसल द्विपक्षीय प्रवाह के साथ–साथ बहुपक्षीय प्रवाह को भी कवर करता है। यह मंत्रालय–वार एवं सेक्टर–वार भारत के विकास सहयोग के प्रवाह और क्षेत्रीय संस्थानों के साथ भारत के विकास सहयोग को भी कवर करता है। इस डेटाबेस की समयावधि वर्ष 1946 से लेकर आज तक है।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचनाः

दक्षिणीय सहयोग

भारत के विकास सहयोग का विश्लेषण करने के लिए अर्थमितीय आधारित तकनीकों का अन्वेषण करें

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, प्रो. मनमोहन अग्रवाल और डॉ. सुशील कुमार

यह अध्ययन भारत के विकास सहयोग का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न अर्थमितीय तकनीकों जैसे कि टोबिट, प्रोबिट मॉडलिंग, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर (ओएलएस) अनुमान; क्रॉस सेक्शन और पैनल डेटा का अन्वेषण करता है। यह दो चरणों में भारत के विकास सहयोग का आकलन करता है। यह अध्ययन वर्ष 2004 से वर्ष 2018 तक 135 देशों के साथ भारत के विकास सहयोग को कवर करने वाले व्यापक डेटासेट पर आधारित है। सबसे पहले, यह इस संभावना का अनुमान लगाता है कि भारत साझेदार देश को विकास सहयोग प्रदान करता है। इस अध्ययन में संबंधित परिवर्तनीय घटक एक प्रतिरूप है जो मूल्य को वैसी स्थिति में एक मान कर चलता है जब भारत ओईसीडी के प्राप्तकर्ता देशों की सूची में शामिल किसी भी विकासशील देश को विकास सहयोग देने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। यह 153 देशों से संबंधित है। दूसरा, यह देखते हुए कि एक देश जिसे भारत विकास सहयोग प्रदान करता है, वह स्थिर 2000 अमेरिकी डॉलर में विकास सहयोग की राशि (लॉग) का अनुमान लगाता है जिसे एक विशेष विकास साझेदार को देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इस मॉडल के स्वतंत्र परिवर्तनीय घटक ये हैंः जीडीपी प्रति व्यक्ति, विकास दूरी, आपदा से प्रभावित लोग, जनसंख्या, दूरी, संयुक्त राष्ट्र मतदान, राष्ट्रमंडल, द्विपक्षीय निर्यात, संसाधनों की कमी, राजनीतिक अधिकार, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, (डमी परिवर्तनीय घटक एशिया और अफ्रीका)। भारत के विकास सहयोग के विश्लेषण से पता चलता है कि सबसे महत्वपूर्ण परिर्वनीय घटक प्रति व्यक्ति आय प्रेरित अनुदान और आपदा प्रेरित एलओसी है। मानवाधिकारों के मामले में किसी देश का रिकॉर्ड भी उस देश द्वारा अनुदान या ऋण प्राप्त करने की संभावना को काफी प्रभावित करता है। अनुदान मुख्य रूप से एशिया को और एलओसी मुख्यतः अफ्रीका को निर्देशित किया जाता है। राष्ट्रमंडल के साथ संबंध जैसे राजनीतिक तर्क विकास सहायता से जुड़े निर्णयों को प्रभावित नहीं करते हैं।

मोजाम्बिक के साथ भारत का विकास सहयोगः सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल विनिर्माण संयंत्र का अध्यन

प्रो. सचिन चतुर्वेदी और डॉ. सुशील कुमार

इस अध्ययन में मोजाम्बिक के साथ विशेषकर पीवी विनिर्माण संयंत्र के लिए भारत के विकास सहयोग का विश्लेषण किया गया है जिसके लिए भारत ने 13 मिलियन अमेरिकी डालर प्रदान किए हैं। मोजाम्बिक में अत्यंत उल्लेखनीय और बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त सौर क्षमता है। सौर ऊर्जा की क्षमता लगभग 1.49 मिलियन जीडब्ल्यूएच है जो देश की मौजूदा ऊर्जा खपत से कई गुना अधिक है। प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि भारत के विकास सहयोग से सौर पैनलों के आयात की लागत को कम करने में मदद मिलेगी, जो वर्तमान में तकरीबन 5–6 मिलियन अमेरिकी डॉलर सालाना है। यही नहीं, इस परियोजना से सौर पैनल कार्यक्रम को काफी बढ़ावा मिलेगा। मोजाम्बिक के सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण संयंत्र से भारतीय जुड़ाव को मोजाम्बिक के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से काफी प्रभावकारी माना जा सकता है। संयंत्र में तैयार सौर पैनलों का उपयोग मोजाम्बिक में गांवों से जुड़ी कई ग्रामीण बिजली परियोजनाओं, स्कूलों और अस्पतालों में किया जाएगा, जबकि अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात अन्य अफ्रीकी देशों को किया जाएगा।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना:

दक्षिणीय सहयोग

'विकास संविदा' की रूपरेखा के तहत भारत के विकास सहयोग की गतिशीलता

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, प्रो. मिलिंदो चक्रबर्ती और श्री प्रणय सिन्हा

आरआईएस विभिन्न अनुसंधान धाराओं के माध्यम से दक्षिणीय सहयोग और भारत के विकास सहयोग पर अपने कामकाज को आदर्श रूप देने के लिए अपनी 'विकास संविदा' की रूपरेखा को आगे बढ़ा रहा है। उन विभिन्न तौर–तरीकों का आकलन करने का प्रयास किया गया, जिनके माध्यम से दक्षिण एशिया की पहुंच विकास वित्त तक संभव हो पाती है। 'दक्षिण एशिया में विकास वित्त' पर एक कार्यशाला दिसंबर 2017 में आयोजित की गई जिसमें मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एवं अफगानिस्तान ने भाग लिया और इन देशों ने उभरते विकास अनुभवों का पता लगाया। इसके अलावा, इन कागजातों के आधार पर एक पुस्तिका स्प्रिंगर के साथ मिलकर तैयार करने की योजना बनाई गई है। इसका शीर्षक होगा 'दक्षिण एशिया में विकास वित्तः उभरती गतिशीलता और दक्षिणीय सहयोग की रूपरेखा।'

एसएससी परियोजनाओं का प्रभाव आकलन

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, प्रो. मिलिंदो चक्रबर्ती और श्री प्रणय सिन्हा

चूंकि एसएससी के प्रभाव और इसकी प्रभावकारिता पर चर्चाओं की संख्या बढ़ रही है, इसलिए विकासशील देशों की सरकारों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे प्रभाव आकलन के लिए एक रूपरेखा तैयार करें। आरआईएस चूंकि एसएससी से संबंधित मुद्दों से निकटता से जुड़ा हुआ है, इसलिए आकलन की रूपरेखा का आइडिया या विचार मौजूदा प्रयासों में अच्छी तरह फिट बैठता है। आगे चलकर प्रभाव आकलन की रूपरेखा के साथ 'लर्निंग एसएससी' को जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम भी विकसित किया जा सकता है। इस तरह के कार्यक्रम को वर्ष 2019 के मध्य में एक विंटर स्कूल के रूप में पेश करने की योजना है।

इस कवायद के ये उद्देश्य हैं: विकासशील देशों के प्रतिभागियों को विकास संबंधी कदमों के प्रभाव आकलन पर दो हफ्तों के प्रशिक्षण और प्रकटीकरण (एक्सपोजर) कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए एक कार्यक्रम विकसित करना; और एसएससी के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक ऐसी नई रूपरेखा विकसित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करना जो डीएसी द्वारा अपनाई जा रही रूपरेखा से भिन्न होगी।

दक्षिणीय वैष्विक विचारकः दक्षिणीय सहयोग के लिए थिंक टैंक नेटवर्कों का वैश्विक गठबंधन

प्रो. मिलिंदो चक्रबर्ती और श्री प्रणय सिन्हा

दो अनुसंधान परियोजनाओं का वित्तं पोषण यूएनडीपी–यूएनओएसएससी द्वारा अपने अनुदान कार्यक्रम के तहत किया गया है। पहली शोध परियोजना का उद्देश्य रुझानों पर फोकस करना है और इसके साथ ही यह खाका तैयार करना है कि एसएससी आखिरकार किस प्रकार की गतिविधियों की बदौलत बहुत विनम्र शुरुआत करने के बाद अत्यंत विकसित हुआ है तथा यह विकासशील देशों के कुछ बड़े निकायों (बीआरआई, एएजीसी) की कुछ अत्यंत बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का अस्तित्व कैसे है। दूसरे शब्दों में, अनुसंधान यह पता लगाएगा कि वर्ष 1978 से आखिरकार क्या बदल गया है, इन बदलावों को कौन सुनिश्चित कर रहा है और तेजी से बन रहे व्यस्त विकास परिदृश्य में एसएससी की दिशा के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? एक अवधारणा के रूप में एसएससी किन–किन चुनौतियों का सामना कर रहा है? अनुसंधान का उद्देश्य एसएससी के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करना है। दूसरी अनुसंधान परियोजना के तहत मौजूदा मूल्यांकन और आकलन रूपरेखाओं को आंकने और राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं के साथ–साथ आपसी साझाकरण व्यवस्था सहित विभिन्न तत्वों को एकीकृत करके एसएससी के आकलन के लिए एक अभिनव रूपरेखा को बेहतर/विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चीन, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से एक–एक केस स्टडी के साथ कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं एसएससी व्यापार और बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित तीन विशिष्ट क्षेत्रों में एसएससी के प्रदर्शन एवं प्रभावों का आकलन करने के लिए नई रूपरेखा लागू की जाएगी। रिपोर्ट यूएनओएसएससी को सौंप दी गई है। समीक्षकों की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं और अंतिम रिपोर्ट जल्द ही प्रस्तुत की जाएगी।

क. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचनाः

दक्षिणीय सहयोग

अफगान नागरिकों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना (एसएसएसएएन) का प्रक्रिया मूल्यांकनः कार्यक्रम आईसीसीआर द्वारा कार्यान्वित

प्रो. सचिन चतुर्वेदी और प्रो. मिलिंदो चक्रबर्ती

भारत सरकार (जीओआई) 'अफगानिस्तान नागरिकों के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति योजना (एसएसएसएएन)' के जरिए क्षमता निर्माण में अफगानिस्तान सरकार की सहायता कर रही है। क्षमता निर्माण भारत और अफगानिस्तान के बीच उस समग्र विकास साझेदारी का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसके तहत अफगानिस्तान के विकास और संचालन में योगदान किया जा रहा है। यह योजना वर्ष 2006–07 से ही लागू है। इस योजना के तहत 1000 वार्षिक छात्रवृत्ति स्थान वर्तमान में भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में कई पाठ्यक्रमों में अफगान छात्रों के लिए निर्दिष्ट हैं। वर्ष 2017 तक दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम कार्य विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में चल रहा है। एसएसएसएएन अफगान युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। आवंटित स्थान पूरी तरह से उपयोग में लाए जा रहे हैं। इस योजना का संचालन भारत सरकार की ओर से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) द्वारा किया जा रहा है। आईसीसीआर के 17 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संस्थान की फीस, ट्यूशन फीस और छात्रवृत्ति राशि का वितरण किया जा रहा है। मौजूदा छात्रवृत्ति योजना का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया गया है, ताकि योजना के प्रबंधन का आकलन किया जा सके और इसके साथ ही, जहां भी उपयुक्त प्रतीत हो, वहां प्रशासन और योजना के प्रबंधन में सुधार के लिए सिफारिशें पेश की जा सकें। मूल्यांकन भारत में योजना के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं तक सीमित है, जिनमें शुल्क का भुगतान, छात्रवृत्तियों का वितरण, छात्रावास का बकाया भुगतान, अफगान छात्रों की शिकायतों का निपटारा करना, भारतीय विश्वविद्यालयों के समक्ष मौजूद विभिन्न मुद्दों को सुलझाना, इत्यादि शामिल हैं। रिपोर्ट पेश कर दी गई है और विदेश मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

डेवलपमेंट कोऑपरेशन रिव्यू (डीसीआर)

राजदूत अमर सिन्हा, प्रो. मिलिंदो चक्रबर्ती, श्री प्रणय सिन्हा और सुश्री अमिका बावा

पत्रिका 'डेवलपमेंट कोऑपरेशन रिव्यू (डीसीआर)' को विश्व स्तर पर अकादमिक और नीति निर्माण हलकों में काफी सराहा गया है। यह विभिन्न देशों में दक्षिणीय सहयोग से जुड़े अनुभवों का दस्तावेज भी है। आरआईएस ने इसे एक संयुक्त प्रकाशन के रूप में प्रस्तुत करने हेतु संभावित सहयोग के लिए सेज पब्लिकेशंस से संपर्क किया है। 'बापा+40' सम्मेलन की पूर्व संध्या पर मार्च 2019 में डीसीआर के एक विशेष अंक को प्रकाशित करने का भी प्रस्ताव है।

ख. व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहलः द्विपक्षीय सहयोग

एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में हो रहे मेगा–एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता) को ध्यान में रखते हुए देश की भावी निर्यात रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में अन्य देशों के साथ अपने व्यापार संबंधों की समीक्षा की है। इस प्रयास के तहत द्विपक्षीय व्यापार के साथ–साथ उन बाजारों पर केंद्रित किया जाता है जिनका दोहन अब तक नहीं हो पाया है या अपेक्षा से अत्यंत कम दोहन हुआ है। व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण पर अग्रणी नीतिगत अनुसंधान संस्थान होने के नाते आरआईएस ने अपना ध्यान केंद्रित करते हुए कई अनुभवजन्य अनुसंधान अध्ययन किए हैं। ये अध्ययन भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से दक्षिण एशियाई देशों जैसे कि ईरान, बांग्लादेश, मालदीव एवं अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों, लैटिन अमेरिकी एवं कैरिबियन (एलएसी) क्षेत्र के साथ व्यापार संबंधों और भारत–मॉरीशस व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर किए गए हैं।

भारत–मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (सीईसीपीए) : संयुक्त अध्ययन समूह की रिपोर्ट

प्रो. एस.के. मोहंती

भारत और मॉरीशस के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंध 18वीं शताब्दी से ही हैं। इसने दोनों देशों के बीच मजबूत और सौहार्दपूर्ण संबंधों में अहम योगदान दिया है। दोनों देशों ने व्यापक क्षेत्रों में कई द्विपक्षीय समझौतों और सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। नवंबर 2003 में सीईसीपीए के लिए सिफारिशें प्रदान करने के उद्देश्य से एक संयुक्त अध्ययन समूह (जेएसजी) का गठन करने का निर्णय लिया गया। भारत–मॉरीशस सीईसीपीए से जुड़ी वार्ताएं वर्ष 2006 में शुरू हुई थीं और 'वस्तुओं के व्यापार' से संबंधित अध्याय पर पारस्परिक सहमति होने के साथ–साथ हस्ताक्षर किए गए थे। ऐतिहासिक दोहरा कराधान निवारण समझौते (डीटीएए) पर 10 मई, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे और इससे वर्ष के आखिर तक जेएसजी रिपोर्ट का मार्ग प्रशस्त हो गया था।

दोनों देशों के बीच सीईसीपीए की वार्ताएं वर्ष 2016 में फिर से शुरू हुईं और भारत–मॉरीशस सीईसीपीए पर वार्ता फिर से शुरू होने पर पहली बैठक 12 से 13 सितंबर, 2016 को मॉरीशस में आयोजित की गई और वर्ष 2004 की जेएसजी रिपोर्ट को अपडेट करने का निर्णय लिया गया। जेएसजी रिपोर्ट तैयार करने के लिए दोनों पक्षों की ओर से दो टीमों का गठन किया गया था। भारत की ओर से आरआईएस की सेवाएं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) द्वारा ज्ञान साझेदार के रूप में ली गई थीं और उसे मसौदा रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तदनुसार, सीईसीपीए जेएसजी रिपोर्ट का प्रारंभिक मसौदा आरआईएस द्वारा तैयार किया गया था। रिपोर्ट वाणिज्य विभाग को सौंपी गई थी।

भारत–बांग्लादेश सीईपीए पर संयुक्त अध्ययन समूह

प्रो. एस. के. मोहंती और सुश्री चांदनी दवानी

वाणिज्य विभाग ने संयुक्त अध्ययन समूह के लिए भारत–बांग्लादेश सीईपीए पर अध्ययन की जिम्मेदारी आरआईएस को सौंपी है। अध्ययन में इन मुद्दों को शामिल किया जाएगाः भारत एवं बांग्लादेश में वृहद आर्थिक स्थितियों का अवलोकन; वस्तुओं में व्यापार एवं व्यापार उदारीकरण; निवेश उदारीकरण; सेवाओं में व्यापार; सहयोग के अन्य क्षेत्र और प्रस्तावित सीईपीए से आर्थिक कल्याण का विचार।

ख. व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल: द्विपक्षीय सहयोग

ईरान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंध

प्रो. एस.के. मोहंती

भारत ने अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने को प्राथमिकता दी है। व्यापार, निवेश, सहायता प्रवाह और पारस्परिक जन संवाद के क्षेत्र में भारत और दक्षिण एशिया के अन्य क्षेत्रीय दिग्गजों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव का दायरा अतीत की तुलना में अब कहीं ज्यादा गहरा एवं व्यापक है। भारत–ईरान द्विपक्षीय संबंध भारत की हालिया 'हार्ट ऑफ एशिया' नीति के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। भारत के ऊर्जा आयात की दृष्टि से भी ईरान महत्वपूर्ण है। भारत–बांग्लादेश सहयोग महज टैरिफ उदारीकरण से कहीं परे है क्योंकि इन दोनों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के साथ–साथ समुद्री सहयोग के लिए एक सहमति पत्र (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भारत और मालदीव ने भी एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत एवं अफगानिस्तान ने एक पीटीए और रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसने उनके द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को काफी मजबूत कर दिया है।

यह अध्ययन ईरान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान के साथ भारत के व्यापक द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य चुनिंदा दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव के वर्तमान स्तर पर गौर करना और व्यापार एवं निवेश में सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करना है। यह भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता के आधार पर उनके साथ द्विपक्षीय व्यापक साझेदारी समझौता करने की संभावनाओं का पता लगाएगा। ईएचएस, पीटीए, एफटीए, सीईपीए, इत्यांदि के लिए बातचीत की संभावनाओं पर गौर किया जाएगा। विश्लेषण के प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार प्रदर्शन, व्यापार क्षमता, निर्यात प्रतिस्पर्धी क्षमता, दीर्घकालिक आयात हित, टैरिफ, एनटीबी, व्यापार विविधीकरण, तीसरे देश से प्रतिस्पर्धा, वरीयता का मार्जिन, एफडीआई इत्यादि शामिल होंगे। इस तरह की रणनीति लक्षित उत्पादों, विशेष ध्यान वाले क्षेत्रों, व्यापार क्षमता, निवेश के अवसरों, व्यापार नीति में बदलाव, इत्यादि के संदर्भ में विचाराधीन दक्षिण एशियाई देशों के साथ अपने व्यापार संबंधों में भारत की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करेगी। इसका वित्त पोषण भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

लेटिन अमेरिका क्षेत्र में भारत को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने की रणनीति

प्रो. एस.के. मोहंती

अध्ययन में डेटा के अलग–अलग स्तर का उपयोग कर विभिन्न परिकल्पनाओं पर गौर करने के लिए अनुभवजन्य दृष्टिकोण अपनाने का इरादा व्यक्त किया गया है। इसके तहत विशेषकर व्यापार पूरकता, व्यापार प्रतिस्पर्धी क्षमता, अन्य उभरते बाजारों की प्रतिस्पर्धी व्यापार उदारीकरण नीति के मुद्दों के संबंध में बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में क्षेत्रीय सहयोग के लिए अर्थव्यवस्थाओं की अंतर निर्भरता का आकलन करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। अध्ययन का उद्देश्य भारत और एलएसी (लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन) देशों के बीच व्यापार एवं निवेश पर भावी सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करना है। अलग–अलग स्तर पर व्यापार विश्लेषण से भारत और एलएसी देशों के बीच आपसी सहयोग के लिए विभिन्न सेक्टरों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। यह आपस में अनुबंध करने वाले पक्षों को घरेलू अर्थव्यवस्था में व्यापार और रोजगार के अवसर सृजित करने की मजबूत संभावनाओं वाले उभरते सेक्टरों में निवेश के अवसरों का पता लगाने में सक्षम कर सकता है। यह अध्ययन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता है। उद्योग परामर्श के बाद अध्ययन को अंतिम रूप दिया गया और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।

ख. व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल: गैर–टैरिफ पर अध्ययन

गैर–टैरिफ उपाय: डेटाबेस

प्रो. एस.के. मोहंती

गैर–टैरिफ उपायों (एनटीएम) पर ज्ञान की वर्तमान स्थिति व्यापक है, लेकिन साधारण निर्यातकों और अकादमिक निरीक्षण की दृष्टि से अधूरी है। एनटीएम पर आंकड़े चुनिंदा दायरे और विभिन्न देशों में सामान्य प्रारूप के अभाव के कारण इनके व्यापार प्रभावों के त्वरित आकलन के अनुरूप नहीं हैं। विश्व व्यापार संगठन द्वारा काफी प्रयास करने के बावजूद एनटीएम डेटा का विश्लेषण बोझिल है और इसमें काफी समय लगता है। कार्यप्रणाली की दृष्टि से एनटीएम की परिभाषा और मात्रा निर्धारण में काफी विरोधाभास है। इसके परिणामस्वरूप व्यापार पर एनटीएम संबंधी बदलावों के प्रभाव के अनुभवजन्य विश्लेषण की गुणवत्ता अत्यधिक व्यक्तिपरक है और डेटा एवं अर्थमितीय तकनीक के चयन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। चूंकि एनटीएम द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के लिए व्यापार नीति के भावी साधन हैं, इसलिए एनटीएम के विभिन्न पहलुओं पर एक ही अध्ययन में प्रकाश डालना अनिवार्य है जो नीति निर्माताओं, विद्यार्थियों और व्यापार डेटा के सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी होगा। वैसे तो अध्ययन का अधिकांश हिस्सा संबंधित सामग्री के एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण को कवर करेगा, लेकिन अध्ययन का उद्देश्य एनटीएम से जुड़े समावेशी या विवादास्पद अकादमिक परिवेश के अनावश्यक फैलाव से बचना है। एक एनटीएम डेटाबेस को विकसित करने पर काम इस अवधि में जारी रहा। इसके तहत मुख्य आइडिया यह है कि जब भी जरूरत हो, तो एनटीएम के व्यापार प्रभावों का अनुभवजन्य आकलन अवश्य किया जाए।

आसियान–भारत गैर–टैरिफ उपायों (एनटीएम) पर अध्ययन

डॉ. प्रबीर डे, डॉ. दुरइराज कुमारसामी और सुश्री कोमल बिस्वाल

एनटीएम को व्यापार के लिए अब और भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। एनटीएम के चलते आसियान और भारत के बीच व्यापार में बाधा उत्पन्न हुई है। प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर यह अध्ययन व्यापारियों, अधिकारियों, व्यापार/व्यवसाय संगठनों एवं पेशेवर जैसे हितधारकों के बीच एनटीएम की धारणा और जागरूकता के स्तर का आकलन करता है। अध्ययन को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहला, प्राथमिक और द्वितीयक डेटा का विश्लेषण, जो हमें व्यापार बाधाओं पर तीव्रता एवं धारणा के बारे में बताता है। दूसरा, नियामकीय माहौल का विश्लेषण, ताकि नियामकीय प्रणाली में विभिन्न अंतरों की पहचान की जा सके। दोनों अंततः हमें कुछ सिफारिशें पेश करने और आगे बढ़ने के मार्ग पर ले जाते हैं। अध्ययन पूरा हो गया है और फरवरी 2019 तक रिपोर्ट प्रकाशित कर दी जाएगी।

ख. व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहलः इब्सा पर ध्यान केंद्रित

आरआईएस बड़ी सक्रियता के साथ ज्ञान को साझा करने और नीतिगत अनुसंधान के जरिए इब्सा देशों में विभिन्न मुद्दों और दृष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित करने पर काम करता रहा है। वर्ष 2017 से ही इब्सा फेलोशिप प्रोग्राम की निरंतरता के अलावा आरआईएस ने सतत विकास एजेंडे को साकार करने के लिए इब्सा फंड की संरचना और उद्भव को समझने के लिए भी एक अध्ययन शुरू किया है।

आरआईएस में इब्सा फेलोशिप

आरआईएस लंबे समय से इब्सा संबंधी मुद्दों पर काम करता रहा है। इस कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में वर्ष 2017 में विदेश मंत्रालय में इब्सा फेलोशिप शुरू की गई थी। ब्राजील से दो, दक्षिण अफ्रीका से एक और भारत से दो रिसर्च फेलो ने भाग लिया। उनके द्वारा पेश कागजात के आधार पर एक पत्रिका भी प्रस्तुत की गई। दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और भारत के रिसर्च फेलो की भागीदारी के साथ इब्सा फेलोशिप का दूसरा संस्करण फरवरी 2019 में प्रारंभ किया गया।

इब्सा : इब्सा फंड की समीक्षाः आगे की राह

डॉ. बीना पांडेय

विकास सहयोग के मामले में 'गरीबी और भुखमरी उन्मूलन के लिए इब्सा सुविधा (इसे इब्सा फंड के रूप में भी जाना जाता है)', जो तीन देशों की अगुवाई में एकमात्र स्पष्ट वित्तीय व्यवस्था है और जिसका प्रबंधन दक्षिणीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओएसएससी) द्वारा किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में विकासशील देशों की सबसे महत्वपूर्ण संरचित पहलों में से एक है। यूएनओएसएससी दरअसल फंड मैनेजर के साथ–साथ इब्सा फंड के सचिवालय के रूप में कार्य करता है एवं इसके निदेशक मंडल का समर्थन करता है क्योंकि यह फंड के रणनीतिक विजन और विकास गतिविधियों को तय करता है। यह फंड मैनेजर के साथ–साथ अन्य दक्षिणीय और त्रिकोणीय सहयोग ट्रस्ट फंडों की संचालन समितियों के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है जिसे संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, अर्थात, पेरेज– गुरेरो ट्रस्ट फंड (पीजीटीएफ), दक्षिणीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र फंड (यूएनएफएसएससी) और भारत–संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी फंड के साथ संयुक्त रूप से लागू किया गया। (इब्सा, यूएनओएसएससी, 2017)

इब्सा फंड का मूल्यांकन करने के लिए संबंधित पेपर पहले खंड में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में परिचय प्रस्तुत करेगा और इसके बाद इब्सा फंड के उद्देश्य एवं औचित्य शामिल होंगे। अगले खंड में अल्प विकासशील देशों में विभिन्न मौजूदा एवं पूर्ण फंड परियोजनाओं और गरीबों के क्षमता निर्माण एवं सशक्तिकरण पर उनके सकारात्मक परिणामों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इन परियोजनाओं को अब सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति से जोड़ दिया गया है। अंतिम खंड में निष्कर्ष और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी।

ख. व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल

अफ्रिका और एशिया

विशाल युवा आबादी और विविध संसाधनों से परिपूर्ण भारत एवं अफ्रीका ने हाल के वर्षों में अपने द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय राजनयिक और आर्थिक जुड़ावों को काफी मजबूत किया है। चूंकि भारत और अफ्रीका दोनों ही कमोबेश एक जैसी विकास चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इसलिए दोनों ही पक्ष अब व्यापार एवं निवेश, ऋणों और सहयोग के विभिन्न रूपों जैसे कि दक्षिणीय और त्रिकोणीय विकास सहयोग प्रतिमान के जरिए विकास सहयोग के नए मॉडलों को अपना रहे हैं। भारत–अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आईएएफएस) ने भारत और अफ्रीकी देशों के बीच संबंधों को संस्थागत रूप दे दिया है। अफ्रीका ने भारत की वर्तमान विदेश नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता हासिल कर ली है। वर्ष 2016 से वर्ष 2018 तक की अवधि के दौरान भारत के प्रधानमंत्री की रवांडा, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, केन्या और तंजानिया यात्रा ने भारत एवं अफ्रीकी महाद्वीप के बीच संबंधों को और मजबूत कर दिया। भारत–अफ्रीका संबंधों पर नए सिरे से विशेष जोर दिए जाने के मद्देनजर आरआईएस ने एशिया–अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (एएजीसी) के तहत कई अध्ययनों की शुरुआत की है जो 'डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट' की रूपरेखा के अंतर्गत भारत एवं अफ्रीकी देशों के बीच और भी ज्यादा गहरे जुड़ाव की संभावनाओं को तलाशेंगे।

एशिया अफ्रीका विकास कॉरिडोर (एएजीसी)

राजदूत अमर सिन्हा, प्रो. अमिताभ कुंडू और डॉ. प्रियदर्शी दाश

जैसा कि कार्रवाई रिपोर्ट में बताया गया है, एएजीसी पर जारी इसके काम के तहत श्री शेषाद्री चारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जो एएजीसी/एफओआईपी की रूपरेखा के अंतर्गत साझेदार देशों के साथ निजी क्षेत्र के मजबूत जुड़ाव के लिए एक समयबद्ध खाका (रोडमैप) तैयार करेगी। मुंबई में प्रस्तावित परामर्श में भागीदारी के लिए ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ चर्चा शुरू कर दी गई है। यह औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) तथा विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों को भी समिति में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकती है, ताकि उनके ज्ञान और अनुभव से लाभ उठाया जा सके। विशिष्ट पहलुओं को स्पष्ट करने वाले आठ परिचर्चा प्रपत्रों (डिस्कशन पेपर) का एक संग्रह लाया गया है। इसके अलावा, एक पत्रिका (वॉल्यूम) की भी योजना बनाई गई है, जिसे स्प्रिंगर द्वारा पेश किया जाएगा। वैसे तो परियोजनाओं के सही शीर्षकों और विशेषताओं की पहचान अभी तक नहीं की गई है, लेकिन एएजीसी पर आरआईएस के परिचर्चा प्रपत्रों ने उन संभावित क्षेत्रों पर प्रकाश डाला है जिनमें भारत–जापान परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं। अक्टूबर 2018 में भारत के प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य में पड़ोसी देशों में सात बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की पहचान की गई है। जापान ने एएजीसी की मीडिया कल्पना के रूप में बीआरआई की तुलना में एक संतुलनकारी कदम उठाया है और प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों के रूप में बीआरआई कई गुना बढ़ गई है। हालांकि, यह एएजीसी के लिए उनकी प्रतिबद्धता को संभवतः प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा, भारत ने अस्पतालों के निर्माण के लिए अफ्रीका में सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करने की भी घोषणा की है। आरआईएस इस कार्यक्रम को जोरदार तरीके से आगे बढ़ा रहा है।

अफ्रीका में विषमता और साझेदार देशों का चयन

प्रो. मिलिंदो चक्रबर्ती और श्री अहमद गार्बा खलील

अफ्रीकी देशों में व्याप्त आर्थिक विषमता के स्तर की पहचान करने के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व विकास संकेतकों से विकसित डेटासेट पर काम करने के लिए एक शोध अध्ययन शुरू किया गया था। इसके उद्देश्य ये हैं: ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कारकों की पहचान करना जिनका उपयोग अफ्रीकी देशों में व्याप्त आर्थिक विषमता का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है; मौजूदा विषमता का वर्णन करने के लिए उनका उपयोग करना और एएजीसी की हालिया पहल को ध्यान में रखते हुए विकास सहयोग में संलग्नता के लिए देश–विशिष्ट रणनीतियां विकसित करने में मदद करना। डेटा विश्लेषण का पहला दौर पूरा हो गया है और कई विशिष्ट कारकों (फैक्टर) की पहचान की गई है। परिचर्चा प्रपत्र के रूप में इस कवायद का पहला परिणाम जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा।

ख. व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल: वित्तीय सहयोग

विकासशील देशों में वित्तीय सेक्टर का विकास असमान और विविध रहा है। 1990 और 2000 के दशकों में वित्तीय संकट के बार–बार गहराने की घटनाओं ने विभिन्न देशों को संभावित जोखिमों एवं असुरक्षा या कमजोरियों को कम करने के लिए अपने–अपने वित्तीय क्षेत्रों (सेक्टर) में सुधारों को लागू करने के लिए प्रेरित किया है। एहतियाती विदेशी मुद्रा भंडार एवं मुद्रा अदला–बदली की व्यवस्थाओं को मजबूत करने और विनिमय दर में समन्वय सुनिश्चित करने के अलावा प्रभावित अर्थव्यवस्थाएं और अन्य विकासशील देश अमेरिकी डॉलर तथा वित्तीय प्रणाली के एंग्लो–सैक्सन मॉडल पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय मुद्रा वाले पूंजी बाजारों के विकास और व्यापार संबंधी इन्वॉयसिंग के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग पर विशेष जोर दिया जाता है। वित्तीय प्रौद्योगिकियां सभी देशों को वित्तीय सेक्टर का विस्तार करने, वित्तीय समावेश को सुनिश्चित करने, वित्तीय बाजार के विविधीकरण, वित्तपोषण के अभिनव मॉडलों को अपनाने और जोखिमों के आकलन के लिए अपार अवसर प्रदान करती हैं। इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए आरआईएस ने बिम्सटेक में स्थानीय मुद्रा वाले पूंजी बाजारों के साथ–साथ स्थानीय मुद्रा एवं वित्तीय प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर दो अध्ययन किए हैं।

विकासशील देशों में स्थानीय मुद्रा पूंजी बाजारों को बढ़ावा देना

डॉ. प्रियदर्शी दाश

विकासशील देशों में वित्त पोषण के बाहरी स्रोतों पर निर्भरता बढ़ रही है क्योंकि बुनियादी ढांचागत विकास, सामाजिक क्षेत्र के विकास और सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वित्तपोषण की आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। ब्याज की बाजार दर पर विदेशी मुद्रा में बाह्य वाणिज्यिक उधारियां (ईसीबी) अक्सर विकासशील देशों के अनुकूल नहीं होती हैं क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार अपेक्षाकृत कम रहने की स्थिति में ऋण अदायगी का बोझ कष्टदायक हो जाता है। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा में अल्पकालिक ऋणों से डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ जाता है और वास्तविक क्षेत्र में अवांछित समायोजन के लिए विवश होना पड़ता है। उस नजरिए से स्थानीय पूंजी बाजार विशेषकर स्थानीय मुद्रा में बांड और अन्य दीर्घकालिक प्रतिभूतियां विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने में प्रभावकारी साबित हो सकती हैं और इनसे घरेलू बचत के कुशल संचालन में मदद मिलती है। एक जीवंत स्थानीय पूंजी बाजार वित्तपोषण के साधनों में विविधता लाने में मदद कर सकता है और इसके साथ ही बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार के जोखिमों को कुशलतापूर्वक एकजुट करने में भी मददगार साबित हो सकता है।

बिम्सटेक क्षेत्र में स्थानीय मुद्रा और वित्तीय प्रौद्योगिकियों का उपयोग

डॉ. प्रियदर्शी दाश

विनिमय दर में अस्थिरता से निर्यात एवं आयात के मूल्य में अनिश्चितता रहती है और हेजिंग की लागत की दृष्टि से यह व्यापारियों के लिए महंगी या नुकसानदेह साबित होती है। इस पहलू पर वित्तीय सहयोग के संदर्भ में चर्चा की गई है जो विभिन्न देशों के बीच मुद्रा अदला–बदली व्यवस्था में वृद्धि में अभिव्यक्त होता है। उदाहरण के लिए, अकेले चीन ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए 31 मुद्रा अदला–बदली व्यवस्थाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी तरह जापान ने भी अपने एशियाई और अन्य व्यापार साझेदारों के साथ कई मुद्रा अदला–बदली व्यवस्थाएं कर रखी हैं। कई मुद्रा अदला–बदली व्यवस्थाओं के अलावा भारत ने अतीत में नेपाल, ईरान और रूस के साथ रुपये में व्यापार की व्यवस्थाएं लागू की हैं। इस पृष्ठभूमि में बिम्सटेक देश विनिमय दर में सहसा होने वाले उतार–चढ़ाव से उत्पन्न वित्तीय असुरक्षा को कम करने के साधन के रूप में स्थानीय मुद्रा में व्यापार की संभावनाओं का भी पता लगा सकते हैं। ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उभरती वित्तीय प्रौद्योगिकियों ने न केवल वित्तीय सेक्टरों को बदल दिया है, बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों और समाज को सशक्त भी बनाया है। बायोमीट्रिक पहचान आधारित आधार कार्ड बनाना; जन धन योजना के जरिए 330 मिलियन बैंक खाते खोलना; मुद्रा स्कीम में लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को 145 मिलियन ऋण देना, और भीम–यूपीआई जैसी स्वयं भुगतान प्रणालियों का विकास इस दिशा में कुछ अत्यंत सफल कदम या उपाय हैं। इस परिप्रेक्ष्य में (ए) बिम्सटेक क्षेत्र में डिजिटल एवं वित्तीय प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोगों (एप्लीकेशन) का आकलन (ख) स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय एवं बिम्सटेक क्षेत्रीय भुगतान व्यवस्था की अवधारणा तथा डिजाइन, और (ग) वित्तीय प्रौद्योगिकियों को साझा करने में सहयोग के विशिष्ट तौर–तरीके जैसे मुद्दों पर गहराई से गौर किया जा सकता है, ताकि बिम्सटेक देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। हाल ही में थिंक–टैंकों के बिम्सटेक नेटवर्क की बैठक में आरआईएस ने इस पर समूह के सदस्यों के साथ कुछ अध्ययनों में योगदान देने का प्रस्ताव रखा।

ख. व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल: बिम्सटेक सहयोग

'पड़ोसी पहले' सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए आरआईएस एक क्षेत्रीय और रणनीतिक संघ (कंसोर्टियम) के रूप में बिम्सटेक की प्रासंगिकता को काफी अहम मानता है। इस बारे में कुछ अध्ययन किए जाते हैं, जिनके तहत स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में बिम्सटेक देशों के बीच सहयोग के दायरे और महत्व का पता लगाने का प्रयास किया जाता है।

बिम्सटेक में स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग

प्रो. टी सी जेम्स और डॉ. आभा जायसवाल

'लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट' की भारत की रणनीति के तहत भारत और अन्य बिम्सटेक देशों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास सहयोग पर एक अध्ययन कराने की योजना है। यह अध्ययन यह भी पता लगाएगा कि सीमावर्ती जिलों का विकास और पड़ोसी देशों के साथ भारत का सहयोग किस तरह से परस्पर जुड़ेंगे। इसके एक भाग के रूप में 'त्रिपुरा में स्वास्थ्य सेवा के सार्वभौमीकरण की स्थिति का तथ्यात्मक विश्लेषण' तैयार किया गया है और नीति आयोग के साथ साझा किया गया है। भूटान में स्वास्थ्य सेवा पर एक तथ्यात्मक स्थिति प्रपत्र तैयार किया गया है और उसके आधार पर 'बिम्सटेक नेटवर्क ऑफ पॉलिसी थिंक टैंक्स' में बिम्सटेक में स्वास्थ्य क्षेत्र के वित्त पोषण के तुलनात्मक विश्लेषण पर एक अध्ययन कराने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था जिसे अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ है। अध्ययन के तहत इन मुद्दों पर गौर किया जाएगा: (1) स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त सार्वजनिक व्यय प्रदान करने में सार्वजनिक नीतिगत चुनौतियां क्या हैं? (2) क्या वित्त पोषण के समान पैटर्न हो सकते हैं? (3) वर्ष 2030 तक यूएचसी की प्राप्ति के लिए किफायती व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए नीति और रणनीति के रूप में क्या–क्या कदम उठाए जा सकते हैं? (4) स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसी कौन–कौन सी सर्वोत्तम प्रथाएं हैं जिन्हें विभिन्न देशों के बीच साझा किया जा सकता है? और (5) स्वास्थ्य क्षेत्र के वित्तपोषण में बाह्य सहायता का इष्टतम उपयोग किस तरह से उस राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंडे के लिए किया जा सकता है जिसे आरआईएस ने इस अध्ययन के हिस्से के तहत बतौर प्रायोगिक परियोजना प्रस्तावित किया है।

बिम्सटेक क्षेत्र में एक संभावित उच्च शिक्षा हब के रूप में भारत का उद्भव

डॉ. बीना पांडेय

यह अध्ययन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए दक्षिण एशियाई और अन्य विकासशील देशों, विशेषकर बिम्सटेक को भारत की विकास सहायता पर केंद्रित है। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहां उच्च शिक्षण संस्थानों की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रणाली है। दरअसल, भारत ने स्वयं को उच्च शिक्षा के एक भावी गंतव्य के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया है जहां किफायती उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली की सबसे आकर्षक विशेषता बन गई है।

इस पृष्ठभूमि में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित सतत विकास लक्ष्य 4 की प्राप्ति के लिए पहली आवश्यकता के रूप में गुणवत्ता, पहुंच, समानता और समावेश को बढ़ावा देने में भारत द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपार गुंजाइश है। इसके अलावा, चूंकि सार्क ने अपनी चमक खो दी है, इसलिए भारत अपनी पहल 'भारत में अध्ययन' के तहत बिम्सटेक देशों के लिए शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता में एक सक्रिय साझेदार हो सकता है।

दक्षिण और बिम्सटेक क्षेत्र में एक संभावित शिक्षा हब (केंद्र) के रूप में भारत की हैसियत का आकलन करने के लिए इसका पहला खंड उच्च शिक्षा मुहैया कराने में अन्य देशों को भारत से अब तक मिलती रही सहायता का ऐतिहासिक अवलोकन प्रस्तुत करेगा। अगला खंड भारत के शैक्षिक सहायता कार्यक्रमों और आपसी डिग्रियों की मान्यता में विकासशील देशों को शैक्षणिक सहयोग देने के तौर–तरीकों पर प्रकाश डालेगा। तीसरा खंड भारत में विदेशी विद्यार्थियों की ताजा स्थिति पर प्रकाश डालेगा। अंतिम खंड में विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने से जुड़ी भारत की क्षमताओं और नीतिगत पहलों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद भविष्य की कार्ययोजना के लिए सहयोग सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह का उल्लेख होगा।

ग. व्यापार सुविधा, संपर्क और क्षेत्रीय एकीकरण: संपर्क

आरआईएस क्षेत्रीय एकीकरण के विभिन्न पहलुओं पर काम करता रहा है। हाल ही में किए गए अध्ययन संपर्क और क्षेत्रीय एकीकरण की ओर उन्मुख हैं। इस बारे में प्रकाशित रिपोर्टों में आसियान–भारत विकास एवं सहयोग 2020 और राष्ट्रीय समुद्री नीति पर रिपोर्ट शामिल हैं। संपर्क के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वह मध्य एशिया के साथ भारत की संपर्क के लिए चाबहार पर रणनीतिक चिंतन हो, या 'सॉफ्ट संपर्क' से जुड़े विचार हों, जिससे तात्पर्य लोगों को आपस में जोड़ने से होता है। आरआईएस स्थित आसियान केंद्र ने ईआरआईए के साथ मिलकर एक अध्ययन किया जिसके तहत त्रिपक्षीय राजमार्ग के विशेष महत्व पर गौर किया गया। विभिन्न अध्ययन भारत एवं आसियान देशों के बीच उत्पादन नेटवर्कों के साथ–साथ 'आसियान आर्थिक समुदाय 2025' की प्रासंगिकता के बारे में पता लगाने में योगदान कर रहे हैं।

त्रिपक्षीय राजमार्ग पर इरिया–आरआईएस अध्ययन

डॉ. प्रबीर डे, डॉ. दुरइराज कुमारसामी और अन्य

त्रिपक्षीय राजमार्ग (टीएच) में आर्थिक गलियारा बनने की व्यापक क्षमता है। इसके साथ ही टीएच का पूरा होना आसियान–भारत सहयोग के लिए विशेष महत्व रखता है। सिंगापुर 2018 में आयोजित आसियान–भारत शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष के वक्तव्य में त्रिपक्षीय राजमार्ग को आर्थिक गलियारा कैसे बनाया जाए, इस बारे में एक अध्ययन पूरा करने का सुझाव दिया गया। वक्तव्य में ईआरआईए से इस बारे में अध्ययन के लिए अनुरोध किया गया। हम अध्ययन का भारतीय भाग पूरा करेंगे।

राष्ट्रीय समुद्री नीति

प्रो. एस. के. मोहंती, डॉ. प्रियदर्शी दाश और श्री अरुण एस. नायर

अध्ययन के निम्नलिखित तीन भाग हैं:

भारत में समुद्री वाणिज्य

यह अध्ययन भारत के समुद्री वाणिज्य को समग्र रूप से देखता है और राष्ट्र की विशाल क्षमता के साथ–साथ उन संभावित आंतरिक एवं बाह्य सामंजस्य का व्यापक आकलन करता है जो समुद्री व्यापार को समावेशी और सतत विकास का इंजन बनाने में मदद कर सकते हैं। इस संबंध में यह आवश्यक है कि तटीय क्षेत्रों, आंतरिक इलाकों और मल्टी–मोडल परिवहन प्रणालियों को प्रभावकारी ढंग से एकीकृत किया जाए, ताकि भारत के विदेश व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके और इसके साथ ही भारत को समुद्री क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने की दिशा में अग्रसर किया जा सके।

भारत में समुद्री अवसंरचना

यह अध्ययन सुव्यवस्थित रूप से समुद्री अवसंरचना में भारत की ताकत एवं कमजोरियों के साथ–साथ उन वैश्विक रुझानों तथा सर्वोत्तम प्रथाओं का विश्लेषण करता है जो उभरते अवसरों के लिए संकेत हो सकते हैं और एक एकीकृत समुद्री संरचना को नया स्वरूप दे सकते हैं। नीति निर्माताओं, भारत के कॉरपोरेट जगत एवं अन्य हितधारकों को यह सलाह दी जाती है कि वे इन कारकों को ध्यान में रखें और देश के बंदरगाहों एवं पत्तनों, अंतर्देशीय जलमार्गों से ढुलाई, जहाज निर्माण एवं शिप–ब्रेकिंग और ड्रेजिंग उद्योगों के साथ–साथ अन्य संबद्ध क्षेत्रों के विस्तार में मदद करने के लिए अपनी अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियां बनाते समय एक लचीला, टिकाऊ और समावेशी दृष्टिकोण अपनाएं। इस अध्ययन में भारत में एक शीर्ष समुद्री प्राधिकरण का गठन करने की वकालत की गई है।

भारत में समुद्री प्रौद्योगिकी

अत्याधुनिक समुद्री प्रौद्योगिकियों को अपनाना एवं इनका दायरा बढ़ाना चौथी औद्योगिक क्रांति और डिजिटलीकरण के कारण बड़े पैमाने पर नजर आ रहे प्रौद्योगिकी अंतर को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है। यह अध्ययन भारतीय समुद्री क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार करने में मदद करने का प्रयास करता है, और समुद्री वाणिज्य, समुद्री संसाधनों और स्मार्ट मल्टीमॉडल परिवहन में प्रौद्योगिकियों से संबंधित विभिन्न रुझानों के साथ–साथ उनके कार्यान्वयन के उपायों में भी देरी करता है। यह अध्ययन भारतीय समुद्री क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार करने में मदद करने का प्रयास करता है, और समुद्री वाणिज्य, समुद्री संसाधनों एवं स्मार्ट मल्टीमोडल परिवहन में प्रौद्योगिकियों से संबंधित विभिन्न रुझानों के साथ–साथ उनके कार्यान्वयन के उपायों पर भी काफी बारीकी से गौर करता है।

ग. व्यापार सुविधा, संपर्क और क्षेत्रीय एकीकरण: आसियन

आसियान–भारत विकास और सहयोग रिपोर्ट 2020

डॉ. प्रबीर डे, डॉ. दुरइराज कुमारसामी, सुश्री श्रेया पान और अन्य

दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के साथ भारत का जुड़ाव उसकी 'एक्ट ईस्ट' नीति के केंद्र में है। एक क्षेत्रीय ब्लॉक के रूप में आसियान दरअसल एशिया–प्रशांत क्षेत्र के किसी भी अन्य ब्लॉक की तुलना में बहुत तेजी से विकसित हुआ है। आसियान और भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (आरसीईपी) के माध्यम से एक व्यापक मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफटीए) स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, इसलिए उनका सहयोग इस क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता, प्रतिस्पर्धी क्षमता, विकास और एकीकरण को बढ़ावा देने में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। हमने वर्ष 2015 में एआईडीसीआर का पहला अंक पेश किया है। पिछले चार वर्षों में आसियान–भारत संबंध कई चुनौतियों से गुजरे हैं।

भारत और आसियान के बीच उभरते उत्पादन नेटवर्कों पर अध्ययन

डॉ. प्रबीर डे और डॉ. दुरइराज कुमारसामी

आसियान–भारत एफटीए ने आसियान देशों और भारत के बीच उत्पादन नेटवर्कों की आवश्यकता को रेखांकित किया है। विदेश मंत्रालय के लिए किए जा रहे इस अध्ययन का उद्देश्य उन उद्योगों के अंतर्गत सीमा–पार उत्पादन नेटवर्क बनाने की संभावनाओं का पता लगाना है, जिनमें भारत की विनिर्माण क्षमता और संपूरकताएं निहित हैं और जो आसियान की मांग या आपूर्ति क्षमता के साथ मेल खाती हैं और बाकायदा इसके ठीक उलट स्थिति भी है। इसके अलावा, यह अध्ययन उत्पादन नेटवर्कों के निर्माण में आने वाली चुनौतियों की पहचान करने का भी प्रयास करता है। यह अध्ययन विशेषकर आसियान एवं भारत के बीच उत्पादन नेटवर्कों को बढ़ावा देने में संपर्क तथा व्यापार सुविधा में निहित अंतर की पहचान करता है और इसके साथ ही संभावित उपाय भी बताता है। इस अध्ययन में से एक अध्याय को पहले से ही एमजीसी रिपोर्ट में शामिल किया जा चुका है जो मई 2017 में प्रकाशित की गई थी।

आसियान आर्थिक समुदाय 2025 के निहितार्थों पर अध्ययन

डॉ. प्रबीर डे और सुश्री श्रेया पान

वर्ष 2015 में आसियान आर्थिक समुदाय (एईसी) की स्थापना आसियान में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के एजेंडे में एक प्रमुख मील का पत्थर है, जो 2.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के विशाल बाजार और 622 मिलियन से भी अधिक लोगों के रूप में अपार अवसर प्रदान करता है। वर्ष 2015 में कुआलालम्पुर में आयोजित 27वें आसियान शिखर सम्मेलन में आसियान नेताओं द्वारा अपनाया गया 'एईसी ब्लूप्रिंट 2025' दरअसल वर्ष 2016 से वर्ष 2025 तक एईसी के लिए रणनीतिक उपायों के माध्यम से व्यापक दिशा–निर्देश प्रदान करता है। 'एईसी ब्लूप्रिंट 2025' का उद्देश्य वर्ष 2025 तक एईसी को अस्तित्व में लाने के विजन को साकार करना है जो अत्यधिक एकीकृत एवं एकजुट होगा; प्रतिस्पर्धी, अभिनव एवं गतिशील होगा; अपेक्षाकृत अधिक संपर्क व क्षेत्रवार सहयोग होगा; और अधिक लचीला, समावेशी तथा जन–उन्मुख, जन–केंद्रित समुदाय होगा एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत होगा। आसियान के सदस्य देश वर्ष 2025 तक एईसी को पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं। भारत के लिए एईसी के कार्यान्वयन के आर्थिक और रणनीतिक निहितार्थ हैं। विदेश मंत्रालय के लिए किए जा रहे इस अध्ययन का उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क से जुड़े विशेष संदर्भ के साथ भारत के लिए एईसी के आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण करना है। इस दिशा में कार्य प्रगति पर है। रिपोर्ट का मसौदा वर्ष 2019 की दूसरी तिमाही तक तैयार हो जाने की उम्मीद है।

ग. व्यापार सुविधा, संपर्क और क्षेत्रीय एकीकरण: संपर्क

चाबहार: ईरान और मध्य एशिया के साथ भारत का संपर्क

प्रो. एस.के. मोहंती

आरआईएस चाबहार में बनाई गई सुविधाओं के माध्यम से निवेश और व्यापार सहयोग की संभावनाओं की पहचान करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस संबंध में एक अवधारणा नोट तैयार किया गया है और आगे का काम चल रहा है।

सॉफ्ट संपर्क

प्रो. एस.के. मोहंती और प्रो. मिलिंदो चक्रबर्ती

सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों – समुद्री एवं तटीय, हवाई अड्डों और संचार प्रणाली जैसी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण से हासिल बेहतर संपर्क दो भौगोलिक क्षेत्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान–प्रदान का प्रवाह बढ़ाने के लिए एक आवश्यक शर्त है। आदान–प्रदान का ऐसा बढ़ा हुआ प्रवाह उत्पादक गतिविधियों के विकास में योगदान देता है, जो मूल्य सृजन प्रक्रिया की आपूर्ति और मांग वाले दोनों ही पक्षों को प्रोत्साहित करता है। हालांकि, ऐसे प्रयासों को पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। किसी भी आदान–प्रदान में अंततः भौतिक संपर्क से जुड़े बुनियादी ढांचे के दोनों ही छोरों पर स्थित व्यक्तियों के बीच संवाद शामिल होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आदान–प्रदान का प्रवाह वास्तव में बढ़ जाए, सामाजिक संपर्क विकसित करने के लिए एक साथ प्रयास करने पर बहुत अधिक जोर दिया जाना चाहिए। आईटीईसी कार्यक्रमों को बनाए रखने के लिए भारत के दृढ़ प्रयास ने सामाजिक संपर्क के इस तरह के बुनियादी ढांचे को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना के साथ दक्षिणीय सहयोग के जरिए लोगों के आपस में जुड़ने से भौतिक संपर्क संबंधी बुनियादी ढांचे में बेहतरी के अपेक्षित प्रभावों को महसूस किया जा सकता है।

एसीएमईसीएस एवं एमजीसी के बीच संबंधों पर अध्ययन और संभावित सामंजस्य

डॉ. प्रबीर डे, डॉ. दुरइराज कुमारसामी और सुश्री श्रेया पान

मेकांग गंगा सहयोग (एमजीसी) और अय्यावाडी–चाओ फ्राया–मेकांग आर्थिक सहयोग रणनीति (एसीएमईसीएस) के बीच कई तरह के संबंध हैं। दोनों का उद्देश्य सतत तरीके से सभी के लिए शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि को बढ़ाना है। क्षेत्र की विविधता अधिक से अधिक आर्थिक एकीकरण का अवसर प्रस्तुत करती है। भारत दुनिया के एक विकास केंद्र के रूप में अधिक से अधिक भूमिका निभाता है और वह अब भी पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में काफी सक्षम है। भारत और मेकांग देशों के बीच आगे भी एकीकरण की गुंजाइश को देखते हुए सांस्कृतिक संपर्कों, संपर्क और आर्थिक संबंधों के माध्यम से बहुआयामी क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूत करने पर आपसी सहयोग और चर्चा की आवश्यकता है। चूंकि मेकांग/ एसीएमईसीएस देश भारत के साथ 'आरसीईपी' के सदस्य हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि हम एमजीसी और एसीएमईसीएस के बीच क्षेत्रीय सहयोग के आर्थिक और संपर्क मुद्दों का विश्लेषण करें। भारत और मेकांग/ एसीएमईसीएस देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंध भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए आर्थिक अवसर सृजित करेंगे। इस अध्ययन का उद्देश्य, अन्य बातों के अलावा, एसीएमईसीएस और एमजीसी के बीच आर्थिक संबंधों का विश्लेषण करना है तथा आगे के सहयोग के लिए चुनौतियों और अवसरों को प्रस्तुत करना है।

घ. नई प्रौद्योगिकियां और विकास से जुड़े मुद्दे

नई प्रौद्योगिकियों और विकास के मुद्दों पर काम प्रो. सचिन चतुर्वेदी के नेतृत्व में एक टीम द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार कार्यक्रम के तहत किया जाता है। डॉ. कृष्णा रवि श्रीनिवास, डॉ. अमित कुमार और सुश्री निमिता पांडेय इसके सदस्य हैं।

- बौद्धिक संपदा अधिकार और पहुंच (दवाएं, बीज)
- पारंपरिक भारतीय चिकित्सा सहित पारंपरिक ज्ञान
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (प्रौद्योगिकी गवर्नेंस सहित)
- जैव प्रौद्योगिकी और जैव विविधता
- स्वास्थ्य और स्वास्थ्य नीति

आरआईएस अपनी शुरुआत से ही विकास नीति के परिप्रेक्ष्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के मुद्दों पर शोध करता रहा है। इन वर्षों में आरआईएस ने कई परियोजनाओं एवं प्रकाशनों में योगदान दिया है और नीतिगत सलाह/जानकारियां (इनपुट) प्रदान की हैं। आरआईएस ने इस विषय में क्षमता का निर्माण किया है और यह अक्सर विभिन्न संस्थानों एवं विभागों का एक पसंदीदा साझेदार या नीतिगत अनुसंधान थिंक टैंक रहता है। विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं के अलावा आरआईएस छोटी शोध परियोजनाएं या चयनित विषयों पर शोध करता है और पत्रिकाओं/संस्करणों में योगदान देता है। अनुसंधान विषयों (थीम) और निष्कर्षों (आउटपुट) का दायरा एवं पहुंच काफी बढ़ गई है।

एशियन बायोटेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट रिव्यू (एबीडीआर) दरअसल अंतरराष्ट्रीय समकक्ष की समीक्षा वाली पत्रिका है और इसका प्रशासन आरआईएस द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और यूनेस्को के सहयोग से की गई। एबीडीआर को स्कोपस, ईबीएससीओ होस्टर में सूचीबद्ध किया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया http://ris.org.in/journals-n-newsletters/Asian-Biotechnology-Development-Review पर जाएं।

उत्तरदायी अनुसंधान और नवाचार (आरआरआई) भी विज्ञान नीति में एक नई अवधारणा और प्रथा के रूप में उभर कर सामने आया है। आरआईएस शायद भारत का एकमात्र संस्थान है जो इस पर काम कर रहा है और आरआरआई पर जारी वैश्विक परिचर्चाओं एवं नित्य प्रयोग में योगदान दे रहा है। आरआरआई पर एक पूर्ववर्ती परियोजना के सफल समापन के बाद आरआईएस 'आरआरआई' पर दो परियोजनाओं में एक साझेदार संस्थान बन गया है।

विज्ञान राजनय हाल के वर्षों में विदेश नीति और विज्ञान नीति दोनों ही में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरी है। जहां एक ओर विकसित राष्ट्र रणनीतिक एवं व्यवस्थित रूप से इसका उपयोग करते रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत अन्य देशों के साथ अपने व्यापक जुड़ाव के तहत विज्ञान राजनय का उपयोग करता रहा है।

उत्तरदायी अनुसंधान और नवाचार (आरआरआई) प्रयोग

यह 'होराइजन 2020' के तहत यूरोपीय संघ द्वारा प्रायोजित अंतरराष्ट्रीय परियोजना है। इस परियोजना कंसोर्टियम में 11 देशों के साझेदार हैं। आरआईएस ने भारतीय परिदृश्य में आरआरआई को प्रासंगिक बनाने के लिए पहुंच, समानता और समावेश (एईआई) पर आधारित रूपरेखा को आगे रखा है। केस स्टडी संगठनों डीएसटी और जेएनयू के फील्ड सर्वेक्षण पूरे हो चुके थे और भारतीय राष्ट्रीय अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी और स्वीकार कर ली गई थी। हिंदी और अंग्रेजी में एक नीतिगत सारपत्र प्रस्तुत किया गया है। अधिक विवरण https://www.rri-practice.eu/ पर उपलब्ध है।

घ. नई प्रौद्योगिकियां और विकास से जुड़े मुद्दे

कार्य प्रदर्शन–आधारित नवाचार पुरस्कार (रिवार्ड)

यह फार्मास्युटिकल क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने और स्वास्थ्य नीति में विभिन्न उपायों के प्रभाव और विकल्पों के आकलन सहित स्वास्थ्य में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर एक परियोजना है। यह पंचवर्षीय परियोजना 2014–2019 यूरोपीय अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंकाशायर द्वारा समन्वित है। द्वितीय चरण के हिस्से के रूप में एक अनुसंधान परियोजना शुरू करने के लिए संशोधित अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया है, और इसे कोष पोषक ईआरसी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। आरआईएस इसके आधार पर परियोजना के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में केरल के एर्नाकुलम जिले में किए जा रहे एक अध्ययन का समन्वय कर रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में काम (फील्ड वर्क) और डेटा संग्रह अगस्त 2018 में शुरू किया गया था, लेकिन बाढ़ और भारी बारिश के कारण इसे जल्द ही बंद कर दिया गया था। नवंबर 2018 में काम फिर से शुरू हुआ जो प्रगति पर है। कुमारकोम में 16 और 17 दिसंबर 2018 को एक परियोजना समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

आरआरआई–होराइज़न

यह 'होराइजन 2020' के तहत एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना है। भारत की ओर से आरआईएस इस परियोजना में गैर–यूरोपीय संघ साझेदारों में से एक है। डा. कृष्णा रवि श्रीनिवास ने अक्टूबर 2018 में वियना में आयोजित परियोजना कार्यशाला में भाग लिया और आरआरआई पर आरआईएस के कार्यों के बारे में एक प्रस्तुति दी।

चिकित्सा उपकरण उद्योग पर अध्ययन

प्रो. टी सी जेम्स और डॉ. आभा जायसवाल

चिकित्सा उपकरण उद्योग आधुनिक स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ की हड्डी है और यह आयुष्मान भारत के तहत परिकल्पित सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने वाला भारत का एक प्रमुख निर्धारक होगा। यह अध्ययन भारत में उद्योग की स्थिति, अगले दशक के दौरान इसकी चुनौतियों और उन प्रभावकारी नीतिगत कदमों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो पूरी दुनिया को चिकित्सा उपकरणों के एक प्रमुख निर्यातक की हैसियत प्राप्त करने हेतु भारत के लिए आवश्यक होंगे। भारत में चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र पर एक प्रासंगिक प्रपत्र तैयार किया जा रहा है।

सतत विकास लक्ष्य 3 की ओर अग्रसर होना: पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका

प्रो. टी. सी. जेम्स, डॉ. नम्रता पाठक और श्री अपूर्व भटनागर

विश्व स्तर पर भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत 'सतत विकास लक्ष्य 3 की ओर अग्रसर होना और पारंपरिक चिकित्सा: मानकों, बौद्धिक संपदा एवं नवाचार की भूमिका' पर एफआईटीएम, डब्ल्यूएचओ और एसएससी की बैठक वर्ष 2019 के दौरान आयोजित की जाएगी। जिन व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा करने का प्रस्ताव है, वे टीएम उत्पादों की गुणवत्ता एवं मानकीकरण, टीएम में नवाचार तथा बौद्धिक संपदा, सामान्य स्वास्थ्य सेवा में पारंपरिक चिकित्सा के एकीकरण और सतत विकास लक्ष्य 3 को प्राप्त करने के प्रयासों में टीएम की भूमिका से संबंधित मुद्दे हैं।

घ. नई प्रौद्योगिकियां और विकास से जुड़े मुद्दे: विज्ञान राजनय

विज्ञान राजनय पर परियोजना

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, डॉ. कृष्णा रवि श्रीनिवास, डॉ. बी. बालाकृष्णन, डॉ. अमित कुमार, सुश्री निमिता पांडेय और सुश्री गीतिका खंडूजा

यह कार्यक्रम डीएसटी द्वारा वित्त पोषित है, जिसका उद्देश्य प्रवासी भारतीय वैज्ञानिक समुदाय का मानचित्रण करना है, ताकि राष्ट्र के विकास के लिए उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके। आरआईएस और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (एनआईएएस) बेंगलुरू संयुक्त रूप से इस परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। इस परियोजना को 7 मई, 2018 को लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत एसडी न्यूज अलर्ट प्रकाशित किया जा रहा है, जबकि 'साइंस डिप्लोमेसी रिव्यू' को भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों और प्रदेय की परिकल्पना की गई है।

आरआईएस ने भी भारतीय विज्ञान राजनय पर फोरम शुरू किया है। यह भारत एवं विदेश में वैज्ञानिकों, राजनयिकों, रणनीतिक विचारकों, नीति निर्माताओं, कारोबारियों और विज्ञान राजनय के विभिन्न पहलुओं में शामिल विद्वानों के बीच एक अंतराफलक (इंटरफेस) के रूप में कार्य करता है। भारत में विज्ञान राजनय के साथ–साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति से संबंधित संसाधनों, अपडेट एवं सूचनाओं को साझा करने के लिए एक समर्पित वेबसाइट (www.fisd.in) है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एसएंडटी से जुड़े घटनाक्रमों पर विज्ञान राजनय समाचार अलर्ट लॉन्च किया गया है और इसे आरआईएस द्वारा हर पखवाड़े में भेजा जाता है। अब तक हमने पांच समाचार अलर्ट भेजे हैं। 'साइंस डिप्लोमेसी रिव्यू' एफआईएसडी द्वारा शुरू की गई एक द्विमासिक पत्रिका है जो सिद्धांत और व्यवहार में भारतीय विज्ञान राजनय से संबंधित परिप्रेक्ष्य प्रदान करेगी। पहला अंक नवंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। विभिन्न क्षेत्रों/विषयगत क्षेत्रों के प्रख्यात प्रोफेशनलों और विद्वानों के लिए अनेक विषय–अध्ययन को मंजूरी दी गई है। विज्ञान राजनय के शब्दकोश पर प्रो. वी. सिद्धार्थ के विषय–अध्ययन का प्रकाशन किया जा रहा है। सेमी–कंडक्टर पर प्रो. अशोक पार्थसारथी के विषय–अध्ययन में अंतिम संशोधन किया जा रहा है। इसी तरह विषय–अध्ययन की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए प्रो. पी.के. घोष (टीका), डॉ. वी.एस. चौहान (आईसीजीईबी/जैव प्रौद्योगिकी) और डॉ. राहुल शर्मा (समुद्री विज्ञान) के साथ विचार–विमर्श फिलहाल जारी है।

एनआरआई/पीआईओ का एक डेटाबेस भी विकसित किया जा रहा है जिसमें एसएंडटी से जुड़े विषयों और सीमांत या अभिनव प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला में शोध कर रहे भारतीय मूल के 300 विद्वानों के प्रोफेशनल विवरण होंगे। विज्ञान राजनय में संलग्न संस्थानों की एक निर्देशिका तैयार करने की भी योजना बनाई जा रही है, जिसमें विज्ञान राजनय गतिविधियों/पाठ्यक्रमों में संलग्न दुनिया भर के 48 संस्थान शामिल होंगे।

हमारी बाहरी सम्पर्क सुदृढ़ करने से संबंधित गतिविधियों के एक भाग के रूप में भारत स्थित विदेशी मिशनों में एसएंडटी के परामर्शदाताओं (काउंसलर) के साथ बैठकें आयोजित की गईं। उपर्युक्त उल्लेखित गतिविधियों के अलावा कई नई गतिविधियों की योजना बनाई गई है, जिसमें आरआईएस द्वारा मध्य–कैरियर स्तर के आईएफएस अधिकारियों के लिए विज्ञान राजनय पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करना भी शामिल होगा।

घ. नई प्रौद्योगिकियां और विकास से जुड़े मुद्दे: एफआईटीम पर ध्यान केंद्रित

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही निरंतर प्रगति से स्वास्थ्य सेवा सेक्टर की तस्वीर बड़ी तेजी से बदल रही है। ये बदलाव न केवल आधुनिक चिकित्सा तक सीमित हैं, बल्कि विभिन्न देशों में पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के दायरे और उपयोग पर भी व्यापक असर डालते हैं। आरआईएस के अनुसंधान कार्यक्रम के तहत पारंपरिक चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, औषधीय पौधों के व्यापार एवं खेती; और वेलनेस पर्यटन के बीच जटिल सामंजस्य के बारे में अन्वेषण किया जाता है।

भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पर फोरम (एफआईटीएम)

प्रो. टी.सी. जेम्स, डॉ. नम्रता पाठक और श्री अपूर्व भटनागर

आयुष मंत्रालय द्वारा आरआईएस में गठित एफआईटीएम का उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा (टीएम) के क्षेत्र में व्यावहारिक नीति बनाने की दिशा में अहम योगदान करना है। भारतीय चिकित्सा प्रणालियों (आईएसएम) की वैश्विक लोकप्रियता और उपयोग में हाल ही में हुई वृद्धि ने प्रणाली के लिए व्यापक अवसर सृजित किए हैं, लेकिन इसके साथ ही इसने गुणवत्ता एवं मानकों पर नियामकीय संरचना या परिवेश के क्षेत्रों में नई चुनौतियों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मार्ग में बाधाओं को भी उत्पन्न किया है। एफआईटीएम इन चुनौतियों का सामना करने और इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर हो रही प्रगति के मद्देनजर सुसंगत राष्ट्रीय नीतियां और उपयुक्त व्यवस्था सुझाने के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराता है। फोरम ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर आईएसएम के प्रचार–प्रसार के लिए कई पहल की हैं जिनके बारे में नीचे चर्चा की गई है:

पारंपरिक ज्ञान, आनुवांशिक संसाधनों और पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का संरक्षण

प्रो. टी.सी. जेम्स, डॉ. नम्रता पाठक और श्री अपूर्व भटनागर

अध्ययन का उद्देश्य डिजिटल दुनिया सहित भारत में पारंपरिक ज्ञान (टीके), आनुवांशिक संसाधनों (जीआर) एवं संबद्ध परंपरागत ज्ञान और पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों (टीसीई) के संरक्षण के लिए वर्तमान में उपलब्ध कानूनी प्रावधानों की पर्याप्तता पर बड़ी बारीकी से गौर करना है। यह जैव–चोरी को रोकने के लिए उनकी पर्याप्तता का आकलन करेगा और मौजूदा कानूनों में आवश्यक बदलाव/परिवर्धन, यदि कोई हो, को प्रस्तावित करेगा। अध्ययन के निम्नलिखित घटकों पर दो विषय–क्षेत्र प्रपत्र (स्कोपिंग पेपर) पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं:

- पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के बारे में गहराई से अध्ययन पर स्कोपिंग पेपर
- पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के संरक्षण के बारे में गहराई से अध्ययन पर स्कोपिंग पेपर

स्कोपिंग पेपर के आधार पर आगे के अध्ययन जारी हैं। 'आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में गहराई से अध्ययन' पर स्कोपिंग पेपर को तैयार करने का काम अभी जारी है। यह अध्ययन एक वर्ष के लिए तय है, जिसके आखिर में आयुष मंत्रालय को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। आरआईएस भी अपनी ओर से संबंधित प्रकाशन या सामग्री प्रस्तुत करेगा।

घ. नई प्रौद्योगिकियां और विकास से जुड़े मुद्दे: एफआईटीम पर ध्यान केंद्रित

'टीसीएम' के राष्ट्रीय और वैश्विक संवर्धन के लिए चीन की नीतिगत पहल

प्रो. टी.सी. जेम्स, डॉ. नम्रता पाठक और श्री अपूर्व भटनागर

अध्ययन का उद्देश्य अपनी सार्वजनिक/सार्वभौमिक स्वास्थ्य प्रणाली के अंतर्गत पारंपरिक चीनी चिकित्सा प्रणालियों (टीसीएम) को मुख्यधारा में लाने और वैश्विक स्तर पर टीसीएम का प्रचार–प्रसार करने में चीन की विभिन्न पहलों के बारे में पता लगाना है। इसका उद्देश्य चीन के मुकाबले भारत की ताकत और कमजोरियों का तुलनात्मक आकलन करना भी है जिससे मिलने वाले सबक को भारतीय चिकित्सा प्रणालियों (आईएसएम) के प्रचार–प्रसार के लिए शामिल/अनुकूलित करना है। यह अध्ययन वर्ष 2019 के आखिर तक एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में सामने आएगा।

टीसीएम के राष्ट्रीय और वैश्विक संवर्धन के लिए चीन की नीतिगत पहलों पर एक स्कोपिंग पेपर प्रकाशित किया गया है। डेस्क स्तरीय अनुसंधान पर आधारित विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट का मसौदा पहले ही तैयार कर लिया गया है। इस विषय पर चीनी समकक्षों के साथ संवाद भी पहले ही किया जा चुका है, जिसके आधार पर 'गरीबी उन्मूलन के लिए औषधीय पौधों की खेती' और 'वेलनेस पर्यटन के लिए विशेष वेलनेस जोन' पर दो नीतिगत सार–पत्र प्रकाशित किए गए हैं।

एफआईटीएम कार्यक्रम के तहत अनुसंधान फेलोशिप

प्रो. टी.सी. जेम्स, डॉ. नम्रता पाठक और श्री अपूर्व भटनागर

एफआईटीएम फेलोशिप कार्यक्रम विश्वविद्यालयों के युवा विद्वानों को प्रणालीगत अनुसंधान (सिस्टम रिसर्च) करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिसके तहत आईएसएम के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक–आर्थिक, व्यापार, प्रबंधन और डिजिटल/सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित पहलुओं पर बारीकी से गौर किया जाता है। फेलोशिप का प्रमुख उद्देश्य भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों (आईटीएम) से संबंधित विषयों और चुनौतियों एवं संभावनाओं पर गहराई से गौर करने के साथ–साथ अनुसंधान करना भी है। बारीकी से गौर करने के बाद प्रस्तुत की गई पुस्तकों सहित प्रकाशनों का उद्देश्य आईटीएम के प्रचार–प्रसार पर नीति संबंधी अनुसंधान जानकारियां प्रदान करना है। आईटीएम से संबंधित अलग–अलग विषयों पर डोमेन विशेषज्ञों के आमंत्रित व्याख्यान भी इस परियोजना का एक हिस्सा हैं। आरआईएस फेलोशिप और भावी प्रकाशनों से जुड़े अनुदान का प्रबंधन करेगा। अब तक पंजाब में औषधीय पौधों की खेती और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में औषधीय पौधों के व्यापार के क्षेत्र में दो डॉक्टरल या डॉक्टरेट फेलोशिप मंजूर की गई हैं।

औषधीय पौधा सेक्टर के निर्यात संवर्धन पर अध्ययन: चुनिंदा औषधीय पौधों के लिए रणनीति

श्री राजीव खेर, प्रो. टी.सी. जेम्स, डॉ. सलाउद्दीन अय्यूब और श्री अंकुर जायसवाल

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित इस अध्ययन का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा वाणिज्य मंत्रालय के एक कार्य बल द्वारा चिन्हित 25 औषधीय पौधों के व्यापार संवर्धन के लिए उपयुक्त व्यवस्थाओं की पहचान करना है। भौगोलिक फैलाव और संग्रह एवं खेती के व्यापक स्तर से जुड़ी जटिलताओं और मूल्य श्रृंखला के अंतर्गत माल की आवाजाही पर ट्रेसेबिलिटी (वर्तमान स्थान का पता लगाने की क्षमता) या डेटा के मौजूदा अभाव को ध्यान में रखते हुए 25 औषधीय पौधों के गहन

घ. नई प्रौद्योगिकियां और विकास से जुड़े मुद्दे: एफआईटीम पर ध्यान केंद्रित

अध्ययन के लिए पर्याप्त समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि यह अध्ययन इस कार्य बल द्वारा चिन्हित पांच सर्वाधिक महत्वपूर्ण औषधीय पौधों के साथ शुरू हुआ है। इसके तहत किसी एक क्षेत्र या आपस में जुड़े एक से अधिक क्षेत्रों में आवश्यक उपाय करने की जरूरत पर फोकस करते हुए प्रत्येक औषधीय पौधे की मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) का संपूर्ण रूप से विश्लेषण किया जाएगा।

आईएसएम और हर्बल उत्पादों के व्यापार वर्गीकरण के विस्तार, गुणवत्ता नियंत्रण एवं मानकीकरण के लिए कार्य बल

श्री राजीव खेर, प्रो. टी.सी. जेम्स, डॉ. नम्रता पाठक और श्री अपूर्व भटनागर

18 मई, 2018 को एफआईटीएम द्वारा आयोजित उद्योग परामर्श में प्रतिभागियों ने जिन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी और प्रकाश डाला था उनमें से एक मुद्दा व्यापार संवर्धन के लिए व्यापार आंकड़ों की विशेष अहमियत से जुड़ा हुआ था। वर्तमान में उपयुक्त एचएस व्यापार वर्गीकरण का अभाव होने के कारण पारंपरिक चिकित्सा उत्पादों के व्यापार की निगरानी सही ढंग से नहीं हो पा रही है। 6–अंकीय एचएस पर वैश्विक व्यापार वर्गीकरण विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) द्वारा किया जाता है जो वैश्विक व्यापार की कुल मात्रा के आधार पर समय–समय पर नए एचएस कोड भी आवंटित करता है। पारंपरिक दवाओं (टीएम) और औषधीय पौधों (एमपी) के लिए आवंटित उत्पादों की संख्या अपेक्षाकृत कम (ज्यादातर समय 6 अंक) होती है जिसका मुख्य कारण इस सेक्टर से जुड़े देशों की ओर से इसके लिए दबाव नहीं पड़ना है। एक कार्य बल का गठन इन उद्देश्यों से किया गया है: आईएसएम उत्पादों, हर्बल उत्पादों एवं औषधीय पौधों को शामिल करने के लिए एचएस राष्ट्रीय लाइनों की सिफारिश करना; विचार–विमर्श करना एवं आवश्यकता पड़ने पर आईएसएम उत्पादों, हर्बल उत्पादों व औषधीय पौधों के लिए अनिवार्य मानकों की जरूरत की सिफारिश करना; और आईएसएम उत्पादों, हर्बल उत्पादों एवं औषधीय पौधों की गुणवत्ता तथा ट्रेसेबिलिटी (वर्तमान स्थान का पता लगाने की क्षमता) सुनिश्चित करने के तरीकों की सिफारिश करना।

आयुष उद्योग और जैविक विविधता अधिनियम 2002 एवं नियम 2004 पर अध्ययन

प्रो. टी.सी. जेम्स, डॉ. नम्रता पाठक और श्री अपूर्व भटनागर

आयुष उद्योग अपने कच्चे माल के लिए जैविक संसाधनों पर काफी हद तक निर्भर है। जैव विविधता संरक्षण से संबंधित कानून में 'पहुंच सुनिश्चित करने और लाभ को साझा करने के प्रावधानों' पर अमल से कभी–कभी उद्योग के लिए समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अध्ययन का उद्देश्य इस मुद्दे पर बारीकी से गौर करना और ऐसे संभावित समाधानों को खोजना है जो आयुष दवाओं की आसान उपलब्धता के साथ–साथ जैव विविधता का संरक्षण भी सुनिश्चित करेंगे।

नीतिगत शोध पत्र

अध्याय 2

हाल के वर्षों में आरआईएस ने नीतिगत जानकारियां मुहैया कराने से जुड़ी अपनी विशिष्ट व्यवस्था का काफी विस्तार किया है। यही नहीं, आरआईएस इसके साथ ही संस्थान में नीतिगत अनुसंधान को निरंतर बेहतर एवं उपयोगी भी बनाता जा रहा है। संस्थान ने कार्यकलाप कार्यक्रम को कुछ इस तरह से संचालित किया है जिससे कि विदेश मंत्रालय के कुछ और प्रभागों (डिवीजन) तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय सहित अन्य लाइन या विशेष कायक्रम वाले मंत्रालयों के साथ जुड़ा जा सके। हम सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर सीएजी या कैग के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं। इसी तरह हम नीति आयोग और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएम–ईएसी) तथा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं। अन्य विकासशील देशों की सरकारों के साथ मिलकर काम करना भी एक अहम उद्देश्य है। इस संबंध में इंडोनेशिया की सरकार ने विशिष्ट साझेदारी के लिए आरआईएस से संपर्क किया। इसके अलावा, आरआईएस ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ जानकारी साझा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है जो विकासशील देशों के लिए काम कर रहे हैं। समय के साथ ही आरआईएस अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ तेजी से जुड़ता चला गया है। आरआईएस विभिन्न सूचनाओं को साझा/प्रसारित कर रहा है और इसके साथ ही उन विशेषज्ञों या निकायों को आवश्यक जानकारियां प्रदान कर रहा है जो भारत की विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं से पूरी तरह अवगत हैं। हाल ही में आरआईएस ने, अन्य जानकारियों के अलावा, निम्नलिखित नीतिगत सलाह दी हैं:

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद

- भारत–नॉर्वे सहयोग पर एक टिप्पणी भेजी गई।
- पूर्वोत्तर वित्तीय समावेश रणनीति पर टिप्पणी भेजी गई।
- प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी–पीएम) – राष्ट्रीय नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) और सतत विकास नीति पर संचालन समिति कार्य समूहों को इनके लिए विभिन्न जानकारियां (इनपुट) उपलब्ध कराई गईं: कार्य समूह रु 1 : नीली अर्थव्यवस्था एवं महासागर के गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय लेखांकन फ्रेमवर्क पर नीली अर्थव्यवस्था कार्य समूह की रिपोर्ट; कार्य समूह रु 4 : विनिर्माण, उभरते उद्योगों, व्यापार, प्रौद्योगिकी, सेवाओं एवं कौशल विकास पर नीली अर्थव्यवस्था कार्य समूह की रिपोर्ट; और कार्य समूह रु 5 : लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचा एवं शिपिंग (ट्रांसशिपमेंट सहित) पर नीली अर्थव्यवस्था कार्य समूह की रिपोर्ट।

नीतिगत शोध पत्र

विदेश मंत्रालय

- 'अफगान नागरिकों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना के आकलन' पर रिपोर्ट।
- 'हिंद महासागर रिम संघ (आईओआरए)' पर विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराईं।
- 'लघु द्वीप अर्थव्यवस्थाओं में ग्रीन एसएमई की निर्यात संभावनाओं के दोहन के लिए एक व्यापार कार्य योजनाः एक मॉरीशस परिप्रेक्ष्य' पर विभिन्न जानकारियां विदेश मंत्रालय के माध्यम से हिंद महासागर रिम संघ (आईओआरए) सचिवालय, मॉरीशस गणराज्य को उपलब्ध कराई गईं।
- विदेश मंत्रालय के माध्यम से आईओआरए सचिवालय में संस्थागत सुदृढ़ीकरण पर रणनीतिक नियोजन कार्यशाला और आगे के कदमों पर विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराई गईं।
- 'सॉफ्ट पावर इंडेक्स' के विकास में योगदान दिया।

नीति आयोग

- त्रिपुरा राज्य की संपर्क बेहतर करने के लिए नीति आयोग को विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराई गईं।
- 'राष्ट्रीय समुद्री नीति पर एनएमपी के लिए नीतिगत कार्रवाई के प्रारूप – नीतिगत वक्तव्यों' पर एक नोट नीति आयोग को प्रस्तुत किया गया।
- 'भारत में नीली अर्थव्यवस्था के लिए एक रोडमैप और बहु–क्षेत्रीय हितधारक के लिए एक एकीकृत महासागर नीति' पर आयोजित बैठक में 'भारत के लिए एक नीली अर्थव्यवस्था रणनीति की ओरः उभरते अवसर और चुनौतियां' विषय पर विभिन्न जानकारियां नीति आयोग को उपलब्ध कराई गईं।
- 'नीली अर्थव्यवस्था के लेखांकन' पर विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराई गईं।
- 'राष्ट्रीय समुद्री नीतिः समुद्री भारत /75 के लिए एक एजेंडा – समुद्री वाणिज्य 2018'य 'राष्ट्रीय समुद्री नीतिः समुद्री भारत /75 के लिए एक एजेंडा – समुद्री बुनियादी ढांचा 2018'य और 'राष्ट्रीय समुद्री नीतिः समुद्री भारत /75 के लिए एक एजेंडा – समुद्री प्रौद्योगिकी 2018' पर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
- भारत–रूस आर्थिक सहयोग' पर विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराई गईं।

वाणिज्य मंत्रालय

- 'भारत–मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते' पर भारत–मॉरीशस सीईसीपीए बैठक के चौथे दौर के लिए विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराई गईं।
- 'एलएसी के साथ भारत की साझेदारीः व्यापार और निवेश' पर विभिन्न जानकारियां दी गईं।
- 'भारत–मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते (सीईसीपीए)' पर विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराई गईं।
- 'भारत पर एलएसी द्वारा लागू एनटीबी – एक खोजपूर्ण विश्लेषण' पर विभिन्न जानकारियां दी गईं।

- 'व्यापार एवं निवेश में लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों के साथ भारत की साझेदारी' पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
- राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों – व्यापार विकास और संवर्धन परिषद के साथ संवाद के लिए विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराई गईं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

- अन्य देशों के साथ भारत के निष्क्रिय एसटीआई सहयोग को सक्रिय करने के प्रयासों पर विभिन्न जानकारियां दी गईं।
- 'विज्ञान राजनय अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए केंद्र' का गठन।
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में संलग्न प्रवासी भारतीय।
- रणनीतिक महत्व के देशों में विज्ञान नीति संस्थानों का मानचित्रण।

आयुष मंत्रालय

- भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के वैश्विक प्रचार के लिए अन्य बातों के अलावा इन पर विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराई गईं: डेटा सृजन, निर्यात संवर्धन, आईएसएम उत्पादों के मानक और गुणवत्ता आश्वासन।
- आईएसएम उत्पादों और कच्चे माल का व्यापार वर्गीकरण।
- फेलोशिप की मंजूरी के जरिए आयुष सेक्टर पर अनुसंधान अध्ययनों में बेहतरी के लिए नई योजना का शुभारंभ।
- विपो में पारंपरिक ज्ञान, पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण पर वैश्विक परिचर्चाएं।

वित्त मत्रांलय

- जी–20 की 'प्रख्यात व्यक्ति समूह रिपोर्ट' पर चर्चा के संबंध में 'विकासशील देशों की वित्तीय जरूरतों' पर नोट।
- आरआईएस तीसरी एआईआईबी की वार्षिक बोर्ड बैठक के लिए ज्ञान साझेदार था।
- भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के वैश्विक प्रचार के लिए अन्य बातों के अलावा इन पर विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराई गईं: डेटा सृजन, निर्यात संवर्धन, आईएसएम उत्पादों के मानक एवं गुणवत्ता आश्वासन, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना/एमएसएमई के लिए सुविधाजनक बनाना, आईएसएम सेवाओं की गुणवत्ता एवं पहुंच को बेहतर बनाना, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करना, औषधीय पौधों की खेती एवं कच्चे माल का पता लगाने की क्षमता: चुनौतियां एवं सर्वोत्तम प्रथाएं, आईएसएम उत्पादों एवं कच्चे माल का व्यापार वर्गीकरण, और पारंपरिक चिकित्सा उत्पादों का निर्यात संवर्धन: घरेलू तैयारियों का आकलन।
- फेलोशिप की मंजूरी के जरिए आयुष सेक्टर पर अनुसंधान अध्ययनों में बेहतरी के लिए नई योजना का शुभारंभ।

- पारंपरिक ज्ञान, पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण पर वैश्विक परिचर्चाएं।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

- जैव प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग' पर टिप्पणी उपलब्ध की।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

- 'हिंद–प्रशांत क्षेत्र के विशेष संदर्भ में तटीय अनुसंधान में प्रगति' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए संचालन समिति के लिए विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराई गईं।

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) का कार्यालय

- 'सतत विकास लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए एसटीआई का इस्तेमालः एक भारतीय परिप्रेक्ष्य' विषय पर अवधारणा नोट, जिसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र–डीईएसए द्वारा शुरू किए गए 'भारत के लिए सतत विकास लक्ष्य रोडमैप के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) पर वैश्विक पायलट कार्यक्रम' से जुड़ने के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

दक्षिणीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय

- 'दक्षिणीय सहयोगः एक सैद्धांतिक और संस्थागत रूपरेखा' पर अध्ययन में योगदान दिया।
- 'दक्षिणीय सहयोग के प्रभाव का आकलन करने' पर अध्ययन में योगदान दिया।

इंडोनेशिया की सरकार

- 'सतत विकास लक्ष्य और वनस्पति तेल' विषय पर नीतिगत अनुसंधान करने के लिए विभिन्न जानकारियां इंडोनेशियाई टीम को उपलब्ध कराई गईं जिसमें विदेश मंत्रालय और जाम्बी विश्वविद्यालय के अधिकारी शामिल थे।

जनसंख्या और विकास पर सांसदों की भारतीय एसोसिएशन

- भारतीय परिदृश्य पर 1 अगस्त 2019 को विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराई गईं जिनका उपयोग एशियाई जनसंख्या और विकास एसोसिएशन (एपीडीए), टोक्यो (जापान) में 'सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे की दिशा में सांसदों के कदमों' पर पैनल परिचर्चा के लिए श्रीमती विप्लव ठाकुर, सांसद; आईएपीपीडी की उपाध्यक्ष की अगुवाई वाले संसदीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा किया जाएगा।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

अध्याय 3

एआईआईबी की वार्षिक बैठक से पहले और उसके दौरान अनेक कार्यक्रम

इस तिमाही का समापन एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की वार्षिक बैठक पर आरआईएस के कार्यक्रम के साथ हुआ। देश भर में सात अलग–अलग स्थानों पर सात प्रमुख कार्यक्रम आरआईएस द्वारा विभिन्न विषयों पर आयोजित किए गएः बंदरगाह एवं तटीय बुनियादी ढांचे को बेहतर बनानाः संभावित क्षेत्रों पर एक प्रस्तुतीकरण (विशाखापत्तनम में 3–4 अप्रैल 2018 को); शहरी विकासः तकनीकी समाधान एवं गवर्नेंस संबंधी चुनौतियां (अहमदाबाद में 19–20 अप्रैल 2018 को); अत्याधुनिक, सुदृढ़ एवं डिजिटल बुनियादी ढांचा (बेंगलुरू में 3–4 मई 2018 को); क्षेत्रीय विकास के लिए भौतिक एवं सामाजिक बुनियादी ढांचा (गुवाहाटी में 14–15 मई 2018 को); स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा (भोपाल में 21 मई 2018 को); जल एवं स्वच्छता (पुणे में 31 मई और 1 जून 2018 को); और संसाधन जुटाने में निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं नवाचार (मुंबई में 11 जून 2018 को)। प्रमुख विशेषज्ञों ने उपर्युक्त कार्यक्रमों के संबंधित विषयों पर तैयार गहन पृष्ठभूमि–पत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया।

वार्षिक बैठक से पहले आयोजित किए गए उपर्युक्त सभी कार्यक्रम इन विषयों पर 'मेजबान देश में सेमिनार' के आयोजन के रूप में फलित हुएः बुनियादी ढांचे का वित्त पोषणः अभिनव तरीकों एवं साझेदारी की तलाश (24 जून 2018 को); सहयोग एवं साझेदारी आगे बढ़ानाः विकसित होती रणनीतियां एवं सामूहिक कार्यकलाप और बुनियादी ढांचे का वित्त पोषण करनाः संसाधन जुटाना एवं नए साधनों की तलाश करना; भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के दृष्टिकोण पर मुख्यमंत्रियों के साथ पैनल परिचर्चा (25 जून 2018 को); संस्थानों, प्रौद्योगिकी एवं विधियों में नवाचारों को समाहित करना और सुदृढ़ एवं बेहतरीन बुनियादी ढांचे का निर्माण करना (26 जून 2018 को)। आरआईएस ने उपर्युक्त कार्यक्रमों के निष्कर्षों पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

एआईआईबी की तीसरी वार्षिक बैठक के दौरान 25 जून 2018 को मुंबई में माननीय वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल ने *'बुनियादी ढांचे हेतु संसाधन जुटाने के लिए नई तलाश*

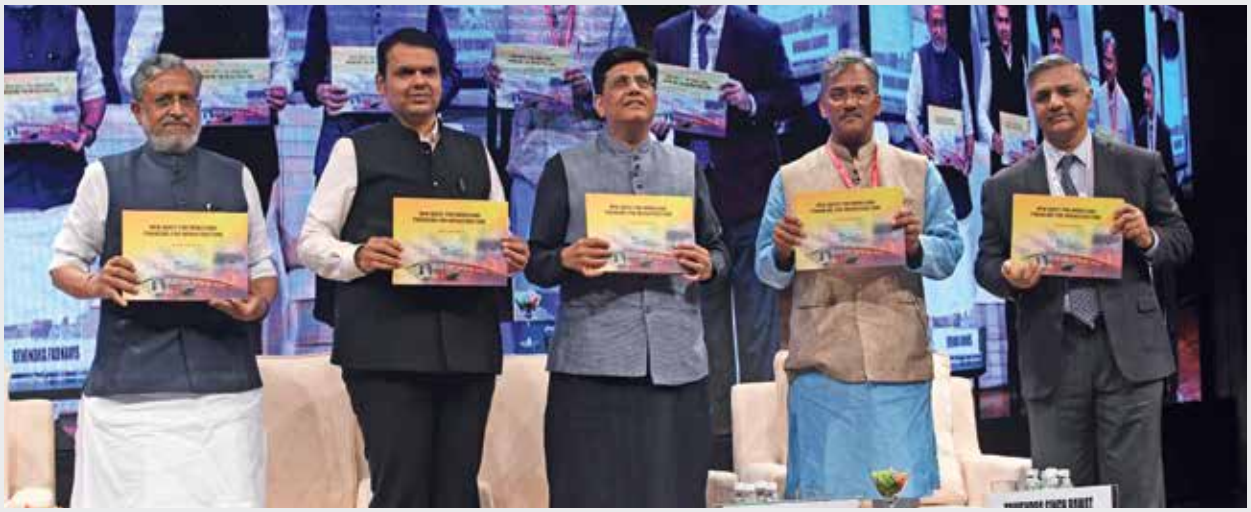

माननीय वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल 'बुनियादी ढांचे हेतु वित्त जुटाने के लिए नई तलाश' नामक आरआईएस रिपोर्ट का विमोचन करते हुए। (बाएं से): बिहार के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी; महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस; उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत; और आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

नामक रिपोर्ट का विमोचन किया। इस दौरान महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस; उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत; बिहार के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी और भारत सरकार के माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पी. राधाकृष्णन की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। इस रिपोर्ट में कई नीतिगत सिफारिशों का उल्लेख किया गया है जिन्हें सभी हितधारक उपयोगी मानेंगे। सभी उपर्युक्त कार्यक्रमों और मेजबान–देश सेमिनारों का एजेंडा आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

एआईआईबी की तीसरी वार्षिक बैठक के साथ आरआईएस की सहभागिता

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मजबूत राजनीतिक नेतृत्व में भारत आर्थिक विकास और सकारात्मक बदलाव के मार्ग पर सतत रूप से आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में स्वयं को भी शुमार करने की दिशा में अग्रसर है। आर्थिक विकास का विस्तृत होता क्षितिज विभिन्न क्षेत्रों में फैले कई स्तरों पर बुनियादी ढांचे के मजबूत वित्त पोषण पर काफी हद तक निर्भर है। बुनियादी ढांचे के एकीकृत विकास से औद्योगिक पुनरुद्धार और सतत विकास की परस्पर जरूरतें पूरी होंगी। समावेशी विकास की उभरती प्राथमिकताओं को साझेदारी एवं सहयोग, अभिनव वित्तपोषण, उद्यमिता और मजबूत कानूनी एवं संस्थागत ढांचे के जरिए आवश्यक सहारा दिया जाएगा। प्रौद्योगिकी पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने से विकास की प्रक्रिया को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।

भारत सरकार ने 25–26 जून 2018 को मुंबई में एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की तीसरी वार्षिक बैठक की मेजबानी की। इस संबंध में आरआईएस ने भारत के अग्रणी उद्योग संगठनों फिक्की, सीआईआई और एसोचैम की अनुकरणीय साझेदारी के साथ ज्ञान साझेदार के रूप में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के संग मिलकर काम किया है। एआईआईबी की तीसरी वार्षिक बैठक से ठीक पहले आरआईएस ने संसाधन एवं संस्थागत चुनौतियों से पार पाने और संपर्क तथा बुनियादी ढांचे के विकास से हो रहे लाभों में वृद्धि के लिए राज्य सरकारों और सिविल सोसायटी संगठनों से भी सहयोग किया है। भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली और एआईआईबी के अध्यक्ष श्री जिन लिक्यून ने नई दिल्ली में 27 फरवरी 2018 को आयोजित एक प्रभावशाली समारोह में औपचारिक रूप से एआईआईबी की तीसरी वार्षिक बैठक का शुभारंभ किया। श्री नितिन जयराम गडकरी, माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और शिपिंग मंत्री तथा श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार ने नीति निर्माताओं, राजनयिकों, बैंकरों, बहुपक्षीय संस्थानों, उद्योग जगत और अन्य हितधारकों के एक बड़े समूह के साथ अपनी ज्ञानविषयक परख या अंतर्दृष्टि साझा की थी।

प्रत्येक संबंधित (लीड–अप) कार्यक्रम के लिए शहर का चयन इन कार्यक्रमों की संबंधित थीम के संदर्भ में उनके विशिष्ट योगदान और अहमियत को ध्यान में रखते हुए किया गया। उदाहरण के लिए, गुवाहाटी भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि पूर्वोत्तर के साथ–साथ अन्य आकांक्षी क्षेत्रों में भी विशिष्ट बुनियादी ढांचे की कमी का उल्लेख बार–बार करता रहा है। इसी प्रकार, भारत के डिजिटल नेतृत्व के साथ–साथ नवाचार आधारित बदलावों में भी बेंगलुरू का एक विशिष्ट स्थान है और अत्याधुनिक, सुदढ़ एवं डिजिटल बुनियादी ढांचे पर हमारे विषयगत सम्मेलन के लिए उसका चयन किया जाना बिल्कुल सही है। उपर्युक्त कार्यक्रमों की संबंधित थीम पर गहन एवं व्यापक पृष्ठभूमि–पत्र प्रस्तुत करने के लिए अथक प्रयास किए गए, जिसमें योगदान देने के लिए प्रमुख विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। यह पृष्ठभूमि–पत्र हैं: त्वरित जन परिवहन प्रणालियों पर श्री राकेश रंजन द्वारा; बंदरगाह एवं तटीय बुनियादी ढांचे पर श्री विश्वपति त्रिवेदी द्वारा; शहरी विकास, डॉ. ओम प्रकाश माथुर द्वारा; समावेशी एवं सुदृढ़ बुनियादी ढांचे, प्रो. पार्थ मुखोपाध्याय द्वारा; डिजिटल बुनियादी ढांचे, डॉ. रजत कथुरिया द्वारा; क्षेत्रीय विकास, प्रो. सेबेस्टियन मॉरिस द्वारा; स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा, डॉ. अरुणव घोष और डॉ. कनिका चावला द्वारा; और जल एवं स्वच्छता, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर द्वारा।

प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के एक पैनल ने समय–समय पर आरआईएस की अनुसंधान टीम के साथ भी बातचीत की। इस पैनल में ये शामिल थे: डॉ. अतुल शर्मा, श्री रजत एम. नाग, डॉ. जगन शाह, श्री किशोर अरुण देसाई, डॉ. कविता

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

अयंगर, श्री एस. के. दास, श्री अशोक खोसला, डॉ. दीपेन्द्र कपूर, डॉ. ललित कुमार, श्री सुरेश रोहिलिया, श्री अशोक खुराना, डॉ. इंदिरा खुराना, सुश्री ममता दाश, डॉ. ओम प्रकाश माथुर, प्रो. के.टी. रविंद्रन, डॉ. वाई. पी. आनंद, श्री शिवराज गुप्ता, डॉ. मिलन शर्मा, श्री प्रवीर पांडेय, श्री ए. जनार्दन राव, श्री समीर भटनागर, कैप्टन सुबेदार, कमोडोर सुजीत समादार, श्री सैबल के. डे और श्री आर.वी. वर्मा। आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव श्री सुभाष चंद्र गर्ग ने निरंतर मार्गदर्शन और अकादमिक अंतर्दृष्टि भी प्रदान की। डॉ. एम.एम. कुट्टी, विशेष सचिव; श्री समीर कुमार खरे, संयुक्त सचिव (फंड बैंक एवं एडीबी); डॉ. कुमार विनय प्रताप, संयुक्त सचिव (बुनियादी ढांचा, नीति एवं वित्त); सुश्री बंदना प्रेयसी, निदेशक (एमआई/आईएफ); श्री ऋषिकेश सिंह, निदेशक (एमआई); आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी ओर से पूर्ण सहयोग दिया। इसी तरह विभिन्न राज्य सरकारों और नीति आयोग, विदेश मंत्रालय एवं अन्य विभागों सहित केंद्र सरकार की एजेंसियों से सभी आवश्यक सहायता प्राप्त हुई। आरआईएस संबंधित (लीड–अप) कार्यक्रमों में फिक्की, सीआईआई और एसोचैम की साझेदारी के लिए आरआईएस सभी का आभारी है।

संबंधित (लीड–अप) कार्यक्रमों के आधार पर आरआईएस ने 'बुनियादी ढांचे हेतु वित्त जुटाने के लिए नई तलाश' नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट आरआईएस की अनुसंधान टीम की व्यापक कड़ी मेहनत का नतीजा है जिसने उपर्युक्त कार्यक्रमों के सफल आयोजन की पूरी प्रक्रिया में भी योगदान दिया है। इस टीम ने आरआईएस के अध्यक्ष राजदूत (डॉ) मोहन कुमार और आरआईएस की अनुसंधान सलाहकार परिषद के अध्यक्ष राजदूत सुधीर देवरे के समग्र मार्गदर्शन में काम किया। डॉ. शेषाद्रि चारी, सदस्य, आरआईएस की शासी परिषद ने संबंधित (लीड–अप) कार्यक्रमों में व्यापक सहयोग दिया। आरआईएस की अनुसंधान टीम के सदस्यों में शामिल थेः डॉ. एस. के. मोहंती, प्रोफेसर; प्रो. अमिताभ कुंडू, प्रतिष्ठित फेलो; डॉ. प्रियदर्शी दाश, सहायक प्रोफेसर; डॉ. सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर; श्री सुभोमय भट्टाचार्जी, परामर्शदाता; श्री अरुण एस. नायर, विजिटिंग फेलो, सुश्री गरिमा धीर, आईबीएसए फेलो; श्री सैयद मोहम्मद अली, रिसर्च एसोसिएट; और श्री वैभव कौशिक, अनुसंधान सहायक। हम आशा करते हैं कि नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, प्रोफेशनलों और हितधारकों को यह रिपोर्ट उपयोगी सिद्व होगी।

विकास के सतत लक्ष्य और सीएसआर एवं प्रमुख कार्यक्रमों के जरिए जीवन स्तर बढ़ाना

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) ने अनेक क्षेत्रों में कई पहल की हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने भी समावेशी विकास और सतत विकास सुनिश्चित करने वाले कई प्रमुख कार्यक्रम प्रक्षेपण किए हैं। स्वच्छ भारत मिशन में देश में क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव लाने की असीम क्षमता है। विशेषकर सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के एजेंडे के कारगर और लाभकारी कार्यान्वयन के लिए भारत द्वारा जताई गई प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाया जाना है। इस संदर्भ में 'सीएसआर' की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है और भारत के समक्ष मौजूद विभिन्न सामाजिक–आर्थिक मुद्दों को हल करने के लिए इस मद में हो रहे योगदान पर चर्चा और समीक्षा करने की तत्काल आवश्यकता है। यह बात रेखांकित की जाती है कि समावेशी विकास को मजबूत बनाने के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सीएसआर योगदान को बढ़ाने की व्यापक गुंजाइश है। इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आरआईएस ने एआईआईबी की तीसरी वार्षिक बैठक के दौरान 25 जून 2018 को मुंबई में रीच स्केल और एफआईडीसी के साथ मिलकर एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया।

'सतत विकास लक्ष्य और सीएसआर एवं प्रमुख कार्यक्रमों के जरिए स्तर बढ़ाने' की थीम पर आयोजित सत्र का आरंभ आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी के संबोधन

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार 'सुदृढ़ एवं बेहतरीन बुनियादी ढांचे के निर्माण' पर आयोजित एआईबीबी मेजबान देश सेमिनार में बोलते हुए।

के साथ हुआ। रीच स्केल के संस्थापक एवं सीईओ श्री डेविड विल्कॉक्स ने प्रारंभिक भाषण दिया। श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार ने विशेष भाषण दिया। सुश्री मेगन फॉलोन, सीईओ, बेयरफुट कॉलेज इंटरनेशनल; प्रो. अमिताभ कुंडू, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस; और श्री रविचंद्रन नटराजन, प्रमुख (साझेदारी एवं कॉरपोरेट संबंध), टाटा ट्रस्ट, मुंबई ने भी इस अवसर पर अपने–अपने विचार पेश किए। सत्र का समापन खुली परिचर्चा के साथ हुआ।

दिल्ली प्रक्रिया–4 के जरिए बापा+40 की ओर

दक्षिणीय सहयोग (एसएससी) और त्रिकोणीय विकास सहयोग (टीडीसी) की अवधारणा की दिशा में हालिया प्रयास अपनी सामान्य शुरुआत के बाद अब लंबा सफर तय कर चुके हैं और इसके साथ ही ये वैश्विक विकास से जुड़ी व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं के रूप में उभर कर सामने आए हैं। विभिन्न संस्थानों जैसे नवीन विकास बैंक, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वैश्विक परिदृश्य में एसएससी के बढ़ते प्रभाव के गवाह हैं। 4 जून, 2018 को प्रिटोरिया में एसएससी पर पेश किए गए हालिया आईबीएसए घोषणापत्र में एसएससी के सिद्धांतों को समूह के सदस्य देशों द्वारा विकास सहयोग के आधार स्तंभ के रूप में दोहराया गया है। ब्यूनस आयर्स कार्य योजना (बापा+40) से जुड़ा संयुक्त राष्ट्र का आगामी स्मरणीय सम्मेलन एसएससी के इस विविध और सक्रिय इतिहास पर टिका हुआ है।

एसएससी के सैद्धांतिक आधार पर विचार करने और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आरआईएस ने विदेश मंत्रालय, दक्षिणीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओएसएससी), एनईएसटी और एफआईडीसी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 13–14 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में 'दक्षिणीय सहयोग और बापा+40 सैद्धांतिक दृष्टिकोण और अनुभवजन्य वास्तविकताओं' पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में एसएससी की सैद्धांतिक बारीकियों को मजबूत करने और विकास सहयोग की वैश्विक समझ का विस्तार करने – इसकी वैचारिक रूपरेखा और प्रासंगिक अनुभवजन्य मान्यताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस साल 'दिल्ली प्रक्रिया' में जिस सैद्धांतिक निर्माण पर विचार–विमर्श किया गया उसमें एसएससी के कुछ गैर–विचारणीय सिद्धांतों पर एक रूपरेखा तैयार करने एवं एक समझौता करने और एसएससी में शामिल

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

73वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की निर्वाचित अध्यक्ष माननीया सुश्री मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गार्सेस सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देती हुईं।

तौर–तरीकों के सैद्धांतिक प्रतिरूपण के रूप में विकास संविदा के उद्भव पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र की निर्वाचित अध्यक्ष माननीया सुश्री मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गार्सेस ने उद्घाटन भाषण दिया और प्रो. अमिताभ आचार्य, विशिष्ट प्रोफेसर, अमेरिकी विश्वविद्यालय, वाशिंगटन डीसी ने मुख्य भाषण दिया। आरआईएस के चेयरमैन राजदूत मोहन कुमार ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की और आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। श्री जॉर्ज चेडिक, निदेशक, यूएनओएसएससी; माननीय श्री डैनियल चुबुरु, राजदूत, अर्जेंटीना गणराज्य का दूतावास, नई दिल्ली और श्री टी.एस. त्रिमूर्ति, सचिव (ईआर), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने विशेष भाषण के साथ सम्मेलन का मान बढ़ाया।

सम्मेलन में चर्चाएं दक्षिणीय सहयोग के लिए एक नई सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करने पर हुईं जो या तो मुद्रावादी एवं संरचनात्मक विचारधाराओं के एक संकर के रूप में विकसित हो सकती है या अर्थशास्त्र में एक नया दृष्टिकोण बना सकती है। जहां एक तरफ मुद्रावादियों के साथ दृष्टिकोण में सामंजस्य स्थापित होता है जो विकास और तरक्की को वृहद आर्थिक स्थिरता के साथ जोड़ कर देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ संरचनावादियों के साथ दृष्टिकोण में सामंजस्य स्थापित होता है जो यह मान कर चलते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना दरअसल सतत विकास करने के लिए जनसंख्या की निर्माण क्षमता के मामले में कहीं अधिक मायने रखती है, भले ही यह अल्प अवधि में वृहद आर्थिक स्थिरता की कीमत पर हो। चाहे यह एक संकलन हो या एक नया दृष्टिकोण, विचार–विमर्श के दौरान इस पर विशेष जोर दिया गया कि एक सैद्धांतिक रूपरेखा में दक्षिणीय सहयोग के मूल सिद्धांतों को शामिल करना चाहिए।

इस सम्मेलन में एसएससी के एक स्तंभ के रूप में घरेलू क्षमता के निर्माण के महत्व को सामूहिक रूप से रेखांकित किया गया, न सिर्फ इसलिए कि विभिन्न देश अपनी स्वयं

सम्मेलन का उद्घाटन सत्र प्रगति पर है।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

सम्मेलन में प्रतिष्ठित पैनलिस्ट विचार–विमर्श करते हुए।

की विकास गाथा का श्रेय पा सकें, बल्कि उत्तर–दक्षिण, दक्षिणीय और त्रिकोणीय सहयोग से भी बेहतर लाभ उठाया जा सके।

एसएससी के प्रभाव के आकलन पर विचार–विमर्श के दौरान व्यापक और सूक्ष्म स्तर पर विश्लेषण के दो स्तर उभर कर सामने आए। व्यापक स्तर पर विश्लेषण बहु–विषयक तरीके से राउल प्रेबिश और अल्बर्ट हिर्शमेन के कार्यों से हासिल असमानता में कमी पर केंद्रित योगदानों से संबंधित है। सूक्ष्म स्तर के विश्लेषण के तहत इस पर गौर किया जाता है कि दक्षिणीय सहयोग से जुड़ी पहल विभागीय प्रक्रिया यानी स्थानीय स्थितियों और विभिन्न व्यक्तिगत विशिष्टताओं के प्रति सम्मान में किस तरह से योगदान करती हैं। एसएससी के अंतर्गत होने वाले प्रमुख वाद–विवादों के तहत इन प्राथमिक प्रश्नों पर गौर किया जाता है : आकलन पद्धति का आधार क्या होना चाहिए और एसएससी के लिए लेखांकन का स्वरूप क्या होना चाहिए? ये प्रश्न एक दूसरे से स्वतंत्र या अलग नहीं हैं और ये अक्सर आपस में जुड़े होते हैं। प्रभाव के आकलन में एसएससी के सिद्धांतों को लागू करने की संभावना से प्रारंभिक निदान में सुधार के अवसर बढ़ जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं को बेहतर ढंग से तैयार करना संभव हो पाता है और इसके साथ ही कहीं ज्यादा निष्पक्ष रूप से प्रभावों का आकलन हो पाता है। ऐसे में स्थानीय आवश्यकताओं से जुड़ी परियोजनाओं का स्वामित्व यहां तक कि समुदाय स्तर पर भी संभव हो पाएगा। प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने यह बात रेखांकित की कि एसएससी सूक्ष्म स्तर पर की जाने वाली परियोजना संबंधी पहलों के स्तर पर सबसे अच्छा काम करता है।

इस दौरान किफायती दर पर विकास वित्त की उपलब्धता और और इसके विभिन्न स्रोतों पर भी चर्चाएं की गईं। इन सत्रों के दौरान यह पाया गया कि व्यापार प्रवाह को स्वाभाविक माना जाता है, लेकिन निवेश रणनीतिक होते हैं और इनमें क्षमता निर्माण की संभावनाएं निहित होती हैं जो विकासशील देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में स्थानीय मुद्रा की प्रभावशीलता को समझना उनके लिए जरूरी है, ताकि उन्हें नाजुक स्थिति का सामना न करना पड़े। अंतरराष्ट्रीय रुपया अदला–बदली एक्सचेंज एक प्रमुख उदाहरण के रूप में उभर कर सामने आए हैं। सशर्त होने या इसके न होने से ऋण संबंधी जोखिम, .ऋणग्रस्तता और विकास सहयोग के अन्य रूपों विशेषकर आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) से उत्पन्न होने वाली वित्तीय अनिश्चितताओं की तुलना में एसएससी का विशिष्ट स्वरूप परिभाषित होगा। ज्ञान प्रवाह विकास के मोर्चे पर बेहतरी को चिन्हित करता है और प्रक्रिया को अंतर्निहित ढंग से सुधारने

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

के लिए क्षमता का निर्माण करता है। सिविल सोसायटी संगठनों को भी मानकों को तय करने और सरकार एवं निजी क्षेत्र के बीच सफल संपर्क बनाने से जुड़ी एसएससी की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभानी है।

इस सम्मेलन ने निरंतर संवाद के लिए रास्ते खोल दिए जिसका उद्देश्य जी–20 में होने वाले वाद–विवादों के साथ–साथ 20 से 22 मार्च 2019 तक अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में होने वाले दक्षिणीय सहयोग पर द्वितीय उच्चस्तरीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भी शामिल होना है। विकासशील देशों के सामूहिक विकास के लिए कामकाज या व्यवसाय, कृषि और बुनियादी ढांचे के भविष्य का विकास बार–बार प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा था, जैसा कि जी–20 शेरपा और अर्जेंटीना के राजदूत द्वारा विशिष्ट रूप से दर्शाया गया। सम्मेलन के दौरान नए शोध एजेंडों को प्रस्तुत किया गया जिन्होंने ''दिल्ली प्रक्रिया+4 के चर्चारत विषयों, अर्थात प्रभाव आकलन की पद्धति और पाठ्यक्रम संबंधी शैक्षणिक पहलों को बांधे रखा। अपने लक्ष्य को बखूबी समझते हुए 'दिल्ली प्रक्रिया+4 मुख्यतः नीति निर्माताओं, सिविल सोसायटी और अकादमियों का नेटवर्क बनाने की दिशा में अग्रसर हो गई, ताकि विभिन्न हितधारकों को सामूहिक कदम उठाने के लिए एकजुट किया जा सके।

सम्मेलन का विस्तृत एजेंडा तैयार संदर्भ के लिए आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

'नेस्ट' का पेरिस शांति फोरम में प्रतिनिधित्व

11 से 13 नवंबर, 2018 तक आयोजित पेरिस शांति फोरम (पीपीएफ) ने प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की 100वीं वर्षगांठ मनाई और इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए टिकाऊ शांति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गवर्नेंस से जुड़ी हस्तियों को एकजुट किया। यह फोरम तीन ठिकानों पर कार्य करता है जहां वाद–विवाद, समाधान और नवाचार सामने लाए जाते हैं। समाधानों के लिए संबंधित ठिकाने पर कुल मिलाकर 121 वैश्विक गवर्नेंस परियोजनाओं को प्रस्तुत किया गया जिनमें से 10 परियोजनाओं को एक वर्ष तक विशेष सहायता के लिए चुना गया।

राजदूत मोहन कुमार, चेयरमैन, आरआईएस पेरिस शांति फोरम में श्री प्रणय सिन्हा, विजिटिंग फेलो, आरआईएस के साथ।

नेटवर्क ऑफ सदर्न थिंक टैंक्स (नेस्ट), आरआईएस को एक वैश्विक गवर्नेंस परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया गया। दक्षिण यानी विकासशील देशों के लिए और दक्षिण की ओर से एक सहयोगी पहल 'नेस्ट' मुख्य रूप से एक थिंक टैंक और शैक्षणिक फोरम है जो दक्षिणीय सहयोग (एसएससी) के क्षेत्र में नीतिगत जानकारियां उपलब्ध कराता है।

'नेस्ट' दक्षिणीय सहयोग के तहत विकास परियोजनाओं के प्रभावों के आकलन पर भी गौर करता है। पीपीएफ में भाग लेने की प्रेरणा ग्लोबल साउथ (वैश्विक दक्षिण)' में अंतर्निहित एकजुटता की विशेषता 'एसएससी के मूल्यों से उभरती है। यह समावेशी विकास सहयोग के लिए पहली आवश्यकता है जो वैश्विक गवर्नेंस और टिकाऊ शांति का आधार है। इसका मूर्त रूप होने के नाते नेस्ट और पीपीएफ सामूहिक रूप से सफल अंतरराष्ट्रीय सहयोग के तहत एक बिल्कुल उपयुक्त साझेदारी को दर्शाते हैं। पीपीएफ में नेस्ट का प्रतिनिधित्व आरआईएस के चेयरमैन डॉ. मोहन कुमार ने किया जिन्होंने श्री प्रणय सिन्हा, विजिटिंग फेलो, आरआईएस और डॉ. एंड्रे डी मेलो ई सूजा, कोऑर्डेनाडोर डी इंटरकाम्बियो ई को–ऑपेराकाओ इंटनेशिअनल (क्वायंट), डायरेटोरिया डी एस्टुडॉस ई रिलैकोस इकोनोमिकास ई पॉलिटिकैस इंटरनेशिअनल्स (डीआईएनटीई), इंस्टीट्यूटो डी पेसक्विसा इकोनोमिका एप्ली काडा (आईपीईए), ब्राजील के साथ प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

आरआईएस की पुस्तक 'राउल प्रिबिश और विकास रणनीति' के विमोचन के अवसर पर प्रतिष्ठित पैनल सदस्य।

बापा+40 में आरआईएस की पुस्तक राउल प्रिबिश और विकास रणनीति

आरआईएस ने संयुक्त राष्ट्र के साथ एक मान्यता प्राप्त साझेदार संगठन के रूप में 20 से 22 मार्च 2019 तक अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में दक्षिणीय सहयोग पर आयोजित द्वितीय उच्चस्तरीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (बापा + 40) में भाग लिया। इस अवसर पर आरआईएस ने नेटवर्क ऑफ सदर्न थिंक टैंक्स् (नेस्ट) के तत्वावधान में अलग से आयोजित चार कार्यक्रमों की मेजबानी भी की। इन कार्यक्रमों के दौरान जाने–माने विद्वानों, विशेषज्ञों, और नीति निर्माताओं के साथ पैनल परिचर्चाएं आयोजित की गईं जिनका उद्देश्य विकास सहयोग के प्रति एशियाई दृष्टिकोण के पहलुओं को प्रस्तुत करना; दक्षिणीय सहयोग (एसएससी) में बहुलता या अनेकता को दर्शाना; स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुंच की आवश्यकता को रेखांकित करना; और आकलन, निगरानी एवं मूल्यांकन से संबंधित मुद्दों पर गहन विचार–विमर्श करना था।

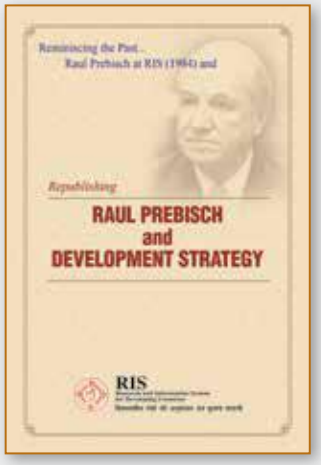

आरआईएस ने नेस्ट के साथ साझेदारी में 20 मार्च 2019 को विदेश एवं उपासना मंत्रालय, पालिसियो सैन मार्टिन, ब्यूनस आयर्स में 'प्रभाव आकलन और निगरानी एवं मूल्यांकन बनाम दक्षिणीय सहयोगः वाद–विवाद की स्थिति' पर परिचर्चा की मेजबानी भी की। इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. फिलानी म्थेम्बु, कार्यकारी निदेशक, इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल डायलॉग, दक्षिण अफ्रीका ने की और सह–अध्यक्षता प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने की। पैनल के सदस्यों में ये शामिल थेः प्रोफेसर शिउली जू, डिप्टी डीन, कृषि में दक्षिणीय सहयोग के लिए चीनी संस्थान (सीआईएसएससीए), सीएयू, चीन; डॉ. एंड्रे डी मेलो ई सूजा, सीनियर रिसर्च फेलो, इंस्टीट्यूटो डी पेसक्विसा इकोनॉमिका एप्लीकाडा (आईपीईए), ब्राजील; डॉ. स्टीफन क्लिंगबिएल, विभाग प्रमुख – द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विकास नीति, जर्मन विकास संस्थान (डीआईई), जर्मनी; श्री मारियो पेजिनी, निदेशक, ओईसीडी विकास केंद्र, फ्रांस; और प्रोफेसर मिलिंदो चक्रबर्ती, विजिटिंग फेलो, आरआईएस। परिचर्चा के बाद एक सवाल–जवाब सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर राउल प्रिबिश पर एक विशेष

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

पुस्तक *'राउल प्रिबिश और विकास रणनीति'* शीर्षक का विमोचन भी किया गया। इस पुस्तक में 'उत्तर–दक्षिण और दक्षिणीय संबंधों में नए परिप्रेक्ष्य' पर आयोजित सेमिनार की कार्यवाही शामिल है। इसमें राउल प्रिबिश के कुछ महत्वपूर्ण योगदानों का भी उल्लेख है। विचार–विमर्श के दौरान प्रभाव आकलन और निगरानी एवं मूल्यांकन के बीच वैचारिक व राजनीतिक मतभेदों की जानकारी और इसके साथ ही मांग–संचालित आकलन एवं मूल्यांकन कार्यों के लिए भारत, पराग्वे और ब्राजील जैसे विकासशील देशों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की गई है।

आरआईएस, नेस्ट और कृषि में दक्षिणीय सहयोग के लिए चीनी संस्थान (सीआईएसएससीए) ने 19 मार्च 2019 को ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय में 'दक्षिणीय सहयोग पर एशियाई वृत्तांत के अन्वेषण' पर एक परिचर्चा का आयोजन किया। सत्र की अध्यक्षता चीन कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू) के अध्यक्ष प्रोफेसर सन किसिन ने की और इसकी सह–अध्यक्षता आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने की। पैनल के अन्य सदस्य में ये शामिल थेः डॉ. एंथेया मुलाकला, निदेशक, द एशिया फाउंडेशन (टीएएफ); श्री आर्टेमी इजमेस्तीव, निदेशक ए.आई., सियोल में यूएनडीपी नीतिगत केंद्र, दक्षिण कोरिया; डॉ. स्वेन ग्रिम, अंतर–सहयोग एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग के सह–अध्यक्ष, जर्मन विकास संस्थान (जीडीआई), जर्मनी; प्रोफेसर शिउली जू, डिप्टी डीन, कृषि में दक्षिणीय सहयोग के लिए चीनी संस्थान (सीआईएसएससीए), सीएयू, चीन; श्री मिनयंग जियोंग, डिप्टी कंट्री डायरेक्टर, कोरियाई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (कोइका), दक्षिण कोरिया; और श्री प्रणय सिन्हा, विजिटिंग फेलो, आरआईएस।

आरआईएस और नेस्ट ने 21 मार्च 2019 को ब्यूनस आयर्स स्थित इंस्टीट्यूटो नेशनल सैनमार्टिनियानो में 'स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच के लिए दक्षिणीय सहयोग' विषय पर एक परिचर्चा की मेजबानी भी की। इस दौरान क्षेत्रवार सहयोग पर गहन विचार–विमर्श किया गया। आयोजन की शुरूआत अर्जेंटीना में भारत के राजदूत श्री संजीव रंजन द्वारा आरआईएस के एक विशेष प्रकाशन 'सम्मिलित रूप से एक स्वस्थ भविष्य की ओर – स्वास्थ्य सेवा में भारत की साझेदारियां' के विमोचन के साथ हुआ। इसके बाद एक परिचर्चा हुई जिसकी सह–अध्यक्षता डॉ. कार्लोस मारिया कॉररिया, कार्यकारी निदेशक, दक्षिण केंद्र, जिनेवा और डॉ. एंड्रे डी मेलो ई सूजा, सीनियर रिसर्च फेलो, इंस्टीट्यूटो डी पेसक्विसा इकोनॉमिका एप्लीकाडा (आईपीईए), ब्राजील ने

आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी साथी पैनल सदस्यों के साथ।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

की। अन्य पैनल के सदस्यों मे यह भी शामिल थेः डॉ. बर्नाबे मलाकाल्जा, रिसर्च फेलो, राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान परिषद, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्विलमेस (यूएनक्यूब), अर्जेंटीना; श्री गोविंद वेणुप्रसाद, समन्वयक, अफ्रीका के लिए भारतीय व्यापार और निवेश का समर्थन (एसआईटीए), अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र ; सुश्री रोक्साना माजोला, कार्यकारी निदेशक, अध्ययन और नीतिगत विकास केंद्र (सीईडीईपी), ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय, अर्जेंटीना; और प्रोफेसर टी.सी. जेम्स, विजिटिंग फेलो, आरआईएस।

नेस्ट ने आरआईएस और ब्रिक्स नीतिगत केंद्र, ब्राजील के साथ साझेदारी में ब्राजील, मैक्सिको, चीन, अर्जेंटीना और अफ्रीका के देश प्रभागों (कंट्री चैप्टर) के साथ 22 मार्च 2019 को एसोसियासिएन डी एमिगोस डेल म्यूजियो नेशनल डी बेलास आर्टेस, ब्यूनस आयर्स में 'दक्षिणीय सहयोग की बहुलता' विषय पर एक पैनल परिचर्चा की मेजबानी की। सत्र की शुरुआत यूएनओएसएससी के निदेशक श्री जॉर्ज चेडिएक के विशेष भाषण के साथ हुई। परिचर्चा की सह–अध्यक्षता डॉ. पाउलो एस्टीव्स, निदेशक, ब्रिक्स नीतिगत केंद्र, ब्राजील और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने की। परिचर्चा में शामिल अन्य सदस्य थेः डॉ. एंड्रे डी मेलो ई सूजा, सीनियर रिसर्च फेलो, इंस्टीट्यूटो डी पेसक्विसा इकोनॉमिका एप्लीकाडा (आईपीईए), ब्राजील; डॉ. जॉर्ज ए. पेरेज–पिनेडा, प्रोफेसर–इनवेस्टिगाडोर, यूनिवर्सिडेड एनाहुआक, मेक्सिको; प्रोफेसर मीबो हुआंग, निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग अकादमी, शंघाई अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय एवं अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय; श्रीमती लुआरा लोपेज, दक्षिणीय सहयोग के लिए अनुसंधान समन्वयक, अनुसंधान एवं नीतिगत केंद्र आर्टिकुलाकाओ एसयूएल, ब्राजील; सुश्री नादीन पाइफर, नीतिगत विश्लेषक, ओईसीडी विकास सहयोग निदेशालय, फ्रांस; प्रोफेसर मिलिंदो चक्रबर्ती, विजिटिंग फेलो, आरआईएस; श्री प्रत्यूष शर्मा, संवाददाता (डीसीआर), आरआईएस; और डॉ. ग्लेडिस टेरेसिटा लेचिनी, यूनिवर्सिडेड नेशनल डी रोजारियो, अर्जेंटीना। 'बापा + 40' में आरआईएस का प्रतिनिधित्व प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने किया। प्रतिनिधिमंडल में प्रो. टी सी जेम्स, प्रो. मिलिंदो चक्रबर्ती, डॉ. सब्यसाची साहा, श्री प्रणय सिन्हा, सुश्री अमिका बावा और श्री प्रत्युष शर्मा ने किया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने इन कार्यक्रमों में भी भाग लियाः 'चुनौतियां और दक्षिणीय एवं त्रिकोणीय सहयोग की संस्थागत रूपरेखा को मजबूत करने' पर बापा + 40 संवादात्मक पैनल परिचर्चा 2, जिसे यूएनओएसएससी और अर्जेंटीना सरकार द्वारा आयोजित किया गया; 'दक्षिणीय एवं त्रिकोणीय सहयोग पर सीमांत अनुसंधान को आगे बढ़ाना', जिसे यूएनओएसएससी एवं यूएनडीपी द्वारा आयोजित किया गया; 'सतत विकास की ओर उन्मुखः एजेंडा 2030 को पूरा करने हेतु सहयोग के लिए नए रास्ते', जिसे ओईसीडी विकास केंद्र द्वारा आयोजित किया गया; 'वैश्विक दक्षिण में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) का विशेष योगदान', जिसे आईटीसी द्वारा आयोजित किया गया; '2030 एजेंडा प्राप्त करने के लिए विकास सहयोगः प्रभावशील सहयोग' पर संपादकों की कार्यशाला, जिसे नेस्ट, डीआईई और जीडीआई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया; '2030 एजेंडा प्राप्त करने के लिए विकास सहयोग' पर विशेषज्ञ कार्यशाला, जिसे नेस्ट, डीआईई, आईपीईए, जर्मन विकास संस्थान और मैनेजिंग ग्लोबल गवर्नेंस द्वारा आयोजित किया गया; और 'सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग में होड़ और सहयोग', जिसे नेस्ट, आईपीईए और जीडीआई द्वारा आयोजित किया गया।

दक्षिणीय सिविल सोसायटी सम्मेलन

दक्षिण एशिया और दक्षिण–पूर्व एशियाई क्षेत्र विकास सहयोग से जुड़ी ऐसी कई पहलों के साक्षी रहे हैं जो न्यायसंगत विकास, प्रौद्योगिकी तक पहुंच और कारोबार करने में आसानी जैसे उद्देश्यों पर केंद्रित हैं। इस क्षेत्र का विशिष्ट बहुपक्षवाद उन व्यापक आर्थिक विकास एजेंडों को सुविधाजनक बनाने वाले प्लेटफार्मों के अभ्युदय में परिणत हुआ है जिन्हें विदेश नीति के उद्देश्यों के अनुसार प्राथमिकता दी गई है। बीबीआईएन (बांग्लादेश, भूटान, भारत एवं नेपाल) और बहु–क्षेत्रवार तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) जैसे प्लेटफॉर्म स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रभाव डालने और सीमा पार आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत क्षेत्रीय रूपरेखा विकसित करने की दृष्टि से अब व्यवहार्य या उपयोगी मंच बनते जा रहे हैं। इसी तरह की तर्ज पर दक्षिण एशिया के साथ आसियान के बढ़ते संबंधों को क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा और व्यापार आधिपत्य का मुकाबला करने की आर्थिक विवशता से बल मिल रहा है। विकास संकेतकों को कारगर ढंग से लक्षित करने के

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

वैश्विक संदर्भ में भारत–रूस संबंधों' पर रिपोर्ट पेश करते हुए।

लिए उन संस्थानों के साथ नीतिगत सामंजस्य और समावेशी सहयोग सुनिश्चित करने की जरूरत है जो एक सुदृढ़ एवं उपयोगी सहयोगात्मक रूपरेखा तैयार करने में अत्यंत अहम साबित हो सकते हैं। बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में विकास संबंधी सहयोग सिविल सोसायटी की भागीदारी के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है।

इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) और एफआईडीसी ने दक्षिण एशिया और दक्षिण–पूर्व एशियाई क्षेत्र के प्रमुख सिविल सोसायटी संगठनों के साथ मिलकर 17–18 दिसंबर, 2018 को नई दिल्ली में दो दिवसीय 'दक्षिणीय सिविल सोसायटी सम्मेलन' का आयोजन किया। इसका उद्देश्य, इन समूहों के लक्ष्यों के साथ–साथ समूचे एशिया के सिविल सोसायटी संगठनों द्वारा ज्ञान एवं डेटा के पारस्परिक आदान–प्रदान के जरिए दक्षिण एशिया के विकास सहयोग पर करीबी नजर रखने के तरीकों पर एक जीवंत संवाद सुनिश्चित करना था। सम्मेलन का आयोजन दो प्रारूपों में किया गया। 17 दिसंबर 2018 को भारतीय सिविल सोसायटी संगठनों को भारत के विकास सहयोग की वैश्विक मौजूदगी से अवगत कराया गया और 18 दिसंबर 2018 को 'दक्षिणीय सिविल सोसायटी सम्मेलन' में भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय सीएसओ की भागीदारी के लिए निवेदन किया गया।

वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका

आरआईएस ने नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल) ; बर्लिन स्थित डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशंस रिसर्च इंस्टीट्यूट (डीओसी); और दैनिक भास्कर के साथ मिलकर 3 जुलाई 2018 को नई दिल्ली स्थित नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय में डॉ. जगदीश सेठ, चार्ल्स एच. केल्स्ताड, मार्केटिंग के प्रोफेसर, गोइजुवेटा बिजनेस स्कूल, एमोरी यूनिवर्सिटी, अटलांटा, अमेरिका द्वारा 'वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका' पर सार्वजनिक व्याख्यान का आयोजन किया।

डॉ. जगदीश सेठ भू–राजनीतिक विश्लेषण में अपने विद्वत्तापूर्ण योगदान के लिए प्रख्यात हैं। उन्हें सदर्न कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, इलिनोइस विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, एमआईटी, और एमोरी विश्वविद्यालय में शिक्षण एवं शोध में 50 वर्षों से भी अधिक का लंबा संयुक्त अनुभव है।

डॉ. विनय प्रभाकर सहस्त्रबुद्धे, अध्यक्ष, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इसका शुभारंभ आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी और एनएमएमएल के निदेशक श्री शक्ति सिन्हा के स्वागत भाषणों के साथ हुआ। डायलॉग

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

आरआईएस के चेयरमैन राजदूत (डॉ.) मोहन कुमार 'वैश्विक विकास पर पहल ' के शुभारंभ के दौरान अन्य प्रतिष्ठित पैनल सदस्यों के साथ।

ऑफ सिविलाइजेशंस रिसर्च इंस्टीट्यूट (डीओसी) के प्रबंध परियोजना निदेशक श्री पूरन चंद्र पांडेय ने प्रारंभिक भाषण दिया। श्री दीपक द्विवेदी, बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य संपादक, दैनिक भास्कर ने विशेष भाषण दिया।

इस अवसर पर 'वैश्विक संदर्भ में भारत–रूस संबंध' पर रिपोर्ट भी जारी की गई जिसे आरआईएस और डीओसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया।

'वैश्विक विकास पर पहल' का शुभारंभ

आरआईएस ने ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 9 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में 'वैश्विक विकास पर पहल' के शुभारंभ का आयोजन किया। इस पहल के जरिए विकास से जुड़े अनुभवों, ज्ञान और तकनीकी जानकारियों को साझा करने की दिशा में एक अहम यात्रा शुरू की गई है जिसने एक समावेशी और समान साझेदारी के लिए एक नया पथ निर्धारित किया है। यह साझेदारी दरअसल विकास संबंधी सहयोग के एक विविध स्वरूप की स्वीकार्यता के साथ–साथ विकासशील देशों के बीच तरह–तरह के दृष्टिकोणों की मौजूदगी पर आधारित है। यह पहल एशिया और अफ्रीका के साथी विकासशील देशों के साथ भारत के विकास संबंधी अनुभवों को साझा करने के लिए एक उपयुक्त मंच सुलभ कराती है।

उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता आरआईएस के चेयरमैन राजदूत डॉ. मोहन कुमार ने की। स्वागत भाषण राजदूत अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस ने दिया। श्री मनोज भारती, अपर सचिव (आर्थिक कूटनीति एवं राज्य प्रभाग), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार; श्री पीट वॉवेल्स, निदेशक, एशिया, कैरिबियन एवं विदेशी क्षेत्र प्रभाग, डीएफआईडी; और श्री गेविन मैकगिलिव्रे, प्रमुख, डीएफआईडी इंडिया ने विशेष भाषण दिए। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने 'वैश्विक विकास पर पहल' के बारे में एक विशेष प्रस्तुति दी।

इस पहल के आरंभ के बाद 'वैश्विक विकास पर पहल की रूपरेखा' पर एक परिचर्चा राजदूत अमर सिन्हा, विशिष्ट फेलो, की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अन्य वक्ता थेः श्री फिलिप परहम, राष्ट्रमंडल में ब्रिटेन के दूत; प्रोफेसर अनुराधा चेनॉय, अध्यक्ष, एफआईडीसी; और डॉ. राजेश टंडन, अध्यक्ष, एशिया में भागीदारी अनुसंधान (प्रिया)। चर्चा के दौरान उभरे कुछ प्रमुख दृष्टिकोण में विकासशील देशों के सभी हितधारकों के बीच संवादों के सह–आयोजन के महत्व पर बल दिया गया। जिसका मुख्य लक्ष्य ज्ञान को जुटाना एवं व्यवस्थित करना और उसे स्थानीय में वैश्विक स्तर पर ले जाना था। परिचर्चा के बाद एक सवाल–जवाब सत्र भी आयोजित किया गया।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

एफआईडीसी का 'विकास सहयोग के लोकतंत्रीकरण' पर सम्मेलन

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हाल ही में अपनाए जाने से विकास सहयोग को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने में एक और व्यापक रूपरेखा जुड़ गई है जिसमें कई हितधारक शामिल हैं। इस व्यापक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय विकास सहयोग फोरम (एफआईडीसी) और आरआईएस ने 9 अगस्त 2018 को आरआईएस में 'बहु–हितधारक साझेदारियों के जरिए विकास सहयोग के लोकतंत्रीकरण' पर एक सम्मेलन का आयोजन किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण के साथ हुआ। पीआरआईए के अध्यक्ष डॉ. राजेश टंडन ने सत्र की अध्यक्षता की। प्रोफेसर गुलशन सचदेव, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय; कार्ल गेर्शमैन, प्रेसीडेंट, नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, अमेरिका; और प्रो. माइको इचिहारा, एसोसिएट प्रोफेसर, हितोत्सुबाशी विश्वविद्यालय, जापान इस अवसर पर मुख्य वक्ता थे।

प्रोफेसर सिउंगजू ली, चुंग–एंग विश्वविद्यालय, दक्षिण कोरिया और प्रो. मिलिन्दो चक्रबर्ती, विजिटिंग फेलो, आरआईएस इस अवसर पर प्रमुख चर्चाकर्ता या प्रतिभागी थे। 'वैश्विक गवर्नेंस संस्थानों के लोकतंत्रीकरण' पर सत्र की अध्यक्षता श्री अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस ने की।

'क्या आर्थिक बहुपक्षवाद बचा रह सकता है' पर विशेष चर्चा

श्री जीन पिसानी–फेरी, ब्रसेल्स में स्थापित ब्रूजेल थिंक टैंक के पूर्व संस्थापक एवं प्रमुख और फ्रांसीसी सरकार के नीति नियोजन के पूर्व महाआयुक्त तथा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष के साथ एक परिचर्चा का 8 जनवरी 2019 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) में आयोजन किया गया। श्री जीन पिसानी–फेरी ने 'क्या आर्थिक बहुपक्षवाद बचा रह सकता है' विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। डॉ. मोहन कुमार, चेयरमैन, आरआईएस ने इसकी अध्यक्षता की। श्री राजीव खेर, विशिष्ट फेलो, आरआईएस ने मुख्य अतिथि और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया। प्रतिभागियों में ये अन्य वक्ता भी शामिल थेः डॉ. सुधांशु पांडे, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; डॉ. सुमन बेरी, पूर्व महानिदेशक, एनसीएईआर; डॉ. रामगोपाल अग्रवाल, विशिष्ट फेलो, नीति आयोग; और डॉ. मुकेश भटनागर, डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र।

नीतिगत संवाद के प्रमुख प्रतिभागी।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

'एसएसीईपीएस' ने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं के द्वार खोलने पर नीतिगत संवाद की मेज़बानी की

आरआईएस ने संयुक्त राष्ट्र एस्कैप और दक्षिण एशिया नीतिगत अध्ययन केंद्र (एसएसीईपीएस) के साथ साझेदारी में 6 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में 'सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करनेः आगे की राह' के लिए दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं के द्वार खोलने पर नीतिगत संवाद का आयोजन किया।

डॉ. नागेश कुमार, प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र एस्कैप के दक्षिण और दक्षिण–पश्चिम एशिया कार्यालय (संयुक्त राष्ट्र एस्कैप–एसएसडब्ल्यूए); राजदूत (डॉ.) मोहन कुमार, चेयरमैन, विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस); प्रो. दीपक नैय्यर, सह–अध्यक्ष, दक्षिण एशिया नीतिगत अध्ययन केंद्र (एसएसीईपीएस) ने आरंभिक भाषण दिए। श्री रजनीश, संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने विशेष भाषण दिया और माननीया डॉ. पुष्पा राज कदेल, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय योजना आयोग, नेपाल ने उद्घाटन भाषण दिया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

संवाद के दौरान इन विषयों पर सत्र आयोजित किए गएः उभरते वैश्विक रुझानों की पृष्ठभूमि में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लिए संभावनाएं और चुनौतियां; परिवहन और ऊर्जा संपर्क की संभावनाएं एवं चुनौतियां; कृषि, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण में क्षेत्रीय सहयोग; दक्षिण एशिया में सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रबुद्ध मंडलों (थिंक–टैंक) के बीच सहयोग पर बैठक; और संपन्न करना एवं समापन सत्र। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत के प्रतिनिधियों ने विचार–विमर्श में भाग लिया।

वैश्विक व्यापार प्रणाली का संरक्षण और बहुपक्षवाद की भूमिका

आरआईएस जापान के साथ भारत के व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापक शोध कार्यरत रहा है। आरआईएस ने एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (एएजीसी) पर काफी काम किया है। इस पहल की भूरि–भूरि प्रशंसा प्रधानमंत्री ने गत वर्ष 2017 में अहमदाबाद में एएफडीबी की वार्षिक बैठक के दौरान की थी। आरआईएस ने एएजीसी की अवधारणा को वास्तविकता में तब्दील करने के लिए आठ परिचर्चा पत्र प्रस्तुत किए हैं। जापानी संस्थानों के साथ जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए आरआईएस ने जापान इकोनॉमिक फाउंडेशन (जेईएफ) के साथ साझेदारी में 22.23 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में एशिया–प्रशांत फोरम की बैठक की सह–मेजबानी की।

जेईएफ जनहित से जुड़ा एक फाउंडेशन है जिसकी देख–रेख जापानी कैबिनेट कार्यालय द्वारा की जाती है। श्री कजुमासा कुसाका इसके मौजूदा चेयरमैन और सीईओ हैं। वर्ष 1985 में अपनी स्थापना के समय से ही जेईएफ अपने साझेदार देशों के साथ मिलकर हर वर्ष इस आयोजन की सह–मेजबानी करता रहा है जिसका उद्देश्य आर्थिक और तकनीकी आदान–प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जापान एवं अन्य देशों के बीच आपसी समझ को और ज्यादा बढ़ाना है। विगत वर्षों के दौरान इसने एशिया, अमेरिका और यूरोप में कई सम्मेलन आयोजित किए हैं।

'एपीएफ 2018' के मुख्य कार्यक्रम के तहत 22 नवंबर 2018 को 'वैश्विक व्यापार प्रणाली का संरक्षण और बहुपक्षवाद की भूमिका' थीम पर इसके द्वारा सार्वजनिक संगोष्ठी आयोजित की गई। इसके अंतगर्त तीन पैनल ट्रेडिंग सत्र आयोजित किए गए जिस दौरान व्यापार एवं नई प्रौद्योगिकी; क्षेत्रीय एकीकरण के लिए अनिवार्यताएंः सेवा क्षेत्र की बढ़ती भूमिका और हिंद–प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य का महत्व एवं भूमिकाः सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। सार्वजनिक संगोष्ठी को एशिया–प्रशांत क्षेत्र के प्रख्यात विद्वानों ने संबोधित किया जिनमें कई भारतीय विशेषज्ञ भी शामिल थे। सार्वजनिक संगोष्ठी में विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, प्रबुद्ध मंडलों (थिंक टैंक), राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निवासी राजनयिकों, सेवारत और उच्च पदस्थ पूर्व अधिकारियों ने शिरकत की। सार्वजनिक संगोष्ठी में मुख्य भाषण सुश्री प्रीति सरन, भूतपूर्व सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया गया। सार्वजनिक संगोष्ठी के बाद 23 नवंबर 2018 को महानिदेशक, आरआईएस एवं अध्यक्ष, जेईएफ की अगुवाई में एपीएफ के सदस्यों के साथ गोपनीय मंत्रणा की गई।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

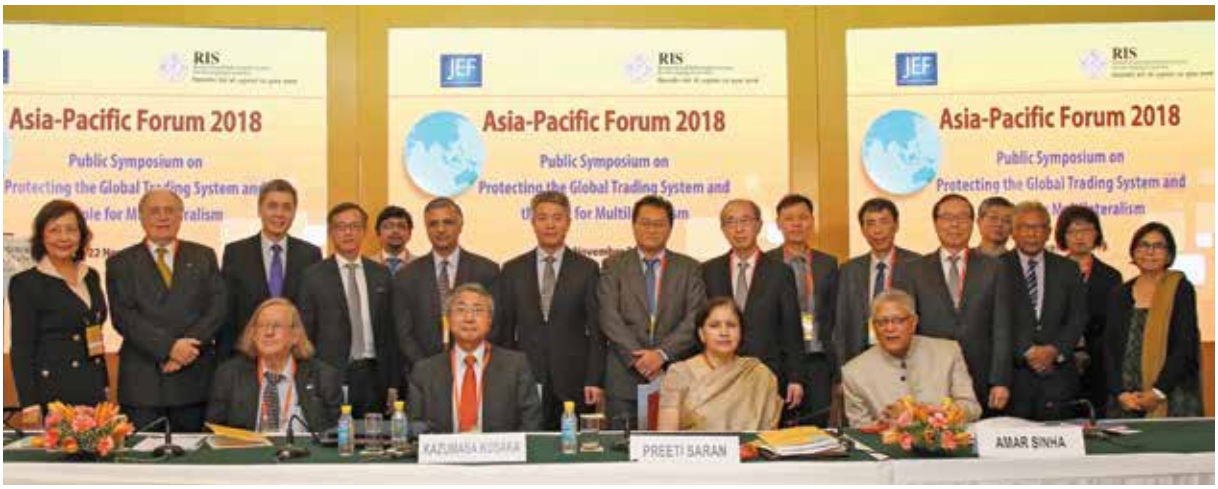

सुश्री प्रीति सरन, भूतपूर्व सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय एशिया–प्रशांत फोरम 2018 में सभी प्रतिष्ठित पैनल सदस्यों के साथ।

प्रभाव आकलन और विकास प्रभावशीलता पर विशेषज्ञ समूह बैठक (ईजीएम)

एफआईडीसी ने 'सदर्न वॉयस', ढाका के सहयोग से 5 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में 'प्रभाव आकलन, विकास प्रभावशीलता और मापः सतत विकास लक्ष्य के युग में उभरते नीतिगत विकल्प' पर एक विशेषज्ञ समूह बैठक (ईजीएम) का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और प्रोफेसर मुस्तफिजुर रहमान, प्रतिष्ठित फेलो, सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग (सीपीडी), ढाका के स्वागत भाषणों के साथ हुआ। राजदूत अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस ने बैठक की अध्यक्षता की। डॉ. देबाप्रिया भट्टाचार्य, प्रतिष्ठित फेलो, सीपीडी और चेयर, सदर्न वॉयस ने मुख्य प्रस्तुति दी। इसके बाद खुली चर्चा आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया।

जी–20 पर परिचर्चा सत्र

हाल ही में जी–20 शिखर सम्मेलन से उभर कर सामने आए मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए आरआईएस ने 12 दिसंबर, 2018 को 'जी–20 पर परिचर्चा सत्र' का आयोजन किया। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया और फिर उन्होंने चर्चाओं की शुरुआत की। श्री आलोक डिमरी, संयुक्त सचिव (एमईआर), विदेश मंत्रालय ने बैठक की अध्यक्षता की। बाद में डॉ. रजत कथूरिया, निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर) और श्री सुभोमय भट्टाचार्जी, सलाहकार, आरआईएस ने अपने–अपने विचार व्यक्त किए।

वर्तमान वैश्विक यर्थाथ को दर्शाने के लिए बहुपक्षीय निकायों में सुधार आवश्यक

दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी), ब्रेटन वुड्स संस्थानों (आईएमएफ एवं विश्व बैंक) और डब्ल्यूटीओ के भीतर सुधार सुनिश्चित करने का आह्वान किया है, ताकि ये अंतरराष्ट्रीय निकाय वैश्विक समुदाय की वर्तमान यर्थाथ को प्रतिबिंबित कर सकें। इसने यह इच्छा भी जताई है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रमुख ब्लॉक ब्रिक्स (जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं) बहुपक्षीय प्रणाली में लंबे समय से मौजूद 'अर्ध–पंगुता' या'–अर्ध–निष्क्रियता' से निपटने के तरीकों पर ध्यान दिया जाए।

इन बहुपक्षीय संस्थानों के भीतर सुधार लाने की वकालत करते हुए दक्षिण अफ्रीका में अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग विभाग के उप महानिदेशक और ब्रिक्स, आईबीएसए एवं जी 20 देशों में दक्षिण अफ्रीका के शेरपा तथा आरआईएस के वरिष्ठ सहायक फेलो प्रोफेसर अनिल सुकलाल ने कहाः

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

आरआईएस के वरिष्ठ सहायक फेलो प्रोफेसर अनिल सुकलाल अन्य प्रतिष्ठित पैनल सदस्यों के साथ।

'आपके पास (अब) एक ऐसी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली है जो 'अर्ध–निष्क्रिय' है। आपके पास एक यूएनएससी है जो ऐसे संकल्पों को अपनाती है जिनकी ओर कोई भी ध्यान नहीं देता है और अब आपको पी2 एवं पी3 के बीच स्थायी विभाजन साफ नजर आता है।' उन्होंने यह भी कहाः 'यही अर्ध–निष्क्रियता (संपूर्ण) बहुपक्षीय प्रणाली में है। हमें इन कमियों को निरंतर दूर करने के लिए ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्मों का उपयोग करना होगा और यह देखना होगा कि जब तक हम इन विचारों (सुधार) पर आम सहमति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त तेजी सुनिश्चित नहीं कर लेते हैं, तब तक हम इसे रडार पर कैसे बनाए रखते हैं।' वरिष्ठ राजनयिक तिरुवनंतपुरम स्थित विकास अध्ययन केंद्र (सीडीएस) में शिक्षाविदों और छात्रों को संबोधित कर रहे थे।

इस ओर ध्यान दिलाते हुए कि संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ जल्द ही मनाई जाएगी (वर्ष 2020 में), उन्होनें कहाः 'हमारे पास अब भी पी5 है, लेकिन यह पी5 कितना प्रभावशाली या कारगर है? एक ऐसा भी समय आएगा जब यह अप्रासंगिक हो जाएगा। आपके पास अन्य प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी या मुल्क होंगे जो वैश्विक परिदृश्य पर अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन करेंगे और उनके व्यापक प्रभाव में आकर आपको संरचना (यूएन की) बदलनी होगी। समय और बदलते वैश्विक परिवेश से यह संभव होगा।' वह 30 जनवरी, 2019 को सीडीएस में 'उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग और वैश्विक गवर्नेंसः ब्रिक्स अनुभव से सबक' विषय पर व्याख्यान देने के बाद सवालों का जवाब दे रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन आरआईएस के सहयोग से किया गया था। प्रोफेसर सुकलाल ने अपने व्याख्यान में वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच सहयोग मजबूत करने की आवश्यकता सहित विभिन्न पहलुओं और जी 20, ब्रिक्स एवं आईबीएस सहित वैश्विक तथा क्षेत्रीय प्लेटफॉर्मों पर होने वाली बैठकों को और ज्यादा सार्थक करने के महत्व पर भी अपने विचार व्यक्त किए। इसके अलावा, उन्होंने ब्रिक्स देशों के लोगों के बीच अधिक से अधिक संवाद सुनिश्चित करने और ब्रिक्स देशों के प्रबुद्ध मंडलों (थिंक–टैंक) के बीच साझेदारियों को बेहतर बनाने हेतु पर भी विशेष जोर दिया। राजदूत ने जी 20 शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्रों में विकासशील देशों के आपसी हितों वाले अधिक पहलुओं सहित ब्रिक्स के संपर्क (आउटरीच) कार्यक्रमों का विस्तार करने का भी सुझाव दिया।

अपने भारत दौरे के दौरान उन्होंने पांडिचेरी विश्वविद्यालय के यूनेस्को मदनजीत सिंह दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संस्थान (यूएमआईएसएआरसी) में भी अपने विचार प्रस्तुत किए जो दक्षिण एशियाई अध्ययन का एक अहम केंद्र है। उन्होंने आरआईएस के सहयोग से आयोजित '21वीं सदी में गांधी की प्रासंगिकता' विषय पर व्याख्यान दिया। राजदूत सुकलाल ने महात्मा गांधी एवं नेल्सन मंडेला के जीवन में समानताओं का उल्लेख किया और इसके साथ ही यह भी बताया कि अहिंसा, सत्य एवं सतत विकास सहित उनके सिद्धांत और दर्शन आज भी किस तरह से प्रासंगिक हैं। उन्होंने गांधी एवं मंडेला के सिद्धांतों के साथ–साथ वसुधैव

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

कुटुम्बकम (पूरा विश्व एक परिवार है) और उबंटू ('मैं हूं क्योंकि हम हैं' या साझाकरण के सार्वभौमिक बंधन में विश्वास जो पूरी मानवता को जोड़ता है) पर भी आधारित एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने 2 फरवरी 2019 को अहमदाबाद में 'गांधी मंडेला विरासत' विषय पर व्याख्यान दिया जिसे गुजरात विकास अनुसंधान संस्थान और गुजरात विद्यापीठ ने संयुक्त रूप से आयोजित किया। इसके अलावा, उन्होंने 28 जनवरी 2019 को 'अफ्रीका में भारत और दक्षिण अफ्रीका' विषय पर भी व्याख्यान दिया जिसे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू, नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा की निर्वाचित अध्यक्ष माननीया सुश्री मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गार्सेस के साथ संवादात्मक सत्र

73वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की निर्वाचित अध्यक्ष माननीया सुश्री मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गार्सेस के साथ एक संवादात्मंक सत्र 11 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम आरआईएस, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और दिल्ली हाट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने सभी का स्वागत किया। डॉ. विधु पी. नायर, निदेशक (यूएनपी), विदेश मंत्रालय ने आरंभिक भाषण दिया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत का संचालन भी किया। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित प्रतिभागी ये थेः डॉ. बिंदेश्वर पाठक, संस्थापक, सुलभ स्वच्छता एवं सामाजिक सुधार आंदोलन; सुश्री सुनंदा के. रेड्डी, अध्यक्ष एवं परामर्शदाता, केयरनिधि; सुश्री मीनु वाडेरा, कार्यकारी निदेशक, आज़ाद फाउंडेशन; सुश्री कविता और श्री गौरव चौहान, नवधान्य; और सुश्री स्नेहा डे, गूंज। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा की निर्वाचित अध्यक्ष माननीया सुश्री मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गार्सेस ने विशेष भाषण दिया। इस अवसर पर आरआईएस ने प्रतिष्ठित मेहमानों को सतत विकास लक्ष्य पर अपना विशेष खंड 'भारत और सतत विकास लक्ष्यः आगे की राह' भी पेश किया। डॉ. बीना पांडे, रिसर्च एसोसिएट, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

भारत और सतत विकास लक्ष्यः आगे की राह' पर विशेष सतत विकास लक्ष्य खंड 73वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की निर्वाचित अध्यक्ष माननीया सुश्री मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गार्सेस को पेश किया गया।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

सतत विकास लक्ष्य 2: 'सभी के लिए स्वस्थ भोजन सुनिश्चित करने हेतु टिकाऊ कृषि और किसानों की आय दोगुनी करना'–पर हितधारक कार्यशाला

आरआईएस सितंबर 2015 में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के उद्भव और उन्हें अपनाए जाने की प्रक्रिया के बाद से ही निरंतर इन लक्ष्यों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा रहा है। सतत विकास लक्ष्य के प्रमुख कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आरआईएस विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया में सतत विकास लक्ष्य के एजेंडे के प्रभावकारी कार्यान्वयन में जुटा रहा जिसके तहत सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। आरआईएस ज्ञान साझेदारियों को मजबूत करने के लिए सतत विकास लक्ष्य से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर भारत में प्रमुख प्रबुद्ध मंडलों (थिंक–टैंक) और संगठनों के साथ भी सहयोग कर रहा है। भारत सरकार का नीति आयोग भारत में सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन में समन्वय और अगुवाई करने की दृष्टि से नोडल एजेंसी है। नीति आयोग, आरआईएस और संयुक्त राष्ट्र भारत द्वारा कई राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य परामर्श संयुक्त रूप से आयोजित किए गए; जिसमें विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन के साथ–साथ सतत विकास लक्ष्य के साथ तालमेल बैठाने और सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, ताकि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानकों को प्रभावकारी ढंग से बेहतर किया जा सके।

इस श्रृंखला में 8 मई 2018 को नई दिल्ली में 'सभी के लिए स्वस्थ भोजन सुनिश्चित करने हेतु टिकाऊ कृषि और किसानों की आय दोगुनी करना – सतत विकास लक्ष्य 2 के रोडमैप फ्रेमवर्क' पर एक दिवसीय हितधारक कार्यशाला आयोजित की गई। शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, सिविल सोसायटी संगठनों, केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, संयुक्त राष्ट्र संगठनों/निकायों के प्रोफेशनलों ने भारतीय संदर्भ में सतत विकास लक्ष्य 2 की प्राप्ति की दिशा में अपनी आकांक्षाओं और प्रतिबद्धताओं को साझा किया। डब्ल्यूएफपी के सहयोग से आरआईएस द्वारा पेश की गई 'सतत विकास लक्ष्य 2 रोडमैप फ्रेमवर्क ' नामक रिपोर्ट भी इस अवसर पर विमोचित की गई।

कार्यक्रम का आरम्भ नीति आयोग के सलाहकार डॉ. अशोक कुमार जैन के स्वागत भाषण के साथ हुआ। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने संदर्भ प्रस्तुत किया। डॉ. हमीद नुरु, प्रतिनिधि और कंट्री डायरेक्टर, डब्ल्यूएफपी ने आरंभिक भाषण दिया। भारत में संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक और यूएनडीपी के निवासी

भारत सरकार के नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार मुख्य भाषण देते हुए।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

प्रतिनिधि श्री यूरी अफानासीव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। डॉ. राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग, भारत सरकार ने मुख्य भाषण दिया। डॉ. पी. के. आनंद, विजिटिंग फेलो, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया। विस्तृत एजेंडा आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

'सतत विकास लक्ष्यों' के लिए दक्षिण एशिया एकजुट

आरआईएस ने संयुक्त राष्ट्र एस्कैप और नीति आयोग के साथ साझेदारी में 4–5 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में सतत विकास लक्ष्यों पर दक्षिण एशिया फोरम सतत विकास पर एशिया–प्रशांत फोरम (एपीएफएसडी) के लिए उप.क्षेत्रीय तैयारी बैठक आयोजित की।

बैठक का उद्देश्य वर्ष 2019 के आरंभ में बैंकॉक में आयोजित होने वाले सतत विकास पर छठे एशिया–प्रशांत फोरम (एपीएफएसडी) के लिए उप–क्षेत्रीय दृष्टिकोण और संबंधित जानकारियां प्रदान करना था। इस दिशा में आगे की कार्यवाही के साथ.साथ सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के 2030 एजेंडे को लागू करने में हासिल उपलब्धियों की समीक्षा करने की दृष्टि से प्रमुख प्लेटफॉर्म होने के नाते एपीएफएसडी दरअसल संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और महासभा दोनों के ही संदर्भ में सतत विकास पर उच्च.स्तरीय राजनीतिक फोरम (एचएलपीएफ) की तैयारियों में आवश्यक सहयोग देता है।

फोरम का शुभारंभ डॉ. नागेश कुमार, निदेशक एवं प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र एस्कैप के दक्षिण और दक्षिण–पश्चिम एशिया कार्यालय (संयुक्त राष्ट्र एस्कैप–एसएसडब्ल्यूए); प्रो.सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस); श्री यूरी अफानासीव, संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक, भारत और डॉ.इस्माइल रहीमी, माननीय उप अर्थव्यवस्था मंत्री, अफगानिस्तान के स्वागत भाषणों के साथ हुआ। डॉ. पुष्पा राज कदेल, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय योजना आयोग, नेपाल ने मुख्य भाषण दिया। डॉ. राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग, भारत ने उद्घाटन भाषण दिया।

बैठक में दौरान इन विषयों पर सत्र आयोजित किए गएः दक्षिण एशिया में 2030 एजेंडे के कार्यान्वयन में प्रगति एवं उपलब्धियों की समीक्षा; दक्षिण एशिया में एचएलपीएफ 2019 के लिए चयनित लक्ष्यों की समीक्षा; दक्षिण एशिया में एचएलपीएफ 2019 के लिए चयनित लक्ष्यों की समीक्षा : कार्य समूहों द्वारा कार्य प्रगति के बारे में सूचना देना एवं आगे की राह; 2019 में एपीएफएसडी और एचएलपीएफ की थीम 'लोगों का सशक्तिकरण और समावेशन एवं समानता सुनिश्चित करने' पर उप क्षेत्रीय दृष्टिकोण; दक्षिण एशिया में सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन के साधनः वित्त, प्रौद्योगिकी, और क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण कमियों की पहचान करना (एसडीजी 17); दक्षिण एशिया में सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन के साधनः संकेतक, डेटा, आंकड़े एवं आगे की कार्यवाही तथा समीक्षा (एसडीजी 17); सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में तेजी के लिए क्षेत्रीय सहयोग; संपन्नं करना और समापन सत्रः आगे की राह। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत के विशेषज्ञों ने बड़ी संख्या में विचार–विमर्श में भाग लिया।

'एचएलपीएफ, 2018' में आरआईएस की भागीदारी

आरआईएस के एक प्रतिनिधिमंडल ने 10–13 जुलाई, 2018 के दौरान न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम (एचएलपीएफ), 2018 की बैठकों में भाग लिया। इस प्रतिनिधिमंडल में महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी और सहायक प्रोफेसर डॉ. सब्यसाची साहा शामिल थे। आरआईएस के प्रतिनिधिमंडल ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी की अगुवाई वाले भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल और संयुक्त राष्ट्र भारत के प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त रूप से एचएलपीएफ की बैठकों में भाग लिया। इस यात्रा के एक हिस्से के रूप में भारत और वैश्विक स्तर पर विशेषकर विकासशील देशों में सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए आरआईएस के प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन और संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट की। इसने आरआईएस को वर्ष 2015 में हुए सतत विकास शिखर सम्मेलन और वर्ष 2017 में एचएलपीएफ के दौरान ठीक इसी तरह की सहभागिता को जारी रखते हुए इन एजेंसियों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने का अवसर दिया।

आरआईएस ने इन विषयों पर आयोजित एचएलपीएफ की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठकों में भाग लिया : 'सतत विकास

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

भारत की माननीया विदेश मंत्री दसवें दिल्ली संवाद के दौरान आसियान के सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ उपस्थित हैं।

लक्ष्य के कार्यान्वयन की समीक्षाः सतत विकास लक्ष्य 11 – शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, सुदृढ़ एवं टिकाऊ बनाना' और 'सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन की समीक्षाः सतत विकास लक्ष्य 17 – कार्यान्वयन के साधनों को सुदृढ़ बनाना और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी में नई जान फूंकना।' आरआईएस की टीम ने 'विकास के लिए वित्त पोषणः प्रगति और संभावनाएं 2018' पर अलग से आयोजित की गई एक बैठक में भी भाग लिया। आखिर में, आरआईएस के महानिदेशक ने 13 जुलाई 2018 को दक्षिणीय सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में अलग से आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया जिसका विषय था 'सतत विकास लक्ष्य के दौर में दक्षिणीय सहयोग के प्रभाव को अंकित करना।'

आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने उपर्युक्त संलग्नताओं के अलावा 14 जुलाई 2018 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन सहित आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी के सम्मान में और संयुक्त राष्ट्र एवं उससे परे साझेदार एजेंसियों के लिए न्यूयॉर्क में रात्रिभोज की मेजबानी की, ताकि विभिन्न देशों के साझेदार संस्थानों और संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों में सतत विकास लक्ष्य पर सहभगिता के दायरे को व्यापक बनाया जा सके।

उच्च स्तरीय भोज में भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी; संयुक्त राष्ट्र महासभा की निर्वाचित अध्यक्ष माननीया सुश्री मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा गार्सेस; संयुक्त राष्ट्र हैबिटैट की कार्यकारी निदेशक सुश्री मईमुना मोहम्मद शरीफ; प्रो. अरविंद पनगढ़िया, कोलंबिया विश्वविद्यालय; संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत एवं स्थायी प्रतिनिधि राजदूत सैयद अकबरुद्दीन; संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत तन्मय लाल; भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक श्री यूरी अफानासीव; दक्षिणीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक श्री जॉर्ज चेडीक; राजदूत लक्ष्मी पुरी इत्यादि ने शिरकत की। भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न विकासशील देशों के राजदूत/स्थायी प्रतिनिधि और संयुक्त राष्ट्र के अन्य प्रभागों के प्रमुख/प्रतिनिधि भी इस भोज में मौजूद थे।

दसवां दिल्ली संवाद : भारत–आसियान समुद्री सहयोग को सुदृढ़ बनाना

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस), आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी), नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन (एनएमएफ), नई दिल्ली; आसियान सचिवालय, जकार्ता; आसियान और पूर्वी एशिया के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान (ईआरआईए), जकार्ता के साथ साझेदारी में नई दिल्ली में 19–20 जुलाई 2018 को दिल्ली संवाद का 10वां संस्करण आयोजित किया। 10वें दिल्ली संवाद का विषय 'भारत–आसियान समुद्री सहयोग को सुदृढ़ बनाना' था। भारत की माननीया विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) और श्री एम. जे. अकबर ने क्रमशः मंत्रिस्तरीय और विशेष पूर्ण

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

सत्रों में मुख्य भाषण दिए। राजदूत प्रीति सरन, सचिव (पूर्व) ने उद्घाटन भाषण दिया और आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। आसियान के सदस्य देशों के कई वरिष्ठ मंत्रियों सहित लगभग 300 प्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों, प्रतिष्ठित विद्वानों, प्रोफेशनलों राजनयिकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, कारोबारियों, व्यावसायिक संघों इत्यादि ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

दिल्ली संवाद का 10वां संस्करण दो दिवसीय आयोजन था, जिसमें पूर्ण एवं विशेष पूर्ण सत्र के अलावा एक मंत्रिस्तरीय सत्र भी शामिल था। पूर्ण सत्र में आसियान–भारत साझेदारी के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं सहित प्रमुख विषयों जैसे कि संपर्क, कॉमर्स और कल्चर (3सी) को शामिल किया गया। विशेष पूर्ण सत्र में भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विशेष भाषण के साथ भारत के विदेश राज्य मंत्री ने मुख्यं भाषण दिया। मंत्रिस्तरीय सत्र में भारत की विदेश मंत्री का मुख्य भाषण शामिल था और इसके साथ ही आसियान के प्रत्येक सदस्य देश और आसियान सचिवालय के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख के विशेष भाषण भी शामिल थे। पूर्ण सत्रों में शामिल प्रमुख विषय ये हैंः आसियान के साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी में पूर्वोत्तर की भूमिका, सामाजिक–सांस्कृतिक संपर्कों को सुदृढ़ बनाना, भारत–आसियान साझेदारी एवं उभरती वैश्विक व्यवस्था, समुद्री सहयोगः भारत–आसियान साझेदारी के लिए एक नई रूपरेखा, आसियान–भारत व्यापार, निवेश एवं प्रौद्योगिकी, विकास सहयोग, एसएमई और क्षेत्रीय विकास, पर्यटन सहयोग और स्मार्ट सिटी का निर्माण।

'दसवां दिल्ली संवाद' समापन सत्र के साथ समाप्त हो गया जिस दौरान 'आगे की राह' पर फोकस किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता आरआईएस के चेयरमैन राजदूत मोहन कुमार ने की। भारत में थाईलैंड के राजदूत श्री चुटिन्टॉर्न गोंगस्की ने विशेष भाषण दिया। भारत के आवास एवं शहरी मामलों के माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने भी विशेष भाषण दिया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद ज्ञापन किया।

नीली अर्थव्यवस्था पर दूसरी आसियान–भारत कार्यशाला

विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय (एमएफए), वियतनाम; आसियान सचिवालय, जकार्ता; आसियान एवं पूर्वी एशिया के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान (ईआरआईए), जकार्ता; नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन (एनएमएफ), नई दिल्ली और आरआईएस, नई दिल्ली स्थित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) के साथ मिलकर संयुक्त

राजदूत मोहन कुमार, चेयरमैन, आरआईएस और राजदूत प्रीति सरन, सचिव (पूर्व) प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ उपस्थित हैं।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

रूप से 18 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) पर दूसरी आसियान–भारत कार्यशाला का आयोजन किया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। ईआरआईए के अध्यक्ष प्रो. हिदेतोशी निशिमुरा और भारत में वियतनाम के राजदूत माननीय श्री टोन सिन्ह थान्ह ने आरंभिक भाषण दिए। राजदूत प्रीति सरन, सचिव (पूर्व), एमईए ने मुख्य भाषण दिया। कार्यशाला में आसियान के प्रत्येक सदस्य देश के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख, आसियान एवं भारत के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया।

इस कार्यशाला का उद्देश्य न्हा ट्रांग, वियतनाम में 24–25 नवंबर 2017 को ब्लू इकोनॉमी पर आयोजित की गई प्रथम आसियान–भारत कार्यशाला में हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाना और आसियान–भारत रणनीतिक साझेदारी के एक प्रमुख पहलू के रूप में समुद्री क्षेत्र में आसियान–भारत सहयोग में प्रगति करने संबंधी राजनेताओं के विजन को साकार करने की दिशा में हो रहे प्रयासों को आगे बढ़ाना था। कार्यशाला के आखिर में चिन्हित की गई विशिष्ट गतिविधियां और क्षेत्र, जिनमें आसियान एवं भारत आपस में मिलकर काम कर सकते हैं, उस आधार के रूप में काम करेंगे जिन पर आसियान और भारत इस सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए कार्य योजना विकसित कर सकते हैं। कार्यशाला के निष्कर्ष के बारे में जानकारी 'दसवें दिल्ली संवाद' के मंत्रिस्तरीय सत्र के दौरान दी गई जिसका आयोजन 19–20 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में किया गया था। कार्यशाला को चार सत्रों में विभाजित किया गया था, ताकि उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने के लिए ब्लू इकोनॉमी पर गहन चर्चा संभव हो सके जिनमें आसियान और भारत आपस में सहयोग कर सकते हैं और साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ये चार सत्र इन विषयों पर आयोजित किए गए थेः नीली अर्थव्यवस्था एवं समुद्री संपर्क; नीली अर्थव्यवस्था के लिए मददगार प्रौद्योगिकी; नीली अर्थव्यवस्था का विकास एवं समुद्री सुरक्षा व कूटनीति, और नीली अर्थव्यवस्था।

आखिर में, समापन सत्र के दौरान भारत में वियतनाम के राजदूत माननीय श्री टोन सिन्ह थान्ह ने समापन भाषण दिया। श्री अनुराग भूषण, संयुक्त सचिव (आसियान एमएल), विदेश मंत्रालय ने समापन सत्र को संबोधित किया, जबकि डॉ. प्रबीर डे, एआईसी के समन्वयक ने कार्यशाला का सार प्रस्तुत किया और इसके साथ ही धन्यवाद ज्ञापन किया।

समुद्री सुरक्षा और सहयोग पर तीसरा 'ईएएस'

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (एमईए) ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमपी और एनजी), भारत सरकार; राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन (एनएमएफ); और आरआईएस स्थित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) के सहयोग से 8–9 जून 2018 को ओडिशा के भुवनेश्वर में समुद्री सुरक्षा एवं सहयोग पर तीसरा 'पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस)' का आयोजन किया। इस अवसर पर स्वागत भाषण आरआईएस स्थित एआईसी के समन्वयक डॉ. प्रबीर डे ने दिया। प्रारंभिक भाषण एनएमएफ के निदेशक वाइस एडमिरल प्रदीप चौहान ने दिया, जबकि विशेष भाषण श्री अनुराग भूषण, संयुक्त सचिव (आसियान–एमएल) ने दिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान,

श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, श्री अनुराग भूषण, संयुक्त सचिव (आसियान–एमएल), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और वाइस–एडमिरल प्रदीप चौहान, निदेशक, एनएमएफ समुद्री सुरक्षा एवं सहयोग पर आयोजित तीसरे ईएएस सम्मेलन के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करते हुए।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

बाएं से दाएं: श्री रवि कपूर, असम सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गुवाहाटी; श्री राम मुइवा, सचिव, एनईसी; श्री नवीन वर्मा, सचिव, डोनर मंत्रालय; सुश्री ममता शंकर, आर्थिक सलाहकार, डोनर मंत्रालय; डॉ. प्रबीर डे, आरआईएस स्थित एआईसी; भारत में थाईलैंड के राजदूत माननीय श्री चुटिनटॉर्न गांगसाकडी।

माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, भारत सरकार ने उद्घाटन भाषण दिया।

ईएएस से जुड़े सदस्य देशों ने अपने यहां से अधिकारियों और विशेषज्ञों को नामांकित किया। इस दो दिवसीय सम्मेलन में लगभग 55 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन को पांच सत्रों में विभाजित किया गया, ताकि समुद्री सुरक्षा, समुद्री हिफाजत, समुद्र में सुव्यवस्था एवं नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) पर गहन चर्चा के साथ–साथ आगे की राह पर पैनल परिचर्चा भी संभव हो सके। आखिर में, श्री अनुराग भूषण, संयुक्त सचिव (आसियान–एमएल), एमईए ने समापन भाषण दिया और डॉ. प्रबीर डे ने धन्यवाद भाषण दिया। प्रतिनिधियों ने 8 जून 2018 को आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया और इसके साथ ही उन्होंने ओडिशा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से वाकिफ होने के लिए 9 जून 2018 को धौली एवं कोणार्क की शोध यात्राएं भी की थीं।

'एक्ट ईस्ट' और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नीतिगत संवाद

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) ने विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) स्थित आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) के सहयोग से 28 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में 'एक्ट ईस्ट' और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नीतिगत संवाद का आयोजन किया। स्वागत भाषण सुश्री ममता शंकर, आर्थिक सलाहकार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर), भारत सरकार द्वारा दिया गया। श्री राम मुइवा, सचिव, एनईसी और श्री रवि कपूर, असम सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गुवाहाटी ने उद्घाटन सत्र के दौरान विशेष भाषण दिए। मुख्य भाषण भारत में थाईलैंड के राजदूत माननीय श्री चुटिनटॉर्न गांगसाकडी द्वारा दिया गया, तथा श्री नवीन वर्मा, सचिव, डोनर ने उद्घाटन भाषण दिया।

आरआईएस स्थित एआईसी में प्रोफेसर डॉ. प्रबीर डे ने 'एक्ट ईस्ट' और 'दक्षिण–पूर्व एशिया के साथ पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक एकीकरण' पर मुख्य प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति के बाद पूर्वोत्तर भारत और भारत के पूर्वी पड़ोस के बीच रणनीतिक एवं आर्थिक संबंधों, इसकी चुनौतियों और आगे की राह पर एक पैनल परिचर्चा हुई। सत्र की अध्यक्षता डॉ. रामगोपाल अग्रवाल, प्रतिष्ठित फेलो, नीति आयोग ने की। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के भारतीय निवासी मिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री केनिची योकोयामा ने विशेष भाषण दिया। इस सत्र के पैनल सदस्यों में ये शामिल थे : श्री एम.पी.बेजबरुआ, पूर्व सदस्य, एनईसी एवं भारत सरकार के सचिव (पर्यटन); सुश्री प्रिया माथुर, सलाहकार, विश्व बैंक; राजदूत गौतम मुखोपाध्याय, म्यांमार में भारत के पूर्व राजदूत; डॉ. प्रियरंजन सिंह, प्रोफेसर, मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल; डॉ. गुरुदास दास, प्रोफेसर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) सिल्चर; और श्री सब्यसाची दत्ता, निदेशक, एशियन कॉन्फ्लूएन्स, शिलांग। आखिर में समापन सत्र में

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

श्री बिमान दत्ता, सदस्य, एनईसी द्वारा समापन भाषण दिया गया, तथा सुश्री ममता शंकर, आर्थिक सलाहकार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया।

आसियान–भारत गैर–टैरिफ उपायों (एनटीएम) पर संगोष्ठी

आरआईएस स्थित आसियान–इंडिया सेंटर (एआईसी) ने 20 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली, भारत में आसियान इंडिया गैर–टैरिफ उपायों (एनटीएम) पर एक सेमिनार आयोजित किया। इस सेमिनार का आयोजन दरअसल आसियान और भारत के बीच एनटीएम पर एआईसी द्वारा किए गए शोध अध्ययन का नतीजा था। स्वागत भाषण डॉ. प्रबीर डे, प्रोफेसर, आरआईएस और समन्वयक, आरआईएस स्थित एआईसी द्वारा दिया गया। आरंभिक भाषण श्री अनुराग भूषण, संयुक्त सचिव (आसियान–एमएल), विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार द्वारा दिया गया। अध्ययन पर प्रस्तुति डॉ. प्रबीर डे और डॉ. दुरइराज कुमारसामी दोनों ही द्वारा दी गई। प्रस्तुतियों के लिए टिप्पणियां श्री प्रणव कुमार, प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं नीति प्रभाग, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और डॉ. अनिल जौहरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी), नई दिल्ली से प्राप्त हुईं। अंत में, डॉ. प्रबीर डे ने अध्ययन का सार प्रस्तुत किया और धन्यवाद ज्ञापन किया। संगोष्ठी में सरकारी अधिकारियों, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों, उद्योग विशेषज्ञों, शोध विद्वानों इत्यादि ने भाग लिया।

युवा राजनयिक कॉन्क्लेव: 'भारत–आसियान संबंधों को और मजबूत करना'

आरआईएस ने विजन इंडिया फाउंडेशन (वीआईएफ) के साथ मिलकर 17 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में 'युवा राजनयिक कॉन्क्लेव 2.0– भारत–आसियान संबंधों को और मजबूत करने' पर सम्मेलन का आयोजन किया। राजदूत ए.के. बनर्जी, आईएफएस (सेवानिवृत्त) और प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने आरंभिक भाषण दिए। 'हिंद–प्रशांत में क्षेत्रीय संरचना को सार्थक स्वरूप प्रदान करने में भारत–आसियान संबंध की भूमिका' पर आयोजित प्रथम सत्र की अध्यक्षता राजदूत अमर सिन्हा, विशिष्ट फेलो, आरआईएस ने की। इस सत्र में श्री संजय पुलिपाका, सीनियर फेलो, एनएमएमएल ने 'हिंद–प्रशांत की गतिशीलता में आसियान की केंद्रीयता' विषय पर अपने विचार व्यक्त किए और प्रो. हर्ष वी. पंत, किंग्स कॉलेज लंदन ने एक रणनीतिक अवधारणा के रूप में 'चतुष्कोण (क्वाड)' के उद्भव पर संबोधित किया। 'भारत–आसियानः भिन्न, लेकिन संबंधित संस्कृतियों' विषय पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता सुश्री अरुणिमा गुप्ता, वीआईएफ ने की। इंडोनेशिया के दूतावास के राजदूत माननीय श्री सिद्धार्थो रेजा सूर्योदिपुरो ने 'पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाने के लिए अतीत के भारत–इंडोनेशिया संबंधों से लाभ उठाने' विषय पर भाषण दिया। डॉ. गौतम कुमार झा, जेएनयू ने 'भारत–आसियान के सभ्यतागत अंतर्संबंध विषय पर भाषण दिया। श्री राजीव

आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी 'युवा राजनयिक कॉन्क्लेव' में अपने विचार व्यक्त करते हुए।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

खेर, विशिष्ट फेलो, आरआईएस ने 'आरसीईपी और क्षेत्रीय आर्थिक संरचना–अवसर, चुनौतियां एवं आगे की राह' विषय पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता की। सीआईआई के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति प्रमुख श्री प्रणव कुमार ने 'आसियान के साथ सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने' विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। श्री शोभित माथुर, कार्यकारी निदेशक, वीआईएफ ने समापन भाषण दिया।

आसियान के एचओएम के साथ 'दिल्ली वार्तालाप 10' पर परामर्श बैठक

आरआईएस ने 14 मई, 2018 को आसियान के एचओएम के साथ 'दिल्ली वार्तालाप 10' पर एक परामर्श बैठक आयोजित की। आरआईएस के चेयरमैन राजदूत डॉ. मोहन कुमार ने परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। श्री अनुराग भूषण, संयुक्त सचिव (आसियान–एमएल), विदेश मंत्रालय (एमईए) ने स्वागत भाषण दिया। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने विशेष भाषण दिया। आरआईएस स्थित एआईसी के समन्वयक डॉ. प्रबीर डे ने 'दिल्ली वार्तालाप 10' पर एक प्रस्तुति दी। इसके बाद आसियान के एचओएम की ओर से टिप्पणियां प्राप्त हुईं। आखिर में डॉ. मोहन कुमार, चेयरमैन, आरआईएस ने सार प्रस्तुत किया और समापन भाषण दिया।

इंडोनेशिया के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

इंडोनेशिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने 19 अप्रैल, 2018 को राजदूत अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस और प्रो. प्रबीर डे, समन्वयक, एआईसी और उनकी टीम के साथ एक संवादात्मक सत्र के लिए आरआईएस स्थित एआईसी का दौरा किया। यह संवादात्मक सत्र भारत, इंडोनेशिया एवं म्यांमार के बीच व्यापार तथा समुद्री संपर्क को बढ़ावा देने और बंगाल की खाड़ी में क्षेत्रीय सहयोग की भूमिका के लिए सहयोग के अवसरों और संभावनाओं के बारे में था।

बिम्सटेक शिखर सम्मेलन पूर्व उच्च स्तरीय सलाहकार बैठक

आरआईएस ने रणनीतिक एवं सामाजिक–आर्थिक अनुसंधान संस्थान (आईएसएसआर) और पवेलियन ग्रुप के साथ मिलकर 2–3 अगस्त 2018 को काठमांडू में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन पूर्व उच्च स्तरीय सलाहकार बैठक आयोजित की। प्रोफेसर

नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री श्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली के साथ अनेक प्रतिभागी।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

डॉ. गोविंद नेपाल, कार्यवाहक अध्यक्ष, आईएसएसआर नेपाल ने बैठक की अध्यक्षता की। माननीय श्री प्रदीप कुमार ग्यावली, विदेश मंत्री, नेपाल इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे और उन्होंने उद्घाटन भाषण दिया। बाद में समूह ने नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री से भेंट की।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। बांग्लादेश की राजदूत सुश्री मैशफी बिनटे शम्स; भारत के राजदूत श्री मनजीव सिंह पुरी; श्रीलंका की राजदूत सुश्री डब्ल्यू. स्वर्णलता परेरा; म्यांमार के राजदूत श्री यू. टुन नेई लिन; श्रीलंका एवं मालदीव में नेपाल के राजदूत प्रोफेसर डॉ. बिश्वंभर पयाकुर्यल और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (बिम्सटेक एवं सार्क) श्री पीयूष श्रीवास्तव ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। सलाहकार बैठक की प्रमुख सिफारिशें 26 अगस्त 2018 को नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री श्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली को प्रस्तुत की गईं।

'आईओआरए और ब्रिक्स की दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षताः शिखर सम्मेलनों में उठाए गए मुद्दों' पर परिचर्चा

आरआईएस और पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने 4 अप्रैल 2018 को यूनेस्को मदनजीत सिंह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संस्थान, पांडिचेरी विश्वविद्यालय में 'आईओआरए और ब्रिक्स की दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षताः शिखर सम्मेलनों में उठाए गए मुद्दों' पर संयुक्त रूप से परिचर्चा आयोजित की।

प्रोफेसर गुरमीत सिंह, कुलपति, पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम से पहले डॉ. एस.के. मोहंती, प्रोफेसर, आरआईएस ने आरंभिक भाषण दिया। दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग विभाग के उप महानिदेशक डॉ. अनिल सुकलाल ने विशेष भाषण दिया। इसके बाद भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायोग के उच्चायुक्त माननीय डॉ. एन.मांजिनी; और श्री आलोक ए. डिमरी, संयुक्त सचिव (एमईआर), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने भाषण दिए। इसके पश्चात बातचीत का दौर चला। डॉ. ए. सुब्रमण्यम राजू, प्रमुख, दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र और समन्वयक, समुद्री अध्ययन के लिए यूजीसी केंद्र, पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

विज्ञान राजनय कार्यक्रम का शुभारंभ

हाल के दशकों में विज्ञान राजनय विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर कर सामने आई है। इसका उपयोग उन वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में किया गया है जिनमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समस्या की पहचान करने और उपयुक्त समाधान प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती है। विज्ञान राजनय विकास सहयोग के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अन्य देशों और समूहों के साथ सहयोग को गहन बनाने में सहायता कर रही है। आरआईएस ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (बेंगलुरू) के सहयोग से विज्ञान राजनय पर एक संयुक्त शोध कार्यक्रम शुरू किया

विज्ञान राजनय कार्यक्रम के शुभारंभ का उद्घाटन सत्र

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

है जिसमें भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की ओर से भी समर्थन प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 7 मई 2018 को नई दिल्ली में किया गया था।

आरआईएस के चेयरमैन राजदूत डॉ. मोहन कुमार ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने परियोजना की एक रूपरेखा प्रस्तुत की। श्री टी. एस. तिरुमूर्ति, सचिव (ईआर), विदेश मंत्रालय ने मुख्य भाषण दिया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और एसएंडटी मंत्रालय में सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने उद्घाटन भाषण दिया। प्रोफेसर डी. सुबा चंद्रन, अंतर्राष्ट्रीय रणनीति एवं सुरक्षा अध्ययन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (एनआईएएस), बेंगलुरू ने धन्यवाद ज्ञापन किया। विस्तृत एजेंडे को हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

भारतीय विज्ञान राजनय के लिए मंच

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के सहयोग से विज्ञान राजनय पर आरआईएस–एनआईएएस के संयुक्त कार्यक्रम के तहत 'भारतीय विज्ञान राजनय के लिए फोरम (एफआईएसडी)' को 4 अक्टूबर, 2018 को लांच किया गया। एफआईएसडी ज्ञान साझा करने के लिए वैज्ञानिकों, राजनयिकों, रणनीतिक विचारकों, नीति निर्माताओं, कारोबारियों और विज्ञान राजनय के विभिन्न पहलुओं में शामिल विद्वानों के बीच एक संपर्क बिंदु (इंटरफेस) बनाने के लिए प्रयासरत है। यह फोरम भारतीय परिप्रेक्ष्य और विश्व के विकासशील देशों की दृष्टि से विज्ञान राजनय को सिद्धांत एवं व्यवहार में फिर से परिभाषित करने का प्रयास कर रहा है। समावेशी, सतत और सामाजिक दृष्टि से उत्तरदायी विकास सुनिश्चित करने में विज्ञान राजनय की महत्वपूर्ण भूमिका है। एफआईएसडी के तहत कुछ मौजूदा गतिविधियों में ये शामिल हैं : विज्ञान राजनय पर आरआईएस–एनआईएएस का संयुक्त कार्यक्रम; विज्ञान राजनय पर आरआईएस–आईटीईसी पाठ्यक्रम; विज्ञान राजनय एवं उत्तरदायी अनुसंधान व नवाचार (आरआरआई) के साथ–साथ आरआईएस में अन्य गतिविधियां जैसे कि ब्लू इकोनॉमी फोरम (बीईएफ), भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पर फोरम (एफआईटीएम) और विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति (एसटीआईपी) फोरम।

एफआईएसडी के पास एक समर्पित वेबसाइट (www.fisd.in) है, जो संयुक्त विज्ञान राजनय कार्यक्रम की विविध गतिविधियों और प्रदेय वस्तुओं या उत्पादों को प्रदर्शित करती है। यह फोरम नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और विज्ञान राजनय में जुटे प्रोफेशनलों के सहयोग से सृजित संसाधनों को साझा करता है। यह फोरम भारत और अन्य विकासशील देशों के वैज्ञानिकों एवं राजनयिकों के लिए क्षमता निर्माण से जुड़ी पहल करेगा। इसके अलावा, यह फोरम भारतीय विज्ञान राजनय से संबंधित मुद्दों पर चर्चाएं करने के लिए व्याख्यान, सेमिनार, अनुसंधान एवं परामर्श से जुड़ी गतिविधियां आयोजित करेगा।

'रिवार्ड प्रोजेक्ट' पर बैठक

आरआईएस यूरोपीय अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित 'रिवार्ड प्रोजेक्ट' में एक साझेदार संस्थान है। वर्ष 2014 में शुरू हुई परियोजना वर्ष 2019 में समाप्त हो जाएगी। इस परियोजना के एक घटक के रूप में वित्त पोषण करने वाली एजेंसी ने 'सूचना विज्ञान और गैर–चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मचारियों का उपयोग करके केरल में हृदय रोग की द्वितीयक रोकथाम के लिए स्वास्थ्य प्रणाली सीखना (एलएचएससीवीडी)' पर अध्ययन को मंजूरी दी है। यह एक वर्ष के लिए है।

अध्ययन की समीक्षा करने के लिए 16 दिसंबर 2018 को केरल के कुमारकोम में इस परियोजना पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत आरआईएस के

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस 'रिवार्ड प्रोजेक्ट' की बैठक में स्वागत भाषण देते हुए।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण से हुई। प्रोफेसर थॉमस पोगे, दर्शन शास्त्र एवं अंतरराष्ट्रीय मामलों के लीटनर प्रोफेसर, येल विश्वविद्यालय; डॉ. मिल्टोस लादिका, सेंटर फॉर प्रोफेशनल एथिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंकाशायर ने 'रिवार्ड प्रोजेक्ट' पर प्रस्तुति दी। डॉ. के. रवि श्रीनिवास, सलाहकार, आरआईएस ने एक प्रस्तुति दी। इसके बाद 'केरल अध्ययन एवं अब तक हुई प्रगति व अगले कदम और प्रदेय उत्पादों (डिलिवरेबल्स)' पर एक प्रस्तुति डॉ. जयदीप सी मेनन, प्रमुख, निवारक कार्डियोलॉजी, अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने दी। यही नहीं, डॉ. मिल्टोस लादिका, सेंटर फॉर प्रोफेशनल एथिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंकाशायर ने 'जीनोम एडिटिंग में व्यापक रुझानः चीन से उभरते अनुभव' विषय पर डिनर के दौरान व्याख्यान भी दिया। प्रोफेसर थॉमस पोगे, दर्शन शास्त्र एवं अंतरराष्ट्रीय मामलों के लीटनर प्रोफेसर, येल विश्वविद्यालय और डॉ. वसंत मुथुस्वामी, पूर्व वरिष्ठ उप महानिदेशक, आईसीएमआर एवं अध्यक्ष, एफईआरसीआई (भारत में आचारनीति समीक्षा समितियों के लिए फोरम) इस अवसर पर प्रतिभागी थे।

नए नैदानिक परीक्षण नियम, 2018 के मसौदे पर हितधारक परामर्श

आरआईएस के नीतिगत अनुसंधान के तहत यह जानने की कोशिश की जा रही है कि कैसे उभरता भारत अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने, उत्पादन श्रृंखला को आगे बढ़ाने और अपनी अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी का विस्तार करने के लिए वैश्विक मंच पर अपनी तुलनात्मक बढ़त से लाभ उठा सकता है। इसके मद्देनजर आरआईएस ने मसौदा नियमों पर हितधारकों के विचारों से अवगत होने के लिए 7 अप्रैल 2018 को नए नैदानिक परीक्षण नियम, 2018 के मसौदे पर एक पूर्ण दिवस विशेषज्ञ परामर्श का आयोजन किया, ताकि पिछले संशोधनों और देश में नैदानिक परीक्षणों पर इन परिवर्तनों के असर को ध्यान में रखते हुए इन नियमों की जांच एवं आकलन करने के साथ–साथ उन पर चर्चा भी की जा सके।

इस तरह के परामर्श का आयोजन अपने–आप में अनूठा था। इस आयोजन से शैक्षणिक क्षेत्र, उद्योग जगत, निजी एवं सार्वजनिक अनुबंध अनुसंधान संगठनों, नैतिकता समितियों, मीडिया और सरकार की ओर से विविध हितधारकों को एक मंच पर लाना संभव हो पाया। इससे चर्चा के दौरान मौजूद विभिन्न प्रतिभागियों की ओर से विभिन्न दृष्टिकोणों को साझा करने और आदान–प्रदान करने में मदद मिली। दिन भर चले परामर्श को चार तकनीकी सत्रों में बांट कर मसौदा नियम, 2018 के बुनियादी पहलुओं को कवर किया गया। इनमें डेटा सृजन, डेटा उपलब्धता एवं पारदर्शिता, सामंजस्य के मुद्दे, क्षमता निर्माण, अकादमिक एवं उद्योग अनुसंधान संवाद (इंटरफेस), अच्छी नैदानिक एवं प्रयोगशाला प्रथाएं, प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा जैसे पहलू शामिल थे।

इस परामर्श आयोजन का आरम्भ आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण के साथ हुआ। उद्घाटन भाषण प्रो. समीर ब्रह्मचारी, पूर्व महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने दिया। विशेष

नए नैदानिक परीक्षण नियम, 2018 के मसौदे पर आयोजित हितधारक परामर्श के दौरान अनेक हितधारक।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

परामर्श का उद्घाटन सत्र प्रगति पर।

भाषण प्रो. डी. प्रभाकरन, उपाध्यक्ष, भारतीय जन स्वास्थ्य फाउंडेशन (पीएचएफआई) और डॉ. नंदिनी एम कुमार, पूर्व उप महानिदेशक (सीनियर ग्रेड), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा दिए गए। प्रो. टी सी जेम्स, विजिटिंग फेलो, आरआईएस ने परामर्श के दौरान विचार–विमर्श किए जाने वाले मुद्दों को प्रस्तुत किया। अन्य वक्ताओं में ये शामिल थेः राजदूत सुधीर टी देवरे, अध्यक्ष, शोध सलाहकार परिषद, आरआईएस; डॉ. जाकिर थॉमस, पूर्व निदेशक (ओएसडीडी), सीएसआईआर; प्रोफेसर वैद्य के एस धीमान, महानिदेशक, सीसीआरएएस, आयुष मंत्रालय; डॉ. सरदिन्दु भादुड़ी, अध्यक्ष, सीएसएसपी, जेएनयू; डॉ. चिराग त्रिवेदी, अध्यक्ष, इंडियन सोसायटी फॉर क्लिनिकल रिसर्च; और श्री अशोक मदन, आईडीएमए। परामर्श का समापन आरआईएस की विजिटिंग फेलो डॉ. आभा जायसवाल के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। परामर्श के आधार पर आरआईएस ने मसौदे के नियमों पर बिंदुवार टिप्पणियां तैयार की हैं और इन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के समक्ष विचारार्थ पेश किया है।

भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के वैश्विक संवर्धन पर उद्योग परामर्श

भारतीय पारंपरिक चिकित्सा फोरम (एफआईटीएम) ने आयुष मंत्रालय और आरआईएस के सहयोग से 18 मई 2018 को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के वैश्विक संवर्धन पर उद्योग परामर्श का आयोजन किया। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य नीतिगत कदम संबंधी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए उद्योग जगत और सरकार के बीच संवाद सुनिश्चित करना था। पैनलिस्टों में उद्योग एवं शैक्षणिक जगत और भारत सरकार के मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल थे। परामर्श के दौरान चर्चाएं प्रतिभागियों के व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित थीं।

भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के वैश्विक संवर्धन के मार्ग में मौजूद चुनौतियों की पहचान करने और उपयुक्त समाधान ढूंढ़ने के लिए परामर्श के दौरान चार प्रमुख पैनल परिचर्चाएं आयोजित की गईं। घरेलू नीति एवं निर्यात को बढ़ावा देने पर नियामकीय तैयारियों की समीक्षा; अंतरराष्ट्रीय विनिर्माण मानकों के लिए उपाय एवं अधिक से अधिक वैज्ञानिक सत्यापन के जरिए गुणवत्ता आश्वासन तथा फार्माकोपिया मानकों का अभिदान; औषधीय पौधों के संग्रह एवं खेती सहित कच्चे माल की आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियां; और भारत एवं विदेश में चिकित्सकों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए वेलनेस उद्योग से जुड़े नियम तथा आईएसएम क्षेत्र पर द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संधि और समझौतों का असर इन परिचर्चाओं के विषयों में शामिल थे।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

स्वागत भाषण प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने दिया, भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के लिए विजन का अवलोकन श्री राजीव खेर, पूर्व वाणिज्य सचिव एवं प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस द्वारा प्रस्तुत किया गया और डॉ. आकाश तनेजा, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, डीजीएफटी ने मुख्य भाषण दिया। आयुष मंत्रालय के सलाहकार डॉ. मनोज नेसारी ने इस परामर्श का उद्घाटन किया। आयुष मंत्रालय में सचिव श्री वैद्य राजेश कोटेचा और आयुष मंत्रालय में अपर सचिव श्री प्रमोद कुमार पाठक भी इस परामर्श में शामिल हो गए। प्रो. टी.सी. जेम्स, विजिटिंग फेलो, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के वैश्विक संवर्धन के मार्ग में मौजूद चुनौतियों की पहचान करने और उपयुक्त समाधान ढूंढ़ने के लिए परामर्श के दौरान चार पैनल परिचर्चाएं आयोजित की गईं जिनमें उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। घरेलू नीति एवं निर्यात को बढ़ावा देने पर नियामकीय तैयारियों की समीक्षा; अंतरराष्ट्रीय विनिर्माण मानकों के लिए उपाय एवं अधिक से अधिक वैज्ञानिक सत्यापन के जरिए गुणवत्ता आश्वासन तथा फार्माकोपिया मानकों का अभिदान; औषधीय पौधों के संग्रह एवं खेती सहित कच्चे माल की आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियां; और भारत एवं विदेश में चिकित्सकों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए वेलनेस उद्योग से जुड़े नियम तथा आईएसएम क्षेत्र पर द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संधि और समझौतों का असर इन परिचर्चाओं के विषयों में शामिल थे। परामर्श के आधार पर सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए आयुष मंत्रालय को प्रस्तुत की गई।

भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देनाः चुनौतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं' पर क्षेत्रीय परामर्श

भारतीय पारंपरिक चिकित्सा फोरम (एफआईटीएम) ने 20 मार्च, 2019 को बेंगलुरू में "भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देनेः चुनौतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं' पर क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन किया था। आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने उद्घाटन भाषण दिया। उद्घाटन सत्र में : श्री राजीव खेर, पूर्व वाणिज्य सचिव एवं विशिष्ट फेलो, आरआईएस; डॉ. बी. आर. रामकृष्ण, कुलपति, एस–व्यास विश्वविद्यालय, बेंगलुरू; और श्री अरविन्द वर्चस्वी, प्रबंध निदेशक, श्री श्री तत्तव, बेंगलुरू विशेष वक्ता थे।

परामर्श के दौरान निम्न चार सत्र अलग–अलग विषयों पर आयोजित किए गए : 'उत्पाद मानक और गुणवत्ता आश्वासनः सफलता एवं चुनौतियां', 'गुणवत्तापूर्ण सेवाएंः मानकीकरण व्यवस्थाएं', 'भारतीय चिकित्सा प्रणालियों का अंतर्राष्ट्रीयकरणः घरेलू तैयारियों के लिए रणनीतियां साझा करना' और 'औषधीय पौधों का गवर्नेंसः संरक्षण और खेती में सर्वोत्तम प्रथाएं।'

परिचर्चा में मुख्य वक्ता थेः श्री प्रमोद कुमार पाठक, अपर सचिव, आयुष मंत्रालय; श्री सुधांशु पांडे, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डॉ. बालकृष्ण पिसुपति, अध्यक्ष एवं ट्रस्टी, कानून, पर्यावरण, विकास एवं गवर्नेंस के लिए फोरम (फ्लेज), बेंगलुरू, और श्रीमती मीनाक्षी नेगी, आयुक्त, आयुष विभाग, कर्नाटक। सरकारी अधिकारियों और शिक्षाविदों के अलावा बड़ी संख्या में उद्योग प्रतिनिधियों ने भी इस बैठक में भाग लिया था। विचार–विमर्श के दौरान आयुष क्षेत्र के समक्ष मौजूद चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया और इसके साथ ही कई ऐसे कदम भी सुझाए गए जिन्हें सरकार एवं उद्योग जगत को इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उठाने चाहिए। एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। परिचर्चा के समापन पर आरआईएस की रिसर्च एसोसिएट डॉ. नम्रता पाठक ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

भारत और वियतनाम पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग

वियतनाम अत्यंत लंबे समय से भारत का रणनीतिक साझेदार रहा है। यह सद्भावना एवं विश्वास हमारे बहुआयामी और बहु–क्षेत्रवार सहयोग में परिलक्षित होता है। यह सहयोग कई मुद्दों पर आधारित है जिसमें रक्षा और हिफाजत; व्यापार एवं वाणिज्य; विज्ञान और तकनीक; क्षमता निर्माण; स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन और लोगों का पारस्परिक आदान–प्रदान; और अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं उप–क्षेत्रीय फोरम शामिल हैं। इसे ध्यान में रखते हुए पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित क्षेत्रों में और अधिक तालमेल का पता लगाना आवश्यक है।

इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आरआईएस और एफआईटीएम ने वियतनाम के दूतावास के सहयोग से नई दिल्ली में 10 दिसंबर, 2018 को 'भारत और वियतनाम में पारंपरिक चिकित्सा' पर आधे दिन का सम्मेलन आयोजित

किया। आयुष मंत्रालय में अपर सचिव श्री प्रमोद कुमार पाठक इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस के स्वागत भाषण और सुश्री ट्रान क्विन्ह हयोंग, निदेशक, वियतनाम पत्रकारिता एवं सोशल मीडिया संस्थान के आरंभिक भाषण के साथ हुआ। भारत में वियतनाम के राजदूत माननीय श्री फाम सान्ह चाऊ ने विशेष भाषण दिया।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (स्टिप) फोरम व्याख्यान श्रृंखला

स्टिप फोरम व्याख्यान श्रृंखला के एक हिस्से के रूप में ज्ञान अर्थव्यवस्था के निर्माण में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर नौवां स्टिप व्याख्यान 19 जून 2018 को नई दिल्ली में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार एवं एसएसी–सी के अध्यक्ष प्रोफेसर के. विजय राघवन ने दिया। राजदूत भास्कर बालाकृष्णन, पूर्व भारतीय राजनयिक और विज्ञान राजनय फेलो, आरआईएस ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रोफेसर के. विजय राघवन 28 जनवरी, 2013 से 2 फरवरी, 2018 तक भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के सचिव थे। वह इंडियन साइंस एकेडेमिक्स, द रॉयल सोसायटी, द एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (यूके) के फेलो और यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के एक विदेशी एसोसिएट हैं। उन्हें वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

डॉ. भास्कर बालाकृष्णन आरआईएस में एक विज्ञान राजनय फेलो हैं। वह एक करियर राजनयिक रहे हैं और उन्होंने ग्रीस, क्यूबा, हैती एवं डोमिनिकन गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया है तथा इसके साथ ही उन्होंने सूडान, सीरिया, जाम्बिया और ऑस्ट्रिया में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। उन्होंने विदेश मंत्रालय के निवेश एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन प्रभाग की अध्यक्षता संभाली। जैसा कि पहले बताया गया था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (स्टिप) फोरम बनाया गया है। यह फोरम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की अंतर–संबद्ध ता को ध्यान में रखते हुए तय सीमाओं से परे जाकर काम करने में सक्षम है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रचार करने के साथ–साथ सामाजिक आकांक्षाओं की बहस को सामान्य बनाने और जिम्मेदार शोधों एवं नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और समाज के बीच की खाई को पाटना है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति पर सार्वजनिक बहस के प्रति जागरूक करने के लिए मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू की गई है। विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस), ऊर्जा संसाधन संस्थान (टेरी), विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (सीएसई), उन्नत अनुसंधान के संवर्धन के लिए भारत–फ्रांस क्रेंद्र (सीईएफआईपीआरए), विज्ञान प्रसार और भारत पर्यावास केंद्र (आईएचसी) सहयोगी संस्थान हैं।

प्रोफेसर के. विजय राघवन स्टिप व्याख्यान देते हुए।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

एसटीआईपी व्याख्यान श्रृंखला के तहत अनेक आयोजित कार्यक्रम

भारत में विज्ञान संबंधी अभियानों पर पैनल परिचर्चा 10 जनवरी 2019 को आयोजित की गई। प्रो. एम. जगदीश कुमार, कुलपति, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने इसकी अध्यक्षता की। पैनल के सदस्यों में शामिल थेः प्रो. वी. एन. राजशेखरन पिल्लई, स्वदेशी विज्ञान अभियान; डॉ. डी. रघुनंदन, ऑल इंडिया पीपुल्स साइंस नेटवर्क; प्रो. दिनेश अबरोल, दिल्ली विज्ञान मंच और श्री जयंत सहस्रबुद्धे, विभा।

'विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाजः लोगों तक पहुंचने की चुनौती' पर व्याख्यान 15 फरवरी 2019 को प्रो. एम. साईं बाबा, टी. वी. रमन पई, चेयर प्रोफेसर, राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान, बेंगलुरू द्वारा दिया गया। श्री गौहर रजा, अग्रणी विज्ञान संप्रेषक और पूर्व वैज्ञानिक, सीएसआईआर ने इसकी अध्यक्षता की।

'भारत में सौर ऊर्जा के विकास' पर व्याख्यान 12 मार्च 2019 को डॉ. अरुण कुमार त्रिपाठी, महानिदेशक, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) द्वारा दिया गया। इसकी अध्यक्षता डॉ. अश्विनी कुमार, वरिष्ठ निदेशक, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) ने की।

प्रोटीन कुपोषण से निपटने के लिए दाल क्रांति

'प्रोटीन कुपोषण से निपटने के लिए दाल क्रांति' पर ग्यारहवां एसटीआईपी फोरम व्याख्यान 7 अगस्त 2018 को कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग में सचिव और आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन मोहापात्रा ने दिया, तथा डॉ. राजेंद्र सिंह परोदा, पूर्व डीजी, आईसीएआर और अध्यक्ष, कृषि विज्ञान के विकास के लिए ट्रस्ट (टीएएएस) ने इसकी अध्यक्षता की। वर्तमान पदभार संभालने से पहले डॉ. मोहापात्रा प्रतिष्ठित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक–सह–कुलपति थे। इससे पहले वह राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (पूर्व में सीआरआरआई), कटक के निदेशक के पद पर कार्यरत थे।

डॉ. राजेंद्र सिंह परोदा एक कृषि वैज्ञानिक हैं और वर्तमान में वह कृषि विज्ञान के विकास के लिए ट्रस्ट (टीएएएस) के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के पूर्व महानिदेशक और भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) में सचिव हैं।

डॉ. राजेंद्र सिंह परोदा, पूर्व डीजी, आईसीएआर और अध्यक्ष, कृषि विज्ञान के विकास के लिए ट्रस्ट (टीएएएस) व्याख्यान देते हुए।

स्वास्थ्य सेवा के लिए किफायती नवाचार

'स्वास्थ्य सेवा के लिए किफायती नवाचार' विषय पर बारहवां एसटीआईपी फोरम व्याख्यान 10 सितंबर 2018 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में सचिव और आईसीएमआर के डीजी प्रो. बलराम भार्गव ने दिया। इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने की। प्रो. भार्गव अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली में कार्डियोलॉजी या हृदय रोग विज्ञान के प्रोफेसर हैं और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायोडिजाइन (एसआईबी) के स्टेनफोर्ड इंडिया बायोडिजाइन सेंटर के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति (एसटीआईपी) फोरम की स्थापना विज्ञान,

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

दक्षिण अफ्रीकी उच्चायोग के नामित उच्चायुक्त माननीय डॉ. एच एन मांझिनी विशेष भाषण देते हुए।

प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। यह फोरम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अंतर–अनुभागीयता और व्याख्यान को ध्यान में रखते हुए विषयक संबंधी सीमाओं से परे जाएगा। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रचार–प्रसार करने के साथ–साथ सामाजिक आकांक्षाओं से जुड़ी बहस का सामान्यीकरण करने और उत्तरदायी अनुसंधान एवं नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और समाज के बीच की खाई को पाटना है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति पर आम जनता को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से ही मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू की गई है। सहयोगी या सहयोगात्मक संस्थान ये हैं – अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस), ऊर्जा संसाधन संस्थान (टेरी), विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (सीएसई), उन्नत अनुसंधान के संवर्धन के लिए भारत–फ्रांसीसी केंद्र (सीईएफआईपीआरए), विज्ञान प्रसार और भारत पर्यावास केंद्र (आईएचसी)।

गांधी–मंडेला विरासत – आगे की राह

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और नेल्सन मंडेला की 100वीं जयंती मनाए जाने से पहले आरआईएस ने दक्षिण अफ्रीकी उच्चायोग, नई दिल्ली, गांधी पीस फाउंडेशन और नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल) के साथ मिलकर संयुक्त रूप से 26 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम "गांधी–मंडेला विरासतः आगे की राह' का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री शक्ति सिन्हा, निदेशक, एनएमएमएल और श्री अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस के स्वागत भाषणों के साथ हुआ। दक्षिण अफ्रीकी उच्चायोग, नई दिल्ली के नामित उच्चायुक्त माननीय डॉ. एच एन मांझिनी ने इस अवसर पर विशेष भाषण दिया।

इंडिया फाउंडेशन के अध्यएक्ष श्री राम माधव ने मुख्य भाषण दिया। गांधी शांति फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री कुमार प्रशांत, जिन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, ने भी गांधी–मंडेला विरासत पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, डीजी, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच साझेदारीः उभरती रूपरेखा

संबंधित श्रृंखला में 28वां ब्रेकफास्ट सेमिनार 24 अक्टूबर, 2018 को आरआईएस में 'भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच साझेदारीः उभरती रूपरेखा को समझना' विषय पर आयोजित किया गया। राजदूत विवेक काटजू ने इस सत्र की अध्यक्षता की। राजदूत अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस इसमें प्रमुख वक्ता थे। अंत में आयोजित की गई परिचर्चा में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

संयुक्त राष्ट्र–एस्कैप की कार्यकारी सचिव सुश्री अरमिदा सलसिया अलिसजहबाना आरआईएस में संवादात्मक सत्र में शिरकत करती हुईं।

यूएन–एस्कैप की कार्यकारी सचिव सुश्री अरमिदा सलसिया अलिसजहबाना के साथ संवादात्मक सत्र

संयुक्त राष्ट्र–एस्कैप की कार्यकारी सचिव सुश्री अरमिदा सलसिया अलिसजहबाना ने एक संवादात्मक सत्र के लिए 22 जनवरी, 2019 को आरआईएस का दौरा किया। उसमे प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया, जिसके बाद संकाय सदस्यों द्वारा आरआईएस के कार्यक्रम पर एक प्रस्तुति दी गई। डॉ. नागेश कुमार, निदेशक, दक्षिण और दक्षिण–पश्चिम एशिया कार्यालय, यूएन–एस्कैप; डॉ. राजन सुदेश रत्न, आर्थिक मामलों के अधिकारी, यूएन–एस्कैप; श्री के.एल. थापर, अध्यक्ष, एशियाई परिवहन विकास संस्थान; और श्री प्रणव कुमार, प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति भी संवादात्मक सत्र में शामिल हुए।

'भारत का शहरी पुनरुत्थान' पर श्री हरदीप सिंह पुरी के साथ चर्चा

आरआईएस और शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान (एनआईयूए) ने 2 जून 2018 को नई दिल्ली में 'भारत के शहरी पुनरुत्थान' पर संयुक्त रूप से एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया। राजदूत अमर सिन्हा, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम का आरम्भ आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण के साथ हुआ। प्रो. जगन शाह, निदेशक ने मुख्य प्रस्तुति दी। आवास एवं शहरी मामलों के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी ने मुख्य भाषण दिया। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों द्वारा खुली चर्चा करने के साथ इसका समापन हुआ।

अर्थशास्त्र की छात्राओं के साथ संवाद

दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमन की अर्थशास्त्र की छात्राओं के साथ एक संवादात्मक सत्र 24 अक्टूबर, 2018 को आरआईएस में आयोजित किया गया।

इस संवादात्मक सत्र में 20 से भी अधिक छात्राओं ने भाग लिया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने 'अनुसंधान एवं वैश्विक अर्थव्यवस्थाः असमानता और सतत विकास लक्ष्य' के क्षेत्र में आरआईएस से जुड़ी गतिविधियों का अवलोकन प्रस्तुत किया। डॉ. प्रियदर्शी दाश, सहायक प्रोफेसर ने 'अंतरराष्ट्रीय व्यापारः सिद्धांतों' पर एक प्रस्तुति दी। डॉ. सब्यसाची साहा ने नीतिगत विकल्पों एवं व्यापार,

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

प्रौद्योगिकी और रोजगार पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया।

दक्षिण अफ्रीका की उप अंतर्राष्ट्रीय संबंध मंत्री माननीया सुश्री रेगिना मैकगाबो महाउले के साथ संवादात्मक सत्र

आरआईएस ने 9 जनवरी, 2019 को दक्षिण अफ्रीका की उप अंतर्राष्ट्रीय संबंध मंत्री माननीया रेगिना मैकगाबो महाउले के साथ एक संवादात्मक सत्र का आयोजन किया। आरआईएस के चेयरमैन डॉ. मोहन कुमार ने सत्र की अध्यक्षता की, और आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर 'भारत–दक्षिण अफ्रीका साझेदारी और नई विश्व व्यवस्था' पर आयोजित पैनल परिचर्चा में जिन विशेषज्ञयों ने विचार विनमय किया: वे थे राजदूत वीरेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद; राजदूत राजीव भाटिया, पूर्व महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए; डॉ. फिलानी म्थेम्बु, कार्यकारी निदेशक, इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल डायलॉग, दक्षिण अफ्रीका; और सुश्री रुचिता बेरी, सीनियर रिसर्च एसोसिएट, आईडीएसए। परिचर्चा में सहयोग पहलुओं और नीतिगत संवादों को सरकार से परे ले जाने की दिशा में 'ट्रैक 1.5 कूटनीति' में गैर–सरकारी पदाधिकारियों के महत्व को रेखांकित किया गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रबुद्ध मंडलों (थिंक–टैंक) के बीच सहयोग बढ़ने से प्रासंगिक, समयबद्ध और व्यावहारिक अनुसंधान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जो वास्तविक जमीनी बदलाव ला सकती हैं। इस तरह के प्रयास सरकारी स्तर पर सहयोग के साथ–साथ लोगों के परस्पर सहयोग को भी नई गति प्रदान कर सकते हैं।

पैनल चर्चा के बाद माननीया सुश्री रेगिना मैकगाबो महाउले, ने दक्षिण अफ्रीका में आजादी के 25 साल' विषय पर संबोधित किया। दक्षिण अफ्रीका के इतिहास, महात्मा गांधी एवं नेल्सन मंडेला के दौर से ही भारत के साथ इसकी साझेदारी और विकासशील देशों में समावेशी विकास सुनिश्चित करने की दिशा में दोनों देशों की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला। देशों के बीच सहयोग से जुड़े मौजूदा बहुपक्षीय फोरमों को प्रेरित किया और इसके साथ ही आरआईएस एवं इसके दक्षिण अफ्रीकी समकक्षों एसएआईआईए और आईजीडी के बीच सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर के परिणामस्वरूप गहन सहयोग की संभावनाओं के बारे में उन्होनें विस्तार से चर्चा की। ?

अंत में भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायोग के कार्यवाहक राजदूत श्री बी.जे. जौबर्ट ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

वृहद–विवेकपूर्ण नीति' पर आयोजित संगोष्ठी में शिरकत करते हुए प्रतिभागी।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

'वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने में 'वृहद–विवेकपूर्ण नीति' की भूमिका पर संगोष्ठी

आरआईएस ने 14 मार्च 2019 को आरआईएस में 'वृहद–विवेकपूर्ण नीति'' पर एक संगोष्ठी आयोजित की। नेशनल बैंक ऑफ स्लोवाकिया के वृहद–विवेकपूर्ण नीति विभाग के निदेशक श्री मारेक लिसाक ने मुख्य प्रस्तुति दी तथा जिसके बाद परिचर्चा आरंभ हुई। जिसमें: डॉ. आलोक शील, आरबीआई चेयर प्रोफेसर, आईसीआरआईईआर; श्री लुडोविक ओडोर, वाइस गवर्नर, नेशनल बैंक ऑफ स्लोवाकिया; और श्री बंदुला जयसेकरा, विजिटिंग फेलो, आरआईएस ने भाग लिया। माननीय श्री इवान लांसरिक, राजदूत और सुश्री कटरीना तोमकोवा, उप प्रमुख, नई दिल्ली स्लोवाक गणराज्य का दूतावास और प्रो. बिश्वजीत बनर्जी, मुख्य अर्थशास्त्री, स्लोवाक गणराज्य का वित्त मंत्रालय एवं अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, अशोका विश्वविद्यालय ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी के डीन प्रोफेसर आर. सुदर्शन ने आरंभिक भाषण दिया।

अन्य मंचों पर नीतिगत संवाद

प्रो. सचिन चतुर्वेदी

महानिदेशक

- 7 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में ऊर्जा फोरम में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्टीफन हार्पर और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ एक सम्मेलन में भाग लिया।
- 8 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा नीली अर्थव्यवस्था पर भारत–नार्वे संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक के दौरान 'स्वच्छ और स्वस्थ महासागरों को कैसे सुनिश्चित करें' विषय पर आयोजित परिचर्चा में पैनल सदस्य थे।
- 11 जनवरी 2019 को ह्यूस्टन में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) द्वारा आयोजित ह्यूस्टन–भारत सम्मेलन के तीसरे संस्करण में 'लोकतंत्र को परिपूर्ण करना: गवर्नेंस पर फोकस' पर एक प्रस्तुति दी।
- 3 फरवरी 2019 को गुवाहाटी में इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित दूसरे आसियान–भारत युवा शिखर सम्मेलन में 'भौतिक संपर्क'' पर एक प्रस्तुति दी।
- 11 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा 'भूमंडलीकरण बनाम राष्ट्रवाद: अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध और भारत' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'व्यापार युद्ध: भारत के लिए चुनौतियां और अवसर' पर एक प्रस्तुति दी।
- 12 फरवरी 2019 को बैंकॉक में संयुक्त राष्ट्र एस्कैप द्वारा आयोजित बापा + 40 की तैयारी से जुड़ी क्षेत्रीय तकनीकी कार्यशाला में 'वैचारिक रूपरेखा: भारतीय परिप्रेक्ष्य' पर एक प्रस्तुति दी।
- 15 फरवरी 2019 को सियोल में केडीआई स्कूल और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) – अनुसंधान संस्थान (आरआई) द्वारा सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर संयुक्त रूप से आयोजित सम्मेलन में 'सतत विकास लक्ष्य के लिए एसटीआई का उपयोग करने' पर एक प्रस्तुति दी।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

- 26 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित कौटिल्य फेलो कार्यक्रम में 'भारत में थिंक टैंक और सिविल सोसायटी की भूमिका' पर एक प्रस्तुति दी।
- 26 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में एनएएसपीएए और जिंदल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी तथा ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा 'असमानता के युग में गवर्नेंसः दक्षिण एशिया में नीति प्रोफेशनलों की अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करना' विषय पर आयोजित संयुक्त सम्मेलन में पैनल सदस्य थे।
- 5 मार्च 2019 को नई दिल्ली में आईसीएसएसआर–ईएसआरसी, ब्रिटेन द्वारा 'बदलते वैश्विक परिवेश में ब्रिटेन–भारत व्यापार और सीमा पार निवेश का भविष्य' विषय पर संयुक्त रूप से आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता की।
- 8 मार्च 2019 को नई दिल्ली में 'वैश्विक आर्थिक रुझान और भारत–जापान आर्थिक साझेदारी' पर आयोजित 9वीं आईसीआरआईईआर–पीआरआई कार्यशाला में 'जापान की जी–20 अध्यक्षता और भारत–जापान सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों' पर सत्र की अध्यक्षता की।
- 18 मार्च 2019 को ब्यूनस आयर्स में नेस्ट, डीआईई और जीडीआई द्वारा संयुक्त रूप से '2030 एजेंडा प्राप्त करने के लिए सहयोगः प्रभावशील सहयोग' विषय पर आयोजित संपादकों की कार्यशाला में भाग लिया।
- 19 मार्च 2019 को ब्यूनस आयर्स में यूएनओएसएसी और यूएनडीपी द्वारा 'दक्षिणीय और त्रिकोणीय सहयोग पर सीमांत अनुसंधान को आगे बढ़ाना' विषय पर आयोजित परिचर्चा का संचालन किया।
- 19 मार्च 2019 को ब्यूनस आयर्स में नेस्ट, डीआईई, आईपीईए, जर्मन विकास संस्थान और मैनेजिंग ग्लोबल गवर्नेंस द्वारा '2030 एजेंडा हासिल करने के लिए विकास सहयोग' पर आयोजित विशेषज्ञ कार्यशाला में भाग लिया।
- 20 मार्च 2019 को ब्यूनस आयर्स में ओईसीडी द्वारा 'सतत विकास की ओर उन्मुखः एजेंडा 2030 को पूरा करने हेतु सहयोग के लिए नए रास्ते' विषय पर अलग से आयोजित कार्यक्रम के दौरान 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में व्यापक बदलाव के लिए नए साधन और दृष्टिकोण' पर एक प्रस्तुति दी।
- 21 मार्च 2019 को ब्यूनस आयर्स में नेस्ट, आईपीईए और जीडीआई द्वारा 'सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग में होड़ और सहयोग' विषय पर आयोजित अलग से कार्यक्रम में भाग लिया।
- 21 मार्च 2019 को ब्यूनस आयर्स में यूएनओएसएससी और अर्जेंटीना सरकार द्वारा आयोजित दक्षिणीय सहयोग पर दूसरे उच्चस्तरीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (बापा +40) में 'चुनौतियां और दक्षिणीय एवं त्रिकोणीय सहयोग की संस्थागत रूपरेखा को मजबूत करने' पर 'बापा+40ः संवादात्मक पैनल परिचर्चा 2' में पैनल सदस्य थे।
- 21 मार्च 2019 को ब्यूनस आयर्स में आईटीसी द्वारा 'वैश्विक दक्षिण में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखला का विशेष योगदान' विषय पर अलग से आयोजित कार्यक्रम के दौरान 'बापा से बापा+40 तकः दक्षिणीय व्यापार और निवेश में भारत का योगदान' विषय पर एक प्रस्तुति दी।
- 28 मार्च 2019 को नई दिल्ली में आईडीएसए द्वारा आयोजित 20वें एशियाई सुरक्षा सम्मेलन में 'ब्रिक्स का भविष्य – एक भारतीय परिप्रेक्ष्य' पर एक प्रस्तुति दी।
- 9 अक्टूबर 2018 को चीन के बीजिंग में 'विकास के लिए चीनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अकादमी' द्वारा 'चीन और विदेश में आरआरआईः एक अंतर्राष्ट्रीय संवाद' पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में 'बड़े विकासशील देश में आरआरआईः भारत में ताजा स्थिति' पर एक प्रस्तुति दी।
- 11 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत द्वारा संयुक्त रूप से 'चिकित्सा उत्पादों तक पहुंचः सतत विकास लक्ष्य 2030 को प्राप्त करना' पर आयोजित द्वितीय विश्व सम्मेलन में 'औषधीय उत्पादों तक पहुंच के लिए साझेदारीः द्विपक्षीय संधियां और क्षेत्रीय समझौतेः सतत विकास लक्ष्य पर फोकस' पर एक प्रस्तुति दी।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

- 29 अक्टूबर 2018 को बैंकॉक में एशियाई विकास बैंक द्वारा 'एडीबी की मसौदा आरसीआई परिचालन योजना (2019–2030) और व्यापार प्रस्तुतियों' पर विचार–विमर्श करने के लिए आयोजित परिचर्चा में भाग लिया।
- 5 नवंबर 2018 को पटना में नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय और ए.एन. सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'क्षेत्रीय विकास के लिए भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा' पर विशेष व्याख्यान दिया।
- 13 नवंबर 2018 को नई दिल्ली में इंडिया फाउंडेशन और म्यांमार के दूतावास द्वारा म्यांमार दिवस पर म्यांमार और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत की 70वीं वर्षगांठ मनाने के अवसर पर 'एक्ट ईस्टः इसे कारगर बनाना' विषय पर संयुक्त रूप से आयोजित सत्र में पैनलिस्ट थे।
- 16 नवंबर 2018 को हरियाणा में कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल द्वारा कृषि एवं सतत विकास लक्ष्यों पर संयुक्त रूप से आयोजित 26वें एईआरए वार्षिक सम्मेलन में 'कृषि और सतत विकास लक्ष्यः वैश्विक नीति में सामंजस्य, अनिवार्यताएं और नई रणनीतियां' विषय पर डॉ. जी के चड्ढा स्मारक व्याख्यान दिया।
- 20 नवंबर 2018 को ढाका में नीतिगत संवाद केंद्र द्वारा आयोजित 'दक्षिण एशिया के लिए सतत विकास लक्ष्य की व्याख्या करनाः एक क्षेत्रीय रूपरेखा की तलाश में' के दौरान 'सतत विकास लक्ष्यः उभरते भारतीय अनुभव' पर एक प्रस्तुति दी।
- 30 नवंबर 2018 को बैंकॉक में आईएफपीआरआई और डब्ल्यूएफपी द्वारा 'एशिया–प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य 2 की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय शून्य भूख रणनीतिक समीक्षाओं का उपयोग करना' विषय पर संयुक्त रूप से आयोजित एक अलग कार्यक्रम में पैनलिस्ट थे।
- 4–5 दिसंबर 2018 को जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए), टोक्यो द्वारा टी–20 के लिए आयोजित टोक्यो आरंभिक बैठक में 'सतत विकास लक्ष्य और निजी क्षेत्र' पर एक प्रस्तुति दी।
- 8 दिसंबर 2018 को बेंगलुरू में तारुण्य शिक्षण सेवा ट्रस्ट, बेंगलुरू द्वारा भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सहयोग से आयोजित 'भारत में स्वास्थ्य परंपराओं के समूह पर जिग्नासा आरोग्य मेला और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन' में 'आयुर्वेद के वैश्वीकरण की संभावनाएं और चुनौतियां–अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य' पर मुख्य भाषण दिया।
- 13 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में अमेजन डिजिटल उत्सव में भारतीय सूक्ष्म एवं लघु और मझोले उद्यम संघ (फिस्मे') द्वारा 'विश्व के लिए मेक इन इंडिया' पर संयुक्त रूप से आयोजित पैनल परिचर्चा में पैनलिस्ट थे।
- 15 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में भारतीय आर्थिक संघ (आईईए) के 101वें वार्षिक सम्मेलन में 'कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाः प्रौद्योगिकी एवं व्यापार से लाभ उठाना' विषय पर मुख्य भाषण दिया।
- 21 दिसंबर, 2018 को नई दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रणनीति बैठक में 'डीबीटी – अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग' पर एक प्रस्तुति दी।
- 21 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में आईसीडब्ल्यूए द्वारा आयोजित तीसरे भारत–चीन थिंक–टैंक फोरम में 'विकास योजनाओं का विश्लेषण करने' पर एक प्रस्तुति दी।
- 4 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित 'प्रौद्योगिकी की अगुवाई में नवाचार नीति' तैयार करने के लिए गठित राष्ट्रीय पैनल की तीसरी बैठक में भाग लिया।
- 4 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल द्वारा आयोजित 'सतत विकास लक्ष्य 16 भारतः डेटा अंतर का मानचित्रण' नामक सीएचआरआई की नवीनतम रिपोर्ट के लांचिंग कार्यक्रम के दौरान 'सतत विकास लक्ष्य 16 : आगे की कार्यवाही एवं समीक्षा' पर पैनल परिचर्चा का संचालन किया।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

- 6 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में नीति आयोग में आयोजित नीली अर्थव्यवस्था की मसौदा समिति की तीसरी बैठक में भाग लिया।
- 6 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में इंडिया टुडे द्वारा आयोजित 'मेक इन इंडिया उभरते उद्यमी शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2018' के दौरान 'निर्यात का दोहन करनाः कौन सी चीज भारत को रोक रही है' पर आयोजित पैनल परिचर्चा में भाग लिया।
- 11 जुलाई 2018 को न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम (एचएलपीएफ) के दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन की समीक्षाः सतत विकास लक्ष्य 11 – शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, सुदृढ़ और टिकाऊ बनाने' पर आयोजित आधिकारिक बैठक में भाग लिया।
- 13 जुलाई 2018 को न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम (एचएलपीएफ) के दौरान 'दक्षिणीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय' द्वारा 'सतत विकास लक्ष्य–17 के लिए डेटा' पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
- 18 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में टेरी द्वारा 'कृषि लाभप्रदता और स्थिरता के लिए गठबंधन (कैप्स)' पर आयोजित संकल्पना बैठक के दौरान 'कृषि में प्रौद्योगिकी' पर आयोजित सत्र में एक प्रस्तुति दी।
- 3 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में नीति आयोग में 'नीली अर्थव्यवस्था पर संचालन समिति' की पहली बैठक में भाग लिया।
- 5 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित TEDxFMS में 'एक विश्व के लिए आगे बढ़नाः वित्त पोषण के सामाजिक जुड़ाव' पर एक प्रस्तुति' दी।
- 10 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन इंडिया सेंटर द्वारा 'एशिया में लोकतांत्रिक सहयोगः भारत और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य' पर आयोजित कार्यशाला में ''लोकतंत्र संवर्धन में भारत के योगदान'' पर हुए विशेष सत्र में पैनलिस्ट थे।
- 24 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में सीआईआई द्वारा आयोजित 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर राष्ट्रीय समिति' की बैठक में भाग लिया।
- 29 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय समुद्री नीति पर मसौदा समिति' की चौथी बैठक में भाग लिया।
- 31 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में टेरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज के प्रबंधन बोर्ड की 29वीं बैठक में सदस्य के रूप में भाग लिया।
- 5 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में सीआईआई द्वारा आयोजित वर्ष 2018–19 के लिए सीआईआई अफ्रीका समिति की बैठक में भाग लिया।
- 11 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) द्वारा आयोजित भारतीय कृषि आउटलुक फोरम 2018 में 'कृषि व्यापार नीति और हालिया घटनाक्रमों' पर आयोजित सत्र में पैनलिस्ट थे।
- 14 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज द्वारा आयोजित 'सामरिक पड़ोस में रचनात्मक कारकों के रूप में व्यापार, निवेश और वित्त की भूमिका' पर एक प्रस्तुति दी।
- 14 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में नीति आयोग में आयोजित 'लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचा और शिपिंग (वाहनांतरण या ट्रांस–शिपमेंट सहित) पर कार्य दल की पहली बैठक में भाग लिया।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

- 17 सितंबर 2018 को ब्यूनस आयर्स में डीआईई/जर्मन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा 'जी–20 में 2030 एजेंडे के राष्ट्रीय कार्यान्वयन' पर आयोजित सत्र में पैनलिस्ट थे।
- 17 सितंबर 2018 को ब्यूनस आयर्स में डीआईई/जर्मन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा 'जी20 क्यों : वैश्विक विकास के लिए अफ्रीका सहयोग से जुड़े मुद्दों' पर आयोजित सत्र में पैनलिस्ट थे। '
- 18 सितंबर 2018 को ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना के विदेश मंत्रालय द्वारा 'दक्षिणीय सहयोग पर द्वितीय संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय सम्मेलन' के परिणाम दस्तावेज के लिए अवयवों' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- चेन्नई में 2 अप्रैल, 2018 को विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित आईबीएसए शेरपाओं की बैठक में 'दक्षिणीय सहयोग में आईबीएसए की भूमिका' पर एक प्रस्तुति दी।
- 6 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा प्रो. वी.वी. कृष्णा की हालिया संपादित पुस्तक '*यूनिवर्सिटीज इन द नेशनल इनोवेशन सिस्टम*' पर आयोजित पैनल परिचर्चा में भाग लिया।
- 9 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में रेल मंत्रालय द्वारा आयोजित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) सम्मेलन में भाग लिया।
- 10 अप्रैल 2018 को अगरतला में नीति आयोग द्वारा आयोजित 'पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम' से जुड़ी पूर्वोत्तर परिषद की पहली बैठक में भाग लिया।
- 11 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय समुद्र तटवर्ती से जुड़ी मसौदा समिति' की उद्घाटन बैठक में एक सदस्य के रूप में भाग लिया।
- लिस्बन में 17–18 अप्रैल 2018 को 'त्रिकोणीय सहयोग के मूल्य वर्द्धित का सर्वोत्तम उपयोग करने' पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय बैठक में 'अहम वैश्विक चुनौतियों को सुलझानाः त्रिकोणीय विकास सहयोग की भूमिका' पर एक प्रस्तुति दी, जिसे 17 अप्रैल 2018 को लिस्बन में कैमियोज – इंस्टीट्यूट दा कोऑपेराकाओ ई दा लिंगुआ और ओईसीडी विकास सहयोग निदेशालय (डीसीडी) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।
- 25 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में पैरवी, मौसम, एपीआरएन, एपीआरसीईएम, सेकोईडेकॉन, फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ और ईटीसी समूह द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'सतत एवं समावेशी विकास में बड़ी तकनीक की भूमिका और उत्तरदायित्व' पर राष्ट्रीय परामर्श के दौरान 'सतत एवं समावेशी विकास में बड़ी तकनीक की भूमिका और उत्तरदायित्व' पर एक प्रस्तुति दी।
- 2 मई 2018 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान (एनआईएपी) के वार्षिक दिवस समारोह में 'विज्ञान की केन्द्रीयता, सामाजिक लक्ष्य और कृषि क्षेत्र में आरएंडडी को प्राथमिकता देने' पर डॉ. दयानाथ झा स्मृति व्याख्यान दिया।
- नई दिल्ली में 2 मई 2018 को नीति आयोग द्वारा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति में 'भारत के लिए नीली अर्थव्यवस्था रणनीति की ओरः उभरते अवसरों और चुनौतियों' पर आयोजित एक बैठक में भाग लिया।
- 17 मई 2018 को उदयपुर में सेवा मंदिर द्वारा आयोजित सेवा मंदिर की कार्यकारी परिषद की बैठक में एक सदस्य के रूप में भाग लिया।
- 21 मई 2018 को नई दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) द्वारा विश्व संस्कृति दिवस के अवसर पर आयोजित 'सॉफ्ट पावर कूटनीति, भारत की ताकत' पर भारत सरकार की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा दिए गए प्रथम पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्मृति अंतर्राष्ट्रीय भाषण में भाग लिया।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

- नई दिल्ली में 23 मई 2018 को भारत–आसियान सामरिक साझेदारी और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पर आयोजित सिविल सोसायटी परामर्श में 'भारत के विकास सहयोग एवं भारत–आसियान सामरिक साझेदारी में सिविल सोसायटी की सहभागिता और एआईआईबी'पर एक प्रस्तुति दी।
- जोहान्सबर्ग में 28 मई 2018 को साउथ अफ्रीकन ब्रिक्स थिंक टैंक्स (एसएबीटीटी) और राष्ट्रीय मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिक्स थिंक टैंक काउंसिल (बीटीटीसी) की बैठक में भाग लिया।
- 29 मई 2018 (स्काइप के माध्यम से) को बैंकाक में कृषि अनुसंधान संस्थानों के एशिया–प्रशांत संघ (एपीएएआरआई) द्वारा 'कृषि जैव प्रौद्योगिकी – एशिया–प्रशांत क्षेत्र में किसानों की आजीविका में बेहतरी लाने के लिए साझेदारी की संभावनाएं ढूंढ़ने' पर आयोजित क्षेत्रीय विशेषज्ञ परामर्श में 'दक्षिणीय सहयोग के लिए कृषि जैव प्रौद्योगिकी' पर एक प्रस्तुति दी।
- जोहान्सबर्ग में 29 मई 2018 को साउथ अफ्रीकन ब्रिक्स थिंक टैंक्स (एसएबीटीटी) और राष्ट्रीय मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिक्स एकेडेमिक फोरम 2018 में 'ब्रिक्स में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की ओर' पर एक प्रस्तुति दी।
- जोहान्सबर्ग में 30 मई 2018 को साउथ अफ्रीकन ब्रिक्स थिंक टैंक्स (एसएबीटीटी) और राष्ट्रीय मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिक्स एकेडेमिक फोरम 2018 में 'सुगम्यं वैश्विक दक्षिण ज्ञान की ओर' पर एक प्रस्तुति दी।
- सोनीपत में 15 जून 2018 को विजन इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित पॉलिसी बूट कैंप 2018 में 'उभरती ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएंः अवसरों और चुनौतियों' पर एक प्रस्तुति दी।
- 19 जून 2018 को मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका द्वारा आईपी, खाद्य कानून और वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर आयोजित पैनल परिचर्चा के दौरान ''नवाचारों एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में कारगर एसएंडटी नीतियों और क्षेत्रीय सहयोग की भूमिका' पर एक प्रस्तुति दी।
- 27 जून 2018 को यूएनओएसएससी, बैंकॉक द्वारा ' एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दक्षिण–दक्षिण सहयोगः ब्यूनस आयर्स कार्य योजना की 40वीं वर्षगांठ की ओर' पर आयोजित क्षेत्रीय परामर्श के दौरान ''दक्षिणीय सहयोग में नई संभावनाएं ढूंढ़ने' पर एक प्रस्तुति दी।

प्रो. एस. के. मोहंती

- विदेश मंत्रालय में 8 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में 'हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए)' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 10 जनवरी, 2019 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में 'राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ संवाद' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया और 'व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषदः बेहतर दक्षता के लिए सुझाव' पर एक प्रस्तुति दी।
- नई दिल्ली में 21 जनवरी 2019 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में 'हिंद–प्रशांत के विशेष संदर्भ के साथ तटीय अनुसंधान में प्रगति' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए आयोजित संचालन समिति की वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 22 जनवरी 2019 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा आयोजित 'नीली अर्थव्यवस्था कार्य समूहः 1 (नीली अर्थव्यवस्था और महासागर के गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय लेखांकन रूपरेखा)' की औपचारिक बैठक में भाग लिया और फिर उसी विषय पर एक प्रस्तुति भी दी।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

- नई दिल्ली में 31 जनवरी 2019 और 19 फरवरी 2019 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा आयोजित 'नीली अर्थव्यवस्था कार्य समूहः 1 (नीली अर्थव्यवस्था और महासागर के गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय लेखांकन रूपरेखा)' की परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 21 फरवरी 2019 और 26 मार्च 2019 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में 'एलएसी अध्ययन' पर आयोजित परिचर्चा बैठकों में भाग लिया।
- 25 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा 'राष्ट्रीय समुद्री नीति' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 7–9 मार्च 2019 को महाबलीपुरम, चेन्नई में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) और कोनराड–एडेनेउर–स्टिफटंग (केएएस) द्वारा मद्रास प्रबंधन संघ (एमएमए) के सहयोग से 'उभरती वैश्विक समुद्री व्यवस्था – भारत की रणनीति' पर आयोजित पांचवें टेरी–केएएस संसाधन संवाद में भाग लिया।
- 26 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में भारत अरब सांस्कृतिक केंद्र, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय द्व ारा 'भारत, चीन और अरब दुनियाः नई गतिशीलता की तलाश करने' पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान अरब दुनिया में भारत और चीन पर एक प्रस्तुति दी।
- नई दिल्ली में 26 मार्च 2019 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में 'एलएसी अध्ययन' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 27 मार्च 2019 को विदेश मंत्रालय में 'हिंद महासागर रिम संघ (आईओआरए) के तहत भारत की पहल – 25वां हिंद महासागर रिम शैक्षणिक समूह (आईओआरए जी) पर आयोजित परिचर्चा बैठक, छठे हिंद महासागर संवाद (आईओडी) और आईओआरए में शैक्षणिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्राथमिकता क्षेत्र पर विशेषज्ञों की बैठक' में भाग लिया।
- 31 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली स्थित नीति आयोग में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा 'नीली अर्थव्यवस्था कार्य समूह 4' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 9 नवंबर 2018 को नई दिल्ली स्थित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में 'नीली अर्थव्यवस्था कार्य समूहः 1 (नीली अर्थव्यवस्था और महासागर के गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय लेखांकन रूपरेखा)' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 23–27 नवंबर, 2018 को सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में आयोजित 'प्रथम भारत–रूस रणनीतिक संवाद' में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य के रूप में भाग लिया।
- 30 नवंबर 2018 को नई दिल्ली स्थित नीति आयोग द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय समुद्री नीति' पर एक प्रस्तुति दी।
- 2 अप्रैल 2018 को चेन्नई में विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित ' आईबीएसए शेरपाओं की पहली बैठक' में 'आईबीएसए देशों के बीच नीली अर्थव्यवस्था संबंधी त्रिपक्षीय सहयोग' पर एक प्रस्तुति दी।
- 6 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित 'भारत–मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते' पर भारत–मॉरीशस सीईसीपीए की बैठक के चौथे दौर से पहले की बैठक में भाग लिया।
- 16 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा 'भारत–मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते' पर आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया।
- 17–19 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित 'भारत–मॉरीशस सीईसीपीए की चौथी बैठक' में भाग लिया।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

- 20 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा 'व्यापार और निवेश में लैटिन अमेरिका और कैरीबियाई देशों के साथ भारत की सहभागिता' पर संयुक्त रूप से आयोजित बहु–हितधारकों की परामर्श बैठक में 'एलएसी के साथ भारत की सहभागिताः व्यापार और निवेश' पर एक प्रस्तुति दी।
- 26 अप्रैल 2018 को नीति आयोग, नई दिल्ली में आयोजित 'ब्लू इकोनॉमी पर मसौदा समिति की दूसरी बैठक' में भाग लिया।
- 2 मई 2018 को नीति आयोग, नई दिल्ली में 'भारत में ब्लू इकोनॉमी के लिए एक रोडमैप और बहुक्षेत्रीय हितधारक के लिए एक एकीकृत महासागर नीति' पर आयोजित बैठक में भाग लिया और 'भारत के लिए एक ब्लू इकोनॉमी रणनीति की ओरः उभरते अवसरों और चुनौतियों' पर एक प्रस्तुति दी।
- 11 जून 2018 को नीति आयोग, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में भाग लिया और 'राष्ट्रीय समुद्री नीति' पर एक प्रस्तुति दी।
- 12 जून 2018 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित 'भारत–मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते (सीईसीपीए) पर समीक्षा बैठक' में भाग लिया।
- 27 जून 2018 को नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया और 'भारत–मॉरीशस सीईसीपीए जेएसजी' पर एक प्रस्तुति दी।

श्री राजीव खेर

विशिष्ट फेलो

- नई दिल्ली में 12 जनवरी 2019 को सीटीआईएल द्वारा 'डब्ल्यूटीओ में नई जान फूंकने' पर आयोजित परिचर्चा बैठक में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।
- 16 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में आईसीआरआईईआर द्वारा 'भारत–आसियान आर्थिक संबंध और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) के लिए निहितार्थ' पर आयोजित गैर–सार्वजनिक कार्यशाला की अध्यक्षता की।
- 22 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित उच्चस्तरीय सलाहकार समूह (एचएलएजी) की बैठक में एक सदस्य के रूप में भाग लिया।
- 25 जनवरी 2019 को पुणे में किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक में अतिरिक्त निदेशक के रूप में भाग लिया।
- जकार्ता में 29–30 जनवरी 2019 को जापान विदेश व्यापार संगठन (जेट्रो) और आसियान एवं पूर्वी एशिया के आर्थिक अनुसंधान संस्थान (ईआरआईए) द्वारा 'डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं के नए वैश्विक युग' पर संयुक्त रूप से आयोजित परिचर्चा में भाग लिया।
- 13 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में आईसीआरआईईआर द्वारा 'एशिया 2050: चीन, भारत और जापान के लिए निहितार्थों की तलाश करने' पर आयोजित सेमिनार में एक प्रतिभागी के रूप में भाग लिया।
- 16 फरवरी 2019 को देहरादून में डीआईटी विश्वविद्यालय द्वारा 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वाणिज्य और समाज (एसटीसीएस 2019)' पर आयोजित सम्मेलन में एक पैनल सदस्य के रूप में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 21 फरवरी 2019 को नीति आयोग द्वारा 'भारत से वाणिज्यिक निर्यात योजना (एमईआईएस)' की समीक्षा करने के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

- 5 मार्च 2019 को नई दिल्ली में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 'ब्रिटेन–भारत व्यापार का भविष्य और बदलते वैश्विक परिवेश में सीमा पार निवेश' पर आयोजित कार्यशाला में 'भारत–ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार और निवेश की संभावनाओं' पर एक प्रस्तुति दी।
- कोच्चि में 7 मार्च से 9 मार्च 2019 तक ट्रू नॉर्थ द्वारा आयोजित 'पथान्वेषी I कारोबारी हस्ती सम्मेलन I 2019' में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 25 मार्च 2019 को आईसीआरआईईआर द्वारा डेटा कैटलिस्ट के साथ '"डिजिटल अर्थव्यवस्था का भविष्यः उभरती व्यवस्थाओं में परस्पर विरोधी हालात' पर आयोजित सम्मेलन में भाग लिया।
- 27 मार्च 2019 को नई दिल्ली में पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल द्वारा 'निर्यात वृद्धि में नई जान फूंकने' विषय पर आयोजित खुली परिचर्चा में उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित किया।

प्रो. अमिताभ कुंडू

विशिष्ट फेलो

- 31 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित "मानव विकास" पर मुख्य भाषण दिया।
- 8 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में न्यूपा द्वारा 'शिक्षा में समानता' विषय पर आयोजित कुलपति कार्यशाला में एक व्याख्यान दिया।
- एक सलाहकार के रूप में 15 फरवरी 2019 को वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक सत्र की अध्यक्षता की और 'वानिकी क्षेत्र के लिए राज्यों को वित्त आयोग द्वारा हस्तांतरण पर सिफारिशें' (आईआईएफएम भोपाल अध्ययन) विषय पर एक प्रस्तुति दी।
- 22 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में 'स्वच्छ भारत मिशन' पर स्थायी समिति की बैठक और इसके द्वारा किए गए विचार–विमर्श की अध्यक्षता की।
- अलीगढ़ में 23 फरवरी 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 'बजट और महिला–पुरुष समावेशी शहरी विकास के लिए प्रेरित करना' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में व्याख्यान दिया।
- 25 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में अमेरिका इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित संगोष्ठी में 'प्रवासी बच्चों की शिक्षा' पर मुख्य भाषण दिया।
- 28 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय द्वारा 'प्रकृति, संस्कृति और भविष्य को व्यवस्थित करना' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य भाषण दिया।
- 9 मार्च 2019 को नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा 'समकालीन भारत में ग्रामीणों की व्यथाः निहितार्थ और चुनौतियां' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में आरंभिक भाषण दिया।
- 13 मार्च 2019 को कोलकाता में जादवपुर विश्वविद्यालय द्वारा 'भारत में सामाजिक और क्षेत्रीय विकासः उभरते नीतिगत मुद्दे' विषय पर आयोजित सम्मेलन में विशेष व्याख्यान दिया।
- 16 मार्च 2019 को नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा 'जल निरंतरता आजीविका और जलवायु परिवर्तन' विषय पर आयोजित 40वीं भारतीय भूगोलवेत्ता बैठक एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में समापन भाषण दिया।
- 26 मार्च 2019 को मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा 'भारत में पारस्परिकता, धार्मिक अल्पसंख्यक और महिलाओं का विकास' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में आरंभिक भाषण दिया।
- 28 मार्च 2019 को चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रैजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स द्वारा 'भारत में अनौपचारिक रोजगारः मुद्दे और चुनौती' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य भाषण दिया।
- 29 मार्च 2019 को नई दिल्ली में विश्व संसाधन संस्थान द्वारा 'उपनगरीकरण का प्रबंधन' विषय पर आयोजित परिचर्चा में एक पैनल सदस्य के रूप में भाग लिया।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

प्रो. टी. सी. जेम्स

विजिटिंग फेलो

- 30 जनवरी 2019 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में 'जी20 और अफ्रीकाः जी20 के लिए अफ्रीकी प्राथमिकताओं का मार्गनिर्देशन करने' पर आयोजित टी20 अफ्रीकी स्थायी समूह की बैठक में भाग लिया और अफ्रीका में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं जी20 पर नीतिगत सार–पत्र प्रस्तुत किया।
- 11 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सम्मेलन और यूनानी दिवस समारोह के दौरान 'सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सतत विकास लक्ष्यः पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका' विषय पर मुख्य भाषण दिया।
- 27 फरवरी 2019 को कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा 'कॉपीराइट के भविष्य' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विचार मंथन सत्र में एक पैनलिस्ट थे और 'कॉपीराइट रचनाओं तक पहुंच और सिमटता पब्लिक डोमेनः वाणिज्यिक प्रथाओं' पर एक प्रस्तुति दी।
- 22 अक्टूबर, 2018 को जोहान्सबर्ग में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) की दिशा में नवाचार एवं ज्ञान साझा करने पर आयोजित ब्रिक्स संगोष्ठी में भाग लिया और 'ब्रिक्स में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की ओर', 'यूएचसी की दिशा में नवाचार एवं ज्ञान साझा करना' और 'आगे की राह' पर प्रस्तुतियां दीं।
- 1 और 2 नवंबर, 2018 को बीजिंग में आयोजित 'ब्रिक्स देशों में पारंपरिक चिकित्सा सहयोग को बढ़ावा देने और मानव स्वास्थ्य के समुदाय का निर्माण करने पर 2018 ब्रिक्स थिंक–टैंक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी' में भाग लिया तथा 'स्वस्थ शहर के निर्माण और पारंपरिक चिकित्सा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' पर प्रस्तुति दी।
- 14-17 नवंबर, 2018 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित विश्व बौद्धिक संपदा फोरम में भाग लिया और 'भारत में भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण का अर्थशास्त्रः विपणन रणनीतियां एवं ब्रांड निर्माण' पर अपने विचार व्यक्त किए।
- भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरू द्वारा 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (एसटीआई) नीति' पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में एक 'संसाधन विशेषज्ञ' के रूप में भाग लिया और इसके साथ ही 19 नवंबर, 2018 को 'बौद्धिक संपदा अधिकारः राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य (पीसीटी)' पर एक सत्र का संचालन किया।
- 30 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और फिक्की द्वारा आयोजित आसियान नवाचार शिखर सम्मेलन में 'व्यावहारिक अनुभव और अनुसंधान प्रयोगशालाओं की ओर से प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण के लिए चुनौतियां' विषय पर आयोजित पैनल परिचर्चा में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।
- महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ द्वारा पंजाब के अधिकारियों के लिए सतत विकास लक्ष्यों पर आयोजित संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक 'संसाधन विशेषज्ञ' के रूप में भाग लिया और इसके साथ ही 3 दिसंबर, 2018 को 'सामाजिक सतत विकास लक्ष्य – अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली (एसडीजी–3) की ओर' पर एक प्रस्तुति दी।
- 6 दिसंबर, 2018 को टीआईएफएसी और डीआरडीओ द्वारा आईपीआर पर आयोजित उन्नत कार्यशाला के दौरान 'साहित्यिक कृतियों के संरक्षण, सॉफ्टवेयर, डिजिटल माध्यम और प्रचलित प्रथाओं में उचित उपयोग के प्रावधान' विषय पर एक प्रस्तुति दी।
- एमएनएलयू, नागपुर और राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) द्वारा 10 जुलाई, 2018 को विपो–इंडिया समर स्कूल में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं पेटेंट और रसगुल्ला के जिज्ञासु मामले' पर आयोजित सत्रों में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

- 18 अगस्त, 2018 को पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय के पूरक एवं एकीकृत स्वास्थ्य केंद्र द्वारा 'आयुर्वेद अनुसंधान के लिए अनुकूल माहौल बनाने' पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया और इसके साथ ही 'गवर्नेंस एवं वित्त पोषण' और 'सामाजिक विज्ञान एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य' पर प्रस्तुतियां दीं।
- 17 अप्रैल, 2018 को एनआईपीओ और कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विश्व आईपी दिवस संगोष्ठी में भाग लिया। इस संगोष्ठी का विषय 'मानव अधिकार (एचआर) और महिला–पुरुष' था। 'आईपीआर और एचआर – महिला–पुरुष परिप्रेक्ष्य' पर एक प्रस्तुति दी।
- 20 अप्रैल, 2018 को लॉ सेंटर – आई, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा कॉपीराइट प्रवर्तन पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में कॉपीराइट और उसके प्रवर्तन पर पैनल परिचर्चा में भाग लिया।
- 20–21 अप्रैल, 2018 को भारतीय कानून संस्थान, नई दिल्ली द्वारा 'बौद्धिक संपदाः प्रक्रिया और अमल' पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन सत्र में व्यांख्यान दिया और इसकी अध्यक्षता की।
- 24 अप्रैल 2018 को बौद्धिक संपदा कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित विश्व आईपी दिवस कार्यक्रम में 'आईपीआर– महिला–पुरुष परिप्रेक्ष्य' पर एक प्रस्तुति दी।
- 10 मई, 2018 को विदेश मंत्रालय और भारतीय कानून संस्थान द्वारा आयोजित संगोष्ठी में 'भारत में भौगोलिक संकेतों और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण' विषय पर म्यांमार के विधि अधिकारियों को संबोधित किया।
- 25 जून, 2018 को निलांबर सागवान के विपणन से जुड़े मुद्दों पर निलांबर सागवान उत्पादक संघ के साथ बातचीत की और भौगोलिक संकेत के रूप में निलांबर सागवान के पंजीकरण की दिशा में आगे की कार्रवाई पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया।

डॉ. पी. के. आनंद

विजिटिंग फेलो

- 18 जनवरी 2019 को टेरी में 'ग्रामीण सड़कें और सतत विकास लक्ष्यः इंजीनियरिंग के लिए छोटे हो सकते हैं, लेकिन क्षमता की दृष्टि से अवश्य ही बड़े हैं' शीर्षक वाले पेपर पर चर्चा करने के लिए आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 15 फरवरी 2019 को आईआईटी, दिल्ली के सहयोग से नीति आयोग, एआईसीटीई, एसटीपीआई, ग्रामीण/अर्ध–शहरी क्षेत्रों के युवाओं के आर्थिक समावेशन की नीतिगत योजना के साथ राष्ट्रीय युवा सहकारी सोसायटी (एनवाईसीएस) द्वारा आयोजित 'रिसर्जेंट इंडिया युवा कॉन्क्लेव – 2019 'सम्मेलन में भाग लिया।
- टेरी द्वारा 20 फरवरी 2019 को आयोजित 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजे के अधिकार एवं पारदर्शिता पर प्रशिक्षण' के उद्घाटन सत्र में एक वक्ता के रूप में भाग लिया।
- 15 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) और अन्य हितधारकों द्वारा कृषि–पोषण पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया और एक प्रस्तुति दी।
- प्रौद्योगिकी सुविधा व्यवस्था के समुचित संचालन के लिए एसटीआई संबंधी यूएनईएस वैश्विक पायलट कार्यक्रम की तैयारी बैठक हेतु सतत विकास लक्ष्य की रूपरेखा के लिए 19 मार्च 2019 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) की अध्यक्षता में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
- 26 मार्च 2019 को आईसीएमआर और राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय द्वारा ''गांधी एवं स्वास्थ्य / 150 – आईसीएमआर की सदी–भर की यात्रा के निशान ' विषय पर आयोजित आईसीएमआर संगोष्ठी में भाग लिया।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

- 30 अक्टूबर 2018 को विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सरकार, बहुपक्षीय संस्थानों, सिविल सोसायटी और शिक्षाविदों के बीच पारस्परिक संवाद के जरिए 'सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण और अच्छी प्रथाओं का मानदंड तय करने' पर आयोजित उच्चस्तरीय परामर्श में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।
- 2-4 नवंबर, 2018 के दौरान त्रिपुरा को एक समृद्ध राज्य बनाने पर अगरतला में आयोजित 'चिंतन शिबिर' में भाग लिया और सिफारिशें पेश कीं।
- 6 दिसंबर 2018 को नए महाराष्ट्र सदन, नई दिल्ली में सेवा इंटरनेशनल द्वारा 'सतत विकास लक्ष्यों' पर आयोजित संगोष्ठी में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।
- 12 दिसंबर 2018 को गुवाहाटी में 'पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम' की दूसरी बैठक में भाग लिया और सुझाव दिए।
- 17-18 दिसंबर 2018 के दौरान नई दिल्ली स्थित भारत इस्लामी सांस्कृतिक केंद्र में दक्षिण एशिया और दक्षिण–पूर्व एशिया के अग्रणी सिविल सोसायटी संगठनों की सहभागिता वाले 'वाणी' द्वारा एफआईडीसी और आरआईएस के सहयोग से आयोजित 'साउथ–साउथ सिविल सोसाइटी कॉन्क्लेव' में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।
- 21-22 दिसंबर 2018 को इटानगर में अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा 'सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण' पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया और इसके साथ ही एक सत्र की अध्यक्षता भी की।

श्री कृष्ण कुमार

विजिटिंग फेलो

- 15 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) और अन्य हितधारकों द्वारा 'कृषि–पोषण' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में एक प्रस्तुति दी।
- प्रौद्योगिकी सुविधा व्यवस्था के समुचित संचालन के लिए एसटीआई संबंधी यूएनईएस वैश्विक पायलट कार्यक्रम की तैयारी बैठक हेतु सतत विकास लक्ष्य की रूपरेखा के लिए 19 मार्च 2019 को पृथ्वी भवन, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) की अध्यक्षता में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
- 2–4 नवंबर, 2018 के दौरान त्रिपुरा को एक समृद्ध राज्य बनाने पर अगरतला में आयोजित 'चिंतन शिबिर' में भाग लिया।
- 12 दिसंबर 2018 को गुवाहाटी में 'पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम' की दूसरी बैठक में भाग लिया।

डॉ. के. रवि श्रीनिवास

विजिटिंग फेलो

- 8 मार्च 2019 को जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्रीय केंद्र (आरसीबी), फरीदाबाद में 'प्रभावकारी एवं समावेशी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीतियों को विकसित करना' विषय पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला (यूनेस्को, यूआईएस और आरसीबी द्वारा आयोजित) में 'विज्ञान राजनय' पर एक व्याख्यान दिया।
- 9 अक्टूबर 2018 को बीजिंग में 'कास्टेड' द्वारा आयोजित 'चीन और विदेश में आरआरआईः एक अंतरराष्ट्रीय संवाद' के दौरान 'बड़े विकासशील देश में आरआरआईः भारत में ताजा स्थिति' पर प्रो. सचिन चतुर्वेदी के साथ मिलकर एक प्रस्तुति दी।
- 22 अक्टूबर 2018 को इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडीज, वियना में आयोजित 'न्यू होराइजन कंसोर्टियम बैठक' के दौरान 'आरआरआईः भारत की ओर से परिप्रेक्ष्य' पर एक प्रस्तुति दी।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

- 23 अक्टूबर 2018 को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी असेसमेंट, वियना में 'विज्ञान राजनय आजः चुनौतियां और संभावनाएं' विषय पर व्याख्यान दिया।
- 4 दिसंबर 2018 को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आयोजित 'होराइजन 2020 सूचना दिवस' पर 'होराइजन 2020 और ईआरसी का वित्त पोषणः अनुभव' पर एक प्रस्तुति दी।
- 18 दिसंबर, 2018 को आईडीएसए, नई दिल्ली में 'दक्षिण एशिया में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियांः सहयोग के लिए एजेंडा' पर आयोजित 11वें दक्षिण एशिया सम्मेलन के दौरान 'प्रौद्योगिकी, सरकार एवं मानव सुरक्षा और गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां' विषय पर एक प्रस्तुति दी।
- 13 सितंबर 2018 को बर्लिन में आयोजित टीए कार्यशाला में 'भारत में प्रौद्योगिकी आकलन' पर व्याख्यान दिया।
- 14 सितंबर 2018 को बर्लिन में आयोजित 'आरआरआई अभ्यास परियोजना बैठक' में एक प्रस्तुति दी।
- 25 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में सतत और समावेशी विकास में बड़ी प्रौद्योगिकी की भूमिका और उत्तरदायित्व पर आयोजित राष्ट्रीय परामर्श के दौरान 'कौन हमारे जलवायु को ठीक करना और हमारे दोपहर के भोजन को खाना चाहता है ' के बारे में कृत्रिम जीवविज्ञान की ताजा स्थिति और बहस पर एक प्रस्तुति दी।

डॉ. सब्यसाची साहा

सहायक प्रोफेसर

- 23 जनवरी 2019 को जापान के टोक्यो में कार्यदल के सदस्य के रूप में व्यापार, निवेश और वैश्वीकरण पर टी20 जापान कार्यदल 8 की बैठक में भाग लिया और 'एक वार्ता फोरम के रूप में विश्व व्यापार संगठन में नई जान फूंकने' एवं 'सतत और समावेशी विकास के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का विस्तार व पुनर्गठन करने' से जुड़े नीतिगत सार–पत्रों पर हुए विचार–विमर्श में योगदान दिया।
- 15 फरवरी 2019 को आईआईटी दिल्ली के हौज खास कैम्पस, नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा सहकारी समिति (एनवाईसीएस) लिमिटेड द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के सहयोग से आयोजित 'रिसर्जेंट इंडिया युवा कॉन्क्लेव – 2019' में वक्ता थे और इसके साथ ही सत्र के दौरान 'छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर सृजित करनाः कृषि एवं उससे परे' विषय पर व्याख्यान दिया।
- 20 मार्च 2019 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में ब्रिक्स नीतिगत केंद्र; डीसीडी/ओईसीडी; डीआईई; आरआईएस द्वारा आयोजित दक्षिणीय सहयोग पर दूसरे उच्चस्तरीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (बापा + 40) के दौरान '2030 एजेंडा प्राप्त करने के लिए गैर– सरकारी निकायों की सेवाएं लेनाः दक्षिणीय और त्रिकोणीय सहयोग से सबक' विषय पर अलग से आयोजित कार्यक्रम में पैनल सदस्य थे।
- 21 मार्च 2019 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र (आईटीसी), जिनेवा और आरआईएस द्वारा 'वैश्विक दक्षिण में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखलाओं का योगदान' विषय पर आयोजित दक्षिणीय सहयोग पर दूसरे उच्चस्तरीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (बापा+40) में भाग लिया। 'वैश्विक दक्षिण के पुनरुत्थान' विषय पर आरआईएस टीम द्वारा योगदान किए गए अध्याय के प्रमुख निष्कर्षों पर प्रस्तुति दी।
- बैंकॉक में 28 मार्च 2019 को 'दक्षिण एशिया में सतत विकास लक्ष्यः एक क्षेत्रीय रूपरेखा की तलाश में' विषय पर आयोजित विचार मंथन कार्यशाला में भाग लिया ('सतत विकास लक्ष्यः उभरते भारतीय अनुभव' पर प्रस्तुति दी)।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

- 4–5 दिसंबर 2018 को टोक्यो, जापान में आयोजित 'टी20 जापान 2019 आरंभिक सम्मेलन' में भाग लिया। व्यापार, निवेश और वैश्वीकरण पर गठित कार्य बल के सदस्य के रूप में चयनित किए गए।
- नई दिल्ली में 06 जून 2018 को सतत विकास लक्ष्य पर आयोजित ओआरएफ–जीआईजेड कार्यशाला में 'प्रौद्योगिकी की भूमिका, डिजिटलीकरण, टीएफएम और सतत विकास लक्ष्य 17' पर व्याख्यान दिया।
- चीन के शंघाई में 28–29 मई 2018 को आयोजित एनडीबी की वार्षिक बैठक में भाग लिया।

डॉ. प्रियदर्शी दाश

सहायक प्रोफेसर

- 29–30 जनवरी, 2019 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में टी20 जापान अफ्रीका कार्यदल की बैठक में भाग लिया।
- 6–7 मार्च, 2019 को जेएनयू स्थित आंतरिक एशिया अध्ययन केंद्र में 'गंगा से वोल्गाः आंतरिक एशिया के साथ भारत के जुड़ाव' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'भारत और आंतरिक एशिया के बीच बेहतर आर्थिक संबंधों के वाहक : व्यापार, निवेश और संपर्क' विषय पर प्रस्तुति दी।
- 14–15 मार्च, 2019 को सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक द्वारा 'बिम्सटेक में नई जान फूंकनाः सांस्कृतिक और आर्थिक एकीकरण के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'बिम्सटेक में वित्तीय क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना' विषय पर प्रस्तुति दी।
- 25–26 मार्च 2019 को भारत–अरब सांस्कृतिक केंद्र, जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा 'भारत, चीन और अरब विश्वः नई गतिशीलता की तलाश' पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में 'तेल व्यापार से परे भारत–अरब आर्थिक संबंध' विषय पर प्रस्तुति दी।
- 13–14 सितंबर, 2018 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आईसीडब्ल्यूए द्वारा आयोजित पांचवें भारत–मध्य एशिया संवाद के दौरान 'भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच व्यापार एवं निवेश के संवर्धन के वाहकों के रूप में मध्य एशिया में संपर्क संपर्कों' पर एक प्रस्तुति दी।
- 13–14 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में 'दक्षिणीय एवं त्रिकोणीय सहयोगः सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य और अनुभवजन्य वास्तविकताओं' पर दिल्ली प्रक्रिया – 4 में 'स्थानीय मुद्रा में व्यापार' पर एक प्रस्तुति दी।
- 2–3 अगस्त, 2018 को नेपाल के काठमांडू में आयोजित बिम्सटेक शिखर सम्मेलन पूर्व परामर्श बैठक में पैनल परिचर्चा के दौरान 'बिम्सटेक में प्राथमिकताओं' पर एक प्रस्तुति दी।
- 14–15 अप्रैल, 2018 को इथियोपिया के अदीस अबाबा में आयोजित टी20 अफ्रीका स्थायी समूह की वार्षिक बैठक में 'अफ्रीका में व्यापार एवं निवेशः सीएफटीए और आगे की राह' पर नीतिगत संक्षिप्त प्रस्तुत किया।

डॉ. दुरइराज कुमारसामी

सलाहकार, आरआईएस स्थित एआईसी

- 5 मार्च 2019 को नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 'समकालीन भारत–मलेशिया संबंधों में उभरती गतिशीलता' विषय पर आयोजित सम्मेलन में 'भारत–मलेशिया आर्थिक संबंधः उपलब्धियां और संभावनाएं' विषय पर एक प्रस्तुति दी।
- 11 मार्च, 2019 को पादांग स्टेट यूनीवर्सिटी, पादांग, इंडोनेशिया में 'हिंद–प्रशांत संपर्क संभावनाएं' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'सागरः हिंद–प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में भारत का अनुभव' विषय पर एक प्रस्तुति दी।

नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ

- 26–27 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, वियतनाम अध्ययन केंद्र, समाजवादी गणराज्य वियतनाम के दूतावास और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'भारत–वियतनाम सुदृढ़ आर्थिक संबंधों' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'भारत और वियतनाम के बीच क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला में सुधार' पर एक प्रस्तुति दी।
- 14 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग में 'बीबीआईएन में क्षेत्रीय संपर्क के संभावित नकारात्मक पहलू' पर आयोजित परिचर्चा में भाग लिया।

क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

अध्याय 4

सतत विकास लक्ष्यों पर नया पाठ्यक्रम

आरआईएस ने नई दिल्ली में 6 से 17 अगस्त, 2018 तक भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में 'सतत विकास लक्ष्यों' पर आईटीईसी के क्षमता–निर्माण पाठ्यक्रम का पहला संस्करण आयोजित किया।

24 देशों के मध्य स्तर के सरकारी अधिकारियों/राजनयिकों, नीति प्रोफेशनलों और विद्वानों सहित 32 से भी अधिक प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

इस कार्यक्रम में व्यापक रूप से इन मॉड्यूल को कवर किया गया – सतत विकास लक्ष्य एवं राष्ट्रीय रणनीति; सतत विकास लक्ष्य एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े मुद्दे; सतत विकास लक्ष्य एवं आर्थिक विकास; पर्यावरणीय स्थिरता; संबंधित व प्रासंगिक मुद्दे एवं कार्यान्वयन के साधन और सतत विकास लक्ष्य के लिए वैश्विक साझेदारी व स्थानीयकरण से जुड़े प्रयास।

आरआईएस के आंतरिक या संस्थानिक संकाय के अलावा प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को भी विभिन्न विषयों पर व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था, ताकि प्रतिभागीगण इससे लाभान्वित हो सकें। इस कार्यक्रम का विस्तृत एजेंडा आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत और प्रथाओं पर आरआईएस–एक्जिम बैंक समर स्कूल

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में काम कर रहे विद्वानों के क्षमता निर्माण में योगदान देने के लिए आरआईएस ने भारतीय निर्यात–आयात बैंक (एक्जिम बैंक) के सहयोग से 11–16 जून, 2018 को नई दिल्ली में ग्रीष्मकालीन स्कूल कार्यक्रम का तीसरा संस्करण आयोजित किया। इसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विशेषज्ञता कर रहे एम.फिल और पीएचडी विद्यार्थियों के लिए किया जाता है।

पिछले कुछ वर्षों में आरआईएस ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाओं, व्यापक आर्थिक सहयोग की संरचना और दक्षिणीय सहयोग जैसे क्षेत्रों से जुड़े अनुसंधान एवं नीति में अपने अहम योगदान के लिए विशिष्टता एवं प्रसिद्धि हासिल की है। व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश के मुद्दे दरअसल किसी भी संस्थान की मूल विशेषज्ञता को परिभाषित करते हैं जिससे कई शोध अध्ययनों और विचार–विमर्श का मार्ग प्रशस्त होता है।

एक्जिम बैंक भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को वित्त पोषित

सतत विकास लक्ष्य पर आईटीईसी के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रतिभागीगण आरआईएस के संकाय सदस्यों के साथ उपस्थित हैं।

क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

विज्ञान राजनय पर आईटीईसी के क्षमता निर्माण हेतु कार्यक्रम के प्रतिभागी।

करने, सुविधाजनक बनाने और इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया देश का प्रमुख निर्यात वित्त संस्थान है। आर्थिक अनुसंधान और अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के अपने सतत प्रयासों के एक हिस्से के रूप में एक्जिम बैंक ने विद्वानों को विशेषकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित आर्थिक शोध अध्ययन करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए भी अनेक पहल की हैं।

विशेषज्ञों द्वारा पाठ्यक्रम के दौरान इन मापांक (मॉड्यूल) पर विस्तृत चर्चा हुई: 1: व्यापार सिद्धांत में हाल के घटनाक्रम; 2: व्यापार विश्लेषण के साधन एवं प्रौद्योगिकियां; 3: एफटीए और क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉकों को समझना; 4: प्रौद्योगिकी में व्यापार के मुद्दे एवं वर्गीकरण मुद्दे; 5: व्यापार एवं विकास: आईपीआर एवं नए मुद्दे; और 6: समूह प्रस्तुतियां।

कार्यक्रम का आरम्भ प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक और प्रो. एस.के. मोहंती, आरआईएस के स्वागत भाषण के साथ हुआ। श्री देबाशीष मल्लिक, उप प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात–आयात बैंक; श्री राजीव खेर, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस; और प्रोफेसर रूपा चंदा, कार्यालय प्रमुख, दक्षिण एवं दक्षिण–पश्चिम एशिया के लिए उप क्षेत्रीय कार्यालय, यूएनएस्कैप ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। प्रतिभागियों में भारत के 24 अभ्यर्थी और बिम्सटेक देशों के 5 अभ्यर्थी शामिल थे। अनुसंधान संस्थानों के प्रमुख विशेषज्ञों एवं शिक्षाविदों को व्याख्यान देने और प्रतिभागियों के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

'विज्ञान राजनय' पर आरआईएस–आईटेक कार्यक्रम

विज्ञान राजनय' पर आईटेक–आरआईएस क्षमता निर्माण कार्यक्रम 7–18 जनवरी 2019 के दौरान आयोजित किया गया। 25 देषों के 35 प्रतिभागियों ने इस पाठ्यक्रम में सक्रिय भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया: विज्ञान राजनय का परिचय: अवधारणाएं एवं रूपरेखा; विज्ञान राजनय में अनुभव साझा करना; जैव प्रौद्योगिकी एवं जैव विविधता; जलवायु परिवर्तन; सांस्कृतिक यात्रा; डिजिटल इकोनॉमी व उभरती प्रौद्योगिकियां; प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं विज्ञान राजनय; और सतत विकास लक्ष्य एवं दक्षिण ीय सहयोग। कार्यक्रम की शुरुआत आरआईएस के महानिदेषक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण के साथ हुई। प्रो. के. विजय राघवन, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। डॉ. भास्कर बालाकृष्णन, विज्ञान राजनय फेलो, आरआईएस एवं पूर्व भारतीय राजनयिक और डॉ. पूर्णिमा रूपल, निदेषक, सीईएफआईपीआरए ने भी वक्तवय दिए। समापन सत्र 18 जनवरी 2019 को आयोजित किया गया जिस दौरान श्री दिनकर अस्थाना, अपर सचिव (डीपीएआईआई), विदेष मंत्रालय ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। तथा इसके बाद प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

व्यापार और स्थायित्व पर नया पाठ्यक्रम

आरआईएस ने नई दिल्ली में 9 से 20 जुलाई, 2018 तक 'व्यापार और स्थायित्व' पर प्रथम आईटीईसी पाठ्यक्रम आयोजित किया। विभिन्न विकासशील देशों के मध्य स्तर के सरकारी अधिकारियों, नीति प्रोफेशनलों और शिक्षाविदों सहित 25 से भी अधिक प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

इस कार्यक्रम में व्यापक रूप से विभिन्न विषयों जैसे कि उत्पादन एवं व्यापार, नियामकीय रूपरेखा, जैव विविधता इत्यादि को शामिल किया गया। आरआईएस के संकाय सदस्यों एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने इन विषयों पर व्यापक परिप्रेक्ष्य के बारे में बहुमूल्य जानकारियां दीं। यह कार्यक्रम प्रो. एस. के. मोहंती, आरआईएस द्वारा समन्वित किया गया। कार्यक्रम का विस्तृत एजेंडा आरआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

दक्षिणीय सहयोग पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम

'दक्षिणीय सहयोग के बारे में जानना' विषय पर आईटीईसी क्षमता निर्माण कार्यक्रम आरआईएस में 12–23 नवंबर, 2018 को आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, प्रो. एस. के. मोहंती, प्रो. मिलिंदो चक्रबर्ती और श्री एम. सी. अरोड़ा, आरआईएस के परिचयात्मक सत्र के साथ हुआ। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (एमईआर) श्री आलोक ए. डिमरी ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। 21 देशों के 29 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। विकास सहयोग के कुछ उदाहरण प्रतिभागियों के समक्ष पेश करने के अलावा इस कार्यक्रम में दक्षिणीय सहयोग की सैद्धांतिक रूपरेखा, एसएससी के लिए वैश्विक स्वरूप; भारत के विकास सहयोग; एसएससी के लिए वर्तमान वैश्विक मुद्दों से जुड़े मॉड्यूल को कवर किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने तकनीकी सत्रों और सामूहिक चर्चाओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने विचार–विमर्श करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की। उन्होंने इसके साथ ही स्थिति पत्र (स्टैटस पेपर) भी पेश किए जिनमें क्षेत्रीय एवं वैश्विक संदर्भों और देश के अनुभवों पर प्रकाश डाला गया। इन्हें *'दक्षिणीय सहयोगः अनुभव और चुनौतियां'* नामक एक रिपोर्ट के रूप में पेश किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों और विकास नीति पर आरआईएस–आईटेक कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों और विकास नीति (आईईआईडीपी)' पर आईटेक क्षमता निर्माण कार्यक्रम 11 फरवरी से 8 मार्च

'दक्षिणीय सहयोग के बारे में जानने' पर आयोजित आईटीईसी क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रतिभागी आरआईएस के संकाय सदस्यों के साथ।

क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों और विकास नीति (आईईआईडीपी) पर आईटीईसी के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के कई प्रतिभागी।

2019 के दौरान आयोजित किया गया। 20 देशों के मध्यम स्तर के सरकारी अधिकारियों/राजनयिकों, नीति से जुड़े प्रोफेषनलों और विद्वानों सहित 30 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य विषय थेः व्यापार एवं वित्त पर वैष्विक संस्थागत संरचना, क्षेत्रीय गतिषीलता, आर्थिक एकीकरण एवं विकास सहयोग; बुनियादी ढांचे का वित्तपोशणः विकासषील देषों एवं अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्यताएं; और समाज, साझेदारियां और संस्कृतिः भारतीय परिप्रेक्ष्य। जाने–माने भारतीय विषेशज्ञों ने इन मुद्दों के विभिन्न आयामों पर व्यापक दृष्टिकोण पेश किया।

कार्यक्रम की शुरुआत प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस के स्वागत भाशण के साथ हुई। श्री जे.एस. मुकुल, डीन, विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई) ने आरंभिक भाषण दिया। समापन सत्र की अध्यक्षता आरआईएस के चेयरमैन डॉ. मोहन कुमार ने की। सुश्री नगमा एम. मल्लिक, संयुक्त सचिव (पीपी एंड आर), विदेष मंत्रालय ने समापन भाषण दिया। इस अवसर पर प्रतिभागियों नें इन मुद्दों पर प्रस्तुतियां दीः सतत विकास लक्ष्य एवं सार्वजनिक नीति पर समूह 1ः सुश्री करीना मारिएला जरा तामायो (इक्वाडोर) ; बुनियादी ढांचे/संपर्क/नवीकरणीय ऊर्जा पर समूह 2ः श्रीमती मीनाक्षी डाबी हौजैरी (मॉरीषस) ; व्यापार (व्यापार संतुलन एवं पूंजी प्रवाह पर एफटीए का असर) पर समूह 3ः श्री मोसेस लुफुके (तंजानिया) ; जी 20 / ब्रिक्स पर समूह 4ः श्री हेल्डर पाउलो मचाडो सिल्वा (ब्राजील) ; व्यापार (व्यापार में विकासषील देषों की सौदेबाजी क्षमता) पर समूह 5 : श्री टेस्फेय अयालेव मेकोनेन (इथियोपिया); और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना, विकास वित्त एवं वैष्विक कर मुद्दों पर समूह 6ः डॉ. हेबैतल्लाह हनाफी महमूद एडम (मिस्र)।

अन्य मंचों पर नीतिगत संवाद

प्रो. सविन चतुर्वेदी

महानिदेशक

- 6 मार्च 2019 को फरीदाबाद में यूनेस्को द्वारा 'प्रभावकारी एवं समावेशी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीतियों को विकसित करने' विषय पर आयोजित एसटीआई क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला में 'प्रभावकारी एवं समावेशी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीतियों के विकास' पर विशेष भाषण दिया।
- 4 जून 2018 को गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 'भारत की उभरती वैश्विक सहभागिताः शैक्षणिक और अनुसंधान समुदाय की भूमिका' पर सिक्किम विश्वविद्यालय के छात्रों को व्याख्यान दिया।

श्री राजीव खेर

विशिष्ट फेलो

- 18 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) के डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र में 'वैश्विक व्यापार की बदलती गतिशीलता' विषय पर आईटीईसी प्रतिभागियों के समक्ष एक व्याख्यान दिया।

प्रो. अमिताभ कुंडू

विशिष्ट फेलो

- 14 मार्च 2019 को नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास केंद्र, जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा आयोजित 'समावेशी शिक्षा' पर शिक्षाविदों के लिए नेतृत्व कार्यक्रम (लीप) में एक विशेष व्याख्यान दिया।

प्रो. टी. सी. जेम्स

विजिटिंग फेलो

- 19 जनवरी, 2019 को एम. डी. विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आईपीआर सम्मेलन में 'कॉपीराइट और साहित्यिक चोरी' विषय पर एक व्याख्यान दिया।
- 30 मार्च, 2019 को किशनगढ़ के श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी गर्ल्स कॉलेज में बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरुकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में 'बौद्धिक संपदा अधिकारों और इसके विभिन्न आयामों' पर मुख्य भाषण दिया।

क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

- दिल्ली न्यायिक अकादमी द्वारा न्यायिक अधिकारियों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों और प्रवर्तन पर आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम में भाग लिया और इसके साथ ही 6 अक्टूबर, 2018 को पारंपरिक/स्वदेशी ज्ञान के संरक्षण एवं कृषि उत्पादों व पौधों की किस्मों के संरक्षण पर प्रस्तुतियां दीं।
- 29 मई, 2018 को केआईईटी, गाजियाबाद में कॉपीराइट संरक्षण के महत्व पर व्याख्यान दिया।
- 23 जून 2018 को कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित 'विधि शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स" में एक संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया और भौगोलिक संकेतों के सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर दो व्याख्यान दिए।.

प्रकाशन कार्यक्रम

अध्याय 5

रिपोर्ट/पुस्तकें

वैश्विक दक्षिण में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखलाओं का अहम योगदान
आईटीसी और आरआईएस, जिनेवा, 2019

राउल प्रिबिश और विकास रणनीति
आरआईएस, नई दिल्ली, 2019

सम्मिलित रूप से स्वस्थ भविष्य की ओरः स्वास्थ्य सेवा में भारत की साझेदारियां
आरआईएस, नई दिल्ली, 2019

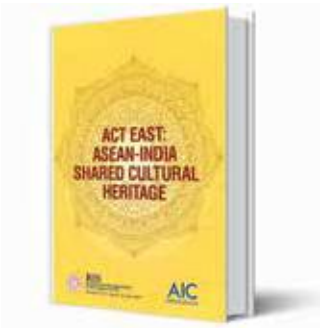

एक्ट ईस्टः आसियान–भारत साझा सांस्कृतिक विरासत
आरआईएस, एआईसी, नई दिल्ली, 2019

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर दक्षिणी परिप्रेक्ष्य
आरआईएस, नई दिल्ली, 2019

व्यापार और विकास के लिए वित्तः दक्षिणी परिप्रेक्ष्य
आरआईएस, नई दिल्ली, 2019

दक्षिणीय सहयोगः अनुभव और चुनौतियां
आरआईएस, नई दिल्ली, 2018

चौथे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के लिए सिफारिशें
आरआईएस, नई दिल्ली, 2018

सतत विकास लक्ष्यः विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य
आरआईएस, नई दिल्ली, 2018

प्रकाशन कार्यक्रम

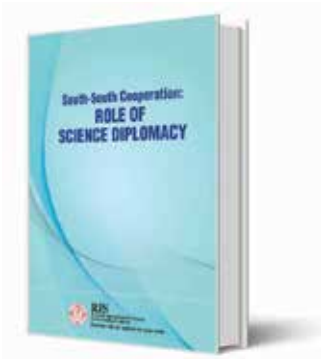

दक्षिणीय सहयोग: विज्ञान राजनय की भूमिका
आरआईएस, नई दिल्ली, 2018

व्यापार और स्थायित्व पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य
आरआईएस, नई दिल्ली, 2018

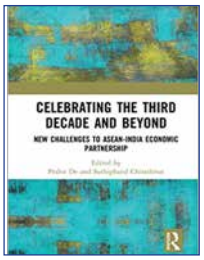

तीसरे दशक और उससे परे का कीर्तिगान करना: आसियान–भारत आर्थिक साझेदारी के लिए नई चुनौतियां,
प्रबीर डे और सुतीपहंद चिरथिवात द्वारा संपादित, रूटलेज, 2018

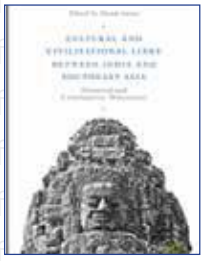

भारत और दक्षिण–पूर्व एशिया के बीच सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत संबंध: ऐतिहासिक और समकालीन आयाम,
श्याम सरन द्वारा संपादित, पालग्रेव मैक. मिलन 2018

दसवां दिल्ली संवाद, आसियान–भारत केंद्र (एआईसी)
आरआईएस, 2018

बुनियादी ढांचे हेतु वित्त जुटाने के लिए नई तलाश
आरआईएस, नई दिल्ली, 2018

एआईआईबी की वार्षिक बैठक 2018 मेजबान देश में सेमिनार पृष्ठभूमि–पत्र
आरआईएस, नई दिल्ली, 2018

संपर्क कॉरिडोर के आर्थिक प्रभावों का आकलन करना: एक अनुभवजन्य विवेचन
प्रबीर डे, सुनेत्र घटक और दुरइराज कुमारसामी, आरआईएस और आरआईएस स्थित एआईसी, 2018

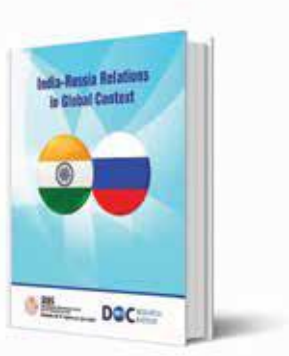

वैश्विक संदर्भ में भारत–रूस संबंध
आरआईएस, नई दिल्ली, 2018

आरआईएस चर्चा पत्र

227 **ब्राजील, चीन, भारत, रूस और दक्षिण अफ्रीका में प्रौद्योगिकी विकास नीतियां,** द्वारा मनमोहन अग्रवाल, अमृता ब्रह्मो और जॉन व्हेली

226 **सौर ऊर्जा का वित्त पोषणः भारतीय अनुभव से सबक,** द्वारा अमितेन्दु पालित

225 **राष्ट्रमंडल और सतत विकास के लक्ष्य,** द्वारा बालाकृष्ण पिसुपति

224 **राष्ट्रमंडल महिला और विकास साझेदारियां,** द्वारा अनुराधा एम. चेनॉय

223 **एक सच्चा जन राष्ट्रमंडलः सामान्य भविष्य की ओर,** द्वारा राजेश टंडन और कौस्तुव कांति बंद्योपाध्याय

233 **औद्योगिक और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विनिर्माण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और क्षेत्रवार प्रोत्साहनों की समीक्षाः 'मेक इन इंडिया' के लिए सबक** द्वारा *सब्यसाची साहा और प्रतिभा शॉ*

232 **भारत में सतत विकास लक्ष्य 4 हासिल करनाः सभी के लिए मात्रात्मक शिक्षा से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ना** द्वारा *बीना पांडे*

231 **भारत में विनिर्माण क्षेत्र** *द्वारा मनमोहन अग्रवाल*

230 **अवसंरचना के विकास के लिए गठबंधन करना और रणनीतियां विकसित करना** द्वारा *गरिमा धीर*

229 **अभिनव व्यवस्थाएं और बहुपक्षवादः नए एमडीबी की गुंजाइश पर एक प्रतिबिंब** द्वारा *सब्यसाची साहा*

228 **अवसंरचना का वित्त पोषण करनाः संसाधन जुटाना और नए साधन तलाशना** द्वारा *प्रियदर्शी दाश*

235 **क्या भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए डिजिटल दृष्टि से तैयार है?** द्वारा रश्मि बंगा

234 **भारत में सतत विकास लक्ष्य के लिए वैचारिक रूपरेखा और निगरानी व्यवस्था विकसित करना** द्वारा कृष्ण कुमार और पी.के. आनंद

238 **देश की आधिकारिक सांख्यिकी के लिए सटीक राह नीतिगत कमजोरी पर विजय पाने की प्रणाली** द्वारा कृष्ण कुमार और पी. के. आनंद

237 **स्थानीय मुद्रा में व्यापारः नेपाल, ईरान और रूस के साथ भारत के रुपया व्यापार का दृष्टांत** द्वारा प्रियदर्शी दाश, मोनिका शर्मा और गुल्फेशान निजामी

236 **सरकार की नीतियां और भारत में दवा उद्योग का विकास 1947–2018 : एक समीक्षा** द्वारा प्रशांत कुमार घोष

आरआईएस का नीतिगत सार पत्र

81 **चाबहारः एक बंदरगाह बेहद दूर** द्वारा *सुभोमय भट्टाचार्जी*

83 **आरआरआईः एक भारतीय परिप्रेक्ष्य**

86 **हेल्थ सिटी के बारे में योजना बनाना और पारंपरिक चिकित्साः अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से सीखना** द्वारा प्रो. टी.सी. जेम्स

85 **आरसीईपी पर उभरती गतिशीलता** द्वारा वी.एस. शेशाद्रि

84 **आरसीईपीः क्यों और कैसे** द्वारा राजीव खेर

83 **आरआरआईः एक भारतीय परिप्रेक्ष्य** (अंग्रेजी)

82 **आरआरआईः एक भारतीय परिप्रेक्ष्य** (हिंदी)

87 **ऊर्जा क्षेत्र और वित्तीय बाजारः भारत के लिए अवसर** द्वारा सुभोमय भट्टाचार्जी

प्रकाशन कार्यक्रम

आरआईएस डायरी

खंड 14 संख्या 2, अप्रैल 2018

खंड 14, संख्या 3, जुलाई 2018

खंड 15 संख्या 1, जनवरी 2019

विकास सहयोग समीक्षा (डीसीआर)

खंड 1, संख्या 1, अप्रैल 2018

खंड 1, संख्या 2, मई 2018

खंड 1, संख्या 3, जून 2018

खंड 1, संख्या 4, जूलाई 2018

खंड 1, संख्या 5, अगस्त 2018

खंड 1, संख्या 6, सितंबर 2018

खंड 1, संख्या 7, अक्टूबर 2018

खंड 1, संख्या 8, नवंबर 2018

खंड 1, संख्या 9, दिसंबर 2018

खंड 1, संख्या 10–12, जनवरी–मार्च 2019

साउथ एशिया इकोनॉमिक जर्नल

खंड 19, संख्या 1 (जनवरी–जून 2018)

खंड 19, संख्या 2 (जुलाई–दिसंबर 2018)

एफआईटीएम का नीतिगत संक्षिप्त

पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय की पहुंच एवं विस्तार और नवाचारों के लिए प्रोत्साहन देना, आरआईएस, संख्या 1, नई दिल्ली, 2017

एफआईटीएम का स्कूपिंग पेपर

#1 टीसीएम के राष्ट्रीय और वैश्विक संवर्धन के लिए चीन की नीतिगत पहल द्वारा टी.सी. जेम्स और नम्रता पाठक

#2 भारत में पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण द्वारा *टी.सी. जेम्स और नम्रता पाठक, सितंबर 2018, नई दिल्ली*

#3 भारत में पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण, अक्टूबर 2018 द्वारा *टी.सी. जेम्स और दिपीका यादव, फरवरी 2016, नई दिल्ली*

विज्ञान राजनय समीक्षा

खंड 1 संख्या 2, जनवरी 2019

विज्ञान राजनय नया अलर्ट

अंक 8 : 16–28 फरवरी 2019; अंक 7 : 01–15 फरवरी 2019;

अंक 6 : 16–31 जनवरी 2019; अंक 5 : 01–15 जनवरी 2019

आरआईएस संकाय द्वारा बाह्य प्रकाशनों में योगदान

चतुर्वेदी, सचिन. 2018. *'आर्थिक विकास और सहयोग'* । नेपाल–भारत संबंधों पर तीन दिवसीय द्विपक्षीय सेमिनार की कार्यवाही, 3–5 मार्च, 2017, सिमारा, नेपाल।

चतुर्वेदी, सचिन 2018. *नेपाल– भारत संबंधों में 'व्यापार, पारगमन और आपूर्ति': आर्थिक विकास और सहयोग,* 3–5 मार्च, 2017 को तीन दिवसीय द्विपक्षीय सेमिनार की कार्यवाही, सिमारा, नेपाल।

चतुर्वेदी, सचिन. 2018. व्यापार युद्धः शुल्कों (टैरिफ) द्वारा पछाड़ा गया – यह अमेरिका नहीं है जो वैश्विक व्यापार आदेश का शिकार बना है; यह भारत है। *द वीक,* 01 जुलाई, 2018।

चतुर्वेदी, सचिन. 2018. 'लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्य का स्थानीयकरण करें।' *फाइनेंशियल एक्सप्रेस,* 15 जून 2018।

चतुर्वेदी, सचिन। 2018 'सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वैश्विक साझेदारी जरूरी' *द एशियन एज,* 9 जुलाई।

चतुर्वेदी, सचिन। 2018 'विकास संविदा' की रूपरेखा के तहत भारत के विकास सहयोग की गतिषीलता। संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली का वित्तपोशणः द्वार खोलना, संयुक्त राष्ट्र एमपीटीपी कार्यालय, पृष्ठ 75–78।

चतुर्वेदी, सचिन। 2018 ''बहुपक्षवाद और उभरती वैश्विक व्यवस्था के प्रति भारत का दृश्टिकोण।' *इंडियन फॉरेन अफेयर्स जर्नल,* खंड 13 (2), अप्रैल–जून 2018, पृष्ठ 128–135।

चतुर्वेदी, सचिन 2018. 'ब्लू इकॉनोमी' , बिबेक देबरॉय, अनिर्बन गांगुली और किशोर देसाई (संपादक), *मोदी सरकार के दौर में नए भारत का निर्माणः बदलाव।* नई दिल्लीः विस्डम ट्री।

चतुर्वेदी, सचिन और चक्रबर्ती, मिलिंदो। 2018. बापा का स्मरण करना और आगे की राह, *स्पैनिश जर्नल ऑफ डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन,* संख्या 43।

चतुर्वेदी, सचिन 2019. 'व्यापार, उत्पादन और उभरती अर्थव्यवस्थाएंः कृशि एवं विनिर्माण में उभरते रुझान' *तुर्की नीति त्रैमासिक,* शीतकालीन 2019, खंड 17

चतुर्वेदी, सचिन 2019. अंतरिम बजट मुख्यतः अल्पकालिक जरूरतों और दीर्घकालिक विजन को संतुलित करने के बारे में है। *द इकोनॉमिक टाइम्स,* 03 फरवरी

चतुर्वेदी, सचिन और प्रियदर्शी दाश। 2019. 'भारतीय परिप्रेक्ष्य से हिंद–प्रशांत सहयोग'। *जापान स्पॉटलाइट,* खंड 38, संख्या 1, पृष्ठ 10–13. जनवरी–फरवरी।

प्रबीर डे और सुथिपंद चिरथिवत. 2018. *तीसरे दशक का जश्न मनाना और उससे परेः आसियान– भारत आर्थिक साझेदारी के लिए नई चुनौतियां,* रूटलेज, नई दिल्ली, 2018 (संपादक और लेखक)।

प्रबीर डे. 2018. 'लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट की ओरः तीसरे दशक में आसियान–भारत साझेदारी को नया स्वरूप देना' रुमेल दहिया और उदय भानु सिंह (संपादक) *आसियान–भारत संबंधः एक नया प्रतिमान,* आईडीएसए, नई दिल्ली।

प्रबीर डे. 2018. "आसियान–भारत मूल्य श्रृंखला के लिए संपर्क का निर्माण करना हर्श वी. पंत (संपादक) *अगले 25 वर्शों के लिए भारत–आसियान संबंधों की दिशा तय करना*। ओआरएफ, नई दिल्ली।

डे, प्रबीर, सुनेत्र घटक और दुरइराज कुमारसामी। 2019. 'भारत में संपर्क कॉरिडोर के आर्थिक प्रभावों का आकलनः एक अनुभवजन्य परख'। *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली,* खंड 54, संख्या 11 ।

डे, प्रबीर और दुरइराज कुमारसामी। 2019. 'व्यापार लागत और व्यापार के आपसी संबंधों का आकलन करनाः ग्रैविटी मॉडल के अनुप्रयोग', *भारतीय व्यापार विष्लेशिकीः रुझान और अवसर* में अध्याय 13, संपादक बिश्वजीत नाग और देबाशीष चक्रबर्ती, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली

डे, प्रबीर (2018) 'बिम्सटेक को नई ऊंचाइयां हासिल करनी चाहिए', *ईस्ट एशिया फोरम,* 25 अगस्त 2018।

डे, प्रबीर। 2018. 'दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ के लिए संपर्क 2.0' , पारस खरेल (संपादक), *दक्षिण एशियाई सहयोगः नए और पुराने मुद्दे,* 'सावटी', काठमांडू।

डे, प्रबीर। 2018. 'हिंद–प्रशांत सहयोगः संपर्क पर कुछ विचार' लतिन मानसिंह, अनूप के. मुद्गल और उदय भानु सिंह (संपादक), पूरबसाः *पूरब का पूरब से समागमः हिंद–प्रशांत के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र और पूर्वी भारत के*

बीच तालमेल बैठाना, पेंटागन प्रेस, नई दिल्ली।

डे, प्रबीर। 2018. 'दक्षिण एशिया में आर्थिक गलियारों को विकसित करनाः प्राथमिकताएं और आगे की जिम्मेदारी', सार्क सचिवालय में (संपादित), *दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ के लिए अगले कदमः क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण पर एक अध्ययन,* काठमांडू।

डे, प्रबीर। 2018. 'दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ के लिए व्यापार में सुविधा के उपाय', सार्क सचिवालय में (संपादित), *दक्षिण एश्याई आर्थिक संघ के लिए अगले कदमः क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण पर एक अध्ययन,* काठमांडू।

डे, प्रबीर। 2018. 'बीसीआईएम आर्थिक गलियारा और पूर्वोत्तर भारतः समावेशी विकास एजेंडे की आवश्यकता', गुरुदास दास और सी. जोशुआ थॉमस (संपादक), *बीसीआईएम आर्थिक सहयोगः भू–अर्थशास्त्र और भू–राजनीति का पारस्परिक प्रभाव,* रूटलेज, नई दिल्ली।

कुंडू, अमिताभ। (सह–लेखक)। 2019. 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानव धनः एक महत्वपूर्ण आकलन।' *भूगोल और आप,* 31 जनवरी।

कुंडू, अमिताभ। 2019. 'भारत में गतिशीलताः हालिया रुझान और डेटाबेस संबंधी मुद्दे' *सोशल चेंज* दिसंबर–जनवरी।

कुंडू, अमिताभ। (सह–लेखक)। 2019. 'भारत में प्रवासन, शहरीकरण और अंतर–राज्य विषमता' हक, टी. (संपादक), *सामाजिक विकास रिपोर्ट,* दिसम्बर–जनवरी।

कुंडू, अमिताभ। 2019. 'गरीबों को अप्रत्याशित लाभ?' *बिजनेस स्टैंडर्ड,* 23 फरवरी।

जेम्स, टी. सी. 2018. आईपीआर में 'जैव प्रौद्योगिकी पेटेंट एवं मानवाधिकार' और '*पारंपरिक ज्ञान, टीकेडीएल एवं मानवाधिकार' और भारत पर विशेष जोर के साथ मानवाधिकार* द्वारा मनोज कुमार सिन्हा और जुपी गोगोई (संपादक), भारतीय विधि संस्थान।

दुरइराज कुमारसामी. 2018. 'दक्षिण और पूर्वी एशिया को एकीकृत करनाः क्षेत्रीय सहयोग और विकास के अर्थशास्त्र' पर पुस्तक समीक्षा, द्वारा जयंत मेनन और टी.एन. श्रीनिवासन (संपादक), ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2018, पृष्ठ 397, *साउथ एशिया इकोनॉमिक जर्नल* में, खंड 19, संख्या 1, पृष्ठ 140–143।

श्रीनिवास, रवि के. 2018. "भारत में स्वास्थ्य प्रभाव कोश के माध्यम से दवाओं तक पहुंच बढ़ानाः एक हितधारक विशलेषण। पैट्रिक मैकमुल्लन, वामादेवन एस. अजय, रवि श्रीनिवास, संदीप भल्ला, दोरइराज प्रभाकरन और अमिताभ बनर्जी (संपादक) *ग्लोबल हेल्थ एक्शन,* 11:1, 1434935, डीओआईः 10.1080 / 16549716.2018.143493.

श्रीनिवास, रवि के. 2018. 'हालियाः 'संघर्शरत शासन व्यवस्थाएंः पहुंच एवं लाभ साझाकरण पर विवाद और वायरस के नमूनों को साझा करना '। *यूरोपियन जर्नल ऑफ रिस्क रिसर्च* (ईजेआरआर) (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस) खंड 8, पष्ठ, 573–579

साहा, सब्यसाची (सह–लेखक)। 2019. 'एक वार्ता फोरम के रूप में विश्व व्यापार संगठन में नई जान फूंकने' पर टी20 जापान नीतिगत सार–पत्र, मार्च।

साहा, सब्यसाची (सह–लेखक)। 2019. 'सतत और समावेषी विकास के लिए वैष्विक मूल्य श्रृंखलाओं के विस्तार एवं पुनर्गठन' पर टी20 जापान नीतिगत सार–पत्र, मार्च।

आंकड़ें एवं सूचना केन्द्र

अध्याय 6

आरआईएस के डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ने हाल के महीनों में नवीनतम विशिष्ट प्रकाशनों, रिपोर्टों, डेटाबेस, ई–जर्नल्स एवं लेखों इत्यादि को हासिल किया है, ताकि आरआईएस की संकाय और आगंतुक विद्वानों को अद्यतन जानकारियां उपलब्ध कराई जा सकें। यह कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विभिन्न प्रकाशनों या आलेखों के कार्यक्रम का आदान–प्रदान करता है और विभिन्न स्तरों पर विकासशील देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर और भी अधिक प्रकाशनों या आलेखों तथा अध्ययन कार्यक्रमों को जोड़कर संसाधन आधार को निरंतर समृद्ध करता रहता है।

इस केंद्र के प्रमुख वैश्विक संस्थानों जैसे कि एफएओ, आईएलओ, ओईसीडी, यूएन, अंकटाड, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, इत्यादि के साथ घनिष्ठ जुड़ाव हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्य–पत्र (वर्किंग पेपर), परिचर्चा पत्र (डिस्कशन पेपर), री–प्रिंट्स, समसामयिक पत्र दरअसल प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में या तो परस्पर आदान–प्रदान किए गए कार्यक्रमों के जरिए प्राप्त होते हैं या संस्थागत वेबसाइटों के माध्यम से डाउनलोड किए जाते हैं। वर्तमान केंद्र में 25,225 से भी अधिक पुस्तकें हैं जिनमें सरकारी प्रकाशन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में अन्य शोध संस्थानों के दस्तावेज शामिल हैं। इनके अलावा सजिल्द पुस्तक के रूप में 1850 पत्र–पत्रिकाएं हैं। इस केंद्र ने 630 से भी अधिक प्रिंट और ऑनलाइन पत्र–पत्रिकाओं की सदस्यता भी ले रखी है जिनमें जस्टर, आईएमएफ ई–लाइब्रेरी, एल्सवियर– साइंसडायरेक्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, विली इत्यादि शामिल हैं। इतना ही नहीं, इस केंद्र को प्रतिष्ठित स्रोतों से सम्मानार्थ भेंट के आधार पर लगभग 50 पत्र–पत्रिकाएं प्राप्त होती हैं। 350 से भी अधिक सीडी रॉम और डेटाबेस हैं। एक और खास बात यह है कि 'डेलनेट' का सदस्य होने के नाते यह संसाधन–साझाकरण को बढ़ावा देता है।

इस केंद्र में आसान पहुंच के लिए इंट्रानेट के माध्यम से ऑनलाइन समृद्ध संग्रह उपलब्ध है।

अभिलेखन केंद्र/पुस्तकालय के संग्रह में ये शामिल हैं

- पुस्तकें
- सांख्यिकीय वार्षिकी
- दस्तावेज–डब्ल्यूपी–ओपी–डीपी

- जर्नल / पत्र–पत्रिकाएं (प्रिंट+ऑनलाइन+सीडी–रॉम)
- भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही तरह के समाचार पत्र
- पिछला संस्करण (बैक वॉल्यूम)
- सीडी–रॉम
- सीडी–रॉम में डेटाबेस
- आरआईएस डेटाबैंक

व्यापार, टैरिफ एवं गैर–टैरिफ उपायों, भुगतान संतुलन, वित्तीय सांख्यिकी, विकास सांख्यिकी, औद्योगिक सांख्यिकी, बौद्धिक संपदा सेवाओं और कॉरपोरेट डेटा एवं सूचना पर आरआईएस का वैश्विक डेटाबेस। भारतीय आंकड़े 8– अंकीय स्तर पर व्यापार संबंधी टाइम सीरीज डेटाबेस, भारतीय कंपनियों एवं उनके वित्तीय प्रदर्शन के डेटाबेस, सामाजिक–आर्थिक डेटाबेस और सीमा शुल्क टैरिफ आंकड़ों को कवर करता है।

आरआईएस का डेटा सर्वर

आरआईएस एक आधुनिक डेटा सर्वर का रख–रखाव बिल्कुल सही ढंग से कर रहा है जिसमें उसके आंकड़ो कोष की बढ़ी हुई सुरक्षा के तहत आंकड़ों को नष्ट करने वाले वाइरल या हैकिंग सहित किसी भी संभावित बाहरी हमले से बचाव की पुख्ता व्यवस्था की गई है। आरआईएस ने त्वरित संदर्भ के लिए

आंकड़े एवं सूचना केन्द्र

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टाइम सीरीज आंकड़ा हासिल किया है। इसने टैरिफ आंकड़ा कोष, भारतीय कंपनियों के डेटाबेस, व्यापार आंकड़ों की दिशा (डॉट्स), विश्व विकास संकेतकों (डब्ल्यूडीआई), इत्यादि के साथ इस पर महत्वपूर्ण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आंकड़ा (एचएस एंड एसआईटीसी) अपलोड किए हैं। सर्वर पर आंकड़ा कोष को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। यह संकाय के सदस्यों को तत्काल अद्यतन डेटा उपलब्ध कराता है जो उनके साक्ष्य–आधारित शोध अध्ययनों में गहराई से मदद करता है। यही नहीं, ऐसे में व्यक्तिगत आरआईएस संकाय सदस्यों के लिए महंगी बहु–वैश्विक डेटा प्रणालियों को खरीदने की जरूरत नहीं रह जाती है।

आरआईएस की वेबसाइट और ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर

(www.ris.org.in)

आरआईएस की वेबसाइट को प्रतिदिन अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली एवं यूजर (उपयोगकर्ता) अनुकूल सामग्री के साथ नवीनीकरण किया जाता है और यह नवीनतम सुविधाओं एवं कार्यों से सुसज्जित या लैस है। इसे आरआईएस की आंतरिक टीम द्वारा वास्तविक समय पर अपडेट किया जाता है, ताकि उसके आउटरीच कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में वैश्विक सार्वजनिक डोमेन में गहन अनुसंधान अध्ययनों और संबंधित घटनाक्रमों को उपलब्ध कराया जा सके। यह स्वास्थ्य, व्यापार, वित्त, निवेश, विकास सहयोग, वैश्विक आर्थिक मुद्दों, क्षेत्रीय सहयोग, दक्षिणीय सहयोग, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित आरआईएस के कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्रों के बारे में व्यापक अद्यतन जानकारी प्रदान करती है। यह अनुसंधान रिपोर्टों, पत्र–पत्रिकाओं, सूचना–पत्र (न्यूजलेटर) और मीडिया लेखों के रूप में आरआईएस द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकाशनों की विस्तृत श्रृंखला की मुफ्त डाउनलोड सुविधा प्रदान करती है। इसमें आरआईएस द्वारा आयोजित विभिन्न सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं का विवरण भी है। चालू वित्त वर्ष (2018–19) के दौरान तीन नए उप–कार्य क्षेत्रों (सब–डोमेन) को आंतरिक तौर पर विकसित किया गया है और फिर उन्हें आरआईएस की वेबसाइट से लिंक कर दिया गया है, ताकि उनकी स्पष्ट और व्यापक पहुंच संभव हो सके। अब आरआईएस की मुख्य वेबसाइट के अंतर्गत ग्यारह उप–कार्य क्षेत्र (सब–डोमेन) हैं। इनमें ये शामिल हैं:

एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर
http://aagc.ris.org.in

आसियान भारत केंद्र
http://aic.ris.org.in

ब्लू इकोनॉमी फोरम
http://blueeconomyforum.ris.org.in

भारतीय विकास सहयोग के लिए फोरम
http://fidc.ris.org.in

भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पर फोरम (एफआईटीएम)
http://fitm.ris.org.in

वैश्विक विकास केंद्र
http://gdc.ris.org.in

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) पहल
http://iora.ris.org.in

न्यू एशिया फोरम
http://newasiaforum.ris.org.in

सतत विकास लक्ष्यों पर आरआईएस का कार्यक्रम
http://sdg.ris.org.in

नेटवर्क ऑफ सदर्न थिंक–टैंक्स (नेस्ट)
http://southernthinktanks.ris.org.in

एफआईएसडी
http://fisd.ris.org.in

इसके अलावा, वेबसाइट पर निम्नलिखित वेबसाइट पेज भी हैं :

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
http://ris.org.in/asian-infrastructure-investment-bank

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (एसटीआईपी) फोरम
http://ris.org.in/science-technology-and-innovation-policy-stip-forum-and-monthly-lecture-series-0

दिल्ली प्रोसेस
http://ris.org.in/delhi-process

गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर दस्तावेज
http://ris.org.in/documents-non-aligned-movement

समर स्कूल
http://ris.org.in/summer-school-0

पेरिस शांति फोरम
http://ris.org.in/deadline-extended-extra-time-submit-your-project-paris-peace-forum

आरआईएस की देख–रेख वाली अन्य वेबसाइटें

नेटवर्क ऑफ सदर्न थिंक–टैंक्स (नेस्ट)
http://southernthinktanks.org

एफआईएसडी
http://fisd.in

इब्सा
http://ibsa-trilateral.org

दक्षिण एशिया नीतिगत अध्ययन केंद्र (एसएसीईपीएस)
http://saceps.org.in

चालू वित्त. वर्ष (2018–19) के दौरान आरआईएस की वेबसाइट ने 'हिट' की कुल संख्या में शानदार वृद्धि दर्ज की है। इसने गूगल द्वारा संचालित शीर्ष अनुसंधान परिणामों में से एक का दर्जा सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है जो इसकी निरंतर बढ़ती दृश्यता को रेखांकित करता है। आरआईएस नियमित रूप से अपने त्रैमासिक ई–न्यूजलेटर और मासिक ई–पत्रिका को भी प्रकाशित करता है जिन्हें प्रमुख नीति–निर्माताओं एवं आकृतिकारों, थिंक टैंकों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, प्रमुख शिक्षाविदों और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अन्य प्रख्यात हस्तियों के बीच दुनिया भर में प्रसारित किया जाता है, ताकि उन्हें विकासशील देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले मुद्दों पर आरआईएस द्वारा किए जा रहे विश्वसनीय शोध कार्यों की विस्तृत विविधता से अवगत कराया जा सके।

सोशल मीडिया

आरआईएस ने ट्विटर, फेसबुक एवं यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया मंचो पर अपनी उपस्थिति काफी बढ़ा दी है और बड़ी संख्या में इसके अनुगामी भी हैं। आरआईएस के यूट्यूब चैनल को निरंतर अपडेट रखा जाता है। लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग वाले आयोजनों को इसकी प्लेलिस्ट में उपलब्ध कराया जाता है। आरआईएस के यूट्यूब चैनल की दर्शक संख्या में अच्छी–खासी वृद्धि दर्ज की गई है तथा उसका ग्राहक आधार भी अब और ज्यादा बढ़ गया है।

आरआईएस फेसबुक और ट्विटर

4 हजार से भी अधिक अनुगामी हैं और इसके पेजों को लोगों की रायशुमारी के आधार पर 5 में से 4.3 रेटिंग दी गई है। ट्विटर हैंडल के 4 हजार से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वास्तविक समय पर लोगों की त्वरित पहुंच के लिए आरआईएस के प्रत्येक प्रमुख कार्यकलाप को इन दोनों ही प्लेटफॉर्मों पर तुरंत उपलब्ध कराया जाता है। यही नहीं, दर्शकों की ओर से मिली प्रतिक्रिया अत्यंत उत्साहजनक है।

आरआईएस की इंट्रानेट सुविधा

संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए इंट्रानेट सुविधा है जो कर्मचारियों को उनकी सेवाओं से जुड़ी बातों के संबंध में पासवर्ड संरक्षित जानकारियां प्रदान करती है, जिनमें अवकाश का रिकॉर्ड, वेतन पर्ची (सैलरी स्लिप), चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति और अन्य विवरण शामिल होते हैं। यह अपने संकाय के लिए अनुसंधान डेटाबेस भी प्रदान करती

है जो सीडी प्रारूप में उपलब्ध होता है और जो अन्य बातों के अलावा व्यापार आंकड़ों की दिशा, कस्टाडा, विश्व विकास संकेतकों, सरकारी वित्तीय आंकड़ों (आईएमएफ) एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आंकड़ों (आईएमएफ) को कवर करता है।

वित्त वर्ष 2018–19 2019 में देशों द्वारा हिट्स

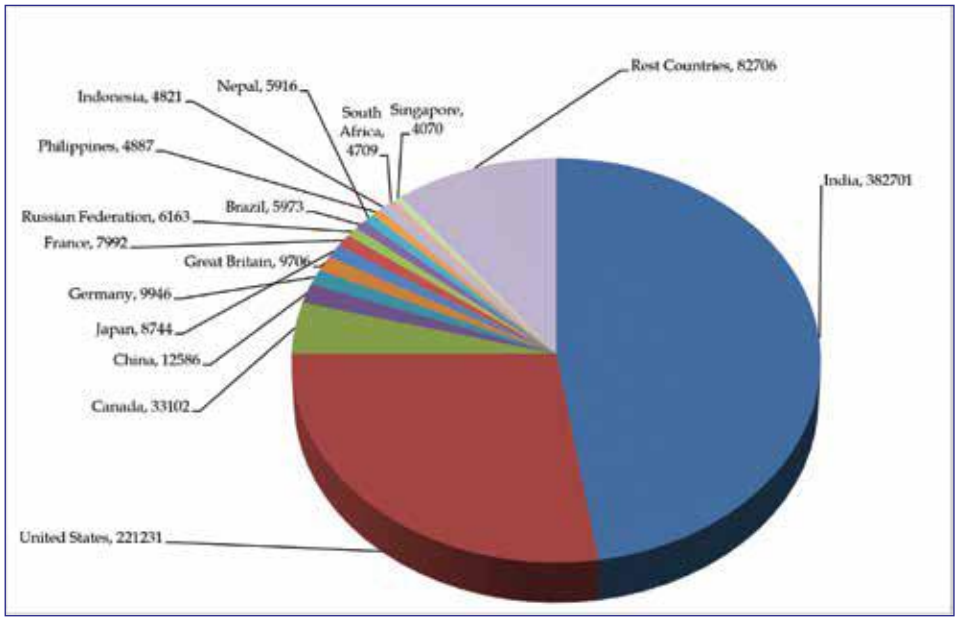

वित्त वर्ष 2018–19 में आरआईएस सब–डोमेन में हिट्स

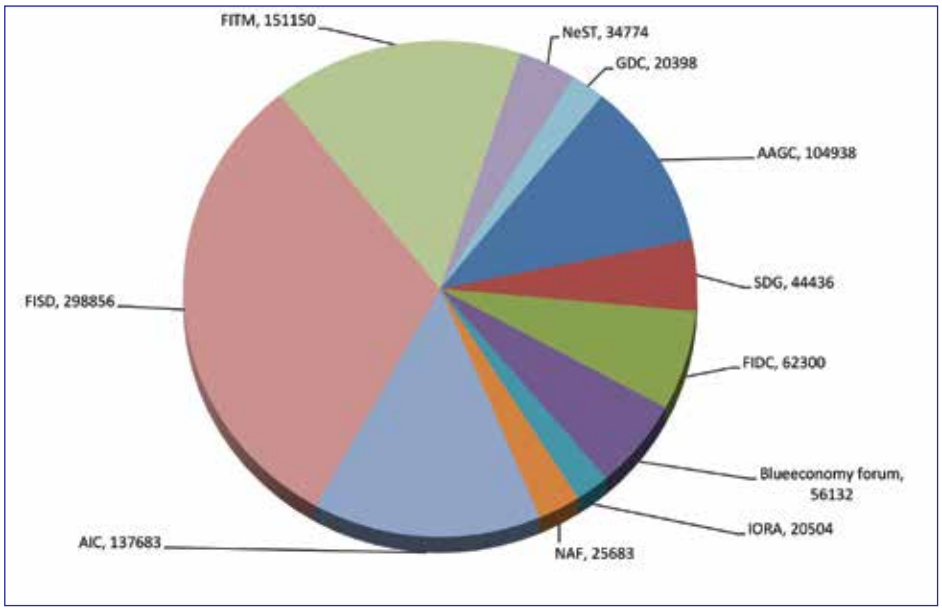

मानव संसाधन

अध्याय 7

प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक
विशेषज्ञता : अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामले, प्रौद्योगिकी एवं नवप्रवर्तत तथा विकास सहयोग

सकाय

डॉ एस के मोहंती
प्रोफेसर
विशेषज्ञता : वैश्विक एवं क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण तथा विकास संबंधी आर्थिक मामले

डॉ सब्यासाची साहा
सहायक प्रोफेसर
विशेषज्ञता : प्रोद्योगिकी एवं विकास, नवाचार और बौद्धिक संपदा अधिकार, आर्थिक विकास एवं विश्व व्यापार संगठन

डॉ प्रियदर्शी दाश
अनुसंधान एसोसिएट
(31 मई 2018 तक)
सहायक प्रोफेसर
(01 जून 2018 से)
विशेषज्ञता : अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त

डॉ बीना पाण्डेय
अनुसंधान एसोसिएट
विशेषज्ञता : सामाजिक क्षेत्र, जेंडर सशक्तिकरण एवं विकास संबंधी मामले

विशिष्ट फैलो

श्री राजीव खेर
सलाहकार
विशेषज्ञता: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य

श्री अमर सिन्हा
सलाहकार
विशेषज्ञता: आर्थिक कूटनीति और दक्षिणीय सहयोग

प्रो. अमिताभ कुंडू
सलाहकार
विशेषज्ञता: सतत विकास लक्ष्य एवं क्षेत्रीय सहयोग के लिए प्रभाव आंकलन पद्धति

विजिटिंग फैलो/सलाहकार/अनुसंधान एसोसिएट

श्री भास्कर बालाकृष्णन
साइंस डिपलोमेसी फैलो
विशेषज्ञताः एसटीआई सहयोग एवं विज्ञान नीति

डॉ. के रवि श्रीनिवास
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञताः बौद्धिक संपदा अधिकार एवं वैश्विक व्यापार

प्रो. टी सी जेम्स
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञताः बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी (आईपीआर)

डॉ. सुशील कुमार
सलाहकार
विशेषज्ञताः अतंर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त

प्रो. मिलिंदो चक्रवर्ती
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञताः सूक्ष्म–अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास सहयोग और मूल्यांकन

श्री सुभोमॉय भट्टाचार्य
सलाहकार
विशेषज्ञताः सार्वजनिक नीति एवं ऊर्जा विशेषज्ञ

डॉ. पी के आनन्द
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञताः आर्थिक विकास और विकास

श्री अरुण सोमाचुदन नायर
सलाहकार
विशेषज्ञताः विदेशी व्यापार एवं निवेश

श्री कृष्ण कुमार
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञताः आधिकारिक सांख्यिकी एवं सतत विकास लक्ष्य

डॉ. आभा जैसवाल
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञताः सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति और प्रबंधन

डॉ. अमित कुमार
अनुसंधान सहयोगी
विशेषज्ञताः नवप्रवर्तन, दूरदर्शिता एवं नियंत्रण

डॉ. नम्रता पाठक
अनुसंधान एसोसिएट
विशेषज्ञताः पारंपरिक ज्ञान

सुश्री निमिता पाण्डेय
अनुसंधान एसोसिएट
विशेषज्ञता: विज्ञान नीति

श्री संजय कुमार मलिक
अनुसंधान सहायक
(मई 2018 तक)

श्री प्रनय सिन्हा
अनुसंधान एसोसिएट
विशेषज्ञता: विकास सहयोग

श्री सईद मोहम्मद अली
अनुसंधान एसोसिएट
(सितम्बर 2018 तक)

श्री सलाउदीन अयूब
अनुसंधान एसोसिएट
(मार्च 2019 से)

आसियन–भारत केंद्र

डॉ. प्रबीर डे
प्रोफेसर/समन्वयक, एआईसी
विशेषज्ञता: अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं परिवहन संबंधी सुविधाएं, सेवा क्षेत्र में व्यापार

डॉ. दूराईराज कुमारासामी
सलाहकार
विशेषज्ञता: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एवं विदेश निवेश एवं व्यवहारिक अर्थमिति

सुश्री श्रेया पान
अनुसंधान सहायक
विशेषज्ञता: वैश्विक व्यापार

सुश्री सुनेत्रा घटक
अनुसंधान सहायक
विशेषज्ञता: श्रम, आर्थिक मामले, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मामले
(दिसम्बर 2018 तक)

सुश्री कोमल बिसवाल
अनुसंधान सहायक
(जनवरी 2019 तक)

वैश्विक विकास पर पहल

श्री गौरव शर्मा
नीती प्रबन्धक
(15 मार्च 2019 से)

अनुसंधान सहायक

सुश्री प्रतिवा सॉव
एम.ए. (इकोनोमिक्स)

सुश्री अमीका बावा
मास्टर्स इन डिप्लोमेसी,
लॉ एवं बिसनेस

श्री अपूर्व भटनागर
एम.ए. (डेवलपमेंट इकोनोमिक्स)

सुश्री चांदनी डवानी
एम.ए. (इकोनोमिक्स)

सुश्री अदिति गुप्ता
एम.ए. (इकोनोमिक्स)

श्री अंकुर जयसवाल
एम.एस.सी (इकोनोमिक्स)

श्री आकांश खण्डेलवाल
एम.ए. (इकोनोमिक्स)
(जून 2019 तक)

सुश्री गीतिका खंडुजा
एम.ए. (पब्लिक पॉलिसी)
(जुलाई 2019 तक)

सुश्री ईशा गुप्ता
एम.ए. (इकोनोमिक्स)
(मार्च 2019 तक)

श्री प्रत्युश शर्मा
एम.ए. (इन्टरनैशनल रिलेशन्स)
(जुलाई 2018 तक)

सुश्री सनूरा फरनैन्डिस
एम.ए. (डेवलपमेंट इकोनोमिक्स)
(जुलाई 2018 तक)

सुश्री श्रुति खन्ना
एम.ए. (इकोनोमिक्स)
(जुलाई 2018 तक)

श्री वैभव कौशिक
एम.ए. (इकोनोमिक्स)
(दिसम्बर 2018 तक)

सुश्री दीपिका यादव
एम.ए. (इकोनोमिक्स)
(मई 2018 तक)

श्री इमरान खान
एम.ए. (इकोनोमिक्स)
(जून 2018 तक)

श्री कौस्तव चक्रबर्ती
एम.ए. (ग्लोबलाइसेशन एवं डेवलपमेंट)
(अप्रैल 2019 तक)

सहायक वरिष्ठ अध्येता

प्रोफेसर अनिल सुकलाल
उप महानिदेशक, एशिया और मध्य पूर्व, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग विभाग, दक्षिण अफ्रीका

प्रोफेसर हरिबाबू ईजनवरजला
पूर्व कुलपति प्रभारी, हैदराबाद विश्वविद्यालय

डॉ. बेनू श्नाइडर
पूर्व में संयुक्त राष्ट्र एवं अंकटाड के साथ और भारतीय रिजर्व बैंक में सलाहकार

प्रोफेसर अमृता नार्लीकर
अध्यक्ष, जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एंड एरिया स्टडीज (गीगा)

प्रोफेसर मुकुल जी. अशर
प्रोफेसरियल फेलो, ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर

डॉ. बालाकृष्ण पिसुपति
चेयरपर्सन, फ्लेज और पूर्व अध्यक्ष, एनबीए, चेन्नई

डॉ. बिष्वजीत बनर्जी
मुख्य अर्थशास्त्री, वित्त मंत्रालय, स्लोवाक गणराज्य और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, अशोक विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा

प्रोफेसर मनमोहन अग्रवाल
आरबीआई के पूर्व चेयर प्रोफेसर, विकास अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम

प्रोफेसर शाहिद अहमद
प्रोफेसर और प्रमुख, अर्थशास्त्र विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया

प्रोफेसर श्रीविद्या राघवान
कानून के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा कॉलेज ऑफ लॉ, नॉर्मन, अमेरिका

डॉ. रामकिशन एस. राजन
वाइस–डीन (अनुसंधान) और प्रोफेसर, ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर

डॉ. सुमा अत्रे
प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस और रणनीति, ब्रुनेल बिजनेस स्कूल, यूके

डॉ. टी. पी. राजेंद्रन
पूर्व सहायक महानिदेशक, आईसीएआर और विजिटिंग फेलो, आरआईएस

प्रोफेसर केविन पी. गालाघेर
प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, बोस्टन यूनिवर्सिटी; सीनियर एसोसिएट, जीडीएई, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी

स्टाफ के अन्य सदस्य

श्री महेश सी अरोड़ा
निदेशक, वित्त एवं प्रशासन

महानिदेशक कार्यालय

श्री तीश कुमार मल्होत्रा, प्रभारी, महानिदेशक कार्यालय
श्रे एन एन कृष्णन, निजी सचिव
श्रीमती रितु परनामी, निजी सचिव
सुश्री गोहर नाज, सचिवीय सहायक

प्रकाशन विभाग

श्री तीश कुमार मल्होत्रा, प्रकाशन अधिकारी
सुश्री शशि वर्मा, (संपादकीय) सहायक
श्री सचिन सिंघल, प्रकाशन सहायक (वेब और डिजाइन)

आंकड़ा एवं सूचना केन्द्र

श्रीमती ज्योति, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
श्रीमती सुशीला, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष

सूचना प्रौद्योगिकी/डॉटाबेस एकक

श्रीमती सुषमा भट्ट, उपनिदेशक, आंकड़ा प्रबंधन
श्री चन्द्र शेखर पुरी, उपनिदेशक, प्रणाली
श्रीमती पूनम मल्होत्रा, डाटा एंट्री आपॅरेटर
श्री सत्यपाल सिंह रावत, जूनियर सहायक
श्रीमती गीतिका शर्मा, डाटा एंट्री आपॅरेटर
श्री सौम्य रंजन, आईटी सहायक

वित्त एवं प्रशासन

श्री वी कृष्णामणि, उपनिदेशक (वित्त एवं लेखा)
श्री डी पी काला, उपनिदेशक (प्रशासन एवं स्थापना) (सितम्बर 2018 तक)
श्रीमती शीला मल्होत्रा, अनुभाग अधिकारी (लेखा)
श्री अमरेन्द्र सिंह बर्तवाल, कन्सलटेंट (लेखा)
श्री हरकेश, अनुभाग अधिकारी
श्रीमती अनु बिष्ट, सहायक
श्री सुरजीत, लेखाकार
श्री अनिल कुमार, सहायक
श्री पियूष वर्मा, अवर श्रेणी लिपिकं
श्रीमती शालिनी शर्मा, स्वागती

अनुसंधान सहयोग

सुश्री किरन वाघ, निजी सचिव
श्री सुरेन्द्र कुमार, निजी सहायक
श्रीमती बिन्दु गंभीर, आशुलिपिक
श्री जे. श्रीनिवास राव, सहायक
श्री बैदनाथ पाण्डेय, कार्यालय सहायक

सहायक स्टाफ

श्री सत्यवीर सिंह, स्टाफ कार चालक
श्री जे बी ठाकुरी, स्टाफ कार चालक
श्री बलवान
श्री प्रदीप
श्री राजू
श्री राज कुमार
श्री मनीष कुमार
श्री राज कुमार
श्री सुधीर राणा
श्री बिरजू
श्री प्रदीप नेगी

वित्तीय विवरण

अध्याय 8

आरआईएस वार्षिक रिपोर्ट 2018–19

सिंह कृष्णा एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटैंट्स

8, सेकेंड फ्लोर, कृष्णा मार्केट, कालका जी, नई दिल्ली–110019

टेलीफोन : 32500444, टेलीफैक्स: 40590344, ई–मेल: skacamail@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली की आम सभा के सदस्यों के लिए

राय

हमने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, (निकाय), के तहत पंजीकृत एक सोसायटी 'विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली' के वित्तीय विवरण का ऑडिट किया है जिसमें 31 मार्च, 2019 तक की बैलेंस शीट, उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का विवरण तथा प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा–जोखा, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार सहित वित्तीय विवरण की अनुसूची शामिल हैं।

हमारी राय में, संलग्न वित्तीय विवरण इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार 31 मार्च, 2019 तक सोसायटी की वित्तीय स्थिति, उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिए इसके वित्तीय प्रदर्शन और प्राप्तियों एवं भुगतान का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण या तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

राय के लिए आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी 'ऑडिटिंग पर मानकों (एसए)' के अनुसार अपना ऑडिट किया। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरण के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जवाबदेही' अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार इस निकाय से बिल्कुल पृथक हैं और हमने आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा यह मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किया है, वह हमारी राय को ठोस आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और बिल्कुल उपयुक्त है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन और गवर्नेंस के प्रभारी की जवाबदेही

प्रबंधन पर ही इन वित्तीय विवरण को तैयार करने की जिम्मेदारी होती है जो भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार सोसायटी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन का एक सही व निष्पक्ष दृष्टिकोण अथवा तस्वीर पेश करते हैं। इस जिम्मेदारी में ऐसे वित्तीय विवरण को तैयार एवं प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त या प्रासंगिक माने जाने वाले आंतरिक नियंत्रण का स्वरूप निर्धारित करना, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं जो एक सटीक एवं निष्पक्ष तस्वीर पेश करते हैं और जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी तरह की तथ्य संबंधी गलतबयानी से मुक्त होते हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबंधन ही 'लाभकारी कारोबार वाले परिचालनरत या चालू निकाय' के रूप में अपनी कंपनी या सोसायटी की क्षमता का आकलन करने के लिए जवाबदेह होता है। प्रबंधन इसके लिए 'लाभकारी कारोबार वाले परिचालनरत निकाय' से संबंधित उन तथ्यों का खुलासा करता है, जो मान्य या लागू होते हैं। प्रबंधन इसके साथ ही लेखांकन के 'लाभकारी कारोबार वाले परिचालनरत निकाय' से संबंधित आधार का उपयोग करता है, बशर्ते कि प्रबंधन या तो अपने निकाय का परिसमापन करने या उसका परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या परिचालन बंद न करने के लिए उसके पास कोई यथार्थवादी विकल्प हो।

गवर्नेंस के प्रभारी लोग संबंधित इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर करीबी नजर रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। .

वित्तीय विवरण के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जवाबदेही

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी तरह की तथ्य संबंधी गलतबयानी से मुक्त हैं। हमारा उद्देश्य एक ऑडिटर रिपोर्ट जारी करना भी है जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत या यथोचित आश्वासन दरअसल आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि 'एसए' के अनुसार किए गए ऑडिट से किसी तथ्य संबंधी गलतबयानी का सदैव पता लग ही जाएगा, बशर्ते कि वह मौजूद हो। गलतबयानी दरअसल धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उसे तथ्य संबंधी गलतबयानी माना जाता है यदि व्यक्तिगत या समग्र रूप से वे इन वित्तीय विवरण के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं (यूजर) के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हों।

'एसए' के अनुसार किए जाने वाले ऑडिट के एक हिस्से के रूप में हम प्रोफेशनल निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान प्रोफेशनल संशय को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- हम धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरण की तथ्य संबंधी गलतबयानी के जोखिमों की पहचान एवं आकलन करते हैं, इन जोखिमों को कम करने में सक्षम ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन एवं निष्पादित करते हैं, और ऐसा ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय को ठोस आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं बिल्कुल उपयुक्त होता है। धोखाधड़ी से उत्पन्न होने वाली तथ्य संबंधी गलतबयानी का पता नहीं लगा पाने का जोखिम दरअसल त्रुटि से उत्पन्न होने वाली तथ्य संबंधी गलतबयानी से जुड़े जोखिम से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- हम ऑडिट के लिए प्रासंगिक माने जाने वाले आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं, ताकि ऐसी ऑडिट प्रक्रियाओं की डिजाइनिंग की जा सके जो विभिन्न परिस्थितियों में बिल्कुल उपयुक्त होती हैं।
- हम इस्तेमाल में लाई जा चुकी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का आकलन करते हैं।
- हम प्रबंधन द्वारा 'लाभकारी कारोबार वाले परिचालनरत निकाय' से संबंधित लेखांकन आधार का उपयोग किए जाने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और यह इस प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित होता है कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित ऐसी कोई तथ्य संबंधी अनिश्चितता है जो एक 'लाभकारी कारोबार वाले परिचालनरत निकाय' के रूप में अपना संचालन निरंतर जारी रखने संबंधी इस निकाय की क्षमता पर संशय प्रकट करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई तथ्य संबंधी अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के संबंधित प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमें अपनी राय में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी ऑडिटर रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण 'लाभकारी कारोबार वाले परिचालनरत निकाय' के रूप में इसका संचालन थम सकता है।
- हम प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री (कंटेंट) का आकलन करते हैं। हम इसका आकलन भी करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन और घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करना संभव हो।

हम अन्य बातों के अलावा ऑडिट की योजनाबद्ध गुंजाइश एवं समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में उन लोगों के साथ संवाद करते हैं, जो गवर्नेंस के प्रभारी हैं। इसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसकी पहचान हम अपने ऑडिट के दौरान करते हैं।

हम गवर्नेंस के प्रभारी लोगों को एक ऐसा विवरण भी प्रदान करते हैं जिसे हमने स्वायत्तता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ संकलन किया है। हम उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों पर संवाद करते हैं जिनका असर संभवतः हमारी स्वायत्तता पर, और जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों पर पड़ सकता है।

अन्य आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

हम यह बयां करते हैं कि :

(1) हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों की मांग की है और उन्हें प्राप्त किया है जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं धारणा के अनुसार हमारे ऑडिट के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

(2) हमारी राय में, कानून के तहत आवश्यक माने जाने वाले बही–खाते को निकाय ने अब तक बिल्कुल सही ढंग से सुव्यवस्थित रखा है, जैसा कि हमारे द्वारा बही–खाते की छान–बीन से प्रतीत होता है; और

(3) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई बैलेंस शीट, आय एवं व्यय का विवरण और प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा–जोखा वस्तुतः बही–खाते के अनुरूप ही हैं।

के लिए, सिंह कृष्ण एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म की पंजीकरण संख्या 008714C

(कृष्ण कुमार सिंह)
भागीदार
एम. संख्या 077494

यूडीआईएन : 19077494AAAABE6846

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 25/10/2019

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

(सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी)

31 मार्च, 2019 तक तुलन पत्र

राशि रु. में

	अनुसूची #	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2019 को	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018 को
देनदारियां			
अनुसंधान और विकास कोष	1	104,886,411.55	98,294,399.62
अचल परिसंपत्ति कोष (गैर – एफसीआरए)	2	20,563,226.00	22,048,929.00
अचल परिसंपत्ति कोष (एफसीआरए)		75,259.00	7,327.00
प्रायोजित परियोजनाओं की अव्ययित राशि (गैर–एफसीआरए)	3	9,715,074.00	13,608,591.04
प्रायोजित परियोजनाओं की अव्ययित राशि (एफसीआरए)		3,312,855.81	11,684,900.84
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (गैर – एफसीआरए)	4	50,783,177.67	32,435,356.00
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (एफसीआरए)		2,840,698.00	741,176.00
कुल		192,176,702.03	178,820,679.50
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां (गैर – एफसीआरए)	5	20,563,226.00	22,048,929.00
अचल परिसंपत्तियां (एफसीआरए)		476,555.00	408,623.00
निवेश (गैर – एफसीआरए)	6	38,032,610.00	35,705,765.00
निवेश (एफसीआरए)		85,701,574.70	78,553,429.70
प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्य राशि (गैर – एफसीआरए)	3	16,248,645.04	21,254,712.36
प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्य राशि (एफसीआरए)		5,473,025.70	495,652.66
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम, इत्यादि (गैर – एफसीआरए)	7	21,234,862.38	11,742,101.32
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम, इत्यादि (एफसीआरए)		4,446,203.21	8,611,466.46
कुल		192,176,702.03	178,820,679.50

खातों पर उल्लेखनीय लेखा परीक्षण नीतियां एवं नोट 16

अनुसूची 1 से 16 खातों के एक अंतरंग हिस्से का निर्माण करते हैं

आज की तारीख तक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न

कृते विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कृते सिंह कृष्णा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स
कंपनी की रजिस्ट्रेशन संख्या 008714सी

ह./–	ह./–	ह./–
(कृष्ण कुमार सिंह)	महेश सी. अरोड़ा	प्रो. सचिन चतुर्वेदी
साझेदार	निदेशक (वित्त एवं प्रशासन)	महानिदेशक

एम. संख्या 077494
यूडीआईएन : 19077494AAAABE6846
स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 25/10/2019

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था)
31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता राशि में

राशि रु. में

	अनुसूची #	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2019 को	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018 को
आय			
भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से अनुदान सहायता	4 (ए)	116,989,000.00	82,302,589.00
प्रायोजित परियोजना अनुदान कार्यक्रमों से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए हस्तांतरित किया गया (गैर – एफसीआरए और एफसीआरए)	3	96,637,564.54	62,317,121.38
प्रायोजित परियोजनाओं के पूरा होने पर अधिशेष राशि हस्तांतरित की गई (गैर – एफसीआरए और एफसीआरए)		5,101,707.56	4,157,669.14
रॉयल्टी, प्रकाशन, इत्यादि से आय (गैर – एफसीआरए)		84,647.52	95,397.00
अर्जित ब्याज :			
सावधि जमा पर (एफसीआरए)		5,766,268.00	5,174,269.00
सावधि जमा पर (गैर – एफसीआरए)		1,004,714.00	1,324,460.00
बचत खाते/ऑटो स्वीप खाते पर (एफसीआरए)		275,746.00	374,988.00
बचत खाते/ऑटो स्वीप खाते पर (गैर – एफसीआरए)		388,124.00	371,295.00
कर्मचारियों को दिए ऋण पर (गैर – एफसीआरए)		30,456.00	17,819.00
आयकर रिफंड पर (गैर – एफसीआरए)		-	26,061.00
अन्य विविध आय (गैर – एफसीआरए)		2,000.00	68,392.00
प्रायोजित परियोजनाओं से प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऊपरी खर्च (ओवरहेड) के लिए रिकवरी (गैर – एफसीआरए और एफसीआरए)		5,751,850.18	1,098,441.00
पूर्व लेखांकन अवधि में अर्जित आय		-	193,511.00
अचल परिसंपत्ति कोष से हस्तांतरित राशि – बेची / बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियों का डब्ल्यू.डी.वी. (गैर – एफसीआरए और एफसीआरए)	2	-	23,745.00
अचल परिसंपत्ति कोष से हस्तांतरित राशि – भारत सरकार / प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्त अनुदान सहायता से अधिग्रहीत अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास (गैर – एफसीआरए और एफसीआरए)		4,840,957.00	8,314,510.25
देय को बट्टे खाते में डाला गया		-	272,583.00
कुल		236,873,034.80	166,132,850.77
व्यय			
कार्यक्रम व्यय – प्रायोजित परियोजनाएं (गैर– एफसीआरए और एफसीआरए)	8	96,637,564.54	62,317,121.38
प्रतिष्ठान व्यय (गैर – एफसीआरए)	9	88,676,184.00	48,070,225.00
प्रशासनिक और अन्य कार्यक्रम व्यय (गैर – एफसीआरए)	10	36,542,700.89	34,217,588.22
प्रशासनिक और अन्य कार्यक्रम व्यय (एफसीआरए)	11	91,987.50	153,030.39
अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास (गैर – एफसीआरए और एफसीआरए)	5	4,840,957.00	13,206,795.25
प्रायोजित परियोजनाओं के पूरा होने पर घाटा राशि हस्तांतरित की गई (गैर – एफसीआरए और एफसीआरए)	3	3,491,628.94	1,997,467.94
पूर्व लेखांकन अवधि में किए गए खर्च		-	105,087.00
अधिशेष को अनुसंधान और विकास कोष में हस्तांतरित कर दिया गया		6,592,011.93	6,065,535.59
कुल		236,873,034.80	166,132,850.77

खातों पर उल्लेखनीय लेखा परीक्षण नीतियां एवं नोट 16

अनुसूची 1 से 16 खातों के एक अंतरंग हिस्से का निर्माण करते हैं आज की तारीख तक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न

कृते सिंह कृष्णा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स
कंपनी की रजिस्ट्रेशन संख्या 008714C

ह./–
(कृष्ण कुमार सिंह)
साझेदार
एम. संख्या 077494
यूडीआईएन : 19077494AAAABE6846
स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 25/10/2019

कृते विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

ह./–
महेश सी. अरोड़ा
निदेशक (वित्त एवं प्रशासन)

ह./–
प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
(1860 के सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी)

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रसीद और भुगतान

	प्राप्तियां	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2019		वर्ष समाप्त 31 अप्रैल 2018			भुगतान	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2019		वर्ष समाप्त 31 अप्रैल 2018	
ए	**प्रारंभिक शेषराशि (ओपनिंग बैलेंस)**					ए	**व्यय (गैर – एफसीआरए)**				
i)	अपने पास नकदी (गैर–एफसीआरए)	41,393.00		33,130.00		i)	प्रतिष्ठान व्यय (अनुसूची – 12)	77,637,698.00		50,040,539.00	
ii)	बैंक में जमा राशि :					ii)	प्रशासनिक और अन्य कार्यक्रम व्यय (अनुसूची–13)	39,086,714.48		31,915,182.89	
	बचत खाते में– आंध्रा बैंक	38,818.00		138,437.00							
	बचत खाते / ऑटो स्वीप में – बैंक ऑफ इंडिया (गैर – एफसीआरए)	7,610,981.32		4,371,201.80		iii)	कार्यक्रम व्यय – प्रायोजित परियोजनाएं (अनुसूची –15)	68,647,158.98		41,903,115.24	
	बचत खाते / ऑटो स्वीप में – बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	3,170,177.46		9,026,540.77			**कुल ए**		185,371,571.46		123,858,837.13
	सावधि जमा में – बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	78,553,429.70		64,099,959.03		बी	**व्यय (एफसीआरए)**				
						i)	प्रशासनिक और अन्य कार्यक्रम व्यय (अनुसूची – 14)	90,927.50		153,030.39	
	सावधि जमा में – बैंक ऑफ इंडिया (गैर – एफसीआरए)	35,705,765.00		32,073,086.35							
iii)	डाक टिकट– फ्रैंकिंग मशीन में बैलेंस (गैर – एफसीआरए)	185,222.00		200,811.00		ii)	कार्यक्रम व्यय – प्रायोजित परियोजनाएं (अनुसूची –15)	12,315,793.12		19,667,738.14	
	कुल ए		125,305,786.48		109,943,165.95		**कुल बी**		12,406,720.62		19,820,768.53
बी	**प्राप्त अनुदान**					सी	**अचल परिसंपत्तियों के लिए भुगतान**				
i)	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से	120,000,000.00		86,500,000.00		i)	अचल परिसंपत्तियों के लिए भुगतान (गैर– एफसीआरए)	2,949,024.00		2,948,224.00	
ii)	विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं से (गैर – एफसीआरए)	77,097,441.00		41,074,496.00		ii)	अचल परिसंपत्तियों के लिए भुगतान (एफसीआरए)	39,991.00			
iii)	विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं से (एफसीआरए)	9,325,520.37		27,548,750.29			**कुल सी**		2,989,015.00		2,948,224.00
	कुल बी		206,422,961.37		155,123,246.29	डी	**अग्रिम और जमा**				
						i)	अग्रिम (गैर – एफसीआरए)	897,576.00		158,990.00	

सी	**अर्जित ब्याज**					ii)	अग्रिम (एफसीआरए)	260,626.00		12,114.00	
						iii)	प्राप्य टीडीएस (गैर – एफसीआरए)	433,077.00		136,859.00	
i)	ऋण, अग्रिम, आदि पर ब्याज (गैर – एफसीआरए)	30,456.00		43,880.00		iv)	प्राप्य टीडीएस (एफसीआरए)	361,715.00		-	
						v)	गतावधि या पुराने चेक (गैर – एफसीआरए)	-		10,614.00	
ii)	बचत बैंक खाता / ऑटो स्वीप पर ब्याज (एफसीआरए)	275,552.00		374,988.00			**कुल डी**		1,952,994.00		318,577.00
iii)	सावधि जमा खातों पर ब्याज (गैर – एफसीआरए)	1,024,176.00		2,795,670.00							
						ई	**अन्य**				
iv)	सावधि जमा खातों पर ब्याज (एफसीआरए)	7,417,153.00		3,954,506.00		i)	अनुदान रिफंड (एफसीआरए)	-		1,616,841.00	
						ii)	कर्मचारियों की ओर से प्राप्त राशि का रिफंड	107,096.00		-	
v)	बचत बैंक खाता / ऑटो स्वीप पर ब्याज (गैर – एफसीआरए)	387,730.00		368,768.00							
						iii)	आरआईएस भविष्य निधि में भुगतान की गई राशि	-		86,737.10	
vi)	बचत बैंक खाते पर ब्याज – आंध्रा बैंक (गैर – एफसीआरए)	394.00		2,527.00							
							कुल ई		107,096.00		1,703,578.10
	कुल सी		9,135,461.00		7,540,339.00						
	कुल अग्रेनीत (कैरिड फॉरवर्ड)		340,864,208.85		272,606,751.24		**कुल अग्रेनीत (कैरिड फॉरवर्ड)**		202,827,397.08		148,649,984.76
	कुल अग्रानीत (ब्रॉट फॉरवर्ड)		340,864,208.85		272,606,751.24		**कुल अग्रानीत (ब्रॉट फॉरवर्ड)**		202,827,397.08		148,649,984.76
डी	**अन्य आय**					**एफ**	**अंतिम शेषराशि (क्लोजिंग बैलेंस)**				
i)	प्रकाशन बिक्री (गैर – एफसीआरए)	1,600.00		4,800.00		i)	अपने पास नकदी (गैर –एफसीआरए)	39,077.00		41,393.00	
ii)	रॉयल्टी (गैर – एफसीआरए)	81,384.00		60,569.00		ii)	बैंक में जमा राशि :				
iii)	विविध आय (गैर – एफसीआरए)	400.00		211,749.00			बचत खाते में – आंध्रा बैंक (गैर – एफसीआरए)	39,140.00		38,818.00	
	कुल डी		83,384.00		277,118.00		बचत खाते / ऑटो स्वीप में – बैंक ऑफ इंडिया (गैर – एफसीआरए)	14,999,045.86		7,610,981.32	

ई	**अग्रिम और जमा**										
i)	ऋण / अग्रिम की वसूली (गैर – एफसीआरए)	188,637.00		236,805.00			बचत खाते / ऑटो स्वीप में – बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	43,044.21		3,170,177.46	
ii)	कर्मचारियों से अग्रिम की वसूली (गैर – एफसीआरए)	-		142,916.00			सावधि जमा में – बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	85,701,574.70		78,553,429.70	
iii)	गतावधि या पुराने चेक (गैर – एफसीआरए)	379,038.00		-			सावधि जमा में – बैंक ऑफ इंडिया (गैर – एफसीआरए)	38,032,610.00		35,705,765.00	
iv)	गतावधि या पुराने चेक (एफसीआरए)	82,134.00									
v)	अग्रिम में प्राप्त राशि (गैर – एफसीआरए)	-		107,096.00							
						iii)	डाक टिकट – फ्रैंकिंग मशीन में बैलेंस (गैर – एफसीआरए)	233,293.00		185,222.00	
vi)	ऋण / अग्रिम की वसूली (गैर – एफसीआरए) (FCRA)	9,780.00		110,107.00							
vii)	आरआईएस पीएफ की ओर से प्राप्त राशि	308,000.00		-			**कुल एफ**		139,087,784.77		125,305,786.48
	कुल ई		967,589.00		596,924.00						
एफ	**अन्य**										
i)	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	-		73,899.00							
ii)	आयकर रिफंड	-		401,079.00							
	कुल एफ		-		474,978.00						
	योग		341,915,181.85		273,955,771.24		**योग**		341,915,181.85		273,955,771.24

खातों पर उल्लेखनीय लेखा परीक्षण नीतियां एवं नोट 16
अनुसूची 1 से 16 खातों के एक अंतरंग हिस्से का निर्माण करते हैं
आज की तारीख तक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न

कृते विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कृते सिंह कृष्णा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स
कंपनी की रजिस्ट्रेशन संख्या 008714IC

ह./–
(कृष्ण कुमार सिंह)
साझेदार
एम. संख्या 077494
यूडीआईएन : 19077494AAAABE6846
स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 25/10/2019

ह./–
महेश सी. अरोड़ा
निदेशक (वित्त एवं प्रशासन)

ह./–
प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

आरआईएस

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस), नई दिल्ली स्थित एक स्वायत्त नीतिगत अनुसंधान संस्थान हैं जोकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों पर कार्य करता है। आरआईएस प्रभावशाली नीतिगत वार्ता को बढ़ावा देने एवं वैश्विक एवं क्षेत्रिय आर्थिक मामलों के संबंध में विकासशील देशों में क्षमता निर्माण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

आरआईएस की कार्य योजना का मुख्य केन्द्र बिन्दु दक्षिणीय सहयोग को बढ़ावा देना और विभिन्न मंचों पर बहुपक्षीय बातचीत में विकासशील देशों के साथ समन्वय करना है। आरआईएस क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के कई प्रयासों की अंतः सरकारी प्रक्रियाओं में कार्यरत है। आरआईएस अपने विचारकों के गहन कार्य के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों एवं विकास भागीदारी के पटल पर नीतिगत सुसंगतता को सुदृढ़ करता है।

आरआईएस एवं इसकी कार्ययोजना के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने क लिए कृपया इसकी वेबसाइटः wwww.ris.org.in देखें।

आरआईएस
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर 4-बी, चौथा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003, भारत । दूरभाषः 91-11-24682177-80
फैक्सः 91-11-24682173-74, ई-मेलः dgoffice@ris.org.in
वेबसाइटः http://www.ris.org.in